राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

कोहली के नाम से कोटला में होगा स्टैंड
>> 14

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 70

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, सोमवार, 19 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

उम्मेद ने जगाई रोजगार और विकास की उम्मीद

उत्तरकाशी : उत्तराखंड के सिंगोठ गांव निवासी 50 वर्षीय उम्मेद सिंह कलूड़ा

स्वरोजगार और उन्नति की राह बनाकर मिसाल बन गए हैं। पारंपरिक तरीकों व नई तकनीक के साथ वह खुद भी कमा रहे हैं और दर्जनों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। किसी को मछली पालन में लगाया है तो किसी को सब्जी उत्पादन में। (पेज-11)

जागरण विशेष

स्कूबा डाइविंग कर देखें द्वारका नगरी

द्वारकापुरी : समुद्र तल में जाकर दुनिया के प्राचीन नगरों में एक द्वारका की भव्यता का

साक्षात दर्शन अब मुश्किल नहीं रहा। स्कूबा डाइविंग कर 60 से 80 फीट नीचे तक जाकर इस प्राचीन नगर के अवशेष को छूकर देखा जा सकता है। (पेज-11)

वर्दी बताएगी जवान कहां हैं

कानपुर : उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान (यूपीटीटीआइ) सेना के लिए स्मार्ट

क्लॉथ (वर्दी) तैयार करने जा रहा है। इसमें लगे सेंसर व चिप से सैनिकों की लोकेशन आसानी से जानकर उनकी मदद की जा सकेगी। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

हमें आजाद करते हैं लोकतंत्र और शिक्षा : मोदी

थिंपू : लोकतंत्र और शिक्षा दोनों का लक्ष्य होता है हमें आजाद करना। दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों ही हमें अपना सर्वश्रेष्ठ पाने में मदद करते हैं। भूटान दौरे के दूसरे दिन रविवार को नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने भारत-भूटान को प्राकृतिक सहयोगी बताते हुए दोनों के संबंधों की तारीफ भी की। देर शाम मोदी भारत पहुंच गए।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

रतुल पुरी पर 354 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मुकदमा

नई दिल्ली : सीबीआइ ने मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी समेत अन्य के खिलाफ 354 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। मामला मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड से जुड़ा है, जिसमें रतुल कार्यकारी निदेशक था। एजेंसी ने रविवार को आरोपित निदेशकों के आवास व दफ्तरों समेत कुल छह ठिकानों पर छापेमारी भी की।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

काबुल में शादी समारोह में आत्मघाती हमला, 63 की मौत

काबुल : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकियों ने एक शादी समारोह को निशाना बनाया है। शनिवार रात एक वेडिंग हॉल में हुए आत्मघाती धमाके में 63 लोगों की मौत हो गई और 182 घायल हो गए। जान गंवाने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। अमेरिका और तालिबान में चल रही शांति वार्ता के बीच हाल के महीनों की इस सबसे भीषण वारदात की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) ने ली है।

हिमाचल में बारिश ने तोड़ा 70 साल का रिकॉर्ड, 22 की मौत

जेएनएन, शिमला

केरल और महाराष्ट्र के बाद अब देश के पहाड़ी राज्य भारी बारिश और बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाके भी शामिल हैं। हिमाचल में तो 70 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। इसके चलते अब तक 22 लोगों को मौत हो चुकी है और दर्जनों घायल हुए हैं। सात लापता बताए जा रहे हैं। कुल्लू जिले का संपर्क शेष दुनिया से कट चुका है। ऊना और शिमला-सोलन के बीच रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। वहीं, उत्तराखंड में बारिश के कारण नौ लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में छह और उत्तर प्रदेश में तीन लोग काल का ग्रास बने। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार कुछ राहत मिलने का संभावना है।

- सात लोग लापता, भूस्खलन और बाढ़ की चपेट में आने से दर्जनों लोग घायल

102 मिलीमीटर बारिश हुई बीते 24 घंटे के दौरान

100 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी 1950 में

330 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है नैनादेवी में

20 साल बाद अगस्त में बर्फ : हिमाचल की चोटियों पर 20 साल बाद अगस्त में बर्फबारी देखी गई है। कुल्लू जिले के रोहतांग दर्रे और लाहुल-स्पीति की चोटियों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई।

श्री नैना देवी में सर्वाधिक बारिश : हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान औसत 102.5 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं, इससे पहले 14 अगस्त 2011 को 74 मिलीमीटर और 1950 में 100 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। सबसे अधिक वर्षा श्री नैनादेवी में 330 मिलीमीटर हुई।

हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान वर्ष 1950 से उपलब्ध डाटा के मुताबिक सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। 20 साल बाद प्रदेश के ऊच्च पर्वतीय इलाकों में अगस्त के महीने में बर्फबारी दर्ज की गई है। सोमवार से विभिन्न जिलों में वर्षा में कमी आएगी।

– मनमोहन सिंह, निदेशक मौसम विभाग हिमाचल प्रदेश

उत्तराखंड में भी बारिश का कहर, नौ की मौत, 15 लापता

उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में बादल फटने, नदी नालों में उफान व भूस्खलन की घटनाओं में जानमाल की काफी क्षति हुई है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 15 लोग नालों के उफान और मलबे के साथ बह गए, जबकि एक ही परिवार के आठ सदस्य मकान के मलबे में दब गए। ऐसे में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 अभी लापता हैं।

पंजाब में 81 गांव खाली करवाने के आदेश, छह की मौत

पंजाब में शनिवार रात तेज बारिश के बाद रविवार सुबह मौसम साफ होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि भाखड़ा बांध से पानी छोड़ने के कारण औद्योगिक नगरी लुधियाना से लेकर फिरोजपुर जिले तक सतलुज का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से जालंधर के 81 गांव खाली करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। लुधियाना के खन्ना में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। इसके अलावा राज्य में तीन अन्य लोगों की भी मौत हुई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ली नदियों का जलस्तर बढ़ने पर रिपोर्ट लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं।

भारी बारिश के दौरान शिमला के ब्योलिंग में हुए भूस्खलन के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई बस और अन्य वाहन। जागरण

अब सिर्फ गुलाम कश्मीर पर होगी बात : राजनाथ

खरी बात ▶ अनुच्छेद 370 हटने से बौखलाए पाक को रक्षा मंत्री की दो टूक

पड़ोसी देश को नसीहत, पहले आतंकवाद रोको फिर होगी कोई बातचीत

सुधीर तंवर, कालका (पंचकूला)

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में अलग-थलग पड़ चुके पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा हमला बोला है। भारत पर वार्ता के लिए दबाव बना रहे पाक को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, पहले वह आतंकवाद रोके। वार्ता होगी भी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर पर।

राजनाथ रविवार को यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पूर्व समारोह को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा, पड़ोसी देश पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है। हमने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए अनुच्छेद 370 को समाप्त किया, जबकि पाकिस्तान बेवजह तिलमिलाया हुआ है। कभी हमें धमकी दे रहा तो कभी दूसरे देशों के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन उसे अमेरिका सहित किसी का समर्थन नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुटकियों में जम्मू-कश्मीर को देश से अलग करने वाले अनुच्छेद 370 को हटाकर अपना 56 इंच का सीना सभी को दिखा दिया है। उन्होंने पुलवामा में आतंकी हमले के बाद बालाकोट में आंतकियों के ठिकाने पर हमले पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए कहा, पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में कहा था कि भारत बालाकोट से भी बड़ा हमला कर सकता है। यानी अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक से इन्कार करते रहे पड़ोसी मुल्क ने भी मान लिया है कि बालाकोट में बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और भारत अपने सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।

...तो भारत की जमीं से ध्वस्त हो जाते पड़ोसी मुल्क में आतंकी ठिकाने : फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में देरी का ठीकरा पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर फोड़ते हुए राजनाथ ने कहा, दस साल पहले ही इनकी खरीद हो जानी चाहिए थी। अगर ये तभी खरीद लिए जाते तो हमारी वायुसेना को बालाकोट में जाकर हवाई हमले नहीं करने पड़ते। हम भारत की सरजमीं से ही पाक में चल रहे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर देते। अब केंद्र सरकार जल्द ही राफेल को खरीदने जा रही है जिससे कोई देश हमारी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकेगा।

बौखलाए इमरान का नया पैंतरा, बोले- भारत में सुरक्षित नहीं परमाणु हथियार पेज>>13

कालका में रविवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत से पूर्व रैली को संबोधित करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जागरण

आतंकवाद से डराने की कोशिश

रक्षा मंत्री ने कहा कि बौखलाया पाकिस्तान आतंकवाद से भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। उसे समझना चाहिए कि अब पूरे देश में एक संविधान, एक विधान और एक निशान हो चुका है। विपक्ष के लोग कहते थे कि इससे भारत बंट जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। कश्मीर में हालात पूरी तरह सामान्य हैं। इससे पहले शुक्रवार को रक्षा मंत्री ने पोखरण (राजस्थान) में भी पाक पर निशाना साधते हुए कहा था कि आज तक नो फर्स्ट यूज' ही भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी रही है। भविष्य में क्या होगा, वो सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

जितेंद्र सिंह ने भी कहा, अब गुलाम कश्मीर लेना है

जम्मू : प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब पाक से गुलाम कश्मीर को वापस कैसे लेना है, यह सोचने का समय है। भगवान वह दिन भी जल्द दिखाए। पार्टी कार्यालय में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, नजरबंद किए गए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे कई नेता स्वयं को कैद में बताकर हालात बिगाड़ना चाहते हैं। इसे कैद नहीं कहते हैं, कैद तो वह थी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और महाराजा हरि सिंह को दी गई।

आरक्षण के मुद्दे पर सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा के पक्ष में आरएसएस के प्रमुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि जो आरक्षण के पक्ष में हैं और जो इसके खिलाफ हैं उन लोगों के बीच इस पर सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत होनी चाहिए। भागवत ने कहा कि उन्होंने पहले भी आरक्षण पर बात की थी लेकिन इससे काफी हंगामा मचा और पूरी चर्चा वास्तविक मुद्दे से भटक गई।

उन्होंने कहा, आरक्षण का पक्ष लेने वालों को उन लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए जो इसके खिलाफ हैं। इसी तरह से विरोध करने वालों को इसका समर्थन करने वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर चर्चा हर बार तीखी हो जाती है जबकि इस दृष्टिकोण पर

कहा, समर्थक और विरोधी दोनों एक-दूसरे के हित को ध्यान में रख बोलें

समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य जरूरी है। भागवत 'ज्ञान उत्सव' के समापन सत्र में बोल रहे थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं पर था। ज्ञात हो, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी संघ प्रमुख ने आरक्षण नीति की समीक्षा की वकालत की थी, जिस पर कई दलों और जाति समूहों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई थी। भागवत ने कहा, आरएसएस, भाजपा और पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार तीन अलग-अलग इकाइयां हैं और किसी को दूसरे के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

नरेंद्र मोदी सरकार पर आरएसएस के प्रभाव की धारणा के बारे में भागवत ने कहा, 'चूंकि भाजपा और इस सरकार में संघ कार्यकर्ता हैं, वे आरएसएस को सुनेंगे, लेकिन उनके लिए हमारे साथ सहमत होना जरूरी नहीं है। वे असहमत भी हो सकते हैं।' चूंकि भाजपा सरकार में है, उसे व्यापक आधार पर देखना होगा और वह संघ की बात से असहमत हो सकती है। एक बार पार्टी के सत्ता में आने के बाद उसके लिए सरकार और राष्ट्रीय हित प्राथमिकता बन जाते हैं। ज्ञान उत्सव का आयोजनआएसएस से जुड़े शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में किया गया था।

पूर्व केंद्रीय मंत्री जेटली की हालत नाजुक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि एम्स ने 10 अगस्त के बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, जेटली को एक्स्ट्रा-कॉरपोरियल मैम्ब्रेन ऑक्सीजेनेशन (एक्मो) पर रखा गया है। जब मरीज का फेफड़ा व हार्ट काम नहीं करता और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो उसे एक्मो मशीन का सपोर्ट दिया जाता है। वहीं, शनिवार को जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, उप्र की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, डॉ. हर्षवर्धन, वायु सेना प्रमुख बीएस धनोआ, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेता एम्स पहुंचे। ज्ञात हो, 66 वर्षीय जेटली को 9 अगस्त को एम्स में भर्ती किया गया था। वह लंबे समय से बीमार चल रहे हैं।

हुड्डा ने हाईकमान को दिखाई ताकत, बोले-कांग्रेस भटक गई है

ओपी वशिष्ठ, रोहतक

हरियाणा में दस साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने गढ़ रोहतक में परिवर्तन महारैली के जरिए कांग्रेस हाईकमान को ताकत दिखाने के साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया। उन्होंने किसान, सैनिक, कर्मचारी, गृहणी, व्यापारी व युवाओं को साधते हुए वादों की झड़ी लगा दी। चार अलग-अलग वर्ग के डिप्टी सीएम बनाने का एलान भी किया। आगामी रणनीति बनाने के लिए 25 सदस्यीय समिति भी बना दी, जो निर्णय लेगी कि हुड्डा कांग्रेस में रहकर लड़ाई लड़ेंगे या अलग राह अपनाएंगे। हुड्डा जहां भाजपा पर गरम दिखे, वहीं पीएम मोदी पर नरम नजर आए।

हुड्डा ने कहा, आज सभी पाबंदियों से मुक्त होकर अपने मन और आत्मा की बात करूंगा। देशभक्ति और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। इसलिए पार्टी से हटकर अनुच्छेद

पूर्व सीएम ने परिवर्तन महारैली में फूंका चुनावी बिगुल, जारी किया घोषणा पत्र

370 हटाने का समर्थन किया है, जबकि पार्टी के उनके कुछ साथियों ने इसे हटाने का विरोध भी किया। उन्होंने कहा, अब कांग्रेस पहले वाली नहीं रही, पार्टी में भटकाव आ गया है।

उन्होंने कहा, उनके शासनकाल में हरियाणा खुशहाली में नंबर वन था। अब अपराध, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी में नंबर वन हो चुका है। अनुच्छेद 370 की आड़ में भाजपा पांच साल के घोटालों को छिपाना चाहती है, लेकिन जनता को हिसाब देना पड़ेगा। इस अवसर पर पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा उनके समर्थित 13 विधायक व 60 पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री मौजूद थे। (पेज-4 भी देखें)

जम्मू में मोबाइल-इंटरनेट फिर बंद, श्रीनगर में आज खुलेंगे स्कूल

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू के पांच जिलों में रविवार सुबह मोबाइल व इंटरनेट सेवा दोबारा बंद कर दी गई। शुक्रवार देर रात हालात सामान्य होने के बाद प्रशासन ने जम्मू, रियासी, सांबा, कठुआ व ऊधमपुर में मोबाइल व इंटरनेट सेवा बहाल की थी। 24 घंटे के भीतर नेट सेवा बंद होने से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। वहीं, देर शाम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जम्मू संभाग में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और न प्रशासन की ओर से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तकनीकी कारणों से मोबाइल और इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है।

- प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा, तकनीकी कारणों से बंद की गई है सेवा
- कहा, सभी जिलों में बेहतर हैं हालात, अफवाहों पर विश्वास न करे आवाम

जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने पत्रकारों को बताया शुक्रवार देर रात 2जी सेवा शुरू की गई। इससे ट्रैफिक ओवरलोड होने से मोबाइल सेवा बंद हो गई। प्रशासन ने मोबाइल कंपनियों को 2जी सेवा बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया है। इसके विपरीत डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान ने प्रशासन के फेसबुक पेज पर जो बयान जारी किया, उसमें कहा कि अफवाहों पर अंकुश लगाने और शरारती तत्व किसी तरह की दहशत न फैलाए, इसलिए मोबाइल इंटरनेट को बंद किया है। वहीं, बाद में उन्होंने नेट बंद करने का कारण तकनीकी बताया। दोनों अफसरों ने दावा किया कि जम्मू से राजौरी-पुंछ तक हालात सामान्य है। सभी जिलों से प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। लैंड लाइन फोन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। ब्राडबैंड पहले दिन से जारी है। मोबाइल इंटरनेट सेवा पुनः बहाली के सवाल पर वर्मा ने कहा, इसमें दो-तीन दिन लगेंगे।

कश्मीर में कई क्षेत्रों में ढील पेज>>5

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
LIVE/ONLINE Classes Available
www.visionias.in

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन 2020
6 Aug | 12 Sept
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक
- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- निबंध लेखन - शैली, PT 365, Mains 365, सीसैट कक्षाएं
- मुख्य परीक्षा, निबंध, PT, सीसैट टेस्ट सीरीज

अभ्यास मेन्स 2019
ऑल इंडिया GS मेन्स मॉक टेस्ट (ऑफलाइन)
30 शहरों में Also in English Medium
GS-I & GS-II 24 अगस्त | GS-III & GS-IV 25 अगस्त
पंजीकरण करें www.visionias.in/abhyaas
पंजीकरण करने की आखिरी तिथि: 19 अगस्त
AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | COIMBATORE
DEHRADUN | DELHI | GHAZIABAD | GREATER NOIDA | GUWAHATI | HYDERABAD | INDORE | JAIPUR
JAMMU | JODHPUR | KANPUR | KOLKATA | LUCKNOW | MUMBAI | PATNA | PRAYAGRAJ | PUNE
RAIPUR | RANCHI | SHIMLA | THIRUVANANTHAPURAM | VARANASI | VISAKHAPATNAM
DELHI • 635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar
• 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6,1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
• Contact : 8468022022, 9019066066, 9650617807
JAIPUR 9001949244 | PUNE 8007500096 | HYDERABAD 9000104133 | AHMEDABAD 9909447040 | LUCKNOW 8468022022

नया नियम

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 18 जुलाई को ही बनाया था यह नया नियम, इससे पहले सिर्फ क्षेत्ररक्षण के लिए स्थानापन्न खिलाड़ी को मैदान में उतरने की थी इजाजत

क्रिकेट इतिहास में पहले स्थानापन्न बल्लेबाज बने लाबुशाने

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

टेस्ट क्रिकेट के 142 वर्ष के इतिहास और 2354 टेस्ट के बाद यह पहली बार हुआ जब बीच मैच में चोटिल होकर बाहर हुए खिलाड़ी की जगह आधिकारिक रूप से स्थानापन्न बल्लेबाज को शामिल किया गया। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की 148 किमी प्रति घंटे की गति वाली गेंद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ की गर्दन पर लग गई थी। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़े थे। स्मिथ बाद में बल्लेबाजी करने आए और 92 रन पर आउट हो गए।

रविवार को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने टेस्ट के पांचवें दिन स्मिथ की जगह मार्नस लाबुशाने को स्थानापन्न बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया। वह दूसरी पारी में स्मिथ की जगह बल्लेबाजी करने आए और 100 गेंद में शानदार 59 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। ऐसे में लाबुशाने इस नए नियम के तहत स्थानापन्न खिलाड़ी बनने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए। लाबुशाने को भी हेलमेट की ग्रिल पर आर्चर की गेंद लगी, हालांकि वह जल्द ही संभल गए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने विश्व कप के बाद ही 18 जुलाई को इस नियम में संशोधन किया था। सीए ने बताया गया है कि स्मिथ की जगह लाबुशाने को बतौर स्थानापन्न टीम में शामिल किया गया है। स्मिथ को जब गेंद लगी तब वह 80 रन बना चुके थे। फीजियो ने मैदान पर स्मिथ को देखा और उन्हें बाहर ले गए। तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर छह विकेट पर 203 रन था। हालांकि अगला विकेट गिरने के बाद वह फिर बल्लेबाजी के लिए आ गए थे। सीए ने साथ ही कहा कि तीसरे टेस्ट के लिए स्टीव की उपलब्धता पर आने वाले दिनों में फैसला लिया जाएगा। स्टीव की फिटनेस का आकलन किया जाएगा। एहतियाती तौर पर रविवार को स्टीव का एक स्कैन हुआ। दोनों टीमों के बीच तीसरा टेस्ट 22 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा।

जोफ्रा की गेंद लगने के बाद घायल स्टीव स्मिथ (फाइल)

क्या है नया नियम : दरअसल, इस नियम के बनने से पहले अगर टेस्ट क्रिकेट के बीच में कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता था तो उस खिलाड़ी की टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ता था। चोटिल खिलाड़ी की जगह आए स्थानापन्न खिलाड़ी को सिर्फ क्षेत्ररक्षण करने का अधिकार था। 14 जुलाई को विश्व कप खत्म होने के बाद 18 जुलाई को लंदन में आइसीसी की सालाना आम बैठक में नया नियम बनाया गया, जिसके तहत अगर खिलाड़ी को सिर्फ सिर के आस-पास गेंद लगती है और वह दोबारा खेलने की स्थिति में नहीं होता है तो उसे बीच टेस्ट से बाहर कर स्थानापन्न खिलाड़ी को शामिल किया जा सकता था। नियम के मुताबिक बल्लेबाज के चोटिल होने पर बल्लेबाज और गेंदबाज के चोटिल होने पर गेंदबाज से ही बदला जा सकता है।

लैंगर बोले, हेलमेट पर 'नेक गार्ड' अनिवार्य होने पर हैरानी नहीं होगी : ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर का कहना है कि उन्हें हैरानी नहीं होगी, यदि भविष्य में हेलमेट पर 'नेक गार्ड' (गर्दन की सुरक्षा के लिए) पहनना अनिवार्य हो जाए। सिडनी में 2014 में फिल ह्यूज की मौत के बाद से सुरक्षा के लिए खिलाड़ियों ने 'नेक गार्ड' लगाना शुरू किया था। हालांकि स्मिथ बिना 'नेक गार्ड' के हेलमेट पहने हुए थे।

29.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा रविवार को राजधानी में। यह सामान्य से चार डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि सामान्य से दो डिग्री कम है। तापमान मे यह गिरावट बारिश के कारण हुई है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 19 अगस्त 2019

एम्स की इमरजेंसी सेवाएं बहाल, ओपीडी भी रहेगी सामान्य

सुधरे हालात ▶ शैक्षणिक ब्लॉक में शनिवार को आग लगने से संस्थान को हुआ है करोड़ों का नुकसान

ऑपरेशन थियेटर खुले रहेंगे और पहले से निर्धारित ऑपरेशन भी होंगे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

एम्स के शैक्षणिक ब्लॉक में आग लगने की घटना के बाद रविवार को इमरजेंसी सुविधा बहाल कर दी गई। साथ ही इमरजेंसी व अस्पताल के एबी ब्लॉक से दूसरी जगह स्थानांतरित किए गए सैकड़ों मरीजों को वापस वार्ड में भर्ती किया गया। इससे अस्पताल का एबी वार्ड भी शुरू हो गया। अब सोमवार को ओपीडी सेवा भी सामान्य रहेगी। ऑपरेशन थियेटर भी खुले रहेंगे और पहले से निर्धारित ऑपरेशन भी होंगे, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, लैब मेडिसिन से संबंधित जांच सुविधाएं प्रभावित रहेंगी। इसलिए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इमरजेंसी लैब ठीक है। इसलिए इमरजेंसी लैब में जांचें होंगी।

दरअसल, दूसरी मंजिल पर स्थित माइक्रोबायोलॉजी विभाग के लैब में ही पहले आग लगी थी। इसलिए माइक्रोबायोलॉजी विभाग की लैब व सभी मशीनें पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई हैं। इसके पास कॉरिडोर के दोनों तरफ के सभी कमरे (डॉक्टरों के दफ्तर, रिकार्ड रूम) व लैब जल गए हैं। उनमें रखा हर सामान, कंप्यूटर, हजारों मरीजों के सैंपल व जांच में इस्तेमाल होने वाले केमिकल भी नष्ट हो गए हैं। घटना से एम्स को करोड़ों का नुकसान हुआ है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक कर की समीक्षा : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने रविवार सुबह एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया व संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठकर स्थिति की समीक्षा की। इसमें एम्स प्रशासन ने उन्हें बताया कि एबी ब्लॉक से दूसरे सेंटरों में स्थानांतरित किए गए मरीजों को वापस वार्ड में बुला लिया गया है। एबी विंग से पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के 30 बच्चों, गायनी विभाग के मरीजों को आरपी सेंटर में स्थानांतरित किया गया था। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स, गैस्ट्रो, जनरल सर्जरी सहित कई विभागों के सैकडों मरीज दूसरे सेंटर में स्थानांतरित किए गए थे। एम्स प्रशासन का कहना है कि अस्पताल के एरिया को नुकसान नहीं पहुंचा है। शैक्षणिक ब्लॉक में लैब थी, इसलिए सिर्फ लैब को नुकसान पहुंचा है। लिहाजा इमरजेंसी वार्ड व इमरजेंसी लैब पूरी तरह कार्यरत हो गए हैं।

केजरीवाल ने आग से नुकसान का लिया जायजा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एम्स में शनिवार को लगी भीषण आग की घटना का रविवार को जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के प्रभावित हिस्से को देखा और अस्पताल कर्मियों से घटना से हुई क्षति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि एम्स में आग लगने के बाद दिल्ली अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने काफी अच्छा काम किया है और आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह रही कि एम्स अधिकारियों की सक्रियता के चलते किसी की जान नहीं गई।

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने प्रभावित हिस्सों को देखा। जागरण

कई लैबों को पहुंचा है नुकसान, भर गया है पानी : स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा स्थिति की समीक्षा किए जाने के बाद एम्स निदेशक ने अलग से सभी विभागाध्यक्षों व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर चिकित्सा व्यवस्था के संचालन की समीक्षा की। इस दौरान यह बात सामने आई कि माइक्रोबायोलॉजी विभाग की लैब तो जलकर रख हो ही गई है। उसके नजदीक स्थित मेडिसिन विभाग की लैब में भी आग का असर है। हालांकि इसमें नुकसान कम हुआ है, मशीनें सुरक्षित हैं, लेकिन तार इत्यादि को नुकसान पहुंचा है। इसे ठीक करने में तकनीकी कर्मचारी जुट गए हैं।

लैब में धुआं भरने की वजह से इसे संक्रमण मुक्त करने में वक्त लगेगा। तीसरी मंजिल पर स्थित पल्मोनरी की दो लैब और उसकी मशीनें भी जली हैं। इससे फेफड़े की जांच नहीं हो पाएगी। आग बुझाने के दौरान लैब में पानी भी भर गया है। पैथोलॉजी विभाग की लैब माइक्रोबायोलॉजी लैब के ठीक नीचे पहली मंजिल पर है। इसमें भी पानी भरा है। इसलिए पैथोलॉजी से संबंधित जांचें भी नहीं हो पाएंगी।

जांच जल्द शुरू करने के लिए एम्स ने बनाई कमेटी : एम्स प्रशासन ने एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी देखेगी कि बंद पड़ी लैबों को किस तरह जल्द शुरू किया जाए। इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर उस पर अमल सुनिश्चित करेगी। हालांकि एम्स के सीएन सेंटर व ट्रॉमा सेंटर में कई तरह की जांच की सुविधा है।

इसके अलावा न्यू इमरजेंसी ब्लॉक के पास पल्मोनरी ओपीडी व मेडिसिन की ओपीडी में भी फेफड़े की जांच की सुविधा है। इसलिए जांच में इन लैबों का इस्तेमाल होगा। एम्स की प्रवक्ता डॉ. आरती विज ने कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जो उनकी मदद करेंगे। साथ ही पीसी (प्री-क्लीनिक) ब्लॉक में प्रभावित सुविधाओं को जल्द शुरू करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है।

आरपी सेंटर के ओटी को किया गया संक्रमण मुक्त : एबी ब्लॉक में मरीजों को स्थानांतरित करने के बाद आरपी सेंटर के ऑपरेशन थियेटर में विशेष सफाई की गई ताकि वह संक्रमण मुक्त हो सके। इसके अलावा आरपी सेंटर की इमरजेंसी व डे-केयर वार्ड की भी सफाई की गई।

एम्स के शैक्षणिक ब्लॉक में लगी आग के बाद काफी नुकसान हुआ है। लैब की मशीनें और कई डॉक्टरों के दफ्तर जल गए हैं। सौजन्य : स्रोत

आरपी सेंटर में आंखों के ऑपरेशन थियेटर में सिजेरियन से दो बच्चों का हुआ जन्म

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ **विपरीत परिस्थिति में भी डॉक्टरों और नर्सों ने पेश की मिसाल**

एम्स में आग लगने की घटना के बीच शनिवार रात आरपी सेंटर में आंखों के ऑपरेशन थियेटर (ओटी) में दो गर्भवती महिलाओं की सर्जरी कर प्रसव कराया गया। इससे एम्स में पहली बार आंखों की ओटी में दो बच्चों ने जन्म लिया। इसमें एक लड़की व दूसरा लड़का है। दोनों जच्चा-बच्चा स्वस्थ हैं और उन्हें आरपी सेंटर के वार्ड से गायनी विभाग के वार्ड में स्थानांतरित भी कर दिया गया है। ऐसे में विपरीत परिस्थिति में भी एम्स के डॉक्टरों व नर्सों ने चिकित्सा की मिसाल पेश की है।

शनिवार को एम्स में आग लगने की घटना के दौरान गायनी विभाग से करीब 80 महिलाओं को आरपी सेंटर में स्थानांतरित किया गया था। इसमें सिर्फ आंखों का इलाज होता है। आरपी सेंटर के वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर व एम्स आरडीए के संयुक्त सचिव डॉ. अश्विनी कुमार बेहरा ने कहा कि आरपी सेंटर में कुछ बेड खाली थे। डॉक्टरों व नर्सों ने एक-एक वार्ड में जाकर यह पता लगाया कि कितने बेड खाली हैं। इसके बाद चार-ए वार्ड से आंख के सभी मरीजों को दूसरी जगह स्थानांतरित कर खाली कराया गया। इस वार्ड में 36 बेड हैं। इसे ही गायनी वार्ड बनाया गया। इसके बाद चार-ए वार्ड में 36 महिलाओं को भर्ती किया गया। इसके अलावा आरपी सेंटर के डे-केयर व लॉबी में भी गायनी विभाग के मरीजों को रखा गया था। नेत्र इमरजेंसी व ओपीडी के पास भी कई विभागों के मरीज स्ट्रेचर पर थे। नेत्र इमरजेंसी के ओटी को लेबर रूम बनाया गया था।

ऑपरेशन के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ्य हैं। सौजन्य : स्रोत

आसान नहीं थी आंखों के ओटी में गर्भवती महिला की सर्जरी

डॉक्टरों ने कहा कि आरपी सेंटर के ओटी में आंखों की सर्जरी होती है। इसलिए उसमें उपकरण भी ऐसे नहीं थे जिससे सिजेरियन हो सके। आरपी सेंटर की नर्स भी इसके लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। आरपी सेंटर व गायनी विभाग के बीच बेहतर तालमेल से यह संभव हो सका। गायनी विभाग के ओटी से तुरंत जरूरी उपकरण व दवाएं मंगाई गईं। गायनी विभाग की नर्सों ने आरपी सेंटर पहुंचकर गर्भवती महिलाओं की देखरेख की कमान संभाली। आरपी सेंटर के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. शक्ति गुप्ता व गायनी विभाग के विभागाध्यक्ष खुद पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रात साढ़े नौ बजे जब एम्स के शैक्षणिक ब्लॉक के पांचवी मंजिल पर आग बुझने का काम चल रहा था, उस वक्त 30 वर्षीय गर्भवती महिला को आरपी सेंटर के पांचवीं मंजिल पर स्थित ओटी में ले जाया गया। वहां उनकी सिजेरियन की गई। उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद एक अन्य महिला ने भी सिजेरियन से लड़के को जन्म दिया। सुबह उन्हें मुख्य अस्पताल के एबी वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया।

ओपन राउंड काउंसिलिंग की तारीख बढ़ाई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : देशभर के एम्स में दाखिले के लिए एमबीबीएस की ओपन राउंड काउंसिलिंग की तारीख आगे बढ़ा दी गई। अब यह काउंसिलिंग 20 व 21 अगस्त के बजाय 26 और 27 अगस्त को होगी। एम्स प्रशासन ने यह कदम संस्थान के शैक्षणिक ब्लॉक में आग लगने की घटना के मद्देनजर उठाया है।

दिल्ली सहित देशभर के 15 एम्स में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली एम्स की सीटें तो भर गई हैं, लेकिन तीन राउंड की ऑनलाइन काउंसिलिंग के बाद भी कई नए एम्स में सीटें खाली हैं। इसलिए एम्स ने 20 व 21 अगस्त को ओपन राउंड काउंसिलिंग के लिए समय निर्धारित किया था। एम्स प्रशासन का कहना है कि इस काउंसिलिंग में काफी संख्या में छात्र और उनके अभिभावक एम्स पहुंचेंगे। इसलिए इंतजाम व सुरक्षा का प्रबंध भी करना होता है। आग लगने की घटना के बाद एम्स का पूरा महकमा इस घटना में हुए नुकसान के आकलन व मौजूदा स्थिति से निपटने में लगा हुआ है। इसलिए एम्स प्रशासन ने काउंसलिंग की तारीख बढ़ा दी है। एम्स प्रशासन का कहना है कि पूरी तैयारी के साथ ही छात्रों की सुरक्षा की व्यवस्था करने के बाद 26 व 27 अगस्त को काउंसिलिंग की जाएगी। इसके लिए छात्र 18 से 21 अगस्त के बीच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 21 अगस्त को शाम पांच बजे रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा।

संस्थान में आग से बचाव के नहीं थे पुख्ता इंतजाम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

एम्स में आग लगने की घटना के बाद प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। घटना के वक्त शैक्षणिक ब्लॉक के आसपास लगे फायर इंस्टिग्यूसर खाली पड़े थे। आग से सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अप्रशिक्षित अधिकारी के हाथ में थी। यही वजह है कि आग दूसरी मंजिल से शुरू होकर पांचवी मंजिल तक पहुंच गई। इससे एम्स में आग से बचाव के लिए किए गए प्रबंध पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही दबी जुबान डॉक्टर व कर्मचारी भी कह रहे हैं कि आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे।

सूत्रों के मुताबिक सबसे हैरानी की बात यह है कि संस्थान में आग से बचाव की कमान ऐसे अधिकारी के हाथ में है, जो आग से सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। वह उप सुरक्षा अधिकारी के साथ ही यह दायित्व संभाल रहे हैं। एम्स में आग बुझाने के लिए पंप व हाइड्रोलिक सिस्टम भी है। इसके अलावा फायर इंस्टिग्यूसर भी लगाए गए हैं, लेकिन समय पर ये खास काम नहीं आए। एम्स के अग्निशमन अधिकारी दीपक ने कहा कि फायर इंस्टिग्यूसर खाली होने की बात गलत है। शैक्षणिक ब्लॉक में आग लगने पर फायर अलार्म बजने पर कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लग गए थे। हालांकि एम्स प्रशासन का दावा है कि संस्थान में आगजनी से बचाव के पूरे इंतजाम हैं और इसके लिए 110 कर्मचारियों की टीम है। फिर भी समय रहते एम्स के फायर सेफ्टी के कर्मचारी आग बुझाने में असफल रहे।

तीन टीमें बनाकर चलाया गया अभियान : फायर सुपरवाइजर महावीर दहिया ने कहा कि फायर अलार्म बजने पर जल्द ही तीन टीमें बनाकर बचाव व आग बुझाने का काम शुरू किया गया। एक टीम आग बुझाने, दूसरी टीम मरीजों को हटाने व तीसरी टीम रास्ता साफ करने व सामान हटाने में लग गई थी।

धुआं भरने से आग बुझाने में आई दिक्कत : महावीर दहिया के मुताबिक आग लगने में काला धुआं चारों तरफ भर गया था। यह धुआं इतना गहरा था कि टीम को आग बुझाने में दिक्कत आ रही थी और कर्मचारियों ने चेहरे पर जो उपकरण पहन रखा था। उसके शीशे पर काली परत जम जा रही थी। इस वजह से उन्हें देखने में परेशानी आ रही थी। उन्होंने कहा कि एम्स में आग बुझाने के लिए 44 सुपरवाइजर व 66 पंप ऑपरेटर हैं। सभी सुपरवाइजर नागपुर स्थित नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से प्रशिक्षित हैं।

गठित की कमेटी, आंतरिक जांच शुरू

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आग लगने की घटना के बाद रविवार को एम्स के सभी डॉक्टर व कर्मचारी संस्थान में पहुंचे। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉक्टरों के लिए यह घटना किसी सदमे से कम नहीं है। एम्स प्रशासन ने भी अधिकारियों के साथ संस्थान में आग की रोकथाम के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा की है। साथ एक कमेटी गठित कर आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। ताकि यह पता चल सके कि आखिर व्यवस्था में चूक कहां हुई, जिसके चलते आग लगने की घटना हुई। एम्स प्रशासन का कहना है कि संस्थान में 24 घंटे फायर सेफ्टी कर्मचारी तैनात रहते हैं। आग से बचाव के लिए लगे उपकरणों की नियमित जांच की जाती है। साथ ही आपात स्थिति में निकास की भी व्यवस्था है। कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए नियमित कार्यक्रम भी होता है। फिर भी यदि व्यवस्था में कोई खामी पाई जाती है तो आग से बचाव की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।

एसी डेक से पांचवी मंजिल पर फैली आग : संस्थान के कर्मचारी कहते हैं कि शैक्षणिक ब्लॉक में लगे एसी डेक से पांचवी मंजिल तक आग पहुंच गई क्योंकि एसी डेक के अंदर थर्मोकोल होता है। पांचवीं मंजिल पर एसी का कंप्रेसर भी फटकर ब्लास्ट हुआ था। इस वजह से दूसरी मंजिल के माइक्रोबायोलॉजी लैब के बाद पांचवी मंजिल पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।

सिग्नेचर ब्रिज के पास पिकनिक स्पॉट की योजना पर चर्चा

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने सिग्नेचर ब्रिज के आसपास के इलाके के सौंदर्यीकरण व यमुना के दोनों किनारों को पिकनिक स्पॉट के तौर पर तैयार करने के लिए योजना बनाई है। पर्यटन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सिग्नेचर ब्रिज के पास पिकनिक स्पॉट विकसित करने की तैयारी कर जा रही है।

योजना पर काम चल रहा है ताकि इस क्षेत्र को दिल्ली वालों की सबसे पसंदीदा जगह बन सके। मौजूदा योजना के मुताबिक यहां फूड प्लाजा व ओपन थियेटर होगा। साथ ही 80 फीसद इलाके को हराभरा रखा जाएगा। चूंकि यह इलाका यमुना के क्षेत्र में आता है। इसलिए यहां किसी प्रकार का स्थाई निर्माण नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि फुटपाथ भी पर्यावरण के अनुकूल बनाए जाएंगे। इनमें ईंटों के बीच घास उगाई जाएगी। सिग्नेचर ब्रिज के सामने ही एक बड़ा नाला यमुना में गिरता है। इसके पानी को प्राथमिकता के आधार पर साफ किए जाने के लिए संबंधित विभाग से कहा गया है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में इसे एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाएगा।

यमुना में हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा आठ लाख क्यूसेक पानी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ **32 घंटे में इस पानी के दिल्ली आने की उम्मीद, यमुना का बढ़ेगा जलस्तर**

▶ **प्रशासन ने खादर इलाकों को खाली करने के लिए मुनादी शुरू की**

हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से रविवार शाम चार बजे आठ लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 32 घंटे में इस पानी के दिल्ली आने की उम्मीद है। इससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ेगा। फिलहाल अभी जलस्तर चेतावनी संदेश से नीचे है। बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से पूर्वी जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन ने खादर इलाकों को खाली करने के लिए मुनादी शुरू कर दी है। प्रशासन ने आपातकालीन स्थिति के लिए 011-22051234 नंबर जारी किया है।

पूर्वी जिले के जिलाधिकारी दीपक शिंदे ने खादर इलाकों में रहने वाले लोगों से इलाका खाली करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि लोग यमुना के किनारे न जाएं। यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इससे खादर इलाकों में भी पानी भरने की आशंका है। दीपक शिंदे ने बताया कि भारी बारिश के कारण हथिनी कुंड बैराज से समय-समय पर पानी छोड़ा जा रहा है।

रविवार शाम चार बजे तक आठ लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यह पानी 32 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा। मौजूदा समय में यमुना का जलस्तर 203.37 मीटर है। यमुना का चेतावनी स्तर 204.50 मीटर और खतरनाक स्तर 205.33 मीटर है। उन्होंने बताया कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने गीता कॉलोनी स्थित पूर्वी जिलाधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया है। यह 24 घंटे काम करेगा।

आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-22051234 भी जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति जलस्तर से संबंधित जानकारी ले सकता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति बाढ़ में फंस गया है तो वह इस नंबर पर फोन करके मदद ले सकता है। उन्होंने बताया कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को यमुना और उसके आसपास न जाने दें। साथ ही प्रशासन की टीम खादर इलाकों को खाली करने के लिए मुनादी कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकती है।

जेएनयू के भाषाई केंद्र में नियुक्ति करने पर रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल विश्वविद्यालय (जेएनयू) की कार्यकारी परिषद को निर्देश दिया है कि भाषाई केंद्र (लिंग्विस्टिक सेंटर) में कोई भी प्राध्यापक सदस्य की नियुक्ति न की जाए। न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ ने जेएनयू प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए यह भी कहा कि अगले आदेश तक कार्यकारी परिषद इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। भाषाई केंद्र की शिक्षिका आयशा किदवई ने याचिका दायर कर सुनवाई पूरी होने तक नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी। इससे पहले आयशा ने पर्सियन विभाग के प्रोफेसर मजहर आसिफ को भाषाई केंद्र (लिंग्विस्टिक सेंटर) का अध्यक्ष नियुक्त करने के खिलाफ याचिका दायर की थी और पीठ ने आसिफ को अध्यक्ष नियुक्त करने के जेएनयू प्रशासन के फैसले को रद कर दिया था।

पीठ ने जेएनयू की कार्यकारी परिषद से कहा था कि वह जेएनयू में चल रही परंपरा व कानून के अनुसार सेंटर से ही अध्यक्ष नियुक्त करें। याचिकाकर्ता आयशा ने दलील दी थी कि परंपरा के अनुसार भाषाई केंद्र के सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, लेकिन जेएनयू ने पर्सियन विभाग के प्रोफेसर को भाषाई केंद्र का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया है जो गलत है।

तीस फीट नीचे गिरी कार, चार की मौत

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

▶ **कंपनी के डायरेक्टर ने एक दिन पूर्व ही खरीदी थी एंडेवर कार**

▶ **यमुना एक्सप्रेस-वे पर लांग ड्राइव से लौट रहे थे कार सवार**

▶ **तेज गति होने के कारण कार चालक ने खोया नियंत्रण**

यमुना एक्सप्रेस-वे जीरो प्वाइंट पर तेज रफ्तार एंडेवर कार तीस फीट नीचे गिर गई। कार में नौ लोग सवार थे। सभी लोग नोएडा में स्थित आइटी कंपनी में नौकरी करते थे। घटना में चार की मौत हो गई। इसमें तीन युवक व एक युवती शामिल है। घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है।

नोएडा सेक्टर-दो में आइटी कंपनी टेरासिस इंफोकाम आइटी कंपनी है। हादसे में घायल कंपनी के डायरेक्टर आशीष उर्फ आशू सूद ने शनिवार को ही एंडेवर कार खरीदी थी। कार लेकर वह रविवार सुबह लगभग आठ बजे कंपनी पहुंचे थे। इस दौरान कंपनी में नाइट शिफ्ट करने वाले कर्मचारियों की छुट्टी हुई थी। उन्होंने आशीष को कार खरीदने की बधाई के साथ पार्टी मांगी थी। सुहावना मौसम देख उनका लांग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बन गया। कार में सवार होकर सभी यमुना एक्सप्रेस-वे पर लांग ड्राइव के लिए निकल गए। कार में आशीष के अलावा चंद्र मोहन, शिव विजय सिंह, नवीन, सुष्मिता, सलीम, शीला, अभिषेक व नैंसी भी थे। अभिषेक कंपनी में मैनेजर है। लगभग साढ़े आठ बजे सभी कंपनी से रवाना हुए। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से होते हुए यमुना एक्सप्रेस-वे पर पहुंच गए। टप्पल तक जाने के बाद वह वापस लौट आए। कार अभिषेक चला रहे थे। पुलिस ने बताया कि कार की रफ्तार 120 किमी प्रति घंटे के आस-पास थी। जीरो प्वाइंट पर तेज घुमाव होने से कार अनियंत्रित हो गई और एक्सप्रेस-वे की दीवार की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गिर गई। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। कार में पड़े घायल तड़पते हुए चीख पुकार मचा रहे थे। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर एक्सप्रेस-वे की पेट्रोलिंग गाड़ी भी पहुंच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डाक्टरों ने नवीन, शिव विजय सिंह, चंद्र मोहन व शीला को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है एक घायल ने बताया कि यात्रा पर निकलने से पहले कुछ लोगों ने बीयर पी थी।

जीरो प्वाइंट पर तीव्र घुमाव है। एक्सप्रेस-वे पर वाहन चालक डेढ़ सौ किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से फर्राटा भरते हैं। जीरो प्वाइंट पर भी चालक रफ्तार को धीमा नहीं करते हैं। कई बार इसका खामियाजा उन्हें दुर्घटना के रूप में भुगतना पड़ता है।

जीरो प्वाइंट पर लगभग दो फीट ऊंची आरसीसी की दीवार बनाई गई है। दीवार के ऊपर लोहे की रेलिंग लगाई गई है। कार की टक्कर से कई फीट तक रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई। लगभग सात फीट लंबा रेलिंग का एक हिस्सा कार के अंदर ही घुस गया था।

यमुना एक्सप्रेस वे के जीरो प्वाइंट पर गिरने के बाद कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार की रफ्तार 120 किमी प्रति घंटा थी। जागरण

योजना

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ग्रेनो प्राधिकरण सीईओ को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का दिया निर्देश

अब नोएडा में भी दौड़ेगी लाइट मेट्रो

जागरण संवाददाता, नोएडा

इस समय जो मेट्रो चल रही है उनको एलिवेटेड में बनाने में एक किलोमीटर पर 250 से 350 करोड़ रुपये का खर्च आता है, जबकि भूमिगत लाइन बिछाने में यह खर्चा 400 से 700 करोड़ प्रति किलोमीटर तक पहुंच जाता है। लाइट मेट्रो पर एक किलोमीटर पर करीब 100 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। अभी यह पेरिस, हांगकांग आदि देशों में है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत दिल्ली के द्वारका व चेन्नई से की जा रही है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में जुटा है।

यह बात केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने रविवार को कही। वह नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) के नोएडा-ग्रेटर नोएडा की एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन सेक्टर-51 से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के सेक्टर-52 स्टेशन के बीच सवारियों की दिए जाने वाले यात्री पथ उद्घाटन समारोह पर आए थे। इस दौरान उन्होंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण से कहा कि वह एक्वा लाइन मेट्रो को बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो से जोड़ने के लिए लाइट मेट्रो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर भिजवाएं। इससे एक्वा लाइन एक्सटेंशन की परियोजना का खर्च एक तिहाई हो जाएगा। इससे काफी बचत होगी।

नोएडा में यात्री पथ के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि अब मेक इन इंडिया की झलक विदेशों में भी देखने को मिल रही है। जागरण

एक मेट्रो, एक कार्ड की भी जल्द होगी शुरुआत

सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि पूरे देश में एक मेट्रो, एक कार्ड की भी जल्द शुरुआत होगी। इस योजना पर तेजी से काम चल रहा है। किसी भी कार्ड से ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट खुल सकेंगे। उन्होंने माना कि नोएडा में एनएमआरसी व दिल्ली में डीएमआरसी का कार्ड प्रयोग करने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

विदेश में मेक इन इंडिया की झलक

सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि अब मेक इन इंडिया की झलक विदेशों में भी देखने को मिल रही है। एस्टम इंडिया के विदेशों में मेट्रो कोच पर मेक-इन-इंडिया लिखा नजर आने लगा है। अब भारत की कंपनी भी मेट्रो के कोच बनाने का जिम्मा ले रही है। चीन, कोरिया, जापानी की कंपनी को पछाड़ भारत की भारत अर्थ मूवर्स को 505 कोच बनाने के लिए चार हजार करोड़ का आर्डर मिला है।

2024 तक 27 शहरों में 1530 किलोमीटर में चलने लगेगी मेट्रो

देश में 657 किमी में मेट्रो चल रही है। (फाइल)

अभी देश में 657 किलोमीटर में मेट्रो चल रही है। 2024 तक देश के 27 शहरों में 1530 किमी में मेट्रो चलने लगेगी। इन योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। आने वाले समय में 50 शहरों तक मेट्रो ले जाने का लक्ष्य है। इसके लिए 23 शहरों में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। पिछले पांच सालों में देश में 410 किलोमीटर में मेट्रो चलनी शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अभी 83 किलोमीटर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ आदि शहरों में मेट्रो चल रही है। अगले पांच सालों में आगरा, मेरठ, कानपुर आदि शहरों में 131 किलोमीटर और एनसीआर क्षेत्र में 82 किलोमीटर रेपिड रेल चलने लगेगी।

'भाजपा ने ढहाया 40 करोड़ दलितों की आस्था का केंद्र'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : तुगलकाबाद स्थित संत रविदास का मंदिर तोड़े जाने का विरोध रविवार को डीडीयू मार्ग पर दिखाई दिया। इसे लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर दलितों की आस्था का केंद्र ढहाया है।

डीडीए ने 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर को तोड़ दिया था। इसके बाद से विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि 12 अगस्त को हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को खत लिखकर मांग की थी कि मंदिर को फिर से उसी जगह स्थापित किया जाए, लेकिन उस खत का कोई जवाब नहीं आया। 10 अगस्त को संत रविदास जी का यह ऐतिहासिक मंदिर डीडीए ने गिरा दिया था। डीडीए केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, इसलिए केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है।

41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, नौ प्रशिक्षण संस्थान, तीन रीजनल मार्केटिंग सेंटर व चार क्षेत्रीय सुरक्षा मानक नियंत्रणालयों को संचालित करता है आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी)। दुनिया के इस सबसे पुराने और बड़े उत्पादन संगठन में करीब 1.6 लाख कर्मचारी काम करते हैं।

चीन को खटकता है भारत-भूटान का रिश्ता

चीन के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा खास मायने रखता है। चीन की कोशिश हमेशा से रही है कि भूटान में उसका प्रभाव बढ़े और कूटनीतिक संबंध बेहतर हों, लेकिन भूटान का साफ रुख यह है कि वो भारत के साथ है। भारत के साथ भूटान के कूटनीतिक रिश्ते हैं, जबकि चीन के साथ उसके इस तरह के रिश्ते भी नहीं हैं। डोकलाम विवाद के समय भी भूटान ने भारत का साथ दिया था।

चीन को खटती है मैत्री संधि : भारत और भूटान की दोस्ती को और करीब लाने में 1949 में हुई इस संधि का बड़ा योगदान रहा है। इस संधि के तहत भूटान को अपने विदेशी संबंधों के मामले में भारत को भी शामिल करना होता है। लेकिन, 2007 में इस समझौते में संशोधन हुआ और इसमें जोड़ा गया कि जिन विदेशी मामलों में भारत सीधे तौर पर जुड़ा होगा, उन्हीं में भूटान उसे सूचित करेगा। यही नहीं, इस संधि से दोनों देश, अपने राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग करने तथा एक दूसरे की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के विरुद्ध अपने क्षेत्रों का उपयोग न करने देने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। इसलिए भारत और भूटान के बीच की यह संधि चीन को हमेशा खटकती रही है।

« दो दिन के दौरे पर भूटान पहुंचे पीएम मोदी का भूटानी पीएम लोते शेरिंग ने कुछ इस अंदाज में स्वागत किया।

मजबूत व्यापार संबंध से परेशानी

भारत और चीन के बीच हिमालय की गोद में बसे आठ लाख आबादी वाले देश भूटान की वित्तीय और रक्षा नीति पर भी भारत का प्रभाव है। यही नहीं, भूटान अपना 98 फीसद निर्यात भारत को करता है और करीब 90 फीसद सामान भी भारत से ही आयात करता है। भारतीय सेना भूटान की शाही सेना को प्रशिक्षण देती रही है। ये बातें भी चीन को कहीं न कहीं परेशान करती रही हैं।

डोकलाम विवाद

ये इलाका वहां है जहां चीन और भारत के उत्तर-पूर्व में मौजूद सिक्किम और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते हैं और भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। यह वही इलाका है जो भारत को सेवन सिस्टर्स नाम से मशहूर उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है और सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।

सासेक परियोजना ने बढ़ाई चिंता

2001 में भारत ने भूटान, नेपाल, बांग्लादेश व म्यांमार को जोड़ने के लिए सासेक (साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक को-ऑपरेशन) कॉरिडोर शुरू किया था। इंफाल से मोरेह (म्यांमार) को जोड़ने वाले इस मार्ग को पूर्वी एशियाई बाजार के लिए भारत का प्रवेश द्वार माना जा रहा है। भारत की योजना इस मार्ग के जरिये पूर्वी एशियाई बाजारों को पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने की है। इंफाल-मोरेह मार्ग के निर्माण के साथ ही बैंकाक तक पहुंचने के लिए भारत को एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। 2014 में मालदीव और श्रीलंका भी इसके सदस्य बन गए। चीन की महत्वकांक्षी ओबीओआर परियोजना के जवाब में भारत यह परियोजना लेकर आया है।

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग।

मोदी बोले ▶ भारत और भूटान प्राकृतिक सहयोगी, दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं

हमें आजाद करते हैं लोकतंत्र और शिक्षा

नए क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर दिया जोर

थिंपू, प्रेट्र : लोकतंत्र और शिक्षा दोनों का लक्ष्य होता है हमें आजाद करना। दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों ही हमें अपना सर्वश्रेष्ठ पाने में सहायता करते हैं। भूटान के दौर के दूसरे दिन रविवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने भारत और भूटान को प्राकृतिक सहयोगी बताते हुए दोनों देशों के संबंधों की तारीफ भी की। मोदी ने कहा कि दोनों देश एक-दूसरे को जितना अच्छी तरह समझते हैं और एक-दूसरे से जितना कुछ साझा करते हैं, वैसा विश्व के किन्हीं दो देशों के बीच नहीं दिखता। दौरा पूरा कर रविवार देर शाम मोदी भारत पहुंच गए।

मोदी शनिवार को भूटान के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। दूसरे कार्यकाल में यह मोदी का पहला भूटान दौरा है। रविवार को मोदी ने भूटान के प्रतिष्ठित रॉयल विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक है कि भूटान और भारत के लोग एक-दूसरे से बहुत लगाव का अनुभव करते हैं। दोनों देशों के लोग न केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण करीब हैं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं ने यहां के लोगों के बीच अनोखे और गहरे बंधन बनाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बौद्ध बहुल देश में कहा, 'भारत भाग्यशाली भूमि है कि हमारे यहां के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। उनके आध्यात्मिक संदेशों और बौद्ध धर्म का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला। भूटान में बौद्ध भिक्षुओं, आध्यात्मिक नेताओं, विद्वानों और साधकों की पीढ़ियों ने उसी लौ को प्रगवलित किया। इसी का नतीजा है कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया एक जैसा है। इस महान विरासत का वाहक होने का हमें गर्व है।' मोदी ने कहा कि भूटान आने वाला कोई भी व्यक्ति यहां के प्राकृतिक सौंदर्य से जितना प्रभावित होता है, उतना ही प्रभावित यहां के लोगों की गर्मजोशी, करुणा और सादगी से भी होता है। मोदी ने कहा, 'इस यात्रा के दौरान मुझे भूटान के वर्तमान नेतृत्व से निकटता से बातचीत करने का अवसर मिला। मैंने एक बार फिर से भारत-भूटान संबंध के लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है।'

थिंपू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक (बाएं)। एएनआइ

नई पीढ़ी के हाथ में है भूटान का भविष्य : छात्रों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, 'आज मैं भूटान के भविष्य के साथ यहां हूं। मैं इनकी गतिशीलता को देख सकता हूं और ऊर्जा को महसूस कर सकता हूं। मुझे विश्वास है कि ये इस महान देश और यहां के लोगों के भविष्य को आकार देंगे। गहरी आध्यात्मिकता और युवा शक्ति भूटान के अतीत, वर्तमान और भविष्य का स्थायी तत्व है। यही हमारे द्विपक्षीय संबंधों की शक्ति भी हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'आज मैं भूटान के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली युवाओं के समक्ष हूं। महामहिम (भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक) ने मुझे बताया कि वह आपसे नियमित बातचीत करते हैं। आप भूटान के भविष्य के नेता, नवप्रवर्तक हैं। आपमें से व्यवसायी, खिलाड़ी, कलाकार और वैज्ञानिक उभरेंगे।'

कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना समय की जरूरत : मोदी ने भूटान के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा, 'भारत-भूटान के बीच पनबिजली और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग अनुकरणीय है। लेकिन हमारे रिश्ते की असली शक्ति और ऊर्जा हमारे लोग हैं। इसीलिए, लोग पहले हैं और लोग ही हमेशा इस रिश्ते के केंद्र में रहेंगे।' उन्होंने कहा कि सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों से परे जाकर दोनों देश स्कूल से अंतरिक्ष तक और डिजिटल भुगतान से आपदा प्रबंधन तक नए मोर्चों पर बड़े पैमाने पर सहयोग करना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि भूटान में हर मोर्चे पर आगे बढ़ने की क्षमता है और 1.3 अरब भारतीय मित्र इस विकास यात्रा में केवल दर्शक या उत्साहवर्धक नहीं बल्कि साझेदार बनकर साथ देंगे। भूटान के छात्रों की योग्यता की सराहना करते हुए मोदी ने कहा, 'कोई सीमा आपको रोक ना पाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि युवा होने के लिए इससे सही समय कोई नहीं हो सकता।'

'प्रसन्नता' है भूटान का संदेश : मोदी ने कहा, भूटान ने प्रसन्नता के सार को समझ लिया है। इस हिमालयी देश ने 'ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस' की अवधारणा के चलते दुनिया में पहचान बनाई है। यहां विकास का पैमाना आंकड़े नहीं, बल्कि प्रसन्नता है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'भूटान ने सद्भाव, एकजुटता और करुणा की भावना को समझा है। यह भावना मुझे उन बचों में दिखाई दी जो मेरा स्वागत करने के लिए सड़कों पर कतारबद्ध थे। उनकी मुस्कान मुझे हमेशा याद रहेगी।' मोदी ने कहा कि यहां विकास, पर्यावरण और संस्कृति का एक दूसरे से टकराव नहीं बल्कि तालमेल है।

मजबूत हुए दिल के रिश्ते : भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने मोदी के दौरे को सफल बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरे ने दोनों देशों के दिल के रिश्ते को और मजबूत किया है। मोदी के भारत रवाना होने के बाद शेरिंग ने कहा, 'हम जो चाहते थे और जो दे सकते थे, विशेषतौर पर दिल के रिश्तों के मामले में, उस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का दौरा सफल रहा। यद्यपि हमारी तरफ से यह आधिकारिक दौरा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह बहुत आध्यात्मिक और दोस्ती भरा दौरा रहा।' शेरिंग ने दौरे को सफल बनाने के लिए सभी स्थानीय अधिकारियों का भी आभार जताया।

प्रधानमंत्री का तीन दिवसीय यूएई और बहरीन दौरा 23 से

▶ मिलेगा संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त से तीन दिनी यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और बहरीन जाएंगे। मोदी वहां दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने रविवार को बताया कि पीएम मोदी सबसे पहले यूएई जाएंगे। यहां पर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण 'आर्डर ऑफ जायद' से सम्मानित किया जाएगा। 24 अगस्त को वह दो दिनी यात्रा पर बहरीन के लिए रवाना होंगे। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की खाड़ी के इस देश में पहली यात्रा होगी। दरअसल, इस साल अप्रैल में यूएई ने पीएम मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री को यह सम्मान दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता और संयुक्त रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए दिया जा रहा है। इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम यूएई के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के नाम पर रखा गया है। खाड़ी नेता के जन्मशती वर्ष पर पीएम मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी बहरीन यात्रा के दौरान अपने समकक्ष राजकुमार शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करेंगे। बहरीन के राजा शेख हमद बिन ईसा अल खलीफा पीएम मोदी के सम्मान में रात्रि भोज देंगे।

बहरीन यात्रा के दौरान पीएम मनामा में श्रीनाथजी (श्रीकृष्ण) मंदिर के जीर्णोद्धार का भी शुभारंभ करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत और बहरीन के बीच संबंधों में आई ताजगी को ऐसे समझा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच 2018-19 में व्यापार बढ़कर लगभग 9300 करोड़ रुपये पहुंच गया है। बहरीन में 3,000 से अधिक भारतीय स्वामित्व वाले संयुक्त वेंचर्स दोनों देशों के बीच गहन आर्थिक जुड़ाव का संकेत देते हैं। बता दें कि बहरीन में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भारतीय नागरिकों का है। इनकी संख्या लगभग 3,50,000 है।

आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति से जूझ रहा है देश : कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था की 'नरमी' पर रविवार को चिंता जताते हुए कहा है कि देश 'आर्थिक आपातकाल' जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। देश में 'आर्थिक आपातकाल' जैसी स्थिति हो गई है। सिंघवी ने वाहन क्षेत्र में नरमी का मुद्दा उठाते हुए कहा, वाहनों की बिक्री में 31 फीसद गिरावट आई है। यह बिक्री में लगातार नौंवे माह की गिरावट रही। 'जुलाई 2018 के बाद के 13 में से 12 महीनों में वाहनों की बिक्री गिरी है। यह विश्व के चौथे सबसे बड़े वाहन बाजार में तेज नरमी का संकेत देता है।' उन्होंने शेयर बाजार में गिरावट, बढ़ते राजकोषीय घाटे, जीडीपी के गिरते आंकड़ों, घटते श्रम बल, रियल एस्टेट में नरमी, कमजोर होता रुपया, गिरते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे उठाए। सिंघवी ने कहा कि पीएम मोदी ने पहली बार जब पद संभाला था, तब डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 58.7 रुपये थी, जो 71 रुपये हो गइ है।

मुकदमे से पहले तलाशे जाने चाहिए मध्यस्थता के विकल्प : जस्टिस बोबडे

▶ कहा, जल्द न्याय के लिए कानूनी सहायता प्रणाली की भूमिका अहम

▶ विधि विश्वविद्यालयों में मध्यस्थता में पाठ्यक्रम की जरूरत बताई

नागपुर, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शरद बोबडे ने मुकदमा दायर करने से पूर्व मध्यस्थता की जरूरत और लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए कानूनी सहायता प्रणाली की भूमिका पर जोर दिया। वह शनिवार को यहां 17वें अखिल भारतीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।

जस्टिस बोबडे ने कहा कि अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के बीच मध्यस्थता के जरिए 1,07,587 मामले निपटाए गए। गुजरात में हाल ही में मध्यस्थता के जरिए एक दिन में 24,000 मामले निपटाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा, ''मध्यस्थता करने पर हमारा जोर है। इसलिए हम 'मुकदमे से पूर्व मध्यस्थता' करने की अनिवार्यता पर विचार कर रहे हैं जो केवल वाणिच्यिक विवादों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए।'' उन्होंने कहा कि देश में विधि विश्वविद्यालयों में मध्यस्थता में डिग्री, डिप्लोमा की पढ़ाई होनी चाहिए।

जस्टिस बोबडे ने कहा, ''समाज के कई वंचित वर्गों को यह तक नहीं पता है कि उनके पास कानून एवं कल्याणकारी योजनाओं के तहत कानूनी अधिकार हैं।'' आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश में करीब 80 फीसदी लोगों को कानूनी सहायता लेने का अधिकार है लेकिन यह आबादी के 0.05 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को उपलब्ध नहीं है। उन्होंने राज्य विधि सेवा प्राधिकरणों की उनके काम के लिए प्रशंसा की और कहा कि इसे देशभर में उच्च न्यायालयों का सहयोग मिल रहा है।

शरद बोबडे फाइल फोटो

समारोह के समापन के मौके पर अपने संबोधन में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कानूनी जागरूकता के अभाव में लोग अपने अधिकारों और लाभों से वंचित और शोषण के शिकार थे। उनका मानना था कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति लाने के लिए लोगों का अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना शक्तिशाली साधन है।

अदालत की निगरानी में जांच के नतीजे बेहतर : जस्टिस चंद्रचूड़

मुंबई में शनिवार को एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत की निगरानी में जिन मामलों की जांच होती है, उनके नतीजे बेहतर आते हैं। पहलू खान मॉब लिंचिंग (उन्मादी भीड़ की हिंसा) मामले के सभी आरोपितों के बरी होने का अवलोकन करते हुए जज ने ये बात कही। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'हम यह लगातार देख रहे हैं.. एक न्यायाधीश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसके समक्ष जिस तरह से सबूत पेश किया जाता है उसी मुताबिक उसे निर्णय करना होता है।' पहलू खान मामले में आरोपितों के बरी होने पर उन्होंने आगे कहा, 'और तब आप पाते हैं कि पुलिस द्वारा की गई जांच बेहद अपर्याप्त है या तो जानबूझ कर अथवा अयोग्य होने के कारण ऐसा हुआ है, जो आगे चल कर बरी होने का कारण बनेगी।' गौरतलब है कि राजस्थान की एक अदालत ने पहलू खान की पीट-पीट कर हत्या किए जाने के मामले में सभी छह आरोपितों को बरी कर दिया था। यह सब पुलिस जांच में बेहद खामी के चलते संदेह के लाभ के कारण हुआ।

200 पूर्व सांसदों ने खाली नहीं किए लुटियंस के बंगले

नई दिल्ली, प्रेट्र : 16वीं लोकसभा के भंग होने के दो महीने बाद भी 200 से ज्यादा पूर्व सांसदों ने लुटियंस दिल्ली में स्थित सरकारी बंगले खाली नहीं किए हैं। नियमानुसार पूर्व सांसदों को लोकसभा भंग होने के एक महीने के भीतर बंगलों को खाली कर देना चाहिए।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर 16वीं लोकसभा को 25 मई को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया था। एक सूत्र ने बताया, 'लोकसभा के 200 से अधिक पूर्व सांसदों ने अब तक अपने सरकारी बंगले खाली नहीं किए हैं। पूर्व सांसदों को ये बंगले 2014 में आवंटित किए गए थे।'

सूत्रों ने बताया, 'नवनिर्वाचित सांसदों को वेस्टर्न कोर्ट और कई अतिथि गृहों में अस्थायी आवास उपलब्ध कराए गए हैं। यह व्यवस्था तब तक बनी रहेगी, जब तक कि उन्हें लुटियंस दिल्ली में स्थायी आवास उपलब्ध नहीं कराए जाते।' ऐसा सांसदों की रिहाइश पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए किया गया है। इससे पहले नव-निर्वाचित सांसद तब तक पांच सितारा होटलों में रुकते थे, जब तक उन्हें पूर्णकालिक सरकारी बंगला आवंटित नहीं किया जाता था। उल्लेखनीय है कि 17वीं लोकसभा में 260 से ज्यादा सांसद पहली बार चुने गए हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी, क्रिकेटर गौतम गंभीर, सूफी गायक हंसराज हंस आदि शामिल हैं।

कर्नाटक में फोन टैपिंग की जांच करेगी सीबीआइ, घिर सकते हैं कई नेता

▶ मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा आज देंगे इस मामले की जांच के आदेश

▶ अयोग्य करार दिए गए जदएस विधायक ने लगाए थे आरोप

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक में जनता दल सेक्यूलर (जदएस) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के दौरान सामने आए फोन टैपिंग के आरोपों की प्रदेश सरकार सीबीआइ जांच कराएगी। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को कहा कि वह कांग्रेस के कई नेताओं की मांग पर इन आरोपों की सीबीआइ जांच का आदेश देंगे।

येदियुरप्पा ने यहां पत्रकारों से कहा, 'फोन टैपिंग के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्दरमैया समेत कई नेताओं ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए, इसलिए मैंने सीबीआइ जांच का आदेश देने का फैसला किया है। सोमवार को मैं जांच का आदेश दूंगा।' उन्होंने कहा कि यह राज्य के लोगों की अपेक्षा है कि विस्तृत जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। ज्ञात हो, अयोग्य करार दिए गए जदएस विधायक एएच विश्वनाथ ने पिछले सप्ताह एचडी कुमारस्वामी की सरकार पर फोन टैप कराने और उनके समेत 300 से अधिक नेताओं की जासूसी कराने के आरोप लगाए थे। इसके बाद येदियुरप्पा ने यह घोषणा की है।

पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार समेत कई भाजपा नेताओं ने कुमारस्वामी पर अपनी सरकार बचाने के लिए इस प्रकरण के पीछे होने का आरोप लगाया है। विधानसभा में विश्वास मत हारने के बाद पिछले महीने जदएस-कांग्रेस गठबंधन सरकार गिर गई थी।

बीएस येदियुरप्पा फाइल फोटो

जांच की घोषणा पर कांग्रेस बंटी : फोन टैपिंग की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) से जांच की घोषणा पर कांग्रेस में एक राय नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया, एम मल्लिकार्जुन खड़गे और गठबंधन सरकार में गृह मंत्री रहे एमबी पाटिल समेत कांग्रेस नेताओं ने जांच की मांग की है, जबकि पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार ने आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्दरमैया ने सीबीआइ जांच का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि भाजपा अपने राजनीतिक हित के लिए इसका उपयोग नहीं करेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फोन टैपिंग को झूठ बताते हुए इसे नफरत की राजनीति की साजिश बताया है।

कुमारस्वामी बोले-किसी भी जांच को तैयार

कुमारस्वामी ने आरोपों से इन्कार करते हुए कहा कि वे किसी भी जांच का सामना करने को तैयार हैं। उन्होंने ट्वीट किया, 'सीबीआइ या अंतरराष्ट्रीय एजेंसी जिससे चाहे वे जांच करा लें। न हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर लें और वे जो एजेंसी बताएं उससे जांच करा लें।' उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका को देखकर ऐसा लगता है कि वह मुझे राज्य की राजनीति और यहां के लोगों से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन वे इसमें सफल नहीं होंगे।

कह के रहेंगे माधव जोशी

नक्सल प्रभावित इलाकों में तेज होगी विकास की रफ्तार

नितिन प्रधान, नई दिल्ली

रणनीति पर मंथन

▶ गृह मंत्रालय ने 26 को बुलाई प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस प्रमुखों की बैठक

▶ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ ही केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव भी हो सकते हैं बैठक में शामिल

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद राज्य में सामान्य होती स्थिति को देख, अब केंद्र सरकार ने अपना ध्यान नक्सल प्रभावित इलाकों की तरफ केंद्रित कर दिया है। सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों की सक्रियता पर जोर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगले सोमवार यानी 26 अगस्त को नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

बैठक में नक्सल प्रभावित 11 राज्यों में हिंसा और विकास की ताजा स्थिति का आकलन किया जाएगा और भविष्य में उठाए जा सकने वाले संभावित कदमों पर विचार विमर्श होगा। विज्ञान भवन में होने वाली बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों के हिस्सा लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशकों को भी बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुखों को भी उपस्थित रहने को कहा गया है। केंद्रीय बलों में सीआरपीएफ, सशस्त्र सुरक्षा बल, बीएसएफ और आइटीबीपी शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हो सकते हैं। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाये रखने में डोभाल की अहम भूमिका रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए रणनीति बनाने में जिन केंद्रीय मंत्रालयों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है उनमें ग्रामीण विकास, वित्त, संचार और सामाजिक विकास मंत्रालय शामिल हैं। हालांकि सरकार के आंकड़ों के मुताबिक नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसा की घटनाओं में पिछले तीन साल में काफी कमी आई है। इसी महीने खत्म हुए संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने कहा था कि साल 2016 से 2019 के दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसा की वारदातों में 2013-15 के मुकाबले 15.8 फीसद और इनमें होने वाली मौतों की संख्या में 16.6 फीसद की कमी आई है। रेड्डी ने कहा कि सरकार की नीति और साल 2015 के एक्शन प्लान पर अमल की वजह से यह कमी आई है।

अमित शाह फाइल फोटो

मंत्रालय ने अपने लिखित जवाब में बताया है कि इस अवधि में नक्सली हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या भी साल 2018 में घटकर 60 रह गई थी। इनमें भी दो तिहाई घटनाएं केवल 10 जिलों में ही हुई हैं। इस साल 30 जून तक नक्सली हिंसा में मरने वालों की संख्या 117 रही है। साल 2018 की इसी अवधि में नक्सली हिंसा में 139 लोगों की मौत हुई थी। मंत्रालय का मानना है कि हिंसा की घटनाओं और मरने वाले लोगों की संख्या में कमी आने की एक बड़ी वजह नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की रफ्तार को तेज करना रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती ने भी नक्सलियों के हौसलों को पस्त किया है। इसके साथ ही राज्य सरकारों की तरफ से चलाए गए आत्मसमर्पण कार्यक्रम और उसके तहत नक्सलियों के पुनर्वास की योजनाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

गृह मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि इसके अतिरिक्त इन इलाकों में संचार का नेटवर्क की मजबूती ने भी नक्सलियों की कमर तोड़ने में मदद की है। संचार मंत्रालय के यूएसओ फंड की मदद से टेलीकॉम कंपनियों ने इन क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की संख्या में काफी वृद्धि की है।

SIHANTA IAS
इतिहास
रजनीश राज
निःशुल्क परिचर्चा
20 Aug. 6:00PM
ONLINE/LIVE Classes Also Available
Ph:011-42875012 8743045487

THE STUDY
इतिहास
द्वारा मणिकांत सिंह
नया बैच प्रारंभ
OPEN LECTURE
कल 8AM
210, VIRAT BHAWAN, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9
9999516388, 9999278966, 42870015

15 अधिकारियों को नौकरी से निलंबित कर दिया है ओडिशा सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए। साथ ही दो पूर्व अधिकारियों की पेंशन सुविधा को संपूर्ण रूप से बंद करने का भी फैसला किया है। इन सभी अधिकारियों को राज्य भ्रष्टाचार निवारण विभाग ने भ्रष्टाचार का दोषी पाया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 19 अगस्त 2019

समानांतर कांग्रेस चलाएंगे हुड्डा, सोनिया बुलाएंगी बैठक

अनुराग अग्रवाल, रोहतक

रोहतक के मेला ग्राउंड में रविवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परिवर्तन रैली करके अपनी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जागरण

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने अगले फैसले तक कांग्रेस में रहकर समानांतर कांग्रेस चलाएंगे। प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद से मुलाकात और सोनिया गांधी से बातचीत के बाद हुड्डा ने अलग पार्टी बनाने का फैसला फिलहाल स्थगित कर दिया है। साथ ही 25 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो अलग पार्टी बनाने या कांग्रेस में रहने का फैसला लेगी। उधर, पार्टी सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी जल्द ही हरियाणा के मसले को लेकर पार्टी नेताओं की बैठक बुला सकती हैं।

रविवार को रोहतक में परिवर्तन महारैली के दौरान हुड्डा ने मंच पर 13 विधायकों और 70 पूर्व मंत्री-विधायकों को जुटाकर हाईकमान में यह संदेश देने की कोशिश की कि असली कांग्रेस उनके साथ है। हुड्डा द्वारा गठित 25 सदस्यीय कमेटी में वह सदस्य हैं जो उनके थिंक टैंक माने जाते हैं। हुड्डा और उनके समर्थक लंबे समय से मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर को हटाकर प्रदेश कांग्रेस की बागडोर अपने हाथों में सौंपे जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें सफलता नहीं मिली तो हुड्डा ने परिवर्तन महारैली में बड़े बदलाव का संकेत दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनके बढ़ते कदमों को रोकने में हाईकमान कामयाब हो गया है। हुड्डा ने करीब दो दर्जन चुनावी वादे कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि हरियाणा में भाजपा उनके निशाने पर है और हाईकमान द्वारा उन्हें जिम्मेदारी नहीं सौंपने की स्थिति में समानांतर संगठन चलाया जाएगा। हुड्डा ने महारैली में उम्मीद से कहीं अधिक भीड़ जुटाई। साथ ही सभी विधायकों को एक मंच पर लाकर यह संदेश दिया कि हरियाणा में भाजपा का सामना करने के लिए हुड्डा कांग्रेस को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए खतरे से खाली नहीं है। कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर हुड्डा समर्थक नेताओं की बड़ी फौज है। इनमें से कोई नेता नहीं चाहता कि हुड्डा कांग्रेस छोड़ें, लेकिन अपनी राजनीतिक पारी को जोशीले अंदाज में खेलना चाह रहे हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी जगह बनाने का इरादा रखते हैं। इसलिए अब हुड्डा समर्थकों की निगाह उनके कदम और 25 सदस्यीय कमेटी पर टिक गई है।

सोनिया से बातचीत के बाद रातों-रात बदल गई रणनीति

जागरण संवाददाता, रोहतक

कांग्रेस हाईकमान से प्रदेश नेतृत्व को लेकर लड़ाई लड़ रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह की रणनीति रातों-रात बदल गई। यही कारण है कि उन्होंने न तो नई पार्टी का एलान किया और न ही बगावत करते हुए कांग्रेस को छोड़ा। हरियाणा की राजनीति में बड़े धमाके की उम्मीद लेकर पहुंचे हुड्डा समर्थकों को अब कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि, भीड़ जुटाकर हुड्डा ने सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस आलाकमान को यह जरूर दिखा दिया कि विधानसभा चुनाव में उन्हें हलके में लेना भूल हो सकती है।

परिवर्तन महारैली से पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निशान पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे थे। हुड्डा के साथी विधायक और उनके खासमखास पूर्व मंत्री भी मीडिया के सामने बड़े परिवर्तन और धमाके के बयान लगातार दे रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

रणनीति बदलने का कारण : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शनिवार रात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया से फोन पर बातचीत हुई। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी ने हुड्डा को सकारात्मक आश्वासन दिया था। हुड्डा हरियाणा में दस साल तक मुख्यमंत्री रहे, इसका पूरा श्रेय सोनिया गांधी को ही जाता है। सोनिया गांधी और हुड्डा के बीच संबंध बेहतर हैं। सोनिया से फोन पर बातचीत के बाद हुड्डा ने रैली को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव किया।

पंडाल में नहीं थे कांग्रेस के झंडे और न बड़े नेताओं के फोटो

परिवर्तन महारैली के पंडाल में न तो कांग्रेस के झंडे थे और न किसी बड़े नेता के फोटो होर्डिंग या बैनर लगाए गए थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद के फोटो नहीं होना, कांग्रेस से सीधे तौर पर नाराजगी दिखा रहे थे, लेकिन रैली में उन्होंने कांग्रेस पर तंज तो कसा पर पार्टी छोड़ने का एलान नहीं किया। नेताओं और कार्यकर्ताओं के सिर पर गुलाबी पगड़ी ही नजर आ रही थी। चार अगस्त को कार्यकर्ता सम्मेलन में जो नेता मंच पर थे, रैली में भी अधिकतर वही नेता थे। कोई बड़ा नेता न तो नदारद रहा और न ही कोई शामिल हुआ।

नेताजी के साथ क्या हुआ, हमें जानने का अधिकार है : ममता

जागरण संवाददाता, कोलकाता : नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय रूप से गायब होने की घटना को याद करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि नेताजी के साथ क्या हुआ, लोगों को यह जानने का अधिकार है। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, '1945 में इसी दिन नेताजी ताइवान के ताइहोकू हवाईअड्डे की एक उड़ान से रवाना हुए और हमेशा के लिए गायब हो गए। हम अब भी नहीं जानते कि उनके साथ क्या घटित हुआ। धरती के महान सपूत के बारे में जानने का लोगों को पूरा अधिकार है।'

उल्लेखनीय है कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी बोस के परिवार के एक वर्ग और कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि नेताजी की ताइहोकू एयरपोर्ट पर एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। हालांकि, परिवार के एक अन्य वर्ग और बड़ी संख्या में शोधकर्ताओं और क्रांतिकारी नेता के प्रशंसकों ने विमान दुर्घटना के सिद्धांत को खारिज कर दिया।

भारत सरकार ने नेताजी के लापता होने की सच्चाई का पता लगाने के लिए तीन जांच आयोगों का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एमके मुखर्जी की अगुवाई में 1999 में मुखर्जी आयोग ने नेताजी की कथित गुमशुदगी को लेकर 6 साल लंबी जांच की।

न्यूज गैलरी

जल्द पारित होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून : गिरिराज

मथुरा : केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटना तो अभी ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जल्द पारित होगा। श्रीराम का भव्य मंदिर भी अयोध्या में बनकर रहेगा। रविवार को वह उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंचे थे। उन्होंने कहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून के रूप में पीएम मोदी ने जो सोचा है, वह देश की भलाई के लिए ही है। कानून बनेगा तो देश में समरसता का माहौल बनेगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले में उन्होंने कहा कि हर दिन सुनवाई हो रही है, जल्द ही मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस नेताओं पर रोक को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार उग्रवाद पर जीरो टॉलरेंस है। उसके समर्थन में जो भी खड़ा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस का पूरा कुनबा 370 पर वही बयान दे रहा है, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दे रहे हैं। सरकार वही काम कर रही है जो जनता चाहती है। (जासं)

छत्तीसगढ़ के पांच कोयला खदानों की लगेगी बोली

रायपुर : केंद्रीय कोयला मंत्रालय छत्तीसगढ़ की पांच कोयला खदानों की नीलामी कर रहा है। साथ ही पांच कोयला खदानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है। मंत्रालय राज्य की इन 10 खदानों के साथ अन्य राज्यों की 32 समेत कुल 42 कोयला खदानों की नीलामी और आवंटन करने की तैयारी में है। इनमें सबसे ज्यादा झारखंड की हैं। मंत्रालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो सितंबर तक चलेगी। खनिज विभाग के अफसरों के अनुसार फिलहाल सर्वे आदि के आधार पर कोल भंडारों की पहचान की गई है। वहां से संभावित उत्पादन का अंदाजा भी लगा लिया गया है। इसके अलावा अन्य कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। नीलामी और आवंटन के बाद आवश्यकतानुसार ग्रामसभा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति के अलावा जमीन अधिग्रहण आदि की प्रक्रिया होगी। कोयला मंत्रालय के अनुसार इन 42 खदानों में से 21 खदान गैर विनियमित क्षेत्र के इस्तेमाल और लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए 6 कोकिंग कोल खदानों की नीलामी होंगी। वहीं पांच कोल ब्लॉक बिजली, नौ कोयला विक्रय और एक लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए आवंटित की जाएगी। इन 42 कोयला खदानों से प्रतिवर्ष अधिकतम 70 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होगा। झारखंड की आठ खदानों की बोली लगेगी और छह का आवंटन होगा। ओडिशा में दो का आवंटन होगा, एक की नीलामी, महाराष्ट्र की एक खदान का आवंटन और नौ की नीलामी होगी। तेलंगाना की एक खदान का आवंटन होगा। बंगाल और मध्यप्रदेश की दो-दो खदानों की नीलामी होगी। (नईदुनिया)

शाह बोले, कांग्रेस को शर्म नहीं तीन तलाक का कर रही समर्थन

साधा निशाना ▶ तीन तलाक के खिलाफ कानून को बताया मुस्लिम समाज में सुधार का बड़ा कदम

कहा, कुप्रथाओं को दूर करने वाले समाज सुधारकों में शामिल हो गए हैं पीएम मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में रविवार को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोलते गृह मंत्री अमित शाह। जागरण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन तलाक के खिलाफ बने कानून का विरोध कर रही कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस इस कानून का विरोध कर रही है। उन्होंने तीन तलाक के खिलाफ कानून को भारतीय मुस्लिम समाज के भीतर मौजूद एक बड़ी कुरीति को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम करार दिया। अमित शाह यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

अमित शाह ने कहा कि 1985 में कांग्रेस को तीन तलाक की कुप्रथा को खत्म करने का ऐतिहासिक मौका मिला था। तब सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो मामले में तीन तलाक को समाप्त करते हुए कहा था कि पत्नी को खर्चा देना अनिवार्य बनाया था। लेकिन, राजीव गांधी ने रूढ़िवादी मुसलमानों के दबाव में और वोट बैंक के लिए अदालत के फैसले को पलट दिया था।

शाह ने कहा, 'आज भी, कांग्रेस को कोई शर्म नहीं है, वो कहते हैं कि वो तीन तलाक के पक्ष में हैं और इसे बना रहना चाहिए। क्यों? उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने अपने रुख के लिए एक भी औचित्य नहीं दिया और केवल विरोध दर्ज करने के लिए तर्क दिया ताकि उनका वोट बैंक बरकरार रहे।'

तीन तलाक के खिलाफ कानून को मुस्लिम समाज के हित में बताते हुए अमित शाह ने कहा कि बदलते वक्त के साथ अपनी कुप्रथाओं को दूर करने वाला समाज निर्मल गंगा की तरह रहता है। तीन तलाक के खिलाफ कानून को इस्लाम विरोधी करार देने वालों को आड़े हाथों लेते हुए शाह ने कहा कि यदि ऐसा होता को 1922 से 1963 के बीच 18 इस्लामिक देश इसके खिलाफ कानून नहीं बनाते।

अमित शाह ने कहा कि जिस कुप्रथा को मुस्लिम देश ने 1963 तक तिलांजलि दे दी थी, भारत में तुष्टीकरण और वोटबैंक की राजनीतिक के कारण उसे दूर करने में 56 साल लग गए। तुष्टीकरण, परिवारवाद और जातिवाद को लोकतंत्र का नासूर बताते हुए शाह ने कहा कि जनता ने 2014 में मोदी के नेतृत्व में भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर इसके अंत की शुरूआत कर दी थी और 2019 में उससे अधिक सीट देकर इसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी।

> कई लोग भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि यह काम मुस्लिम विरोधी है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह काम केवल और केवल मुस्लिम समाज के फायदे के लिए है।
> -अमित शाह, गृहमंत्री

तीन तलाक के खिलाफ कानून की जरूरत बताते हुए शाह ने 2015 में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की ओर से किए गए एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि सर्वे में 92.1 फीसदी मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक को खत्म करने की जरूरत बताई थी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि समाज में मौजूद कुप्रथाओं को दूर करने में राजाराम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी से लेकर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जैसे कई समाज सुधारकों ने अहम भूमिका निभाई थी। तीन तलाक जैसी कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन समाज सुधारकों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं।

भाजपा ने हरियाणा में किया चुनावी शंखनाद, रथ पर सवार हुए मनोहर

जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलने से पहले कालका में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जागरण

अनुराग अग्रवाल, कालका (पंचकूला)

हिमाचल प्रदेश से सटे हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र कालका में मां काली की पूजा फिर साथ लगते ऐतिहासिक गुरुद्वारे में गुरु साहिब का आशीर्वाद और उसके बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की विजयी भव की मंगल कामना। कुछ इस अंदाज में हरियाणा की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को रथ पर सवार हो गए।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य के सभी 90 हलकों में रथ यात्रा के जरिये दस्तक देंगे और अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के साथ ही अगले पांच साल का विजन लोगों को समझाएंगे। भाजपा ने इस बार 75 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे हासिल करने को मुख्यमंत्री रथ यात्रा के जरिये पूरे प्रदेश में दस्तक देंगे। जन आशीर्वाद यात्रा की रवानगी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चार मंत्रियों के साथ मनोहर कैबिनेट के तमाम मंत्रियों और सांसद-विधायकों व संगठन पदाधिकारियों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए साफ कर दिया कि मिशन-75 को पूरा करने से पहले उनके कदम थमने वाले नहीं। कालका में बारिश के बीच शंखनाद और भारत मां के जयकारों के साथ शुरू हुई रैली में मुख्यमंत्री ने अपनी पांच साल की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही पूर्ववर्ती सरकारों को घेरा। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पूरे नंबर देते हुए कहा कि पांच साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की जनता को जो हीरा दिया था, वह कसौटी पर खरा उतरा है।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत कंधों की तलाश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▶ इम्तिहान का काम करेंगे राजीव गांधी जन्म समारोह के कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चाहती है कि अब जिलों में संगठन की जिम्मेदारी ऐसे मजबूत कंधों पर डाली जाए जो पार्टी को सक्रिय कर खड़ा कर सके। तमाम दौड़-धूप के बावजूद ऐसे चेहरे अब तक सामने नहीं आ सके हैं। अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म समारोह के कार्यक्रमों को बतौर इम्तिहान देखा जाएगा और यहां से भी काबिलों की तलाश का प्रयास होगा।

लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश की सभी जिला इकाइयों को भंग कर दिया था। उसके बाद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नेता विधानमंडल दल अजय कुमार लल्लू को ऐसे कार्यकर्ताओं को चिह्नित करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जो संगठन को मजबूत कर सकें। वह तमाम जिलों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक यह काम पूरा नहीं हो सका है। यही वजह है कि बेहतर जनाधार और संगठन में पकड़ वाले कार्यकर्ताओं की तलाश के लिए पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म समारोह को भी एक जरिया बनाने जा रही है। 20 अगस्त को राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर समाज से जुड़े कई कार्यक्रम होने हैं, जबकि 25 अगस्त को हर जिले में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी। खास बात यह है कि इन कार्यक्रमों के आयोजनों की जिम्मेदारी निवर्तमान जिला और शहर अध्यक्षों के साथ ही उन कार्यकर्ताओं को भी दी गई है, जिन्होंने संगठन में पद के लिए दावेदारी की है। इनमें बहुतेरे ऐसे भी हैं, जिनका साक्षात्कार खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ले चुकी हैं। माना जा रहा है कि इन कार्यक्रमों की रिपोर्ट के आधार पर भी जिला और शहर अध्यक्षों के चयन का निर्णय लिया जा सकता है।

शत्रुघ्न ने सराहा प्रधानमंत्री का संबोधन

पटना, एएनआइ : शत्रुघ्न सिन्हा को नरेंद्र मोदी का कट्टर आलोचक माना जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस नेता ने अलग राय व्यक्त की है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री के संबोधन की सराहना की है। शत्रुघ्न के मुताबिक पीएम का संबोधन नए विचारों को जन्म देने वाला और बेहद साहसिक था। शत्रुघ्न गत लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वह पटना साहिब संसदीय सीट से चुनाव भी लड़े, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा।

शत्रुघ्न ने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) पद के सृजन के एलान के लिए भी मोदी की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए प्रसिद्ध या बदनाम हूं। मुझे स्वीकार करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लाल किले से आपका संबोधन बेहद साहसिक, शोधयुक्त और नए विचारों को जन्म देने वाला था। देश इस समय जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उस पर आपने बखूबी ध्यान दिया।

पीएम की अक्सर आलोचना करने वाले कांग्रेस नेता के बदले बोल

अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न ने कहा, मोदी निश्चित रूप से सराहना के पात्र हैं। उन्होंने समस्या की जड़ को पहचाना है। उन्होंने भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी योजना पर खुलकर बात की है। पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। अगले कुछ सालों में ही तमाम प्रमुख शहर पानी की किल्लत से घिर जाएंगे। अगली समस्या जनसंख्या विस्फोट की है। इसे सही तरह से निपटाना होगा। पीएम ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बात की है और सुधार के कई कदम बताए हैं। हममें से कई लोगों ने इन मसलों पर बात की थी, लेकिन कोई ठोस कार्ययोजना सामने नहीं रखी गई थी। आप बहादुर हैं। बधाई। इसके पहले शत्रुघ्न ट्विटर के प्लेटफार्म का इस्तेमाल खास तौर पर भाजपा और प्रधानमंत्री को निशाना बनाने के लिए करते थे। उन्होंने आगे लिखा कि सीडीएस के रूप में एक पॉवरफुल कमांड फर्क पैदा कर सकता है। आप देश के मित्र और पथप्रदर्शक हैं। आपने सही दिन, समय और प्लेटफार्म चुना है। मेरा अनुरोध है कि सीडीएस के मामले में तत्काल कदम उठाया जाना चाहिए। पूरा देश आपके साथ है। शत्रुघ्न ने नदियों को जोड़ने की योजना पर भी प्रधानमंत्री से बात करने की इच्छा जताई।

चिदंबरम भी कर चुके हैं पीएम की तारीफ : शत्रुघ्न सिन्हा से पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम के संबोधन की सराहना कर चुके हैं। चिदंबरम ने तीन मसलों-आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले उद्यमियों के मान सम्मान, जनसंख्या नियोजन और प्लास्टिक पर अंकुश पर पीएम के विचारों की तारीफ की थी।

भीमा मंडावी की नक्सली हत्या की जल्द आएगी अंतरिम रिपोर्ट

नईदुनिया, रायपुर: भाजपा के दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की नक्सली ब्लास्ट में मौत के मामले में न्यायिक जांच आयोग ने जांच तेज कर दी है। आयोग के अध्यक्ष सतीश अग्निहोत्री ने शनिवार को बैठक ली। सर्किट हाउस में बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में अग्निहोत्री ने कहा कि भीमा मंडावी की नक्सली हत्या के मामले में पहले अंतरिम रिपोर्ट पेश की जाएगी। यह प्रारंभिक रिपोर्ट होगी।

सरकार ने सात बिंदुओं पर जांच तय की है। इसके आधार पर जांच शुरू की गई है। इसमें घटना साजिश है या नहीं, कौन-कौन शामिल था, उसकी जांच की जाएगी। रिपोर्ट में यह भी बताना है कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो इसके लिए क्या करने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों ने दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की हत्या कर दी थी। सरकार ने न्यायिक जांच आयोग को जांच का जिम्मा सौंपा है।

अलग राह

बिहार के पूर्व सीएम ने राजद से बनाई दूरी तो दूसरे दलों के खुले दरवाजे, प्रियंका गांधी वाड्रा ने हम को दिया कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव

फिर नया किनारा तलाश रही मांझी की नाव

अरविंद शर्मा, पटना

जीतनराम मांझी फाइल फोटो

महागठबंधन से अलग राह पकड़ने का एलान करके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अपनी सियासी अहमियत और जरूरत का दायरा बढ़ा लिया है। उनके तौर-तरीके से लग रहा कि वह अब फिर नया किनारा तलाश रहे हैं। हालांकि, वह विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपने गठबंधन को खास फायदा नहीं पहुंचा पाए, लेकिन इतना है कि राज्य की राजनीति में उन्हें महत्व मिल जा रहा है।

जनाधिकार पार्टी वाले पप्पू यादव उनके साथ मिलकर बिहार में तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाह रहे हैं। कांग्रेस भी कृपा बरसाने में पीछे नहीं रहना चाह रही है। जदयू के शब्दकोष से भी मांझी के लिए अच्छे-अच्छे शब्द निकलने लगे हैं और भाजपा को भी मांझी से परहेज नहीं रहा है। आखिर क्या है मांझी की मंशा? सियासत में कब किसकी अहमियत बढ़ जाए और कब कम हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। महागठबंधन को खरी-खोटी सुनाने के बाद माना जा रहा था कि मांझी के चंचल मन को दूसरे ठिकाने की तलाश है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अनुभव पर सवाल उठाने के बाद राजद की ओर से भी दो-टूक कह दिया गया कि उनका मन अगर इधर नहीं लग रहा है तो जहां चाहे चले जाएं। राजद के बंधन से मुक्त होकर मांझी दिल्ली गए और खबर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात भी की। मांझी के प्रमुख सहयोगी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के प्रवक्ता दानिश रिजवान का दावा है कि मांझी को कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव मिला है। मांझी की सियासत की शुरुआत कांग्रेस से ही हुई है। अपनी पार्टी बनाने और जदयू से पहले मांझी कांग्रेस में ही थे। रिजवान कहते हैं कि अभी कुछ तय नहीं है कि आगे क्या करना है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी के मुताबिक, प्रियंका से मांझी ने मुलाकात की या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन किंतु हम चाहते हैं कि वह हमारे साथ रहें। मांझी की सबसे ज्यादा अहमियत पप्पू यादव की नजरों में है। लोकसभा चुनाव में राजद ने पप्पू को महागठबंधन में शामिल नहीं होने दिया था। कांग्रेस प्रत्याशी और उनकी पत्नी रंजीत रंजन की राह में भी राजद ने कांटे बिछाए थे। अब पप्पू के पास तेजस्वी को सबक सिखाने का मौका है। ऐसा करने से उनके लिए राजग और महागठबंधन से अलग एक रास्ता भी निकल आएगा। वह भाकपा के कन्हैया कुमार के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाना चाह रहे हैं।

जदयू का दरवाजा बंद नहीं

बहरहाल, तेजस्वी को निशाने पर लेकर मांझी ने अपनी मंशा को जब उजागर किया तो जदयू ने ज्यादा देर नहीं की। उसने भी अपना दरवाजा खोल दिया। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने साफ कर दिया कि मांझी के लिए जदयू का दरवाजा बंद नहीं है। राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी के स्वर में भी आमंत्रण था। उन्होंने कहा कि मांझी के साथ सबसे बड़ा न्याय नीतीश कुमार ने ही किया। उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश ने गांधी के सपनों को साकार किया था।

शिवराज ने कहा-मध्य प्रदेश में जंगल राज, तबाह कर दिया मेरा प्यारा राज्य

नईदुनिया, भोपाल

जुबानी जंग

- पूर्व मुख्यमंत्री ने सतना में बच्चे के अपहरण के बाद साधा निशाना
- कमलनाथ बोले- आप ही लाए बर्बादी के कगार पर, धो रहा हूं दाग

मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में जंगल राज है। अपहरण उद्योग चल रहा है। कमलनाथ सरकार ने मेरा प्यारा राज्य तबाह कर दिया। इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि आप ही इसे बर्बादी के कगार पर लाए थे। मैं तो इस बदहाल व्यवस्था को दुरस्त करने और दाग धोने में जुटा हूं।

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने सतना में बच्चे के अपहरण और 10 लाख की फिरौती मांगे जाने की घटना पर यह प्रतिक्रिया दी। चौहान ने कमलनाथ सरकार के आठ महीने के कार्यकाल पर सवाल उठाकर सियासत गरमा दी है। उन्होंने कहा कि हमने डकैत खत्म कर इसे शांति का टापू बना दिया था, लेकिन कमलनाथ सरकार ने अपहरण को उद्योग बना दिया। अपराधी खुले आम खेल रहे हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पैसे लेकर पुलिस अफसरों के तबादले हो रहे हैं। उन्होंने कहा, 'कमलनाथ जी अब तो जागिए, ट्रांसफर-पोस्टिंग से फुर्सत मिल जाए तो मध्य प्रदेश को बचाइए। महिला-बच्चे, व्यापारी और पत्रकार कोई सुरक्षित नहीं। चारों तरफ लूट मची है।' वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में डकैत समस्या सिर उठा लेती है।

पांच साल में ऐसा मप्र बनाऊंगा, आपको अपने कार्यकाल पर शर्म आएगी : मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित करते हुए कहा है कि यह वही मध्य प्रदेश है, जो आपने मुझे बर्बादी के कगार पर लाकर सौंपा था। कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति में अपराधों व दुष्कर्म में नंबर वन था। बेरोजगारी, कुपोषण और युवाओं की बेरोजगारी में भी आपने प्रदेश को नंबर वन बनाकर छोड़ा था।

मुख्यमंत्री ने दूसरे ट्वीट में शिवराज के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि केवल आठ महीने में ही सरकार से इतनी अपेक्षाएं... । उन्होंने शिवराज से कहा कि आपने जैसी बदहाल व्यवस्था छोड़ी थी, उसे दुरुस्त करने में वह पूरी तत्परता से लगे हैं। आपकी सरकार के दाग धोने में लगा हूं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से कहा कि आप विश्वास रखें, अगले पांच साल में ऐसा मध्य प्रदेश बनाऊंगा कि आपको अपने 13 साल के कार्यकाल पर शर्म आएगी।

190 स्कूल खोले जाएंगे श्रीनगर में आज से। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूलों के प्रधानाचार्यों की बैठक में यह जानकारी दी गई।

जम्मू-कश्मीर में शांति भंग करने के लिए पुलिस के खिलाफ दुष्प्रचार

होगी कार्रवाई ▶ राज्यपाल के सलाहकार बोले, अफवाहें फैलाने वालों को कर रहे हैं चिह्नित

सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर अफरातफरी फैलाना चाहते हैं शरारती तत्व

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर पुलिस सबसे ज्यादा पेशेवेर व कर्मठ है। आतंकवाद पर काबू पाने में जो शहादतें जवानों से लेकर अधिकारियों ने दी हैं उसकी दूसरी मिसाल नहीं है। आतंकवाद को इसी पुलिस ने ही सबसे ज्यादा झेला है। कुछ तत्व राज्य पुलिस के बारे में दुष्प्रचार कर अफवाहें फैला शांति भंग करने की साजिश कर रहे हैं। अफवाहें फैलाने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। रविवार को श्रीनगर में राज्यपाल के सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि बीते दिनों अनुच्छेद 370 हटाने से हताश कुछ तत्व अफरातफरी फैलाना चाहते हैं। वह सोशल मीडिया पर पुलिस के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। राज्य प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबर चली थी कि एक

के विजय कुमार। फाइल

पुलिसकर्मी ने पांच सीआरपीएफ कर्मियों को गोली मार दी। इसी तरह एक फिरन पहने महिला और जुलूस की फोटो सोशल मीडिया पर चली जो पुरानी थी। हम किसी भी तरह का दुष्प्रचार सहन नहीं करेंगे। अफवाहें फैलाने वाले तत्वों की निशानदेही कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कश्मीर के हालात नियंत्रण में : वादी के हालात पर उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे प्रशासनिक पाबंदियों को हटाया जा रहा है। हमने लोगों के जान माल की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए एहतियात के तौर पर टेलीफोन और मोबाइल सेवाओं को ठप किया था। हम नहीं चाहते थे कि शरारती तत्वों को हालात बिगाड़ने का मौका मिले। हालात में सुधार के साथ अन्य पाबंदियों को भी हटाया जाएगा।

बच्चों को स्कूलों में भेजने की अपील : अभिभावकों से सोमवार को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमने सुरक्षा के सभी प्रबंध किए हैं। स्कूली छात्रों , स्कूल वाहनों की आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत न हो, के लिए पूरे प्रबंध किए हैं। हमारा प्रयास है कि शैक्षिक गतिविधियां जल्द सामान्य हो।

युवाओं को जिहादी बनाने के लिए हर कोशिशें हो रहीं : के विजय कुमार ने बताया कि पाकिस्तान और उसके एजेंट कश्मीर में स्थानीय युवाओं को जिहादी बनाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। राज्य प्रशासन ने साजिश को नाकाम बनाने की अपनी कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है। विभिन्न शहरों और कस्बों में ऐसे युवकों की निशानदेही की है जिन्हें आसानी से बरगलाया जा सकता है। पत्थरबाजी में लिप्त या हाल-फिलहाल में आतंकियों के संपर्क में आए युवकों को चिन्हित किया जा रहा है। इन सभी युवकों में से अधिकांश किशोर ही हैं। सभी के पुनर्वास के लिए विशेष केंद्र बनाए हैं। इन केंद्रों को मीडिया और आम लोगों से दूर रखा गया है।

डीजीपी ने कहा-राज्य में हालात नियंत्रण में

राज्य ब्यूरो, जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू के साथ कश्मीर में भी हालात नियंत्रण में हैं। पुलिस आतंकवादियों को अलग-थलग करने का दबाव बना रही है ताकि वे लोगों को गुमराह न कर सकें। इसमें एक ओर पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और सेना अहम भूमिका निभा रही है, वहीं लोगों का भी शांति बनाए रखने में योगदान रहा है।

डीजीपी ने कहा कि पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ ही पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में विकास का नया युग शुरू होगा। पुलिस का पूरा प्रयास है कि पाकिस्तान के आतंकवादी लोगों को गुमराह न कर सकें। इसके लिए एक ओर पुलिस आतंकवादियों पर दबाव बना रही है तो वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने पर काम किया जा रहा है। सुरक्षाबल हालात को पूरी तरह से नियंत्रण में रखे हैं।

श्रीनगर में गली क्रिकेट...

जम्मू संभाग के पांच जिलों इंटरनेट मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई, लेकिन श्रीनगर में रविवार को कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद गली क्रिकेट खेलते बच्चों की यह तस्वीर राज्य में स्थिति सामान्य को दर्शाती है। प्रेट्र

जम्मू एयरपोर्ट अक्टूबर में 15 दिनों के लिए रहेगा बंद

अवधेश चौहान, जम्मू

जम्मू एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के चलते अक्टूबर के पहले सप्ताह से एयरपोर्ट करीब 15 दिनों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान एयरपोर्ट पर कोई भी विमान न तो लैंड करेगा और न ही उड़ान भर सकेगा। अलबत्ता, श्रीनगर जाने वाले सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमानों का रोजमर्रा की तरह आवागमन रहेगा।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक जम्मू में एयर इंडिया समेत 30 कंपनियों के जहाज यहां रोजाना आवागमन करते हैं। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने कहा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से जम्मू एयरपोर्ट विमानों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। उधर, जम्मू एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर प्रभात रंजन ब्यूरिया का कहना है कि इतने दिनों तक एयरपोर्ट को बंद रखने से अथॉरिटी को करोड़ों रुपये का नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन एयरपोर्ट के विकास के लिए यह जरूरी है। जम्मू में इंडियन एयरलांइस, स्पाइसजेट, इंडिगो, विस्तारा, गो इंडिया आदि के करीब 30 विमानों का रोजाना आवागमन होता है। अलबत्ता, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर

जम्मू एयरपोर्ट। फाइल

रोजमर्रा की तरह विमानों का आवागमन रहेगा। जम्मू एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए इसका विस्तारीकरण होना है। इस दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा अधिग्रहित की कई जमीन को रनवे में बदलने के लिए पेड़ों की कटाई से लेकर रनवे का निर्माण किया जा रहा है।

एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम राज्य प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जरूरी है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए जमीन अगस्त 2018 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी गई है। अतंरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनने से विदेशों से भी विमान जम्मू में उतर सकेंगे।

पुंछ के मनकोट-झलास सेक्टर में भारी गोलाबारी बच्ची घायल

जागरण संवाददाता, पुंछ : जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होते देख पाकिस्तान बौखला चुका है। सीमा पर गोलाबारी की आड़ में पाक सेना आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिशें कर रही है। जम्मू संभाग के पुंछ के मनकोट व झलास सेक्टर में पाक सेना ने लगातार दूसरे दिन रविवार को भी गोलाबारी जारी रखी। मनकोट क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्ची घायल हो गई। भारतीय सेना ने दोनों सेक्टरों में पाक सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। राजौरी से लेकर पुंछ में नियंत्रण रेखा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।

शनिवार को भी पाक सेना ने राजौरी के नौशहरा, पुंछ के मनकोट व झलास सेक्टर में भारतीय चौकियों और रिहायशी क्षेत्रों में भारी गोलाबारी की थी। नौशहरा सेक्टर में सेना के लांस नायक संदीप थापा शहीद हो गए थे। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाक सेना की तीन चौकियां तबाह होने के साथ दो अधिकारियों सहित पांच सैनिक मारे गए थे। रविवार सुबह पाक सेना ने पुंछ के मनकोट व झलास सेक्टर में फिर गोलाबारी शुरू कर दी। मनकोट गांव में घर के आंगन में गिरे शेल से 10 वर्षीय बच्ची घायल हो गई थी।

नेहरू की नीति लद्दाख में पड़ी भारी : जामयांग

राज्य ब्यूरो, जम्मू

लद्दाख से भाजपा के सांसद जामयांग त्सीरिंग नांग्याल ने कहा है कि कांग्रेस की कमजोर नीतियों के कारण ही चीन ने लद्दाख में डेमचौक सेक्टर में भारतीय जमीन पर कब्जा किया। अगर कांग्रेस के नेतृत्व में लद्दाख की सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध होते तो ऐसे हालात न पैदा होते।

लद्दाख से पहली बार भाजपा के सांसद बने जामयांग ने कहा कि नेहरू ने चीन को लेकर जो नीति बनाई थी वह भारी पड़ गई। नेहरू ने कहा था कि हम इंच इंच कर चीन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। चीन हमारे इलाकों में घुसपैठ करता रहा व हम पीछे हटते रहे। संसद में अपने शानदार भाषण से विशिष्ट पहचान बनाने वाले 34 वर्षीय युवा सांसद रविवार को लेह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आज हमारा अक्साई चिन इलाका पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है। चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी डेमचौक नाले तक पहुंच गई। इसके लिए कांग्रेस द्वारा चीन के प्रति 55 साल तक अपनाई गई कमजोर नीतियां जिम्मेवार रही।

जामयांग ने कहा कि गत वर्ष जुलाई में चीनी सैनिकों ने डेमचौक इलाके में नहर बनाने पर आपत्ति जताई थी। इस वर्ष भी जुलाई में दलाई

जामयांग त्सीरिंग नांग्याल। फाइल

लामा के जन्मदिन पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख के कुछ निवासियों द्वारा तिब्बत का झंडा फहराने के विरोध में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की थी। बाद में थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने घुसपैठ होने से इंकार किया था।

लद्दाख की सुरक्षा पर मोदी सरकार गंभीर : भाजपा सांसद ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि अब लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जाना तय है। पाकिस्तान, चीन जैसे देशों से सीमाएं साझा करने वाले लद्दाख की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार गंभीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट किया है कि लद्दाख के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सड़क, संचार समेत हर सुविधा जुटाई जाएगी ताकि उन्हें वहां से पलायन करने की जरूरत न पड़े। लद्दाख की सुरक्षा को और पुख्ता बनाना समय की मांग है।

कांग्रेस ने कश्मीर मुद्दे को संरा में ले जाकर बड़ी गलती की : जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह की सराहना करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर बहुत बड़ी गलती की थी। इसी नीति के कारण कश्मीर में हालात खराब हुए। जब भी कश्मीर में हालात बिगड़े, कांग्रेस ने लोगों को खुश करने के लिए विशेष पैकेज दिए। इससे वहां पर पत्थबाजों के हौंसले भी बुलंद हुए। लद्दाख के हितों को भी नुकसान पहुंचा। अनुच्छेद 370 पर राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे नेता कुर्सी के लिए कुछ भी बयान दे सकते हैं।

कश्मीर संभाग से जुड़ने से होता रहा भेदभाव : सांसद ने कहा कि लद्दाख को कश्मीर संभाग का हिस्सा बनाने से शिक्षा, रोजगार, विकास के क्षेत्र में भेदभाव हुआ। एक लद्दाख के युवक को कश्मीर विश्वविश्व विद्यालय के कॉलेज से डिग्री करने में 5 साल लग जाते थे। यह कहना गलत है कि लद्दाख में बाहर से लोग जा जाएंगे। लद्दाख आटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल अधिनियम 1997 में स्पष्ट है कि भूमि संबंधी सभी मामले काउंसिल के अधीन आते हैं।

कई इलाकों में प्रतिबंधों में राहत

राज्य ब्यूरो, जम्मू : प्रशासनिक पाबंदियों में राहत का असर रविवार को भी कश्मीर के विभिन्न इलाकों में सुबह से ही नजर आया। सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही के साथ दुकानें भी खुली रहीं। रविवार को 50 और थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधों में राहत दी गई। प्रशासन ने सोमवार से पहले चरण में जिला श्रीनगर में 194 प्राथमिक स्कूलों को खोलने की तैयारी कर ली है। वहीं, कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाओं को छोड़ पूरे कश्मीर में स्थिति शांतिपूर्ण रही। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। शनिवार देर रात श्रीनगर के डाउन-टाउन में हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की कथित तौर पर आंसूगैस के गोले से निकली गैस से मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है। ऊधर, शरारती तत्वों ने बारामुला, बडगाम और श्रीनगर में डाउन-टाउन के विभिन्न हिस्सों में पथराव कर रहे तत्वों को खदेड़ने के लिए सुरक्षाबलों को भी बल प्रयोग करना पड़ा। सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल के मुताबिक चार से पांच जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई हैं।

नई उम्मीदें और युवा जोश

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद युवाओं में नई उम्मीदों का संचार हो रहा है। बेहतर भविष्य की आस में युवा जोश में तिरंगे लहरा रहे हैं। जम्मू में मनाए गए अखंड भारत दिवस पर रविवार को निकली तिरंगा रैली में हाथ में तिरंगा लेकर बलिदान स्तंभ की परिक्रमा करते युवा। उन्हें उम्मीद है कि राज्य में अब तेजी से विकास होगा और उनके दिन भी फिरेंगे। सियासी भेदभाव और चरमपंथ के दिन अब लद चुके हैं। संजीव मगोत्रा

पंडितों ने पूछा सवाल - अब वह किस पहचान की बात करते हैं

नवीन नवाज, शेखपोरा (बडगाम)

- **कश्मीरियत को मिटाने की साजिश तो 1990 में ही रच दी गई थी**
- **घाटी में बनी पंडितों की कालोनी तक पहुंच दैनिक जागरण ने उधेड़ा उनका दर्द**

तंग गलियों के सन्नाटे से गुजरते हुए किसी को आभास नहीं होता कि यहां जिंदगी अभी भी खौफ के साये में कैद है। 370 से आजादी का जश्न पूरे देश में मन रहा है लेकिन अपने घरों से उजड़कर इस कालोनी में कैद हुए कुछ कश्मीरी पंडित अभी भी अनिश्चय के दौर से गुजर रहे हैं। कालोनी के गेट पर लगा बैरियर और सादे कपड़ों में तैनात सुरक्षाबलों की मौजूदगी अहसास करा देती है कि इनके हालात बदलने के लिए अभी काफी कुछ करना होगा।

कालोनी में अजब का सन्नाटा है। यहां रह रहे परिवार 5 अगस्त को आतंकवाद और अलगाववाद पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक की खुशी चाहकर भी नहीं मना सकते। बडगाम के कई क्षेत्रों में रह रहे कई कश्मीरी पंडितों ने 1990 के दशक में भी घाटी से पलायन नहीं किया था, लेकिन बाद में हुए नरसंहार के बाद वह अपने घरों से उजड़ गए और पुनर्वास के नाम पर बनाई गई कालोनी में बसा दिया गया। उनके साथ कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए घोषित रोजगार पैकेज के तहत नौकरियां पाने वालों को भी आश्रय दिया गया। लेकिन एक पखवाड़े में यहां रहने वाले 294 परिवारों में से भी 243 जम्मू चले गए हैं। शेष परिवारों के अधिकांश सदस्य भी जम्मू, उधमपुर या दिल्ली में हैं।

पूरी कालोनी में कोई चहल-पहल नहीं हैं। सिर्फ चार रिटायर्ड बुजुर्ग ही अखरोट के पेड़ के नीचे ताश खेल रहे हैं। एक महिला धूप में कपड़ों को सुखा रही है और तीन-चार युवक सड़क पर टहलते दिखते हैं। अनजान चेहरों को देखकर भी स्थिर बनने का प्रयास करते बुजुर्गों की भाव भंगिमा में बदलाव स्पष्ट देखा जा सकता है।

पहले हालात के बारे में बातचीत करने को कोई राजी नहीं हुआ। जोर देने पर एक ने कहा कि हमसे क्या पूछते हो, बाहर जाकर बात करो? तभी दो युवक पिंटू और उपेंद्र भी वहां पहुंच गए। पेशे से अध्यापक उपेंद्र ने कहा कि हमारी खुशी-गम के बारे में मत पूछो। हम तो पहले ही उजड़ चुके हैं। पर निश्चित तौर पर इससे अलगाववाद की भावनाएं फैलाने वालों को अब कोई और ठिकाना तलाशना पड़ेगा।

उपेंद्र की बात सुन बुजुर्ग भी कुछ सहज हुए। राजस्व विभाग में पटवारी के पद से रिटायर्ड भूषण कौल ने कहा कि हमने कभी कश्मीर नहीं छोड़ा। पर हमारा क्या बचा था जो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, रियासत की बेटियों के साथ जो यहां राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भेदभाव सरकारी तौर पर होता था, वह खत्म हो जाएगा।

लेखक मनोहर लालगामी ने कहा कि पहचान का डर दिखाने वालों को बता दें कि हमारी पहचान और कश्मीरियत 1990 के दशक में मिटाने की साजिश रची गई थी। हमारा अब क्या छिनेगा। निश्चित तौर पर अब वह परेशान होंगे, जिनका सामाजिक और सियासी वर्चस्व समाप्त हो रहा है।

अभी भी 3500 कश्मीरी पंडित हैं वादी में : आतंकियों की धमकियों के बावजूद करीब 3500 कश्मीरी पंडित आज तक वादी में डटे हैं। इन कश्मीरी पंडितों के एक संगठन कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिक्कू ने कहा कि हमारे लिए हालात ज्यादा अनुकूल नहीं हैं। इसे टीवी चैनलों द्वारा किसी की जीत घोषित करने से यहां तनाव बढ़ ही रहा है। इसलिए बरसों से रह रहे हमारे समुदाय के कई लोग अब अपने भविष्य और सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। मुझे लगता है कि ऐसी बातों से बचा जाना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। विश्वास बहाली का प्रयास तेज करना होगा।

अनंतनाग से सात परिवारों का हुआ पलायन : संजय टिक्कू ने बताया कि अनंतनाग के सोमरन में कश्मीरी पंडितों के सात परिवार पलायन कर चुके हैं। इसके अलावा 5 अगस्त को गांदरबल में पुलिस ने लार, वुसन और मनिगाम से भी कश्मीरी पंडितों के पांच परिवारों को पुलिस ने किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है।

अनुच्छेद 370 हटने से दुनिया भर के कश्मीरी पंडितों में खुशी

ह्यूस्टन, आइएएनएस: अनुच्छेद 370 हटने से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बसे कश्मीरी पंडितों में खुशी है। जश्न मनाने के लिए प्रवासी कश्मीरी पंडितों के संगठन ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा) ने शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख विजय चौथीवाले ने की। बैठक को भारत सहित आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी और सिंगापुर स्थित कश्मीरी पंडितों के सभी संगठनों के प्रमुखों ने टेलीकांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया।

बैठक को संबोधित करते हुए चौथीवाले ने कहा कि अनुच्छेद-370 खत्म करना ऐतिहासिक क्षण था। यह हमारी मजबूत वैचारिक प्रतिबद्धता का परिणाम है। इस सकारात्मक परिवर्तन से समुदाय में खुशी का माहौल है। जीकेपीडी के अंतरराष्ट्रीय समन्वयक सुरिंदर कौल ने कहा कि यह समय देश की शक्ति और विविधता का जश्न मनाने का है। वीना अंबरदार ने पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को बधाई दी।

उम्मीद

तीनों सेनाओं की एकीकृत थियेटर कमांड और प्रस्तावित स्पेस कमांड युद्ध क्षमता में करेगा इजाफा, नौकरशाही के वर्चस्व के साथ तीनों सेनाओं की आपसी प्रतिस्पर्धा होगी चुनौती

दुश्मनों की सामरिक चिंता बढ़ाएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

संजय मिश्र, नई दिल्ली

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के गठन के एलान को सामरिक रणनीति में गुणात्मक बदलाव के संकेत के साथ ही सैन्य आधुनिकीकरण को बड़ी छलांग देने की मंशा माना जा रहा है। सीडीएस की नई व्यवस्था में तीनों सेनाओं की एकीकृत संयुक्त थियेटर कमांड दुश्मनों के लिए चिंता का सबब बनेगी। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक आधारित हाइटेक हथियारों के दौर में थियेटर कमांड और प्रस्तावित 'स्पेस कमांड' सीडीएस की नई व्यवस्था में तीनों सेनाओं की एकीकृत युद्ध क्षमता में इजाफा करेगी। हालांकि सीडीएस के कारण तीनों सेनाओं के आपसी प्रशासनिक वर्चस्व की शुरुआती खींचतान की चुनौतियों की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा रहा है।

सीडीएस पर सैन्य विशेषज्ञों की लगभग एक राय है कि इसकी वजह से मौजूदा संसाधनों में ही तीनों सेनाओं की संयुक्त युद्ध क्षमता बढ़ेगी। सैन्य आधुनिकीकरण और नये अस्त्र-शस्त्र हासिल करने की भविष्य की रूपरेखा तीनों सेनाओं की संयुक्त सामरिक ताकत में और भी गुणात्मक बेहतरी लाएगी। एकीकृत थियेटर कमांड में आने से तीनों सेनाओं के बीच आपरेशन के दौरान रणनीतिक और सामरिक समन्वय ज्यादा प्रभावी होगा। सैन्य विशेषज्ञ 16वीं क्राप्स के रिटायर्ड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय के मुताबिक सीडीएस के गठन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि तीनों सेनाएं एक चीफ और एक कमांड के अंदर होंगी। इससे तीनों सेनाओं की संयुक्त रणनीतिक दृष्टि और क्षमता दोनों बढ़ेगी। सैन्य बलों में नेतृत्व की दुविधा नहीं रहेगी क्योंकि वे एक चीफ और एक कमान के अधीन होंगे।

लेफ्टिनेंट जनरल राय के मुताबिक जब तीनों सेनाओं की संयुक्त ताकत एक कमान के अंदर होगी तो इसकी सामरिक क्षमता विरोधी को परेशान करेगा। रणनीतिक विशेषज्ञ मेजर जनरल (रिटायर्ड) जेकेएस परिहार कहते हैं कि तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान होने से हमारी न्यूक्लियर कमान और स्ट्रैटजिक कमान को दीर्घकालिक सामरिक रणनीति के हिसाब से फायदा होगा। वहीं सैन्य विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह का साफ कहना है कि सीडीएस का फैसला दुश्मनों को हमारी संयुक्त सामरिक ताकत का संदेश देने में बेहद कारगर रहेगा। सीडीएस की नई व्यवस्था दुश्मनों के लिए चिंता की बात होगी क्योंकि थियेटर कमांड और स्पेस कमान भी इसमें शामिल होगा।

सामरिक लिहाज से सीडीएस के गठन को तीनों सेनाओं को एकीकृत थियेटर कमांड में लाने के लिए जहां कारगर माना जा रहा है, वहीं सरकार के राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी इसमें सिंगल प्वाइंट कांटेक्ट की सुगम व्यवस्था है। विशेषज्ञों के अनुसार सीडीएस एक तरह से प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। इसकी वजह से तीनों सेनाओं के हथियारों की खरीद प्रक्रिया में भी तेजी आएगी इनकी सामरिक जरूरत के हिसाब से अस्त्र-शस्त्रों की आपूर्ति समय पर होगी। कर्नल दानवीर अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के खरीदने का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वास्तव में सेना को इसकी जरूरत थी मगर टशन में वायुसेना ने इसे अपने लिए भी हासिल किया। सीडीएस से सैन्य खरीदी का ऐसा दोहराव रुकेगा। वहीं तीनों सेनाओं के लॉजिस्टक का खर्च कम होगा, ट्रेनिंग और आधुनिकीकरण में भी गुणात्मक बदलाव आएंगे और तीनों सेनाओं के मानव संसाधन क्षमता में कमी आएगी।

सीडीएस के प्रशासनिक ढांचे और शक्ति को लेकर चिंता के सवाल भी कायम हैं। पहली चुनौती रक्षा मंत्रालय की नौकरशाही होगी जो मौजूदा व्यवस्था में हावी रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि नई व्यवस्था में सीडीएस कितना प्रभावशाली होगा यह इस पर निर्भर करेगा कि उसे रक्षा सचिव के ऊपर रखा जाता है बराबर या अधीन। इन विशेषज्ञों की राय में सीडीएस को प्रभावी बनाने के लिए उसे नौकरशाही पर निर्भरता से आजाद करना अहम होगा। सैन्य विशेषज्ञ यह भी मान रहे कि तीनों सेनाओं के बीच सीडीएस पर वर्चस्व के लिए खींचतान भी होगी। ऐसे में तीनों सेनाओं के जनरल को बारी-बारी से वरिष्ठता के आधार पर सीडीएस बनाने का विकल्प रखना होगा। सीडीएस भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों की तरह चार स्टार जनरल ही होगा, ऐसे में सीडीएस के सुपर बॉस के रूप में स्थापित करना भी सहज नहीं होगा।

हर पल सतर्क हैं जवान, ताकि सुरक्षित रहे कश्मीर

राज्य ब्यूरो, जम्मू

सूरज की पहली किरण हो या फिर ढलती शाम, कश्मीर में सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। मकसद एक ही है कि कश्मीर में शांति बनी रहे, किसी भी बेकसूर का आतंकी खून न बहा पाएं और शरारती तत्व कश्मीर के माहौल को खराब न कर सकें।

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने का फैसला किया था तो पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात कर दी थी। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। पूरे कश्मीर में जब लोग सो रहे होते हैं तो कश्मीर में सूनी पड़ी रात में सीआरपीएफ के जवानों के कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। वे हाथों में हथियार लिए पूरी तरह से सतर्क रहते हैं। रात को जवानों के लिए चुनौतियां अधिक होती हैं।

डल झील के किनारे ड्यूटी देने वाले जवानों का कहना है कि चुनौती तो होती है, लेकिन एहतियात बरतने से ही हर घटना को रोका जा सकता है। अभी सूरज की पहली किरण ने जमीन पर अपने कदम रखे भी नहीं होते हैं कि सुरक्षाबलों की सुबह की तैनाती को पूरा कर लिया जाता है। इस दौरान जवान पूरी तरह से सतर्क रहते हैं। उनकी नजर इस पर होती है कि कोई भी आतंकी कहीं पर भी आइईडी न लगा दे। यही नहीं जिन जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं, वहां पर बैरीकेड लगाए गए हैं। इन क्षेत्रों में 24 घंटे सुरक्षाबलों की तैनाती होने के कारण पत्थरबाजी की घटनाओं पर भी अंकुश लगा हुआ है। मुहल्लों में होने वाली पत्थरबाजी की घटनाएं न के बराबर हो गई हैं।

वहीं, एसएमएचएस अस्पताल के पास ड्यूटी दे रहे जवानों का कहना है कि उनके लिए कई चुनौतियां हैं। यह ऐसा क्षेत्र है, जहां पर मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। उनका काम है कि ऐसे क्षेत्रों में आने वालों को कोई भी नुकसान न पहुंचे।

59 लोगों को एनडीआरएफ व सीआरपीएफ ने सुरक्षित निकाला झारखंड के प. सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में बाढ़ से। यहां कोयल व कोयना नदी उफान पर है। बाढ़ आने की वजह से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 19 अगस्त 2019

कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी पर 354 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मुकदमा

कार्रवाई ▸ मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के निदेशकों के छह ठिकानों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने छापेमारी भी की

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहन व बहनोई भी मुकदमे में नामजद

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी समेत अन्य के खिलाफ 354 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। मामला मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड (एमबीआइएल) से जुड़ा है, जिसमें रतुल कार्यकारी निदेशक था। एजेंसी ने रविवार को आरोपित निदेशकों के राष्ट्रीय राजधानी स्थित आवास व दफ्तरों समेत कुल छह ठिकानों पर छापेमारी भी की। इनमें ओखला औद्योगिक क्षेत्र स्थित मोजर बेयर का दफ्तर और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित पुरी परिवार का आवास शामिल हैं। कंपनी कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी और स्टोरेज डिवाइस बनाती है।

एक अधिकारी ने बताया कि रतुल के साथ-साथ सीबीआइ ने उसके पिता व कंपनी के प्रबंध निदेशक दीपक पुरी, उसकी मां व कंपनी की निदेशक नीता पुरी (कमलनाथ की बहन) तथा अन्य निदेशक संजय जैन व विनीत शर्मा व कंपनी एमबीआइएल पर भी आपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी, धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

रतुल पुरी। फाइल फोटो

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआइ को की गई शिकायत में कहा है कि रतुल ने वर्ष 2012 में कंपनी के कार्यकारी निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उसके अभिभावक बोर्ड में कायम रहे। यह शिकायत अब प्राथमिकी का हिस्सा है। बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी वर्ष 2009 से ही कई बैंकों से कर्ज ले रही थी। इस अवधि में कंपनी ने विभिन्न बैंकों से 1,962 करोड़ रुपये के कर्ज ले लिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर 2011 तक 332 करोड़ रुपये के कर्ज दे दिए। बैंक ने कहा कि कर्ज अदा करने में विफल रहने पर कंपनी ने कारपोरेट कर्ज पुनर्गठन (सीडीआर) तंत्र के तहत इसके पुनर्गठन की मांग की, जिसे वर्ष 2012 में स्वीकार कर लिया गया। बाद में कंपनी ने सीडीआर का अनुपालन नहीं किया और बैंक ने उससे खाते वापस ले लिए। इस प्रकार 29 नवंबर 2014 को कर्ज खाता नॉन प्रॉफिट अकाउंट (एनपीए) घोषित हो गया।

बैंक कर्ज के लिए दस्तावेज से भी छेड़छाड़ का आरोप

शिकायत में बैंक ने दावा किया है कि कंपनी और इसके निदेशकों ने कर्ज पाने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फर्जी और छेड़छाड़ किए गए कागजात प्रस्तुत किए। इसमें कहा गया है कि एमबीआइएल ने 29 नवंबर 2014 तक अपनी अनैतिक आमदनी के लिए बैंक को 354 .51 करोड़ रुपये तथा उसके ब्याज का नुकसान पहुंचाया।

शिकायत के अनुसार, फोरेंसिक ऑडिट के दौरान पता चला कि कंपनी परिसंघ के बाहर खातों का संचालन और उनके जरिये राशि का विचलन कर रही थी। कंपनी ने सहायक इकाइयों में 1,456 करोड़ रुपये का निवेश किया। यहां तक कि कंपनी ने बिना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति के सहायक कंपनियों की तरफ से 2051.87 करोड़ रुपये की कारपोरेट गारंटी भी दे दी।

बैंक ने कहा, 'एमबीआइएल के तैयार, अर्ध तैयार और कच्चा माल बैंकों के सुरक्षा प्रतिभूति थे, लेकिन कंपनी और इसके निदेशकों ने बेईमानी और धोखाधड़ी से इनका दुरुपयोग किया। एमबीआइएल और इसके निदेशकों ने बैंकों की तरफ से दी गई राशि का निजी हित में दुरुपयोग किया। कंपनी, इसके निदेशक और प्रमोटर्स ने कर्ज रिपोर्टिंग बुक में भी धोखाधड़ी की, जो बैंक की प्राथमिक प्रतिभूतियों में से एक थी।'

आइएएनएस के अनुसार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम मुरली चेत्तुरी की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ शनिवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। रतुल के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाले में भी जांच चल रही है। ईडी का आरोप है कि इस मामले में रतुल की कंपनियों से जुड़े खातों में मनी लांड्रिंग के जरिये 3,600 की राशि भेजी गई है। हाल ही में आयकर विभाग ने दिल्ली स्थित रतुल पुरी के 300 करोड़ का बंगला व 40 मिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जब्त किया था।

इंदौर का जिला अंधत्व निवारण अधिकारी निलंबित किया गया

नईदुनिया, इंदौर

▸ मध्य प्रदेश में ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी जाने का मामला

मध्य प्रदेश के इंदौर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी जाने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने अंधत्व निवारण समिति के जिला प्रभारी टीएस होरा को रविवार को निलंबित कर दिया। मंत्री ने अंधत्व निवारण अभियान के प्रदेश नोडल अधिकारी डॉ. हेमंत सिन्हा, धार सीएमएचओ और इंदौर सीएमएचओ डॉ. प्रवीण जड़िया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तीनों अधिकारियों पर जानकारी छिपाने के संबंध में जवाब मांगा गया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में बिना अनुमति स्वास्थ्य शिविर लगाने पर मंत्री ने रोक लगा दी।

उधर, रविवार को शंकरा नेत्रालय चेन्नई के डॉ. राजीव रमन ने चोइथराम नेत्रालय में पीड़ित 11 मरीजों का परीक्षण किया। इनमें से तीन मरीजों को सोमवार को विमान से चेन्नई भेजा जाएगा। बाकी आठ में से चार मरीजों का ऑपरेशन रविवार को किया गया। अन्य चार मरीजों की विभिन्न जांचों के बाद उनके इलाज का निर्णय लिया जाएगा।

चोइथराम नेत्रालय में रविवार को दो और महिला मरीज पहुंचीं, जिन्होंने पांच अगस्त को इंदौर आई अस्पताल में इलाज कराया था। इलाज और ऑपरेशन के बाद दोनों की एक-एक आंख में मवाद हो गया था। एक मरीज स्कीम नंबर 51 निवासी मुन्नीबाई रघुवंशी की दाईं आंख डॉक्टर ने निकाल दी थी। साथ आए नाती शुभम ने बताया कि वे पांच अगस्त को अस्पताल पहुंचे थे। जांच के बाद मोतियाबिंद होना बताया गया। फिर 10 अगस्त को ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद आंख में दर्द हुआ तो सुबह फिर अस्पताल पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने सही जानकारी नहीं दी, सिर्फ दवाई दे दी। फिर भी लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा मवाद के कारण आंख खराब हो चुकी है। नहीं निकाली तो इंफेक्शन से जान का खतरा हो सकता है। नानी दर्द से परेशान थीं, इस पर परिजन ने आंख निकालने की अनुमति दे दी। 14 अगस्त को हुए इस ऑपरेशन के पैसे भी नहीं लिए।

ऑपरेशन के बाद भी नहीं लौटी रोशनी

पांच अगस्त को महिला राधा यादव निवासी पवनपुरी का ऑपरेशन भी किया गया था। ऑपरेशन के बाद आंख में दर्द होने पर वे जांच के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने बताया मवाद हो गया है, फिर से ऑपरेशन करना होगा। परिजन ने दूसरे डॉक्टर से भी चेकअप कराया तो उन्होंने इंफेक्शन होने के बाद सूजन आने की बात कही, लेकिन ऑपरेशन करने से मना कर दिया। इसके बाद परिजन इंदौर आई अस्पताल पहुंचे और वहीं ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के बाद भी राधा की आंख की रोशनी नहीं आई। दोनों महिला मरीजों की चोइथराम अस्पताल में रविवार को जांच की गई।

उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार टला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी अंतिम दौर में थी लेकिन, अचानक इसे टाल दिया गया। दो वर्ष पांच माह पुराने मंत्रिमंडल में सोमवार को पहली बार विस्तार होना था। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह बीते दिनों भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मार्गदर्शन लेकर लौटे थे।

सोमवार सुबह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सपा और कांग्रेस छोड़कर आने वाले राज्यसभा के पूर्व सदस्यों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलाने उनके पांच कालिदास मार्ग स्थित आवास पर गए थे। इस दौरान योगी और स्वतंत्रदेव के बीच मंत्रिमंडल विस्तार पर भी अंतिम चर्चा हुई और इसके बाद तैयारी शुरू हो गई। बड़ी संख्या में विधायकों और मंत्रियों को राजधानी में रविवार रात तक पहुंचने के निर्देश भी दे दिए गए। हालांकि राजभवन में देर रात तक अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार टाल दिया गया है। सोमवार को दोपहर बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिल्ली जाना है और उनकी वापसी दो दिन बाद होनी है। ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना बुधवार के बाद ही है। मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए जाने वाले संभावित नामों को लेकर खूब अटकलें चलती रहीं।

इस बीच, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के पद से इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया। भाजपा में एक व्यक्ति-एक पद का सिद्धांत चलता है। इसी आधार पर स्वतंत्र देव ने त्यागपत्र भेजा है।

रेलवे की छोटी खानपान इकाइयों को बचाने की रेलमंत्री से गुहार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली।

▸ सांसद राहुल शेवाले ने रेलमंत्री पीयूष गोयल को लिखा पत्र

▸ समय-समय पर जारी वाणिज्यिक परिपत्रों को रद करने की मांग की

रेलवे की छोटी खानपान इकाइयों ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से उनके साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने की गुहार लगाई है। इस संबंध में रेलवे कंवेंशन कमेटी के सदस्य सांसद राहुल शेवाले ने रेलमंत्री को पत्र लिखा है।

पत्र में सांसद शेवाले ने छोटी खानपान इकाइयों के संगठन अखिल भारतीय रेलवे खानपान लाइसेंसीज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से उठाए गए मुद्दों को उचित ठहराते हुए रेलमंत्री से रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए वाणिज्यिक परिपत्रों को रद करने की मांग की है। शेवाले का कहना है कि अगर इन परिपत्रों को लागू किया गया तो इससे हजारो पुराने वेंडर तथा उनके आश्रित सड़क पर आ जाएंगे। खानपान लाइसेंसीज वेलफेयर एसोसिएशन ने 2017 की खानपान नीति लाए जाने से पहले ही रेलवे बोर्ड को इस बाबत आगाह किया था। हालांकि अफसोस है कि उसके सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नतीजतन, रेलवे बोर्ड की ओर से जारी की गई मल्टीपरपज स्टॉल (एमपीएस) पॉलिसी से मौजूदा वेंडरों के समक्ष अनेक मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पॉलिसी के तहत प्रत्येक डिवीजन में अधिकतम पांच एमपीएस तथा प्रत्येक जोन में अधिकतम 10 एमपीएस की इजाजत दी गई है। हालांकि पुराने वेंडरों को इसकी अनुमति नहीं देकर उनके साथ भेदभाव किया गया है।

इसी प्रकार बिक्री के लिए अनुमत खाने-पीने की चीजों के मामले में भी पुराने वेंडरों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है। शेवाले ने नियमानुसार पांच वर्ष के बाद सभी मौजूदा छोटी खानपान इकाइयों केलाइसेंस नवीनीकृत करने का अनुरोध किया है। इससे पहले अखिल भारतीय खानपान लाइसेंसीज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रवींद्र गुप्ता स्वयं रेल मंत्री तथा रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को इस संबंध में ज्ञापन दे चुके हैं।

धर्मेंद्र प्रधान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा...

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को ओडिशा में बाढ़ प्रभावित बलांगीर, कालाहांडी, बौद्ध और सोनेपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने इन जिलों में जमीनी हालात का भी जायजा लिया। गौरतलब है कि राज्य के कई जिलों में मूसलधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों की शरण लेनी पड़ी है। सौ. पीआइबी

'पहलू खान मामले में पूर्व की सरकार ने बरती लापरवाही'

जागरण संवाददाता, जयपुर

▸ सीएम ने आरोपितों के बरी होने का ठीकरा भी वसुंधरा सरकार पर फोड़ा

▸ कहा, इस मामले में पूर्व सरकार की भूमिका की कराएगी जांच

तथाकथित उन्मादी भीड़ की हिंसा (मॉब लिंचिंग) में मारे गए पहलू खान को लेकर राजस्थान में राजनीति फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले के आरोपितों के एडीजे कोर्ट से बरी होने के लिए तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की लापरवाही से आरोपित बरी हो गए। उनकी सरकार इस मामले में पूर्व सरकार की भूमिका की जांच कराएगी।

उन्होंने कहा कि उस समय सरकार ने अपनी मर्जी से जांच कराने के लिए चार जांच अधिकारी बदले। जांच में कमियां रखी गईं, जिसके कारण आरोपित बरी हो गए। गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ही पहलू खान मामले में चालान पेश हो गया था लेकिन सरकार ने आरोपितों की न तो शिनाख्त कराई थी और न ही वो मोबाइल जब्त किया था, जिसमें पहलू खान के साथ मारपीट की रिकॉर्डिंग हुई थी। वह रविवार को जयपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भविष्य में गंभीर व सनसनीखेज अपराधों का त्वरित एवं प्रभावी जांच कराने के लिए प्रदेश स्तर पर जघन्य अपराध मॉनिटरिंग यूनिट बनाने का निर्णय लिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को इस यूनिट का प्रभारी बनाया गया है। दो कानूनी विशेषज्ञों को इसमें रखा जाएगा, जिससे कोर्ट में ऐसे मामलों की पैरवी पर लगातार नजर रखी जा सके।

सरकार कर रही वर्ग विशेष के लिए काम : वसुंधरा

इसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि सरकार वर्ग विशेष के लिए काम कर रही है। गहलोत सरकार एक तरफ तो उन्मादी भीड़ की हिंसा के लिए कानून बना रही है वहीं पहलू खान मामले की दोबारा जांच भी करा रही है। वह अलवर में हुए दूसरे उन्मादी भीड़ की हिंसा मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है।

लता मंगेशकर से मिले राष्ट्रपति, स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दीं

मुंबई, प्रेट्र : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को भारत रत्न से सम्मानित स्वरकोकिला लता मंगेशकर से मुलाकात की और उनके स्वस्थ जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। राष्ट्रपति उनसे मिलने उनके घर पहुंचे थे। कोविंद राजभवन में भूमिगत 'बंकर संग्रहालय' का उद्घाटन करने शहर आए थे।

मुलाकात का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा, 'लता मंगेशकर जी से रविवार को उनके निवास पर मिलकर प्रसन्नता हुई। उनके स्वस्थ जीवन के लिए मैंने उन्हें शुभकामनाएं दीं। लता जी भारत का गौरव हैं। उनके मर्मस्पर्शी गीत हमारे जीवन में मधुरता घोलते रहे हैं। उनकी प्रेरणादायी सादगी और सौम्यता हम सबको प्रभावित करती रही है।' लता मंगेशकर ने अपने ट्वीट में लिखा, 'नमस्कार, रविवार को भारत के राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने हमारे घर आकर जो हमारा सम्मान किया है, उसके लिए मैं ऋणी रहूंगी। सर, आप हमें गौरवान्वित करते हैं।'

लता मंगेशकर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रविवार को मुंबई स्थित उनके आवास पर मुलाकात हुई। प्रेट्र

कोविंद ने राजभवन में किया बंकर म्यूजियम का उद्घाटन

राष्ट्रपति कोविंद ने रविवार को मुंबई के राजभवन में भूमिगत 'बंकर संग्रहालय' का उद्घाटन किया। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि 15,000 वर्ग फुट के भूमिगत बंकर संग्रहालय में आभासी वास्तविकता बूथ हैं, जहां आने वाले लोग 19 वीं शताब्दी की झलक पाएंगे। 19वीं सदी में इस बंकर का निर्माण दुश्मन देशों के जहाजों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई के लिए किया गया था।

आरोप रद करने वाली तरुण तेजपाल की अर्जी पर फैसला आज

नई दिल्ली, प्रेट्र : तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुना सकता है। तेजपाल ने अपनी अर्जी में एक पूर्व महिला सहकर्मी द्वारा दर्ज कराए गए कथित यौन शोषण मामले के आरोपों को खारिज करने की मांग की है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीआर गवई की पीठ यह फैसला सुनाएगी।

बता दें कि गोवा पुलिस ने पहले दावा किया था कि वाट्सएप संदेश और ई-मेल यह प्रदर्शित करते हैं कि तेजपाल को कथित यौन उत्पीड़न मामले में मुकदमे का सामना करना चाहिए। पुलिस ने भी तेजपाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उसके पास मुकदमा शुरू करने लायक पर्याप्त सुबूत हैं। हालांकि तेजपाल के वकील ने आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि कुछ वाट्सएप संदेश छिपाए गए थे। कोर्ट से उस होटल के सीसीटीवी फुटेज का भी संदर्भ लेने को कहा था जहां पर यह कथित घटना हुई थी। तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में पूर्व सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।

पुलिस को चकमा देकर भागे अनंत सिंह ने कहा-जल्द करूंगा सरेंडर

जागरण संवाददाता, पटना

घर से एके-47 और ग्रेनेड मिलने के बाद बाहुबली विधायक अनंत सिंह पुलिस के साथ लुका-छिपी खेल रहे हैं। शनिवार देर रात पुलिस पटना स्थित विधायक निवास पहुंची, तो वह गायब थे। पुलिस ने तलवार व सरकारी मोबाइल फोन जब्त कर लिया। पत्नी से भी पूछताछ की गई। उनके आवास से एक फरार आरोपित छोटन सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। रविवार देर शाम टीवी चैनल पर अनंत सिंह का वीडियो दिखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह भागे नहीं हैं। बीमार दोस्त को देखने आए हैं। उन्हें फंसाया गया है। वह आत्मसमर्पण करेंगे। उनके दिल्ली में होने की सूचना के बाद एक टीम वहां भेज दी गई।

एक न्यूज चैनल पर अनंत सिंह का रिकॉर्डेड वीडियो प्रसारित हुआ। इसमें उन्होंने कहा कि बीमार दोस्त को देखने के लिए आए हैं। तीन-चार दिन में पटना स्थित सरकारी आवास पर लौट आएंगे। इसके बाद वह मीडिया से रूबरू होकर अपनी बात रखेंगे, फिर आत्मसमर्पण करेंगे। केयरटेकर सुनील राम की गिरफ्तारी के बारे में अनंत सिंह ने कहा कि वह बीमार इंसान है, उसे पुलिस ने परेशान किया है। उन्होंने कहा कि घर की तलाशी गांव के लोगों के सामने क्यों नहीं ली गई? पुलिस छोटी-छोटी उपलब्धियों को मीडिया के सामने साझा करती है, फिर इतनी बड़ी कार्रवाई के दौरान पत्रकारों को क्यों अनजान रखा गया?

अनंत सिंह। फाइल फोटो

अनंत के एक मॉल रोड स्थित सरकारी आवास में छापेमारी के दौरान अपराधी छोटन सिंह को पकड़ा गया। उसे घर में पनाह दिए जाने को लेकर सचिवालय थाने में अनंत और उनकी पत्नी नीलम देवी के खिलाफ आइपीसी की धारा 212 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

'फेक न्यूज' फैलाने वाली असम की वेबसाइट पर मुकदमा

गुवाहाटी, आइएएनएस : गुवाहाटी विश्वविद्यालय की शोध छात्रा के भाई ने 'फेक न्यूज' पर असम की वेबसाइट 'इनसाइड एनई' पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि वेबसाइट ने बीफ से जुड़े फर्जी मामले में उनकी बहन को फंसाने की कोशिश की है। शोध छात्रा रेहाना सुल्ताना के भाई रफीकुल इस्लाम ने वेबसाइट की संपादक अफरीदा हुसैन के खिलाफ कामरूप जिले के बोको थाने में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने रिपोर्ट में बताया है, 'वेबसाइट ने 12 अगस्त को एक स्क्रीनशॉट प्रसारित कर दावा किया था कि उसे रेहाना ने पोस्ट किया है। यह दावा असत्य, दुर्भावनापूर्ण और समाज में धार्मिक आधार पर अशांति फैलाने का प्रयास है।' इस्लाम ने कहा, 'एनआरसी के प्रकाशन से पहले शांति भंग करने के लिए वेबसाइट ने जानबूझकर पोस्ट की गलत व्याख्या की और तथ्यों को दबाया। इसके कारण मेरी बहन को लोगों की आलोचना और अपशब्दों का सामना करना पड़ा।'

मदद की आस

एक माता-पिता के बेटे चार साल की उम्र पाते ही हो जाते हैं मानसिक दिव्यांग, भीषण गरीबी की वजह से नहीं करा पाते इलाज

जंजीरों में बंधे रहते हैं चार बेटे, बिलखते रहते मां-बाप

उपेंद्र मिश्र, डेहरी ऑन-सोन

बिहार के रोहतास जिले के डेहरी शहर का एक मोहल्ला बारह पत्थर है। यहां एक घर के अहाते में चार युवक-किशोर जंजीरों से बंधे हुए हैं। सरफुद्दीन अंसारी और परवीन बीबी के ये बेटे मानसिक दिव्यांग हैं। इस दंपती के आठ बच्चे हैं, जिनमें चार बच्चे चार साल की उम्र के बाद ही मानसिक बीमारी के शिकार होते गए। पांचवें के लक्षण भी अब उन्हीं जैसे होते जा रहे हैं। सरफुद्दीन की मजदूरी से परिजनों का भरण-पोषण होता है और कमाई इतनी नहीं कि इलाज करा पाएं। इसलिए मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग अपने बेटों का बचपन जंजीरों में जकड़ दिया गया है। इन्हें रात-दिन जंजीरों में बांधकर ही रखा जाता है।

मौका मिलते ही भागने लगते हैं, इसलिए बांधकर रखा : सरफुद्दीन अपना दुख सुनाते हैं। थोड़ा सा मौका मिलते ही ये घर से भाग जाते और उपद्रव करने लगते थे। एक साथ चार-चार मानसिक दिव्यांगों को नियंत्रण में रखना इस मजदूर परिवार के बस की बात नहीं रह गई। थकहार कर इन लोगों ने चारों भाइयों के पैरों में लोहे की बेड़ियां पहना दीं।

घर में जंजीर से बंधे मानसिक दिव्यांग बेटे। साथ में इनकी मां परवीन बीबी और पिता सरफुद्दीन अंसारी। जागरण

जन्म के समय रहते हैं स्वस्थ, फिर घेर लेती है बीमारी : पिता सरफुद्दीन कहते हैं कि जन्म के समय उनके बच्चे स्वस्थ थे, लेकिन जब चार साल की उम्र हुई तो धीरे-धीरे मानसिक स्थिति बिगड़ गई। कहते हैं कि एक बच्चे को बीमारी हो तो किसी तरह इलाज भी करवा देते। एक साथ चार-चार बच्चे मानसिक रोग से ग्रसित हो गए, तो मुझ जैसे मेहनत-मजदूरी कर घर चलाने वाले के पास इनका इलाज कराना अब संभव नहीं है।

अभी तक नहीं मिली है सरकारी सहायता : इन लोगों को किसी प्रकार की कोई सरकारी सुविधा अबतक नहीं मिल सकी। यहां तक कि दिव्यांगों को दिए जाने वाले पेंशन तक भी मयस्सर नहीं हो सका। अब आयुष्मान भारत का कार्ड आधार कार्ड से लिंक होने की प्रक्रिया में है। पहले मनोचिकित्सकों से इलाज भी कराया, लेकिन गरीबी में महंगे इलाज के चलते बेहतर उपचार नहीं करा सके। मनोचिकित्सक डॉ उदय कुमार सिन्हा ने कहा कि पहले उन चारों को जंजीरों से मुक्त किया जाए। वे निशुल्क सलाह देने को तैयार हैं। उन्हें इलाज की जरूरत है। बिहार मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार राज्य में केवल कोइलवर मेंटल हॉस्पिटल और पीएमसीएच निबंधित हैं। एक्ट के अनुसार पुलिस को उन्हें अस्पताल में पहुंचाने का प्रबंध करने का प्रावधान किया गया है। वहीं एसडीएम लाल ज्योतिनाथ शाहदेव का कहना है कि प्रशासनिक स्तर से जल्द ही चारों के इलाज की व्यवस्था कराने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन की शुरुआत करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।

एलएसी पर महिला सैन्य दल ने चार दिन की पेट्रोलिंग पूरी की

नई दिल्ली, प्रेट्र : अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर 18 महिला सैनिकों के दल ने चार दिन की पेट्रोलिंग (गश्त) पूरी की। भारतीय सेना की महिला सैन्य अधिकारी ने इस गश्ती दल का नेतृत्व किया। आधिकारिक बयान के मुताबिक, महिला सैनिकों की इस टीम ने 10 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किबुतु से गश्त की शुरू की थी। इस दल में भारतीय सेना के साथ ही असम राइफल्स और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) की सदस्य शामिल थीं।

बयान में कहा गया है कि हिमालय की पहाड़ियों में साहसिक सह परिचालन गश्त पूरा करने वाली महिलाओं की यह पहली टीम थी। ऐसा कर इस टीम ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। बयान के मुताबिक इन महिला सैनिकों ने इतिहास में अपना नाम ही नहीं दर्ज कराया है, बल्कि 'नारी शक्ति' की जबरदस्त क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। सरकारी बयान में कहा गया है, 'दुरूह पहाड़ियों, घने जंगलों, नदियों की तेज धाराओं को पार करते हुए गश्त के चार दिन, गश्ती सदस्यों के धैर्य, दृढ़ संकल्प और नौसैनिक कौशल का परीक्षण करते हैं, जो देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर महिला सशक्तीकरण का वास्तविक प्रतीक है।'

▸ चीन की सीमा पर गश्त करने वाली पहली महिला टीम होने का बनाया रिकॉर्ड

▸ टीम में सेना, असम राइफल्स और आइटीबीपी की 18 सैन्यकर्मी शामिल

पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने गश्ती दल में शामिल महिला सैन्यकर्मियों के व्यावसायिकता और दृढ़संकल्प की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन पूर्वोत्तर में तैनात सुरक्षा बलों के बीच तालमेल का प्रदर्शन और देश को ताकत प्रदान करते हैं। साथ ही सैन्यकर्मियों को सीखने का भी मौका मिलता है।

3 लोगों की मौत हो गई पंजाब के लुधियाना जिले के गांव हौल में रविवार को। मरने वालों में दंपती और उनका एक आठ साल का बेटा शामिल है। हादसा बारिश में कमजोर हो चुकी छत गिरने से हुआ।

झारखंड में तिहरे हत्याकांड के बाद भड़का आक्रोश, घंटों रेल ट्रैक जाम

गुस्सा ▶ रेलकर्मी के घर में घुसकर आरपीएफ जवान ने पांच लोगों को मार दी थी गोली

तीन लोगों की हो गई थी मौत, दो का चल रहा है इलाज

जेएनएन, बरकाकाना (रामगढ़)

झारखंड के रामगढ़ जिले के बरकाकाना रेलवे कॉलोनी में शनिवार की रात आरपीएफ जवान द्वारा रेलकर्मी के घर में घुसकर पांच लोगों को गोली मार दिए जाने की घटना के बाद दूसरे दिन भी स्थानीय लोगों का आक्रोश चरम पर रहा। तिहरे हत्याकांड को लेकर रविवार को लोगों का गुस्सा सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक दिखा। घटना से आक्रोशित लोगों ने यहां दिनभर सड़क और रेलवे ट्रैक को जाम रखा। पौ फटते ही सैकड़ों की संख्या में आसपास के लोग रेलकर्मी अशोक राम के परिजनों के साथ सड़क पर उतर आए और आरोपित आरपीएफ जवान पवन सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रामगढ़-भुरकुंडा-पतरातू फोरलेन को पूरी तरह जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने टायर जलाकर नारेबाजी भी की।

झारखंड के रामगढ़ जिले के बरकाकाना रेलवे स्टेशन के पास प्रदर्शन कर रेल ट्रैक जाम कर रहे लोगों को समझाते एडीआरएम व रेल एसपी। जागरण

रेल ट्रैक पर घंटों जमा रहे लोग, रोकी गईं गाड़ियां : इसके बाद बरकाकाना स्टेशन पहुंचकर लोगों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। यहां गुस्साए लोगों ने प्लेटफार्म पर रखे रेलवे गार्ड के बक्सों को उठाकर रेलवे ट्रैक पर रख दिया। वहीं लाल कपड़े को झाड़ू में बांधकर बीच ट्रैक में गाड़ दिया। उग्र लोगों को ट्रैक पर देख डाउन गोमो-बरवाडीह पैसेंजर ट्रेन को ड्राइवर ने स्टेशन के बाहर ही रोक दिया। वहीं अप गोमो-बरवाडीह पैसेंजर बरकाकाना स्टेशन नहीं आ पाई। ट्रेन के रुक जाने से यात्रियों को दिनभर काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। सभी यात्री ट्रेन से उतर कर पैदल ही इधर-उधर जाते देखे गए। ट्रैक जाम हो जाने से इस रूट पर मालगाड़ियों का भी आवागमन बाधित रहा।

टिकट काउंटर व पूछताछ केंद्र भी कराया बंद : गुस्साए लोगों ने रेलवे के पूछताछ केंद्र व आरक्षण टिकट काउंटर को भी हंगामा कर बंद करा दिया। इससे दिनभर ना तो रेल टिकट बिके और ना ही किसी प्रकार की सूचना ध्वनि-विस्तारक यंत्र से दी गई। ट्रेनों के परिचालन बंद होने के बाद एडीआरएम, धनबाद रेल एसपी, रामगढ़ एसपी, एसडीपीओ, डीएसपी, रेल डीएसपी सहित वरीय अधिकारी बरकाकाना स्टेशन पर कैंप किए रहे। रेलवे ट्रैक जाम कर रहे परिजनों व स्थानीय लोगों को प्रशासन ने समझाने का खूब प्रयास किया, लेकिन लोग आरोपित जवान की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवार के दो आश्रितों को रेलवे में नौकरी तथा एक करोड़ रुपये का मुआवजा सहित अन्य मांगों पर अड़े हुए थे। पोस्टमार्टम के बाद अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे तीनों शव को लेकर परिजन व पुलिसकर्मी बरकाकाना पहुंचे तो लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने पुलिस-प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए एक शव को आरपीएफ पोस्ट में रख दिया। साथ ही दो शवों को स्टेशन परिसर में रेलवे ट्रैक पर रख कर विरोध-प्रदर्शन करने लगे।

देर शाम लिखित आश्वासन पर माने लोग : देर शाम करीब 5.43 बजे काफी मशक्कत के बाद समाज के प्रतिनिधियों की अगुआई में पुलिस-प्रशासन की वार्ता हुई। इसके बाद लिखित आश्वासन पर लोगों ने रेलवे ट्रैक व सड़क से जाम हटाया। इस बीच साढ़े आठ घंटे बरकाकाना-सीआइसी रेलखंड पूरी तरह जाम रहा। वहीं 12 घंटे के जाम के बाद सड़क मार्ग को भी चालू कराया गया।

क्या है मामला : शनिवार देर शाम बरकाकाना रेलवे कॉलोनी के एक घर में घुस कर आरपीएफ जवान पवन सिंह ने साधारण सी बात पर गोली चला दी थी। जवान की गोली से रेलकर्मी अशोक राम, उसकी पत्नी लीला देवी और गर्भवती पुत्री मीना देवी की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद जवान फरार है।

फाइनेंस कंपनी के निदेशक ने की 345 करोड़ की ठगी

जासं, नई दिल्ली : म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए 345 करोड़ रुपये फर्जी दस्तखत करके दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करके निवेश करने वाली कंपनी को चूना लगाने का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने फंड ट्रांसफर करने वाली फाइनेंस कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया है।

ईओडब्ल्यू के एडिशनल कमिश्नर सुभाशीष चौधरी ने बताया कि एलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एएफएसपीएल) के निदेशक अवनीश कुमार मिश्रा को 345 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फंड निकालने के लिए अवनीश कुमार मिश्रा ने शिकायत करने वाली कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के जाली हस्ताक्षर किए थे।

डालमिया सीमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव गेमावत ने 26 मार्च को अवनीश कुमार मिश्रा के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई थी। गेमावत ने आरोप लगाया था कि एएफएसपीएल, ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और आइएल एंड एफएस सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड (आइएसएसएल) ने उन्हें ठगा है। गेमावत ने कहा कि डालमिया सीमेंट एएफएसपीएल के साथ दो डीमैट अकाउंट्स में 344.07 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी और म्यूचुअल फंड मौजूद थे, जिन्हें जाली दस्तावेजों पर धोखाधड़ी करके दूसरी कंपनी के साथ गिरवी रख दिया गया। जांच में सामने आया कि अवनीश कुमार मिश्रा ने जाली हस्ताक्षर करके यह फंड आइएलएफएस नाम की कंपनी को ट्रांसफर कर दिए थे।

जिस डॉक्टर की रिपोर्ट की होनी थी जांच, उसे ही बोर्ड में शामिल किया

नीरज अग्रवाल, रांची

- धनबाद के दो डॉक्टरों के विरुद्ध हाई कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश
- स्वास्थ्य सचिव ने पीएमसीएच के अधीक्षक को किया तलब
- सभी कागजात और फाइल के साथ आज बुलाया

झारखंड हाई कोर्ट ने पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच), धनबाद के जिस डॉक्टर की रिपोर्ट की जांच का आदेश दिया था, उसी को जांच बोर्ड में शामिल कर लिया गया। हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध यह गंभीर लापरवाही धनबाद स्थित पीएमसीएच के अधीक्षक द्वारा की गई है। झारखंड हाई कोर्ट द्वारा इस पर गंभीर टिप्पणी करने तथा कार्रवाई के आदेश के बाद स्वास्थ्य सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी ने पीएमसीएच के अधीक्षक को तलब किया है। उन्होंने अधीक्षक को सारे संबंधित कागजात और फाइलों के साथ सोमवार को अपने कार्यालय में आने को कहा है।

दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद के बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 167/18 से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के क्रम में दो डॉक्टरों की रिपोर्ट में विरोधाभास होने पर रिपोर्ट की सत्यता की जांच मेडिकल बोर्ड गठित कर करने का आदेश पीएमसीएच के अधीक्षक को दिया था। इधर, पीएमसीएच अधीक्षक ने उक्त मेडिकल बोर्ड में डॉ. स्वपन कुमार सरकार, फॉरेंसिक विभाग को भी शामिल कर लिया, जिसकी रिपोर्ट की जांच का आदेश कोर्ट ने दिया था। सुनवाई के क्रम में हाई कोर्ट ने इस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए इसे कोर्ट की अवमानना बताया है। साथ ही डॉक्टरों द्वारा बरती गई लापरवाही से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) को अवगत कराने का निर्देश स्वास्थ्य सचिव को दिया। कोर्ट ने एमसीआइ को इस मामले की जांच का आदेश देते हुए की गई कार्रवाई से अवगत भी कराने को कहा है।

एक डॉक्टर ने कहा गर्भवती थी महिला, दूसरे ने कहा नहीं था गर्भ

कांड से संबंधित मृतका अंजुम बानो का पोस्टमार्टम पीएमसीएच के फॉरेंसिक विभाग के चिकित्सक स्वपन कुमार सरकार ने 11 अगस्त 2018 को किया था। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया कि पोस्टमार्टम में मृतिका का गर्भ होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। वहीं, कोर्ट के समक्ष रखी गई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गर्भ होने का जिक्र किया गया। क्लिनीलैब डाइग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर के डॉक्टर योगेश आनंद ने घटना से पूर्व पांच अगस्त 2018 को अंजुम बानो का अल्ट्रासाउंड किया था। कोर्ट ने दोनों की रिपोर्ट के विरोधाभासी होने के कारण दोनों की सत्यता की जांच करने तथा दोषी डॉक्टरों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई का निर्देश एमसीआइ को दिया है।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भाई सहित पत्रकार की गोली मारकर हत्या

जागरण संवाददाता, सहारनपुर

- हमलावर और उसके वेटे फरार, पत्नी व वेटी हिरासत में
- मुख्यमंत्री ने की मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये देने की घोषणा

आशीष कुमार धीमान

आशुतोष धीमान फाइल फोटो

उप्र के सहारनपुर स्थित पुराना माधोनगर में रविवार सुबह दबंग पड़ोसी और उसके बेटों ने घर में घुसकर दैनिक जागरण के युवा पत्रकार आशीष कुमार धीमान व उनके छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के प्रति शोक जताते हुए उनके आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये देने की भी घोषणा की है।

मोहल्ला पुराना माधोनगर में दिवंगत प्रवीण कुमार धीमान की पत्नी उर्मिला पुत्र आशीष (25), आशीष की सात माह की गर्भवती पत्नी रुचि, छोटे पुत्र आशुतोष उर्फ गौरी (18) तथा बुजुर्ग सास के साथ रहती हैं। इनके घर के सामने ही रहने वाले महीपाल सैनी ने सुबह दस बजे गाय का गोबर नाली में बहाने की बात कहते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी।

आशुतोष बाहर आये तो उनके सिर में आरोपितों ने डंडा मार दिया। आशीष बाहर दौड़े तो महीपाल व बेटों ने उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया। आशीष के मामा व क्षेत्रवासियों ने बीच-बचाव कर सभी को अलग कराया और भांजों को लेकर घर में चले गए। थोड़ी देर में महीपाल तमंचा लेकर आशीष के घर में घुस गया और पहले आशुतोष को गोली मारी और फिर आशीष को दो गोली मार दी। घटना के बाद बाप-बेटे फरार हो गए। दोनों भाइयों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि आशीष की मां उर्मिला धीमान की तरफ से महीपाल सैनी, उसकी पत्नी, बेटी व तीनों बेटों के खिलाफ हत्या व बलवे की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। महीपाल की पत्नी विमलेश व बेटी वर्षा को हिरासत में ले लिया गया है।

अवैध शराब की बिक्री में संलिप्त था महीपाल : स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपित अवैध शराब की बिक्री में संलिप्त थे। उनके घर पर पूर्व में पुलिस की छापेमारी भी हो चुकी है। महीपाल को आशीष पर पुलिस को सूचना देने का शक था। वे आशीष से रंजिश रखने लगे थे।

मां ने सोते हुए बच्चों का कुल्हाड़ी से काटा गला

नईदुनिया, शहडोल : मध्य प्रदेश स्थित शहडोल जिले के कोनी क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक मां ने अपने सोते हुए दो बच्चों पर कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनके शव घर के बाहर फेंककर खुद को घर में कैद कर लिया। मृतक बच्चों में 10 वर्षीय काजल बैगा और पांच वर्षीय राहुल बैगा है। घटना रविवार सुबह करीब सात बजे की है। आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एडिशनल एसपी प्रवीण भूरिया ने बताया कि बच्चों का पिता मुन्ना बैगा सुबह छह बजे शौच के लिए नदी की ओर गया था। इसी बीच मां गुड्डन बैगा (40) ने वारदात को अंजाम दे दिया। लगभग आठ बजे जब पिता आया तो उसने घर के बाहर दोनों बच्चों का शव देखा और पुलिस को सूचना दी।

पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह पिछले कई महीनों से अजीब हरकतें कर रही है। पुलिस ने घर का छप्पर काटकर देखा तो आरोपित महिला सब्बल (खोदाई में उपयोग होने वाला उपकरण) लेकर बैठी हुई थी। पुलिस ने मुश्किल से उससे दरवाजा खुलवाया। इसके बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया।

सुरम्य वादियों के बीच सर्पीली घाटी

प्रकृति के सुरम्य और रमणीय नजारे खुद में समेटे झारखंड की राजधानी रांची की पतरातू घाटी बारिश में और निखर उठी है। घाटी के ऊपरी हिस्से से खड़े होकर देखने पर एक-दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई सर्पीली और परतदार सड़कों की श्रृंखला का अद्भुत नजारा पेश करती यह घाटी अब झारखंड के पसंदीदा सेल्फी प्वाइंट और सबसे खूबसूरत स्थान में शुमार हो चुकी है। संजय सुमन

ताज में प्रतिबंध के बाद भी महिला पर्यटक ने बनाई पेंटिंग

जागरण संवाददाता, आगरा

अतिसंवेदनशील ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था की कलई रविवार को एक बार फिर खुल गई। महिला पर्यटक स्मारक में कलर लेकर प्रवेश कर गई। मुख्य मकबरे पर इत्मीनान से बैठकर उसने पेंटिंग भी बनाई, लेकिन उसे किसी ने नहीं रोका। ताजमहल में पेंटिंग सामग्री के साथ ही खाने-पीने तक का सामान ले जाना प्रतिबंधित है। पर्यटक अपने साथ केवल पानी की बोतल ही लेकर जा सकते हैं।

रविवार सुबह सात बजे मुख्य मकबरे पर मेहमानखाने की तरफ बैठकर महिला पर्यटक वाटर कलर से पेंटिंग बनाती नजर आई। स्मारक में पेंटिंग सामग्री प्रतिबंधित होने के बावजूद उसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के कर्मचारियों ने नहीं रोका। महिला पर्यटक को पेंटिंग बनाता देख कुछ गाइडों व फोटोग्राफरों ने उसकी फोटो खींच लीं। पूर्व में भी स्मारक में एक महिला पर्यटक के छुरी से फल काटकर खाने और एक पर्यटक के फोरकोर्ट में बीड़ी पीने के वीडियो वायरल हो चुके हैं। सीआइएसएफ कमांडेंट ब्रजभूषण ने बताया कि वह मामले की जांच कराएंगे।

ताज के दीदार में पर्यटकों को उठानी पड़ीं मुश्किलें

आगरा : ताजमहल के दीदार में पर्यटकों को रविवार को मुश्किलें उठानी पड़ीं। दोपहर साढ़े बारह बजे बारिश रुकने के बाद एक साथ भीड़ उमड़ने से टिकट विंडो पर लंबी कतारें लग गईं। पश्चिमी द्वार पर टिकट विंडो व टर्न स्टाइल गेट एक ही जगह होने से गफलत में गलत लाइन में लगने से पर्यटकों का समय बर्बाद हुआ। उमस होने से बुजुर्गों और बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार को ताज की टिकट विंडो से 21747 टिकट जारी हुए। ऑनलाइन बिक्री के आंकड़े उपलब्ध नहीं होने से उनकी संख्या करीब 25 हजार बताई जा रही है।

डीएम ने माना, लोकसभा चुनाव में वोटों का ब्योरा दर्ज करने में हुई चूक

जासं, बरेली

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार ने बरेली के कालीबाड़ी मुहल्ले में मिले महज पांच वोट को लेकर सवाल उठाया तो डीएम ने मौखिक जवाब दे दिया। वह यह कि कंप्यूटर में ब्योरा दर्ज करते समय वोटों की गिनती का आंकड़ा नीचे का ऊपर हो गया है। उनके इस जवाब पर मंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह को पत्र लिखकर कहा था कि लोकसभा चुनाव में कालीबाड़ी मुहल्ले के विष्णु बाल सदन के बूथ संख्या 290 पर भाजपा को महज पांच जबकि सपा को 583 वोट मिलना दर्ज हुआ है। यह मुहल्ला उप्र सरकार में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल का है। उनके परिवार के वोट भी इसी बूथ पर पड़ते हैं। भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले बूथ पर महज पांच वोट मिलना चूक दर्शाता है। शनिवार को डीएम ने मंत्री को मौखिक जवाब दिया। कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद वोट फीडिंग (मतों का ब्योरा कंप्यूटर में दर्ज करना) में चूक हुई। बूथ संख्या 289 के मत बूथ संख्या 290 में दर्ज हो गए, जबकि बूथ संख्या 290 में पड़े वोट बूथ संख्या 289 में दर्ज हो गए हैं। इसी गलती से 290 नंबर बूथ में भाजपा के महज पांच वोट दर्ज हैं। हार्ड कॉपी में यह गलती सुधार ली गई है। डीएम के इस जवाब पर पूर्व मंत्री एवं सपा के बरेली से लोकसभा प्रत्याशी रहे भगवत सरन गंगवार बोले कि वह पहले से कहते आ रहे कि प्रशासन ने गिनती में चूक की है। अब गलती करने वाले पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा वह चुनाव आयोग जाएंगे।

यह हुई गड़बड़ी

प्रशासन के अनुसार, बूथ संख्या 289 में भाजपा को पांच, सपा को 583, कांग्रेस को 29 वोट मिले थे। बूथ संख्या 290 में भाजपा को 569, सपा को 105, कांग्रेस को 33 वोट मिले। यही सही आंकड़ा है जोकि हार्ड कॉपी में ठीक करा लिया गया। जबकि कंप्यूटर में फीडिंग के वक्त बूथ संख्या 289 के वोट 290 में दर्ज हो गए, जबकि बूथ नंबर 290 के वोट 289 में चढ़ा दिए गए, जोकि गलती से हुआ।

मतदान का जो आंकड़ा गड़बड़ बताया जा रहा है, वह कंप्यूटर में फीड होते समय ऊपर नीचे हो गया है। हालांकि हार्ड कॉपी में आंकड़ा सही दिया गया है।

-वीरेंद्र कुमार सिंह, डीएम।

बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता को मौत के घाट उतारा

जागरण संवाददाता, वीरभूम : लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल के वीरभूम जिले में शुरू हुआ सियासी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को एक गांव में बम से हमला बोलकर भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई तो दूसरे गांव में तृणमूल और भाजपा समर्थकों के बीच रातभर बमबाजी होती रही। इसमें कई लोग जख्मी हो गए। तनाव के चलते गांवों में भारी पुलिस बल तैनात है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

सूत्रों के अनुसार, शनिवार रात लाबपुर के मीरबांध निवासी डालू शेख द्वारका गांव से अपने साथी के साथ घर लौट रहे थे। वह इलाके में भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में परिचित थे। आरोप है कि घर के पास ही तृणमूल आश्रित बदमाशों ने उन्हें घेरकर बम से हमला कर दिया। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव उठाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को खदेड़ दिया। इसमें कई लोग जख्मी हो गए। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गांव में तनाव के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष श्यामापद मंडल ने तृणमूल समर्थकों पर डालू शेख की हत्या करने का आरोप लगाया है। जबकि तृणमूल के जिला उपाध्यक्ष अभिजीत सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तृणमूल खून की राजनीति पर विश्वास नहीं करती है। आपसी गुटबाजी की वजह से ही डालू की हत्या की गई है।

उधर, लाबपुर की घटना के विरोध में थाने का घेराव करने जा रहे हातिरा गांव के भाजपा समर्थकों का तृणमूल समर्थकों के साथ टकराव हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि तृणमूल समर्थकों ने भाजपाइयों के घरों को निशाना बनाकर बमबाजी की। पुलिस ने गांव पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

उपलब्धि

मिट्टी के डॉक्टर की बात सुन प्रभावित हुए केंद्रीय सचिव, देश के अन्य प्रांतों को झारखंड से सीख लेने की नसीहत

केंद्र सरकार तक पहुंची झारखंड की मिट्टी की सुगंध

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड की राजधानी रांची के अनगड़ा प्रखंड के नवागढ़ पंचायत में खेत-खलिहान की सेहत संवारने को लेकर हुआ छोटा सा प्रयोग अब राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बंटोरने लगा है। इस पंचायत में मिट्टी की सेहत संवारने को लेकर हुए प्रयोगों ने भारत सरकार का ध्यान कुछ इस कदर आकृष्ट किया कि केंद्रीय आला अधिकारियों की फौज मिट्टी की खुशबू भांप नवागढ़ पंचायत पहुंच गई। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव राहुल भटनागर के नेतृत्व में शनिवार को पहुंची इस टीम ने न सिर्फ झारखंड सरकार की इस पहल की प्रशंसा की, बल्कि इस प्रयोग से देश के अन्य प्रांतों को सीख लेने की नसीहत भी दे डाली।

सचिव ने इस पंचायत का दौरा कर खेत-खलिहान तक पहुंच कर इस जांच से हुए फायदों को भी जांचा-परखा। सचिव इस दौरान मिट्टी के डॉक्टरों (प्रशिक्षण पाने के बाद खेतों की मिट्टी की जांच करनेवाले स्त्री-पुरुष) से मिले और उनके अनुभवों को भी ध्यान से सुना। मिट्टी के डॉक्टर तैयार कर इस पंचायत ने न सिर्फ एक मिसाल पेश की है बल्कि महिला सशक्तीकरण का अनोखा उदाहरण भी देश के सामने रखा है। मिट्टी की जांच की महिला टीम से केंद्रीय पंचायती राज सचिव खासे प्रभावित दिखे और उन्होंने टीम के सदस्यों की खासी सराहना भी की। मिट्टी जांच चिकित्सक पंचमी देवी ने मिट्टी की जांच के विभिन्न पहलुओं और मिट्टी के तत्वों की बारीक जानकारियां जब सचिव को दी तो वे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इस मौके पर झारखंड सरकार के पंचायती राज सचिव प्रवीण टोप्पो सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

मिट्टी की जांच को लेकर झारखंड में चल रही विशेष मुहिम का जायजा लेने रांची के अनगड़ा प्रखंड की नवागढ़ पंचायत पहुंची केंद्रीय टीम। जागरण

सभी पंचायतों में मिट्टी जांच केंद्र खोले जाने की जरूरत : राहुल भटनागर : नवागढ़ पंचायत में मिट्टी के डॉक्टरों की महिलाओं की टीम से प्रभावित केंद्रीय पंचायती राज सचिव राहुल भटनागर ने स्पष्ट कहा कि देश के अन्य प्रांतों को इनसे सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने स्वस्थ धरा, स्वस्थ जीवन के सिद्धांत से खेती करने की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि देश की सभी पंचायतों में इस तरह के मिट्टी जांच व प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की जरूरत है। झारखंड सरकार मिट्टी की जांच को लेकर बेहतर काम कर रही है।

21 को रांची में मिट्टी के डॉक्टरों का भव्य सम्मेलन : झारखंड में पहली बार मिट्टी के डॉक्टरों का राज्यस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 21 अगस्त को रांची में होने वाले इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में पूरे राज्य से किसान भाग लेंगे।

अशर एग्रो का एमडी 25 करोड़ की धोखाधड़ी में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मथुरा

मथुरा के छाता में स्थापित धान कंपनी अशर एग्रो के प्रबंध निदेशक विनोदम चतुर्वेदी को तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक से 25 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में शनिवार को मुंबई में गिरफ्तार किया गया है। इंडोनेशिया के पीटी बैंक से 18 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में वह मई से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद था और हाल में ही छूटा था।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने विनोदम चतुर्वेदी को फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक से 25 करोड़ की धोखाधड़ी करने के मामले में मुंबई में गिरफ्तार किया। पुलिस उसके छोटे भाई मनोज पाठक को भी तलाश रही है। मनोज पाठक पर मर्केंटाइल बैंक से धोखाधड़ी करने के मामले में अहम भूमिका निभाने का आरोप है।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में इस जांच से जुड़े एक अफसर के अनुसार, यह दिखाने के लिए कि उसकी अशर एग्रो का धान का कारोबार बढ़ रहा है, आरोपित ने तीन फर्जी कंपनियां खोलीं और बताया कि वह इन कंपनियों को अनाज की आपूर्ति कर रहा है। उसने बैंक से 20 करोड़ का नकद ऋण हासिल कर लिया। जांच अफसर के मुताबिक, कुछ महीने बाद पांच करोड़ के ऋण-पत्र खरीदे गए। कंपनी के निदेशक मनोज पाठक ने इसके लिए व्यक्तिगत गारंटी दी। एक चार्टर्ड एकाउंटेंट ने खरीद-फरोख्त के फर्जी चालान बनाने व जमा कराने में मदद की। विनोदम और मनोज ने 25 करोड़ की राशि दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी, जो नॉन परफार्मिंग एसेट बन गए। घोटाला सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने जुलाई में अशर एग्रो के मथुरा समेत उप्र के कई ठिकानों पर तलाशी ली थी।

अशर एग्रो पर दो हजार करोड़ से ज्यादा के बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले बताए जा रहे हैं। इसमें से 950 करोड़ के मुकदमे सीबीआइ की मुंबई शाखा ने दर्ज किए हैं। अशर एग्रो पर स्थानीय धान व्यापारियों का भी कई करोड़ बकाया है।

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 19 अगस्त 2019

दैनिक जागरण
शिक्षा भविष्य के लिए किया गया सबसे बेहतर निवेश है

असहमति के स्वर

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले को मिल रहे व्यापक समर्थन के बीच असहमति के भी कुछ स्वर उठे हैं। इतने बड़े देश में ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन इस फैसले से असहमत लोग कश्मीर की अशांति की आड़ में अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने वालों को जाने-अनजाने जिस तरह खाद-पानी देने का काम कर रहे हैं वह ठीक नहीं। इन लोगों की ओर से एक दलील यह दी जा रही है कि घाटी के नेताओं को भरोसे में लेकर ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए था। आखिर यह दलील देने वाले इससे अनजान क्यों बने रहना चाहते हैं कि कश्मीर के अधिकांश नेता तो पाकिस्तानपरस्त अलगाववादियों वाली भाषा बोलने में माहिर हो चुके हैं? उन्हें इस सच से भी अवगत होना चाहिए कि अनुच्छेद 370 अलगाव का जरिया बन गया था और राजनीतिक अधिकारों की आड़ में कश्मीरियत का उल्लेख कुछ इस तरह किया जाता था मानो वह भारतीयता से भिन्न और कोई विशिष्ट संस्कृति हो। बेहतर हो कि अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर रहे नेता और विचारक इस प्रश्न पर विचार करें कि आखिर इस अनुच्छेद से कश्मीर और साथ ही देश को हासिल क्या हुआ? इस प्रश्न पर कम से कम कांग्रेस नेतृत्व को अवश्य ही विचार करना चाहिए, क्योंकि उसके एक के बाद एक नेता विभाजनकारी अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन करते हुए यह भी कह रहे हैं कि पार्टी राह से भटक गई है। अच्छा हो कांग्रेस नेतृत्व यह देखे कि उसका रुख किसे बल प्रदान कर रहा है?

यह सही है कि कश्मीर में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ानी पड़ी है, लेकिन इसे लेकर चिंतित हो रहे लोग यह क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि वहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं और पाबंदियां हटाने का सिलसिला बढ़ रहा है? यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बीते एक पखवाड़े में घाटी में जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। निःसंदेह तथाकथित आजादी के सपने से प्रभावित कश्मीर के लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने में समय लगेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ऐसे कश्मीरियों को यह दिवास्वप्न दिखाया जाए कि बीते हुए दिन फिर लौट सकते हैं। यह नहीं हो सकता, क्योंकि इस मामले में देश न केवल एकजुट है, बल्कि दृढ़ संकल्पित भी है। इसी संकल्प भाव के कारण ही कश्मीर में आतंक और अलगाववाद के समर्थकों के हौसले पस्त हैं और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वह करे तो क्या करे? यह सही समय है जब कश्मीर संबंधी फैसले पर राष्ट्र एक स्वर में बोले, क्योंकि इसी से दुनिया को यह संदेश जाएगा कि भारत अपने रुख से टस से मस होने वाला नहीं।

प्राकृतिक आपदा

उत्तराखंड में एक बार फिर प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। आपदा में अभी तक 40 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। इससे आपदा प्रबंधन के दावों की हकीकत भी सामने आ गई है। उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्रों में रविवार को आई आपदा की बात करें तो यहां घटना के कई घंटों बाद तक हालात की सही जानकारी ही नहीं मिल पाई। घटना के कई घंटे बाद राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव दल देर शाम तक भी नहीं पहुंच पाया था। यहां संचार व्यवस्था ठप थी और बामुश्किल घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई। यह सारी स्थिति आपदा प्रबंधन के दावों को आईना दिखाने के लिए काफी है। यह बात सही है कि आपदा पर किसी का वश नहीं है, लेकिन राहत बचाव कार्य तो प्रशासन के हाथ में थे। छह साल पहले केदारनाथ में आई आपदा के बाद आपदा प्रबंधन के तमाम बड़े-बड़े दावे किए गए। संचार व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सेटेलाइट फोन खरीदे गए, त्वरित आपदा राहत कार्य चलाने के लिए प्रशिक्षण दिए गए। बड़े होटलों में कई कार्यशालाओं के माध्यम से आपदा से निपटने के गुर सिखाए गए। उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद आई आपदा के दौरान ये सारी तैयारियां कहीं दूर-दूर तक धरातल पर नजर नहीं आईं। इस आपदा में कितने लोग हताहत हुए, इसका कोई सटीक आंकड़ा घंटों बाद भी प्रशासन के पास नहीं था। हालांकि दोपहर बाद से सोशल मीडिया पर घटना की भयावह तस्वीरें सामने आने लगी थीं और लोग मदद की गुहार भी लगा रहे थे, लेकिन इन्हें समय पर सहायता नहीं मिल पाई। यह बात सही है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति बेहद जटिल है। यहां सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुंचना आसान नहीं है, मगर आपदा प्रबंधन में इसी का तो प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसी ही परिस्थितियों से निपटने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर उपकरण खरीदे जा रहे हैं। बावजूद इसके यदि घटना के 12 घंटे या उससे अधिक समय बाद राहत बचाव कार्य शुरू हो पाता है तो यह बेहद चिंताजनक है। ऐसी परिस्थितियां आपदा प्रबंधन को लेकर की जा रही तैयारियां पर सवालिया निशान लगाती हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन के कार्यों को और मजबूत बनाने की जरूरत की ओर भी इशारा करती हैं। सरकार को भी चाहिए कि आपदा प्रबंधन की तैयारियों की नए सिरे से समीक्षा की जाए। इसके लिए सुदूरवर्ती इलाकों में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक दुरुस्त करने के लिए कदम उठाने होंगे।

समावेशी विकास की दिशा में सार्थक कदम

एम वेंकैया नायडू

अनुच्छेद 370 की समाप्ति से जहां देश की एकता-अखंडता को मजबूती मिलेगी वहीं इससे विकास के मोर्चे पर पिछड़ गए राज्य में नई संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले ने एक देशव्यापी बहस छेड़ दी है। देश के अधिकांश लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वे यह भी मानते हैं है कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह देश की एकता-अखंडता से जुड़ा मुद्दा है। इसे राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस विषय पर किसी गंभीर बहस से पहले अनुच्छेद 370 के पीछे मूल उद्देश्य को समझना जरूरी है। वास्तव में यह एक अस्थायी प्रावधान था जिसे स्थायी बनाने की कोई मंशा ही नहीं थी। यह भी एक तथ्य है कि अनुच्छेद 370 वर्ष 1952 में अमल में आया। जम्मू-कश्मीर के भारतीय संघ में विलय के समय यह अस्तित्व में नहीं था। संविधान सभा ने अक्टूबर 1949 में इसे संविधान में शामिल किया था। इसका बीड़ा सभा के सदस्य शेख अब्दुल्ला ने उठाया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को अपने झंडे और अलग संविधान के साथ ही कई विशेषाधिकार भी मिले हुए थे। हालांकि इसे संविधान में शामिल कराना उतना आसान भी नहीं रहा था।

जब इसे संविधान में शामिल करने पर विचार हो रहा था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को सलाह दी कि वह डॉ. भीमराव आंबेडकर को इस विषय पर मनाएं। डॉ. आंबेडकर इसके पक्ष में ही नहीं थे। 'डॉ. आंबेडकर, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कांस्टिट्यूशन' में लेखक डॉ. एसएन बुसी ने इस संदर्भ में डॉ. आंबेडकर के बयान का उल्लेख किया है, 'श्री अब्दुल्ला, आप चाहते हैं कि भारत कश्मीर की हर आवश्यकता की पूर्ति करे और कश्मीर को भारत में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन आप यह नहीं चाहते कि भारत सरकार या भारत के किसी नागरिक को कश्मीर में कोई अधिकार मिले। ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृति देना भारत के हितों के साथ विश्वासघात होगा और कानून मंत्री के रूप में, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा।'

पंडित नेहरू ने भी 27 नवंबर, 1963 को संसद में अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान बताते हुए कहा था कि यह काफी घिस चुका है। फिर भी इतिहास साक्षी है कि कश्मीर के लोगों को शेष भारत के निकट लाने के बजाय अनुच्छेद 370 ने इस खाई को और चौड़ा ही किया। स्वार्थी तत्वों ने सुनियोजित तरीके से इसे अंजाम दिया। अनुच्छेद 370 आम नागरिकों को कोई फायदा पहुंचाने में नाकाम रहा, वहीं अलगाववादी राज्य और शेष भारत के बीच नफरत बढ़ाने में इसका इस्तेमाल करते रहे। यह सब पड़ोसी देश की शह पर होता रहा।

अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग लंबे समय से होती रही है। वर्ष 1964 में तो इस पर संसद में चर्चा भी हुई थी। तब इसे समाप्त करने के लिए एक निजी विधेयक को व्यापक समर्थन भी मिला था। प्रकाशवीर शास्त्री के इस प्रस्ताव को राममनोहर लोहिया और कांग्रेसी दिग्गज के. हनुमंथैया जैसे वरिष्ठ नेताओं का साथ मिला था। तब चर्चा हुई कि दलगत राजनीति से ऊपर सदस्य चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए कानून बने। सदन में अनुच्छेद को पूर्ण अखंडता की राह में रोड़ा माना गया। तब जिन 12 सदस्यों ने इसे हटाने का समर्थन किया उनमें सात कांग्रेस के थे। इनमें जम्मू-कश्मीर के इंदर जे. मल्होत्रा, श्यामलाल सर्राफ, समाजवादी एचवी कामथ, भाकपा के सरजू पांडेय और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद शामिल थे।

देश को लगा कि देर-सवेर इसकी विदाई हो जानी चाहिए। तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने इस पर कहा था कि 'अनुच्छेद 370, निहित प्रावधानों के बिना सिर्फ एक खोखला आवरण मात्र बचा है। इसमें अब कुछ भी नहीं रह गया है। हम इसे एक दिन में या 10 दिन में या फिर 10 महीने में समाप्त कर सकते हैं। यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है।'

मौजूदा सरकार और संसद अब इस फैसले पर पहुंची कि इस निरर्थक प्रावधान की कोई जरूरत नहीं रही। इसीलिए इसे समाप्त कर दिया गया। यह राज्य के लोगों के जीवन सुधार में एक बड़ा अवरोध बना हुआ था। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में उल्लेख भी किया कि देशवासियों को मालूम होना चाहिए कि केंद्र के वे कौन से लोक कल्याणकारी कानून थे जो अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं हो रहे थे। इसके हटने से कुल 106 केंद्रीय कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो सकेंगे। इस कड़ी में वहां भ्रष्टाचार निरोधक कानून, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, शिक्षा का अधिकार कानून, 72वें और 73वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय निकायों के सशक्तीकरण से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन की राह भी खुलेगी। इसी तरह अनुच्छेद 35 ए की समाप्ति से जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के साथ दशकों से हो रहे भेदभावपूर्ण अन्याय का अंत हो गया है। भले ही उन्होंने राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह किया हो, लेकिन उन्हें अब संपत्ति सहित अपने अन्य अधिकारों से हाथ नहीं धोना पड़ेगा।

मेरी दृष्टि में अनुच्छेद 370 को समाप्त करना भारत की एकता-अखंडता को अक्षुण्ण रखने की दिशा में एक सही कदम है। जम्मू-कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। ऐसे में इससे जुड़ा कोई भी निर्णय हमारा नितांत आंतरिक मामला है। इसमें किसी बाहरी पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। इस मामले में देसी-विदेशी मीडिया के एक वर्ग द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार के प्रति सजग रहना होगा।

अब जम्मू-कश्मीर का पूर्ण एकीकरण संभव हुआ है। संभवतः पंडित नेहरू स्वयं भी यही चाहते थे। यह एक सुधारवादी कदम है जिसका समय आ चुका था। जो आलोचक इसकी संवैधानिक प्रक्रिया पर प्रश्न उठा रहे हैं तो वे यह जान लें कि यह व्यापक चर्चा के बाद राज्यसभा में दो तिहाई और लोकसभा में 4/5 बहुमत से पारित हुआ है। मुझे विश्वास है कि यह एकीकरण लद्दाख सहित जम्मू और कश्मीर के कई वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। लद्दाख के सांसद जम्यांग शेरिंग नमग्याल का इस संदर्भ में लोकसभा में भाषण खासा उल्लेखनीय था जिसमें उन्होंने कहा कि लद्दाख मात्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि भारत की बेशकीमती मणि है।

मुझे भरोसा है कि जम्मू-कश्मीर में हालात सुधरने के बाद उसका पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 370 को हटाना वास्तव में एक साहसी और ऐतिहासिक कदम है जो देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, प्रगति और व्यवसाय के समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करने के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने का अवसर देता है। इससे राज्य में तमाम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश होगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ जवाबदेही भी बढ़ेगी। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाला यह कदम विकास में अपेक्षाकृत रूप से पिछड़ गए राज्य में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। वास्तव में यह स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में पहला कदम है।

(लेखक उपराष्ट्रपति हैं)

response@jagran.com

आर्थिक मंदी की डरावनी दस्तक

विवेक कौल

तमाम वस्तुओं की गिरती हुई बिक्री दर्शाती है कि लोगों को अपना आर्थिक भविष्य कुछ डांवाडोल नजर आ रहा है

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अंदाजा वहां की आर्थिक गतिविधियों को देखकर लगाया जा सकता है। 2019 के आरंभ से भारत में आर्थिक मोर्चे पर हाल कुछ सही नहीं रहे हैं। इन दिनों स्थिति और भी बदतर हो गई है। हम आर्थिक सूचकों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अब गाड़ियों की बिक्री को ही ले लीजिए। अप्रैल से जून 2019 के बीच में इनकी बिक्री पिछले साल की तुलना 23.3 प्रतिशत गिरी है। यह करीब 15 वर्षों में गाड़ियों की बिक्री में आई सबसे बड़ी गिरावट रही है। यहां यह कहना जरूरी है कि गाड़ी खरीदने की हैसियत सब भारतीय नहीं रखते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम दोपहिया वाहनों की बिक्री पर भी नजर डालें। इनकी बिक्री भी अप्रैल से जून 2019 के बीच में पिछले साल की तुलना में 11.7 प्रतिशत गिरी है। अक्टूबर से दिसंबर 2008 के बाद यह सबसे बड़ा संकुचन है। उन तीन महीनों में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 14.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी। पते की बात यह है कि मोपेड की बिक्री में भी भारी गिरावट आई है। उनकी बिक्री अप्रैल और जून 2019 के बीच पिछले साल के बनिस्बत 19.9 प्रतिशत गिरी है। इसके अलावा ट्रैक्टरों की बिक्री में भी 14.1 प्रतिशत की गिरावट आई है।

इन आर्थिक सूचकों को देखकर हमें क्या पता चलता है? कोई भी आदमी एक गाड़ी या एक दोपहिया वाहन या फिर एक ट्रैक्टर अपनी मर्जी से खरीदता है। इस बात के लिए उसे कोई मजबूर नहीं करता है। ऐसा करते हुए वह अपनी बचत का एक हिस्सा इन पर खर्च करता है। इसके अलावा इस खरीद के लिए पूरे पैसे का जुगाड़ करने के लिए ज्यादातर लोगों को बैंक या एनबीएफसी से कर्ज लेने की जरूरत भी पड़ती है। अब कर्ज लिया है तो इस कर्ज की भरपाई करने के लिए आने वाले दिनों में ईएमआइ भी देनी पड़ेगी। जब एक आदमी ईएमआइ देने की प्रतिबद्धता दिखा रहा है तो उसे अपने आर्थिक भविष्य पर विश्वास होता है। उसे यह भरोसा है कि ईएमआइ देने के लिए जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी उससे कहीं ज्यादा पैसा कमा लेगा, पर हाल-फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। वाहनों की गिरती हुई बिक्री दर्शाती है कि लोगों को अपना आर्थिक भविष्य कुछ डांवाडोल नजर आ रहा है। इसलिए वे खर्चा नहीं कर रहे हैं और इसका गुणक प्रभाव भी प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है।

गाड़ी या दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी सब कुछ खुद नहीं बनाती है। जैसे एक कार निर्माता कंपनी को ही लीजिए। पहिये कोई और बनाता है तथा स्टियरिंग कोई और। गाड़ी को बनाने के लिए जो स्टील लगता है वह भी किसी और कंपनी से आता है। तो अगर गाड़ियों की बिक्री में एक ठहराव सा आता है तो इसका असर बाकी कंपनियों पर भी पड़ता है। यह गुणक प्रभाव धीरे-धीरे पूरी अर्थव्यवस्था में फैलता है।

जब ऐसा होता तो इन कंपनियों में काम करने वाले लोगों की नौकरियां जा सकती हैं या वेतन स्थिर या कम हो सकता है। इसका प्रभाव उनके खर्चे पर पड़ता है। इसकी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी उपभोक्ता वस्तु बनाने वाली कंपनियां भी पहले जैसा कारोबार नहीं कर पा रही हैं। अप्रैल से जून 2019 के बीच में उसकी वॉल्यूम ग्रोथ (पैक बेचने में वृद्धि) करीब पांच प्रतिशत रही। पिछले साल यह करीब 12 प्रतिशत थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बाकी कंपनियां भी अपने कारोबार में पहले जैसी वृद्धि नहीं पा रही हैं। इन सब नकारात्मक कारकों के बीच बैंकों द्वारा दिया गया खुदरा ऋण अभी भी काफी मजबूत चल रहा है। अप्रैल से जून 2019 के बीच इसकी वृद्धि 16.6 प्रतिशत रही। पिछले साल इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 17.9 प्रतिशत रही थी। उपभोग व्यय भारतीय अर्थव्यवस्था का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा है। यदि उपभोग व्यय में मंदी देखी जा रही है तो यह स्वाभाविक है कि व्यापक अर्थव्यवस्था में भी मंदी फैल रही है।

अगला प्रश्न यह उठता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश की क्या स्थिति है? यदि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की मानें तो अप्रैल से जून 2019 के बीच मूल्य के हिसाब से नई निवेश परियोजनाओं की घोषणाओं में पिछले साल के मुकाबले करीब 80 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके अलावा निवेश परियोजनाओं के पूरे होने में भी 48 प्रतिशत की गिरावट आई है। इससे स्पष्ट है कि कारोबारियों को वास्तव में भारत के आर्थिक भविष्य में भरोसा नहीं है, चाहे वे सार्वजनिक रूप से इस बात को मानें या न मानें। यह आर्थिक मंदी सरकार के कर संग्रह में भी दिख रही है। अप्रैल से जून 2019 के बीच केंद्र सरकार का सकल कर संग्रह केवल 1.4 प्रतिशत बढ़ा। पिछले साल इसमें 22.1 प्रतिशत का इजाफा हुआ था। इसके अलावा वस्तु निर्यात अप्रैल से जून के बीच में 81.1 अरब डॉलर रहा। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 82 अरब डॉलर रहा था।

ये सारे आर्थिक सूचक आर्थिक मंदी का संकेत कर रहे हैं। ऐसे समय में सरकार क्या कर सकती है? कारोबारियों ने सरकार से एक लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग की है। इसका एक तरीका यह हो सकता है कि सरकार चालू वित्त वर्ष में बजट में तय खर्चे से एक लाख करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करे। बेहतर यह होगा कि सरकार ये पैसा उपभोक्ताओं के हाथों में दे और उन्हें खर्चा करने दे। यह कैसे होगा? इसके लिए जरूरी है कि इनकम टैक्स की दरें इस साल के लिए कम की जाएं। दूसरा वस्तु एवं सेवा कर की दरों में भी कुछ संशोधन किया जाए। इससे उपभोक्ताओं के हाथों में कुछ पैसा आएगा और चीजों के दाम भी गिरेंगे। इससे फिर उपभोक्ताओं द्वारा अधिक उपभोग की संभावना बढ़ेगी।इसके साथ यह भी जरूरी है कि सरकार बीएसएनएल, एमटीएनएल और एयर इंडिया जैसी कंपनियों पर और पैसा न गंवाए। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के पास जो जमीनें हैं उन्हें भी बेचने की कोशिश होनी चाहिए। इससे सरकार के पास पैसा आएगा और उधार लेने की जरूरत कम होगी। सरकार अगर कम उधार लेगी तो ब्याज दरें भी कम होंगी। इन सब चीजों के अलावा सरकार को यह भी कोशिश करनी पड़ेगी कि व्यापारियों के लिए चीजें और मुश्किल न बनाई जाएं।

(इजी मनी ट्राइलॉजी के लेखक अर्थशास्त्री एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समय के आगे

जो बीत चुका है उसका मोह छोड़ना सरल नहीं होता। वर्तमान में जीने वालों की भी संख्या कम होती है। वहीं समय से आगे का सोचने और करने की क्षमता और संकल्प ढूढने पर भी शायद ही मिले। वास्तव में मनुष्य की दृष्टि संकुचित होती जा रही है। प्राचीन काल में लोग पेड़ लगाया करते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसकी छाया में बैठ सकें, इसके फल खा सकें। कुएं खोदे जाते थे और तालाब बनवाए जाते थे जो किसी भी अनजान पथिक की प्यास बुझा सकें। एक तरह से पूरी सृष्टि का चिंतन था। इसी तरह मनुष्य के लिए मात्र वर्तमान जीवन ही नहीं, अगले जीवन को भी संवार लेने की प्रेरणा थी। कितने ही पुण्य कर्म, दान, जप, तप किए जाते थे कि आवागमन से मुक्त हो जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाए। मानव सभ्यता के विकास और ज्ञान के प्रसार ने मनुष्य को अधिक चैतन्य बना दिया है, किंतु उसे एक तरह से भूत और वर्तमान का कैदी बना दिया है।

आज मनुष्य की अधीरता प्रबल हो रही है। वह सब कुछ तुरंत पा लेना चाहता है। उसे अपने हर कर्म का ऐसा फल चाहिए जो उसकी कामनाओं को पूरा करने में सहायक हो। उसके पास दूसरों के लिए सोचने का समय नहीं है। दूसरों के लिए वह तभी सोचता है यदि कोई स्वहित सिद्ध होता हो। दृष्टि का यह संकुचन धर्म से दूर होते जाने का परिणाम है। आज धर्म स्थलों पर भीड़ है, पर उन लोगों की जो धर्म चिंतन से विहीन हैं। धर्म मूलतः चिंतन है जो कर्मों में प्रकट होता है। चिंतन विहीन कर्म बस कर्मकांड बन कर रह गए हैं। धर्म और आध्यात्म से जुड़ना मन, वचन और कर्म का समन्वित प्रयास है। इससे ही वर्तमान से आगे देख पाने की योग्यता विकसित होती है। समाज का हित इसी में है।

यदि आज पेड़ नहीं लगेंगे तो कल छाया और फल कैसे मिलेंगे। आज यदि गुणों का सम्मान नहीं होगा तो कल का समाज कैसा होगा। यदि कल के लिए कुछ करना है तो आज ही करना होगा। आज यदि भोजन कर रहे हैं तो पौष्टिकता तो कल ही मिलेगी।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

युवाओं में लोन लेने की बढ़ती प्रवृत्ति

मीनाक्षी भटनागर

इंडियालेंड्स की मानें तो देश के युवाओं द्वारा 2018-19 में सबसे ज्यादा लोन अपनी शादी के लिए लिए गए

हाल ही में डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडियालेंड्स के एक सर्वेक्षण में इस बात का खुलासा हुआ है कि देश के युवाओं द्वारा 2018-19 में सबसे ज्यादा लोन अपनी शादी के लिए लिए गए। यानी 20 से 30 वर्ष के युवा अन्य जरूरतों के बदले सबसे ज्यादा अपनी शादी को फंड करने के लिए लोन ले रहे हैं। देश के छह शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में नौकरी करने वाले और खुद का बिजनेस करने वाले 5200 युवाओं के बीच यह सर्वे किया गया है। शादी के बाद पर्यटन के शौक को पूरा करने के लिए युवाओं द्वारा लोन लिए जा रहे हैं। यानी 2018-19 में घूमने-फिरने के लिए 19 फीसद युवाओं ने लोन लिया। वहीं इस दौरान 11 फीसद युवाओं ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए और सात फीसद ने जीवनशैली से संबंधित वस्तुओं को खरीदने के लिए लोन लिया।

इसके अलावा अलग-अलग शहरों के नौजवानों की इस मामले में प्राथमिकताएं भी अलग-अलग हैं। जैसे कि मुंबई में 22 फीसद युवाओं ने अपनी शादी के लिए लोन लिया। यह सभी शहरों में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 27 फीसद युवाओं ने जीवनशैली से जुड़ी सुविधाओं को जुटाने के लिए लोन लिया। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा 27 फीसद लोन बेंगलुरु के नौजवानों द्वारा लिए गए। शिक्षा के लिए भी सबसे ज्यादा तकरीबन 20 फीसद लोन बेंगलुरु के ही युवाओं ने लिया। इसके अलावा घूमने के लिए सबसे ज्यादा लोन हैदराबाद के युवाओं ने लिया। वहां 20 फीसद युवाओं ने इसके लिए लोन लिया। सवाल है कि युवाओं में लोन की इस बढ़ती प्रवृत्ति की वजह क्या है? दरअसल यह पीढ़ी में आए बदलाव का नतीजा है। इसकी वजह से आज देश के युवाओं की सोच का तरीका काफी हद तक बदल गया है। वे पुरानी पीढ़ी की तरह हाथ बांधकर खर्च नहीं करते, बल्कि वे खुलकर खर्च करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। इसके लिए कर्ज लेने में भी संकोच नहीं करते। देखा जाए तो आज की युवा पीढ़ी पर पिछली पीढ़ी का दबाव भी कम है। वे अपने अधिकांश छोटे-बड़े निर्णय खुद ही कर रहे हैं। इसलिए युवा अपनी पसंद का काम करने के लिए स्वयं ही पैसे भी जुटाने लगे हैं। आज के युवा घूमने-फिरने के भी शौकीन हैं। पहले के लोग साधन के अभाव में ज्यादा दूर नहीं जा पाते थे, जबकि आवागमन की सुविधा के विस्तार ने आज युवाओं को मानों पंख दे दिए हैं। इस पर वे खुलकर खर्च भी कर रहे हैं।

इसी तरह वे अपनी जीवनशैली से जुड़ी चीजों पर भी काफी खर्च कर रहे हैं। समाज में दिखावे की बढ़ती संस्कृति इसकी एक वजह है। वे अपने साथी से कमतर नहीं दिखना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आज के युवा भविष्य की चिंता के बजाय वर्तमान में जीना अधिक पसंद करते हैं। यह जीवन को लेकर आए उनके नजरिये में फर्क की देन है। वे दबाव के बजाय ज्यादा खुलकर जीना चाहते हैं। भले ही इसके लिए कर्ज ही क्यों न लेना पड़े।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

मेलबाक्स

संकल्प से ही होगा नए भारत का निर्माण

नए भारत के निर्माण का नजरिया शीर्षक से संजय गुप्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण का गंभीरता से विश्लेषण किया है। निश्चित रूप से स्वतंत्रता के बाद देश को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था वह नहीं बढ़ पाया, क्योंकि तत्कालीन सत्तापक्ष का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं था, चुनौतियों की व्यापक समझ नहीं थी। चुनौतियों को समझे बिना उनके समाधान की ओर बढ़ना संभव नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने गंदगी, गरीबी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बुनियादी ढांचा, अंतरराष्ट्रीय संबंध आदि विभिन्न चुनौतियों को गंभीरता से समझा और फिर उनके अनुरूप योजनाएं बनाकर उनको संकल्पबद्ध होकर लागू किया। आज जल संकट, बढ़ती आबादी, आर्थिक चुनौतियां, प्लास्टिक पर अंकुश आदि अनेक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर गंभीरता से योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। यह भी सत्य है कि नौकरशाही योजनाओं को लागू करने में एक बड़ी बाधा है, लेकिन नए भारत के निर्माण के लिए दो स्तरों पर काम करने की आवश्यकता रहेगी-जन भागीदारी तथा उद्योग जगत का साथ। अंतरराष्ट्रीय संबंध और दिग्गज राष्ट्रों के साथ तालमेल भी आवश्यक है। नए भारत के निर्माण का रास्ता दृढ़ संकल्पों से ही तय होगा।

डॉ. वेदप्रकाश, हंसराज कॉलेज, दिल्ली

गलती में सुधार

दुनिया के किसी भी संप्रभु राष्ट्र को यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने द्वारा शासित किसी भी परिक्षेत्र, राज्य या प्रदेश के इतिहास में हुई गलती को सुधार ले। जम्मू कश्मीर में भी ऐसी ही गलती पूर्व में हुई थी। करीब 70 साल तक ऐसे ही चलता रहा। सभी सरकारों को पता था कि यहां गलती हुई है, लेकिन उसे सुधारने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। इसका नतीजा रहा कि वहां अशांति बनी रही। अपने ही देश के कुछ लोग पड़ोसी देशों के बहकावे में आकर अलगाववादी तत्वों का साथ देने लगे। हालांकि इनकी संख्या बहुत सीमित रही, लेकिन देश में गलत संदेश तो जा रहा था। अब सरकार ने इस गलती को सुधार लिया है। इसका नतीजा है कि राज्य में शांति स्थापित हो गई है। कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबरें नहीं आ रही हैं। यानी वहां ऐसी कोई बात थी ही नहीं, जिसके बारे में प्रचारित किया जा रहा था। सब कुछ पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित था। वहां के लोग सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। कहीं कोई हिंसा में शामिल नहीं है। यह बात न तो पाकिस्तान को अच्छी लग रही है और न ही देश के अंदर विरोधी दलों को, क्योंकि इससे उनकी राजनीति पर असर पड़ रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर सब कुछ शांत रहा तो उन्हें कौन पूछेगा? इसीलिए पाकिस्तान जहां वहां अशांति पैदा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, वहीं विरोधी दल के नेता सरकार पर अनाप-शनाप आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अब कश्मीर में शांति है। उम्मीद है अब राज्य का विकास होगा।

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

खतरनाक चीनी मांझा

हर साल 15 अगस्त पर पतंगबाजी के दौरान कुछ लोगों की मौत हो जाती है। कुछ बच्चे पतंग को पकड़ने के चक्कर में तो कुछ चीनी मांझे की चपेट में आ जाते हैं। तमाम पक्षी अलग से घायल हो जाते हैं। चीनी मांझे पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है। बेचने और खरीदने वाले इसके खतरे से कैसे अंजान रहते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि यह जानलेवा है? क्या कुछ पैसा कमा लेना ही उनका मकसद है? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? वह क्यों नहीं ऐसे मांझा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है। चीनी मांझे को बेचने और खरीदने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जिससे कोई इसे बेचने की हिम्मत न कर सके।

विजय कुमार धनिया, नई दिल्ली

आवासीय विद्यालय

गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय सराहनीय है। इन विद्यालयों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए की उनके बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की दोनों सुरक्षित तरीके से इन विद्यालयों में रहेंगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त वहां पर योग्य शिक्षकों का होना भी जरूरी है, अन्यथा शिक्षकों के अभाव में ये पूरा प्रयास ही निरर्थक हो जाएगा।

बाल गोविंद, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

1,689 शिक्षक ही हैं उत्तराखंड के 13 जिलों के 1,500 प्राथमिक विद्यालयों में, जिनमें करीब 39,000 छात्र पढ़ते हैं। इस तरह से प्रत्येक स्कूल में औसतन एक ही शिक्षक से स्कूल में पढ़ाई हो रही है।

आजकल

अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

कश्मीर पर विपक्ष का विरोध गलत राजनीति

बीते संसद सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए गए बड़े फैसले लेने के बाद कांग्रेस पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इसका विरोध किया और इनमें से कई नेता तो अब भी अनाप-शनाप बयान दिए जा रहे हैं। वास्तव में कांग्रेस पार्टी के अनेक नेता जिस तरह का बयान दे रहे हैं उनसे अगर किसी को थोड़ा बल मिल रहा है तो वे हैं पाकिस्तान तथा जम्मू कश्मीर को 370 के कारण अपने चंगुल में रखने वाले नेतागण। ऐसे में इस मामले से जुड़ी समस्या को समग्रता से समझे बिना विरोध करना सही नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि हमारे विरोध करने से फायदा किसे होगा

लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रश्न उठाया कि अगर अनुच्छेद 370 और 35ए को आप सही मानते थे तो फिर उसे संविधान में स्थायी क्यों नहीं कर दिया? आपके पास अपार बहुमत था। आप कर सकते थे। आपने नहीं किया, इसका मतलब है कि आप भी जानते थे कि जो हुआ वह सही नहीं था, लेकिन सुधार करने की आपमें हिम्मत नहीं थी। प्रधानमंत्री का कहना था कि राजनीतिक लाभ-हानि की दृष्टि से विचार करने के कारण आप ऐसा न कर सके। लाल किले के प्राचीर से ऐसा बोलने का महत्व क्या है यह बताने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने तथा उसके साथ 35 ए के अपने-आप समाप्त हो जाने को लेकर पूरे देश में सरकार को भरपूर समर्थन मिल रहा है। किंतु जिस तरह विरोधी आवाज उठा रहे हैं उनसे गलतफहमियां पैदा हो रही हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का यह कहना किसी विवेकशील व्यक्ति को स्वीकार होगा कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुल आबादी के कारण भाजपा ने अनुच्छेद 370 हटाया है? लोग पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल होने के कारण 370 लगाया तथा पीछे के रास्ते से 35ए लागू कर दिया? इस कदम का सांप्रदायीकरण करना कितना खतरनाक हो सकता है यह आसानी से समझा जा सकता है। चिदंबरम देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री रहे हैं। उनके पास जम्मू कश्मीर समस्या का पूरा ज्ञान होगा। अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिति की भी जानकारी होगी। स्वयं चिदंबरम के गृह मंत्री रहते हुए वहां भारी हिंसा हुई है।

इसी तरह कांग्रेस के एक और बड़े नेता मणिशंकर अय्यर ने अपने लेख में कह दिया कि नरेंद्र मोदी ने हमारी उत्तरी सीमा पर एक फिलिस्तीन पैदा कर दिया। उन्होंने लिखा कि जिस तरह फिलिस्तीनियों ने अमेरिका के पैकेज को ठुकरा दिया वैसे ही कश्मीर के लोग मोदी के आर्थिक पैकेज को ठुकरा देंगे। इन दोनों नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि क्या आप जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काकर आग लगवाना चाहते हैं? यह भारत के खिलाफ एक समुदाय को हिंसक संघर्ष के लिए उकसाना है। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को ही खत्म कर दिया। इन नेताओं को आप इनका निजी बयान कैसे मान सकते हैं? राहुल गांधी ने स्वयं कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक से बाहर आकर बयान दे दिया कि कश्मीर में गोलियां चल रही हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को यह कहते हुए इसका खंडन करना पड़ा कि लंबे समय बाद पूरे सप्ताह में एक भी गोली चलाने की आवश्यकता नहीं हुई है।

रजनीकांत का वक्तव्य इस बात का प्रमाण है कि सरकार के इस फैसले का सकारात्मक संदेश गया है। पी चिदंबरम और मणिशंकर अय्यर जैसे नेता रजनीकांत का विरोध नहीं कर सकते। उनके लिए तमिलनाडु में प्रवेश करना तक कठिन हो जाएगा। किंतु चिदंबरम ने जो कहा उसके पीछे अगर उनकी रणनीति है कि केवल कश्मीर नहीं, देश भर के मुसलमानों के अंदर यह भाव पैदा किया जाए कि मोदी सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिशंकर का लेखन भी इसी का विस्तार है। यह भारत विरोधी स्थायी हिंसा को प्रोत्साहित करने की भूमिका है। हालांकि इससे हम आप आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आज तक जम्मू कश्मीर समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? ऐसे वैचारिक दिशाभ्रम के शिकार नेताओं के हाथों देश के रहते हुए समस्या समाप्त होने का सवाल ही नहीं था।

इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि पाकिस्तान को यह प्रचार करने का आधार मिल रहा है कि भारत में ही विपक्षी पार्टियां मोदी के इस कदम को गलत मानती हैं। लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जैसे ही इसे संयुक्त राष्ट्र में लंबित बताया तथा शिमला एवं लाहौर समझौते के तहत द्विपक्षीय करार दिए जाने का उल्लेख करते हुए एकपक्षीय कार्रवाई का विरोध किया, पाकिस्तानी मीडिया में यह सुर्खियां बन गई। उस बयान के चार दिन बाद अधीर रंजन ने जम्मू कश्मीर की तुलना हिटलर के यातना शिविर से कर दी। इसका मतलब यह कांग्रेस की नीति है। राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बीच ट्विटर के जरिये हुआ द्वंद्व इसका साक्षात प्रमाण है। राहुल के बयान से नाखुश मलिक ने कहा कि राहुल गांधी को सोच-समझकर बयान देना चाहिए था। मैं उनके लिए जहाज भेज दूंगा, वो आकर देख लें कि यहां कोई गोली नहीं चली है।

कम्युनिस्ट पार्टियों की नासमझी समझ में आती है। उन्हें भाजपा जो भी करेगी उसका विरोध करना है। इसी में वे नष्ट हो गए। इसलिए माकपा और भाकपा के महासचिव क्रमशः सीताराम येचुरी और डी राजा का श्रीनगर चला जाना किसी को हैरत में डालने वाला नहीं था। उनको पता था कि इतने बड़े कदम के बाद जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसमें इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा पर इससे उनको सुर्खियां मिल जाएगी। लेकिन कांग्रेस इनकी नीति का अनुसरण करे, यह पार्टी के शर्मनाक वैचारिक पतन का प्रमाण है। सबको पता है पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लिए किसी सीमा तक जा सकता है। चीन भी इसे अंतर्मन से स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे में पूरे देश को एकजुट होना चाहिए था। कांग्रेस सबसे ज्यादा समय तक देश में शासन करने वाली पार्टी रही है। उससे ऐसे मामलों पर इस तरह के गैर-जिम्मेदार भूमिका की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। भाजपा से राजनीतिक मतभेद समझ में आता है, किंतु यह राजनीति नहीं देश की एकता-अखंडता का प्रश्न है। ऐसे संवेदनशील मामले में सोच-समझकर कुछ बोलना चाहिए।

बहरहाल इनके खिलाफ देश भर में गुस्सा पैदा हो गया है। आगामी चुनावों में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर ही इस मामले पर असंतोष है। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक भुवनेश्वर कलिता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सभी राज्यों में कांग्रेस के अंदर नेताओं के खिलाफ माहौल बना हुआ है। अनेक नेताओं ने खुलकर 370 हटाए जाने का समर्थन कर दिया है। कांग्रेस सहित विपक्ष के नेता विचार करें कि ऐसा करके वो किसका साथ दे रहे हैं? हालांकि ये सारे बयान कांग्रेस के लिए राजनीतिक आत्महत्या साबित होगी। किंतु यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तब तक ये देश का काफी अहित कर चुके होंगे।

घाटी में निवेशकों को जुटाने की चुनौती

शत्रुघ्न सैनी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों अपने एक विशेष संबोधन के जरिये पूरे देश और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को जो भरोसा दिया है, वह अपनेआप में बेहद खास है। प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिया है उनको 'एक आम जिंदगी लौटने का' जो आतंकवाद के चलते कश्मीर घाटी के लोगों के लिए बेहद दुर्लभ हो चली है। एक आम नागरिक की जरूरतें बेहद आम होती हैं। वो सरकार से बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, सुरक्षा और रोजगार की ही उम्मीद करता है। अगर सरकार पहली पांच बुनियादी जरूरतें पूरी कर देती है तो राज्य में नए नए रोजगार के मौके खुद ब खुद पनपने लगते हैं और युवाओं को काम मिलने लगता है। किसी भी राज्य की तरक्की के लिए उसके पास भरपूर फंड होना चाहिए। किसी भी राज्य को मिलने वाला यह फंड तीन तरीके का होता है। पहला केंद्र सरकार से मिलने वाला फंड, दूसरा राज्य सरकार द्वारा टैक्स और चुंगी के रूप में एकत्र किया गया फंड और तीसरा राज्य में बड़े उद्योग-धंधे चालू करने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स द्वारा राज्य में लाया जाने वाला फंड।

केंद्र सरकार से पहले ही जम्मू कश्मीर को बजट में से एक बड़ा हिस्सा फंड के रूप में मिल रहा है, लेकिन बदले राजनीतिक समीकरणों और नई चुनौतियों के चलते इसमे और इजाफा होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं राज्य के अपने टैक्स और चुंगी आदि से जुटाए जाने वाले फंड की जिसमें फिलहाल कोई बदलाव या इजाफा नहीं होने वाला है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है राज्य के विकास की योजनाओं के लिए पार्टनर के रूप में निवेशकों का आना।

कश्मीर को मुख्यधारा में लाने के लिए जरूरी है कि राज्य में काम-धंधे पनपें और युवाओं के पास भरपूर रोजगार हो। राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और नई नौकरियों के लिए काम धंधों को पनपने के लिए बेहतर माहौल चाहिए। किसी भी राज्य में निवेशकों को लाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि सरकार कुछ भी वादे करे, लेकिन निवेशक जमीनी हकीकत पर काम करता है। अगर किसी राज्य में बिजली सस्ती है, सड़कें अच्छी हालत में हैं, मजदूरी की दर कम है और अपराध की दर कम है तथा राजनीतिक स्थिरता है तभी कोई निवेशक उस राज्य में कोई नया उद्योग लगाने या काम-धंधा शुरू करने के बारे में सोचता है, लेकिन अगर इनमें से एक भी बात ठीक नहीं है तो निवेशक उस राज्य से अपना हाथ खींच लेता है। ऐसे में इस राज्य में निवेशकों को लेकर आना आसान काम नहीं है।

जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी चुनौती वहां पाक समर्थित आतंकवाद और अलगाववाद की सोच को समाप्त करना है जिसके बाद ही निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा और वो वहां की विकास योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे। घाटी में आतंकवाद को समाप्त करना और एक सुरक्षित माहौल बनाना ही मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जानकारों का मानना है कि घाटी में आतंकवाद को जड़ से मिटाना है तो अलगाववाद की सोच को हवा देने वाले चंद लोगों और उनको पाकिस्तान से मिलने वाली मदद को रोकना होगा और अगर आने वाले छह महीने मोदी सरकार ऐसा कर पाने में कामयाब हो जाती है तो घाटी के बेहतर माहौल को लेकर निवेशकों के मन में भी भरोसा पैदा करना होगा।

जम्मू और कश्मीर में एक बेहतर और सुरक्षित माहौल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को वहां की आम जनता के भरोसे को जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना वहां की जनता का साथ मिले मोदी सरकार इस सभी मोर्चों पर नहीं जीत सकती है। और जनता के भरोसे को कैसे जीता जाता है यह नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। वह यह भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के आम लोग आतंकवाद और अलगाववाद से तंग आ चुके हैं और अब वह अपने लिए एक सुकून भरा सुंदर भविष्य और विकास चाहते हैं। कश्मीर घाटी के लोगों की इसी इच्छा को समझते हुए प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा जोखिम भरा दांव खेला है और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कश्मीर से अभी तक मिली हैं उनसे तो यही लगता है कि घाटी को फिर से अमन चैन और तरक्की की राह पर ले जाने की इस लड़ाई में मोदी सरकार को आम जनता का पूरा साथ मिलेगा और कश्मीर घाटी के लोगों को भी देश की मुख्यधारा में शामिल किया जा सकेगा। इसी से वहां तरक्की की राह भी खुलेगी।

संस्मरण

सुषमा स्वराज संग बिताए अनमोल क्षण

गौरीशंकर राजहंस

सुषमा स्वराज से मेरी जान-पहचान दशकों पुरानी है। यह घटना उन दिनों की है जब सुषमा जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थीं। मैं जहां रह रहा हूं उस कॉलोनी को डीडीए ने रिहायशी कालोनी के रूप में विकसित कर वहां के निवासियों को जमीन आबंटित कर दी थी। लोगों ने मकान बना लिए थे। कुछ दिनों बाद डीडीए और एमसीडी ने नोटिस भेजा कि यह सार्वजनिक जमीन है, इस पर मकान नहीं बनाए जा सकते हैं। अतः जिन लोगों ने मकान बनाए हैं उन्हें अपने मकान तोड़ने होंगे। हम सभी इस नोटिस से हैरान थे। आपस में सहमति बनी कि उस समय की मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज के पास आवेदन किया जाए। उन्होंने हमारी समस्या को सुना और भरोसा दिलाया कि हमारे साथ न्याय अवश्य होगा। दूसरे ही दिन उन्होंने डीडीए और एमसीडी के अफसरों को बुलाया। अफसरों ने कहा कि यह बहुत पहले से ही सार्वजनिक भूमि थी। पहले यहां पार्क था। सुषमा स्वराज ने कहा कि यदि ऐसी बात थी तो इस जमीन के टुकड़े को सार्वजनिक रूप से नीलामी की बात अखबार में दी जानी चाहिए थी। डीडीए अफसरों ने कहा कि कुछ लोगों से अनजाने में भूल हो गई। सुषमा स्वराज ने कहा कि लोगों ने अपने मकानों को बनाने में जीवन भर की कमाई लगा दी है। यदि इनके मकानों को गिराया गया तो यह भला कहां जाएंगे। हम सभी ने राहत की सांस ली। उसके कुछ महीनों के बाद सुषमाजी राज्यसभा सदस्य हो गईं और मैं लोकसभा में बिहार से चुनकर आया था। हम प्रायः प्रतिदिन सेंट्रल हॉल में मिला करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी।

सुषमाजी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से राजनीति में आई थीं। 1977 में वह पहली बार 25 वर्ष की उम्र में हरियाणा विधानसभा की सदस्य बनीं। उसी समय चौधरी देवीलाल सरकार में केबिनेट मंत्री बनीं। 1980 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं और उसके बाद अनेक चुनाव सफलता पूर्वक उन्होंने लड़े। विदेशों में जो भारतीय किसी कारण फंस जाते थे, चाहे उनका पासपोर्ट खो गया हो या उन्हें बिना कारण विदेशों में जेल में डाला गया हो, उनकी सारी समस्याओं को पूरे लगन से वह सुलझाती थीं। सुषमा स्वराज में अनेक गुण थे। संयुक्त राष्ट्र में वह अंग्रेजी और हिंदी में धाराप्रवाह भाषण देती थीं। सुषमाजी अपनी सादगी और आत्मीयता की छाप हम पर छोड़कर सदा के लिए चली गईं।

(लेखक पूर्व सांसद व पूर्व राजदूत हैं)

ट्वीट-ट्वीट

इमरान खान भारत के परमाणु हथियारों के गलत हाथों में पड़ने की दुहाई दे रहे हैं तब क्या परमाणु हथियार उन जनरलों के हाथ में सुरक्षित हैं जो जिहादी आतंकी तैयार करते हैं। या उन कट्टरपंथियों के हाथ में जो अपने इस्लाम के स्वरूप से मतभेद रखने वालों के खिलाफ आग उगलते रहते हैं।

तवलीन सिंह@tavleen_singh

असल में इमरान की बौखलाहट इस बात को लेकर ज्यादा बढ़ रही है कि भारत अब उनकी सोच जैसा नहीं रहा। इमरान उसी भारत को जानते थे जो बहुत ज्यादा उकसाने पर ही कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करता था। इसीलिए उन्हें अब नेहरू-गांधी याद आ रहे हैं।

मेजर गौरव आर्या@majorgauravarya

अगर मोदी उद्यमियों को सम्मान देने की बात पर खरा उतरना चाहते हैं तो उन्हें अपनी सरकार के उस कानून को बदलना होगा जिसमें बड़ी कंपनियों के लिए अपने मुनाफे का दो प्रतिशत सरकार द्वारा तय सामाजिक कार्यों में लगाना अनिवार्य बना दिया है। यह समाजवाद की पराकाष्ठा है।

सदानंद धूमे@dhume

सद्गुरु शरण
स्थानीय संपादक, लखनऊ

उत्तर प्रदेश डायरी

प्रदेश में इतना सन्नाटा क्यों है भाई

वो तो गनीमत है कि दिल्ली में मोदी-शाह की जोड़ी कुछ न कुछ और खास करती रहती है जिससे माहौल में चार्ज आ जाता है, अन्यथा लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अजीब सन्नाटा छाया है। दो-ढाई साल पहले समाजवादी पार्टी सत्ता के सिंहासन पर विराजमान थी। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मनोबल इस कदर सातवें आसमान पर था कि उन्होंने यदुवंशियों की परंपरा के तर्ज पर अपने ही बंधु-बांधवों को निपटाना शुरू कर दिया। वक्त ने उन्हें सबक भी दिया। पहले 2017 में सत्ता गई। फिर 2019 में पूरी तरह पैदल हो गए। मुलायम सिंह की इच्छा के खिलाफ मायावती से गठबंधन करके अपने समर्थकों में इस हद तक अलोकप्रिय हुए कि कन्नौज सरीखी मजबूत सीट पर उनकी बेगम चुनाव हार गईं। चुनाव खत्म होते ही उनकी बुआजी ने अपनी आदत के अनुरूप खरी-खोटी सुनाकर उन्हें दूर छिटक दिया। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने मीडिया से दूरी बनाकर रखी थी तो अब मीडिया हिसाब बराबर करने में जुट गया। लोकसभा चुनाव के बाद उनकी सबसे चर्चित गतिविधि नए महलनुमा मकान में गृहप्रवेश रही, पर इस घर के दरवाजे आम सपा कार्यकर्ताओं के लिए बंद रहते हैं। उन्हें मानो कार्यकर्ताओं की फिक्र ही नहीं। चुनाव में हार का गम कम करने खुद परिवार के साथ विदेश निकल गए, पर मुलायम सिंह से लेकर आम कार्यकर्ता क्या करें? कैसे दिल बहलाएं? इसका नतीजा सामने आने लगा है। भाजपा का थिंकटैंक लोकसभा चुनाव में सपा का गढ़ ढहाने के बाद अब उसका मलबा साफ करने में जुट गया है। सारे दिग्गज सपाई एक-एक कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, पर अखिलेश बाबू इससे बेपरवाह हैं। जिस पीढ़ी ने मुलायम सिंह का संघर्ष देखा, उसे स्वाभाविक रूप से उनकी पार्टी के इस हश्र पर तरस आ रहा होगा, पर अपने ही उपक्रम से नष्ट हो जाना यदुवंश की पौराणिक परंपरा है। मुलायम सिंह ने कुछ साल पहले सपा की मजबूत नेतृत्व श्रृंखला को

नजरअंदाज कर अखिलेश पर भरोसा जताया था। पता नहीं, उन्हें अपने फैसले पर अब पछतावा है या वह इसे प्रारब्ध मान मौन हैं?

शांत और सहिष्णु बहनजी : बसपा में आंतरिक उठापटक की समस्या तो नहीं है, पर मायावती को इतना शांत और सहिष्णु इससे पहले कभी नहीं देखा गया। आखिर हुआ क्या बहनजी को? लोकसभा चुनाव में उनका कूटनीतिक कौशल सराहा जा रहा है, क्योंकि मोदी-नाम के आंधी-तूफान में भी वह बसपा का दीया नए सिरे से जलाने और विपक्ष में अपनी प्रतिद्वंद्वी सपा की दीया लगभग पूरी तरह गुल कर देने में कामयाब रहीं। इसके बावजूद उनकी चिर-परिचित आक्रामकता कहीं गुम हो गई है। चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री पद को लेकर उनकी महत्वाकांक्षा बार-बार व्यक्त हो रही थी। तब उन्हें ऐसे तूफान की आहट नहीं थी जो सब कुछ तहस-नहस करके गुजर जाएगा। सामने 2022 है, पर अखिलेश की तरह मायावती कैंप में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। समर्थक चिंतित हैं कि अब क्या होगा। 2014 से लेकर 2019 तक हर चुनाव में बसपा के कोर वोटबैंक में जिस तरह भाजपा के पक्ष में विचलन दिखा, उससे बसपा नेतृत्व में बेचैनी स्वाभाविक है, पर इसका साहसपूर्वक सामना करने के बजाय हथियार डाल देने की मुद्रा अख्तियार कर लेना अपने समर्थकों और लोकतांत्रिक रिवाज के प्रति अन्याय है। शायद मायावती को सबक मिल गया कि कोई पार्टी समय से अधिक बलशाली नहीं होता। इसीलिए वह फिलहाल मौन रहकर सन्नाटे का आनंद ले रही हैं।

कांग्रेस की बेदम उछलकूद : कांग्रेस के बारे में कहना ही क्या। प्रियंका गांधी अकेले अपने बूते उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ऐसा दीया जलाना चाहती हैं, जिसमें न तेल बचा है और न बाती। वह उत्तर प्रदेश सरकार को असंवेदनशील, नाकारा, भ्रष्ट और असफल साबित करने के लिए दिनभर ट्वीट करती रहती हैं, पर आम आदमी को धरातल की बातें समझ में आती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी प्रियंका गांधी ऐसा ही माहौल बना रही थीं, मानो उत्तर प्रदेश को भाजपा सरकार की नीतियों ने बर्बाद कर दिया, पर लोकतंत्र में आम आदमी का मत महत्वपूर्ण होता है। चुनाव-दर-चुनाव परिपक्व हो रहे लोकतंत्र के साथ आम आदमी की सियासी समझ बेहतर हो रही है। राजनीति, वह भी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में अब आसान नहीं रही। प्रियंका गांधी को यह बात समझनी चाहिए।

खाली मैदान में भाजपा : जब विपक्ष लुटा-पिटा दिख रहा हो तो सत्तारूढ़ पार्टी का काम आसान हो जाता है। प्रदेश में भाजपा इसी परिदृश्य का सुख भोग रही है यद्यपि सन्निपात के शिकार विपक्ष को सीखना चाहिए कि खाली मैदान पाकर भी भाजपा अपने राजनीतिक रूटीन को नहीं भूली। पार्टी ने पिछले दिनों न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बदला, सदस्यता अभियान, संगठन चुनाव व उपचुनाव की तैयारी को लेकर सक्रियता बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के बाद अपनी सरकार के कामकाज की समीक्षा का क्रम शुरू किया है। योगी की नजर 2022 पर है। सामने प्रबल चुनौती नजर न आने के बावजूद गंभीर दिखना योगी का राजनीतिक चातुर्य ही माना जाएगा।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में रवि शास्त्री का चयन सही है?

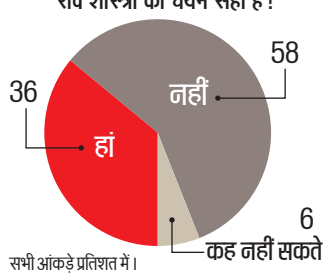

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या परमाणु हथियार पहले इस्तेमाल नहीं करने की नीति को लचीला बनाया जाना चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

दिल्ली में देखो शुरू हुआ चुनावी दौर,
कपिल-ऋचा की राह पर कई दिखेंगे और।
कई दिखेंगे और मचेगी भगदड़ भारी,
सरजी कर लो आप रुदन की अब तैयारी।
मिला जहां पर ताज उड़ेगी अबकी खिल्ली,
झेल चुकी है यार बहुत तुमको यह दिल्ली।

– ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

पहुंचानी होगी पहाड़ों तक शिक्षा की लौ

उत्तराखंड जैसे देश के पहाड़ी राज्य में सभी गांवों में सभी बच्चों तक शिक्षा व्यवस्था को पहुंचाना सरकार के लिए अब भी बड़ी चुनौती है जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग शिक्षा से वंचित हैं। सभी को शिक्षित बनाने के लिए इसका समाधान आवश्यक है

डॉ. दर्शनी प्रिय
स्वतंत्र टिप्पणीकार

भारत की एक बड़ी आबादी पहाड़ी इलाकों में बसती है। सुदूर पहाड़ों पर बसे गांव आज भी मुख्यधारा की शिक्षा से कटे हैं। मैदानी इलाकों से दूर और बाहरी दुनिया से अलग-थलग इन गांवों में बुनियादी शिक्षा की स्थिति खस्ताहाल है। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 40 प्रतिशत पहाड़ी बच्चे बुनियादी शिक्षा से महरूम हैं। अगर केवल उत्तराखंड की ही बात करें तो वहां छात्रों की कुल संख्या करीब चार लाख के आसपास है और शिक्षकों की उपस्थिति केवल आठ हजार। विभिन्न स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 760 पद इसलिए खाली पड़े हैं, क्योंकि अभावग्रस्त इलाका होने के चलते बहुत ही कम शिक्षक वहां जाने को राजी होते हैं। छात्रों की उपस्थिति के लिहाज से अगर स्कूलों की संख्या गिनें तो वह भी बहुत कम है। ढांचागत सुविधाओं की कमी के चलते अधिकतर स्कूल टेंट, अस्थायी शेल्टर या पेड़ के नीचे चलाए जा रहे हैं। अगर जोड़-तोड़ कर स्थान की कमी पूरी भी कर ली जाती है तो शिक्षकों की अनुपस्थिति एक अन्य बड़ी समस्या बनती है। गांवों के ज्यादातर स्कूल एक या दो शिक्षकों के भरोसे ही चलाए जा रहे हैं। कहीं स्कूलों से छत गायब है तो कहीं भवन इतने जर्जर स्थिति में हैं कि शिक्षक भयाक्रांत हो बच्चों को पढ़ाने से परहेज कर रहे हैं। कुछ संस्थानों द्वारा किए गए शोध से यह भी पता चला है कि जो शिक्षक दूरदराज इलाकों में पढ़ाने को लेकर इच्छुक नहीं हैं, वे वहां के स्थानीय युवाओं को डमी शिक्षक के तौर पर स्कूलों में भेज देते हैं और उन्हें मामूली मानदेय देकर काम चलाते हैं। कई बार बाहर के शिक्षकों को वहां शिक्षण हेतु भेजकर हालात नियंत्रित करने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन पर्याप्त संसाधन व सुविधा के अभाव में वे जगह छोड़कर चले जाते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षकों के ज्यादातर पद खाली पड़े हैं। दूसरी ओर तैनात शिक्षकों को नियमित वेतन भी नहीं मिल रहा जिससे नौनिहालों की शिक्षा प्रभावित हो रही है।

कुल मिलाकर पहाड़ों में शिक्षा की स्थिति दयनीय है। सुदूर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के पहाड़ी गांव भी इसी क्रम में हैं, लेकिन उत्तर भारत के गांवों के बरक्स उनकी व हालत

कमोबेश ठीक है, लेकिन पूरी तरह फिर भी ठीक नहीं। कहना न होगा कि देश के दोनों छोर पर शैक्षिक हालात एक जैसे हैं।

दूरदराज के इन गांवों में अब तक सरकारी सुविधाएं और योजनाएं पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाई हैं। सर्वविदित है कि पहाड़ों पर जीवन बहुत कठिन है और मुख्य इलाकों से कटे होने की वजह से उन तक संसाधनों की पहुंच भी आसान नहीं होती है। क्षेत्र या तहसील स्तर पर योजनाएं अगर लागू होती भी हैं तो पर्याप्त निगरानी के चलते कार्यान्वित नहीं हो पाती जिसके चलते जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। मैदानी इलाकों में सरकारी योजनाओं को समग्र रूप में लागू करना जितना आसान होता है उतना पहाड़ों में नहीं। जिनके पास गांव छोड़ कर जाने का विकल्प नहीं, वे यथास्थिति में बने हुए सरकारी सहायता की बाट जोह रहे हैं। अशिक्षित कृषक ग्रामीणों के पास सरकारी महकमे की ओर टकटकी लगाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं।

अन्य सभी बुनियादी सुविधाओं की बात को छोड़ भी दें तो शिक्षा एक ऐसी जरूरत है जिसे हर हाल में नौनिहालों तक पहुंचाया जाना चाहिए। संविदान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार पर उनका सर्वाधिकार है और प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्हें इसका पूरा लाभ मिलना ही चाहिए। सुदूर पहाड़ी देहात के ग्रामीण दोहरी मार झेल रहे हैं। एक ओर जहां उन्हें रोजगार के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है, वहीं दूसरी ओर अपने बच्चों की शिक्षा के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए भोले-भाले असहाय लोग या तो स्वयं के स्तर पर प्रयास कर रहे हैं या फिर सरकारी पहल की प्रतीक्षा में हैं।

राज्य के 13 जिलों के 1,500 प्राथमिक विद्यालयों में करीब 39,000 छात्र पढ़ते हैं जिन्हें केवल 1,689 शिक्षकों के भरोसे चलाया जा रहा है यानी प्रत्येक स्कूल के लिए केवल एक शिक्षक। अमूमन सभी स्कूलों में एक ही शिक्षक सभी विषय पढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति तो बागेश्वर जिले की है जहां 235 स्कूलों को प्रति विद्यालय एक शिक्षक के जरिये चलाया जाता है। इसी तरह चमोली में 122, पिथौड़ागढ़ में 222, रुद्रप्रयाग में 165 और पौड़ीगढ़वाल में 158, उधमसिंह नगर में 61, हरिद्वार में 60, चंपावत में 49 और देहरादून में 53 तथा नैनीताल जिले में 32 स्कूल हैं जो स्कूलवार केवल एक शिक्षक के बूते चलाए जा रहे हैं। इसके उलट इस स्थिति की एक दूसरी तस्वीर भी है जो यह बयां करती है कि उत्तराखंड के 748 स्कूलों में कोई छात्र ही नहीं है। इसमें से करीब 200 स्कूल तो अकेले अल्मोड़ा और पौड़ी क्षेत्र में हैं। वर्ष 2000 से इन्हीं दो इलाकों में विभिन्न कारणों से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। ऐसी स्थितियां विरोधाभास पैदा करती हैं।

ऐसा नहीं है कि केवल नीति नियंताओं की असजगता के चलते वहां ऐसा हो रहा हो। दरअसल वहां स्थानांतरित शिक्षक भी बहुधा अपना कार्यभार ठीक से नहीं संभालते और नौकरी के साथ हीलाहवाली बरतते हैं। पिछले दिनों इसी कारण कई शिक्षकों को बर्खास्त भी किया गया है। स्थिति जो भी हो, सवाल नौनिहालों की शिक्षा का है। शिक्षा की लौ उनलोगों तक पहुंचे, इसके लिए नीति नियंताओं और सरकारी एजेंसियों को मिलकर प्रयास करने होंगे। नई पौध की जड़ों में जब तक शिक्षा रूपी खाद नहीं डाली जाएगी, लहलहाती फसल की आकांक्षा बेमानी है। शिक्षा का दीप घर-घर जलना चाहिए चाहे समतल हो या पहाड़। शिक्षा के पावन आलोक से कोई अछूता न रहे, इसके लिए सचेष्ट प्रयास होने ही चाहिए।

16 से 18 आयु वर्ग वाले किशोरों को बिना गियर के दोपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति है। इसमें भी शर्त यह है कि वाहन 50 सीसी से कम होना चाहिए। अहम बात यह है कि देश में 2010 में ही 50 सीसी के वाहन बनने बंद हो गए।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 19 अगस्त 2019

गरीब और अनपढ़ बच्चों के घर पहुंचेगी मस्ती की पाठशाला

देश का हर नौनिहाल कंधे पर बस्ता टांग कर स्कूल जाने का सपना देखता है। मां-बाप हैसियत के मुताबिक, उसकी इच्छा पूरी भी करते हैं। इन सब के बावजूद लाखों बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, घर-परिवार की जरूरत या मजबूरी के कारण वह एक तो स्कूल जा नहीं पाते और अगर गए तो फिर वहां टिक नहीं पाते। हालांकि केंद्र व राज्य सरकारें सर्वशिक्षा और मध्याह्न भोजन समेत तमाम योजनाओं के माध्यम से स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के निरंतर प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में इंदौर के जिला प्रशासन ने शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्य धारा में लाने की एक नई पहल की है।

नई पहल

नईदुनिया, इंदौर

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की ऐसी बस्तियां, जहां के बच्चों का स्कूल से कोई नाता नहीं है, जो दिनभर काम करते हैं और पढ़ाई से वंचित हैं, उनके लिए मस्ती की पाठशाला उनकी बस्ती में ही आएगी। यह चलती-फिरती पाठशाला होगी, जिसमें बैठकर बच्चे पढ़ सकेंगे। इनके लिए दो विशेष बसें तैयार की जा रही हैं, जो क्लास रूम का काम करेंगी। कारपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) के तहत जिला प्रशासन इस चलते-फिरते स्कूल की योजना पर काम कर रहा है। यानी जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल खुद उनके पास पहुंचेगा।

सीएसआर के तहत यह बसें जुटाई गई हैं। इन बसों को गुजरात में डिजाइन कराया जा रहा है। योजना के लिए शहर के एक बड़े ट्रांसपोर्टर ने सीएसआर के तहत बसें उपलब्ध कराई हैं। यही नहीं, बसों के लिए ईंधन और ड्राइवर भी वही उपलब्ध कराएंगे। शहर में ऐसे कई बच्चे हैं, जो सामान्य रूप से स्कूल नहीं जाते हैं। घर-परिवार की जरूरत या मजबूरी के कारण दिनभर किसी दुकान, संस्थान या अन्य जगह काम और मजदूरी करते हैं। इनके पास स्कूल जाने का समय नहीं होता, इसीलिए वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। काम करने के कारण इन्हें शाम को ही फुर्सत मिल पाती है। जिलाधिकारी लोकेश कुमार जाटव का कहना है कि मस्ती की पाठशाला ऐसे ही बच्चों के लिए बनाई जा रही है। ऐसे बच्चे, जो कभी स्कूल ही नहीं गए या ड्रॉप आउट हो गए हैं, वे मस्ती की पाठशाला के विद्यार्थी बनेंगे। जब शाम को वे काम करके लौटेंगे तो यह विशेष बस उनके क्षेत्र में पहुंचेगी। बस को क्लास रूम की तरह सजाया जा रहा है, जिसमें बैठकर बच्चे पढ़ेंगे। प्रशासन ने बस तैयार कराने की जिम्मेदारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) जितेंद्र सिंह रघुवंशी को सौंपी है।

इन बच्चों को शिक्षित करने का विशेष मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। इसमें ऐसी शिक्षा प्रणाली होगी, जिससे बच्चे खेल-खेल में सीख सकेंगे। शिक्षक भी विशेष रूप से प्रशिक्षित होंगे, जो रोचक और रचनात्मक तरीके से पढ़ा सकें। बस में टीवी भी होगा, जिस पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा और उनको नाश्ता भी दिया जाएगा। एक बस में अधिकतम 40 बच्चे बैठकर पढ़ पाएंगे। हर दिन शाम को चिन्हित बस्ती में तय समय पर यह बस पहुंचेगी। बस ऐसे स्थान पर खड़ी होगी, जहां मैदान भी हो। यहां बस में पढ़ने के अलावा बच्चों को खेल भी खिलाए जाएंगे।

इंदौर में मस्ती की पाठशाला के लिए तैयार हो रही बस। नईदुनिया

देश में प्राथमिक शिक्षा की तस्वीर

88 फीसद औसत नामांकन है देश के प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा एक से पांच) में छात्र-छात्राओं का

23 का औसत आता है प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों और शिक्षक की संख्या (पीटीआर) का

85,010 करोड़ रुपये आवंटन किए हैं सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए

50,000 करोड़ रुपये स्कूली शिक्षा व साक्षरता पर खर्च के लिए आवंटित किया है सरकार ने 2018-19 में

चंबल का बीहड़ बना साइबर शातिरों का नया ठिकाना

जामताड़ा के बाद अब यहां के शातिरों ने उड़ाई कई राज्यों की पुलिस की नींद, साइबर सेल ने 25 गैंग चिह्नित किए

तहकीकात

यशपाल चौहान, आगरा

देश में साइबर ठगों के 'अभयारण्य' के रूप में पहचान रखने वाले झारखंड के जामताड़ा के बाद अब उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के 22 गांव साइबर शातिरों का नया ठिकाना बन गए हैं। हालांकि, यहां के शातिरों का अंदाज अलग है, लेकिन काम वही- बैंक खातों को साफ करना। चंबल के बीहड़ के इन गांवों से ऑपरेट हो रहे 25 गैंगों ने कई राज्यों की पुलिस की नींद उड़ा रखी है। ये शातिर सैकड़ों लोगों के खातों से करोड़ों रुपये पार कर चुके हैं।

मुंबई के बांद्रा वेस्ट निवासी जोयल गोंजालविस ने ई-मेल से आगरा रेंज साइबर सेल में शिकायत की थी। उनसे नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई थी। साइबर सेल की टीम ने 27 जुलाई को साइबर ठगों के सरगना बाह के बिजौली निवासी मुकेश बाबू, उसके भाई विजयकांत और विजयकांत के साले कृष्णवीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। महाराष्ट्र और गुजरात में ठगी का शिकार हुए लोगों ने यहां साइबर सेल की टीम से संपर्क किया। महाराष्ट्र पुलिस के पास भी साइबर ठगी की तमाम शिकायतें थीं। जिन मोबाइल नंबरों के जरिये ठगी की गई थी वे महाराष्ट्र और गुजरात के ही थे, लेकिन इनकी लोकेशन बाह क्षेत्र में मिल रही थी। दोनों राज्यों की पुलिस ने सभी नंबर साइबर सेल से साझा किए। इसके बाद उन नंबरों से जुड़े लोगों की जानकारी की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।

सूत्रों का कहना है कि बाह, जैतपुर, पिनाहट के 22 गांवों में साइबर ठगों के 25 गैंग संचालित हैं। 150 से 200 लोग इन गिरोहों में शामिल हैं। इनमें एक-एक गांव फीरोजाबाद और फतेहाबाद के भी हैं। ये लोगों से नौकरी, टावर लगवाने या लॉटरी निकलने के नाम पर ठगी करते हैं। कुछ शातिर वर्षों से इस गंदे खेल में लगे हैं, जबकि कुछ गैंग नए तैयार हुए हैं। पुलिस अब इन सभी गैंगों की तलाश में बीहड़ में दबिश दे रही है।

ऐसे करते हैं ठगी : गांव के लोग भले ही अनपढ़ या कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वे ठगी पढ़े-लिखे लोगों से भी कर लेते हैं। जिस राज्य के लोगों से ठगी करनी होती है, उस राज्य की सिम हासिल करने के बाद प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में नौकरी या टावर लगवाने के विज्ञापन देते हैं। शातिरों ने अपने घरों की महिलाओं को बात करने में कुशल बना लिया है। वे खेतों में बैठकर टेली कॉलर बनकर बात करती हैं। कॉल करने वाले लोगों से पहले पंजीकरण के नाम पर 550 रुपये ई-वॉलेट में ट्रांसफर करा लेती हैं। योग्यता पूछकर उनके योग्य नौकरी बताती हैं। आकर्षक सेलरी के लालच में कुछ लोग फंस जाते हैं। वे ई-वॉलेट में ही 10-15 हजार रुपये जमा करा लेती हैं। शातिरों ने अपने और रिश्तेदारों के नाम से आगरा, एत्मादपुर, टूंडला और इटावा की बैंकों में फर्जी आधार कार्ड के जरिये खाते खुलवा रखे हैं। इन खातों में रकम ट्रांसफर कर शातिर एटीएम या चेक से रकम निकाल लेते हैं।

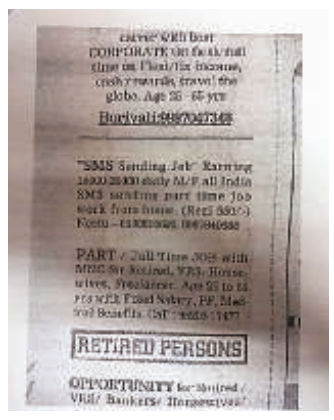

इस तरह के विज्ञापन के जरिये लोगों को जाल में फंसाते हैं साइबर शातिर। जागरण

22 गांव में सक्रिय हैं अपराधी

25 गैंग संचालित हो रहे हैं बीहड़ से

15 महिलाएं और करीब 200 पुरुष हैं संलिप्त

नौकरी का लालच देकर अपने ई-वॉलेज में पैसे जमा कराते हैं ठग। प्रतीकात्मक

> साइबर ठगों के करीब 25 गिरोहों के बारे में जानकारी मिली है। इनके पर्दाफाश को साइबर सेल की टीम लगाई गई है।
> – ए सतीश गणेश, आइजी, आगरा

इन गांवों में है ठिकाना

बाह, पिनाहट, जैतपुर, दड़हेता, गढ़वार, भगतन का पुरा, स्याही का पुरा, तिवरिया, रीठई, कांकर, छारबाग, मझटीला, जरार, फरैरा, मई, शंकरपुर घाट रोड (फतेहाबाद), टूला शाहपुरा (शमसाबाद), शाहवेद (निबोहरा), प्रताप पुरा, बिजौली।

लग्जरी लाइफ जी रहे शातिर

कुछ दिन पहले तक झोंपड़ी डालकर रह रहे शातिर गांव में ही लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। पक्के मकान और हर सुविधा के साथ लग्जरी गाड़ियां भी इनके दरवाजों पर खड़ी हैं। कुछ समय में बदले इनके रहन-सहन से ही पुलिस पहचान कर रही है।

अधिकारी चले गए, ई-टेंडर प्रक्रिया उनके डिजिटल हस्ताक्षर से चलती रही

राग दरबारी

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये के ई-टेंडर घोटाले में अधिकारियों द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षरों को न केवल विभाग के साथियों को देकर टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई गई, बल्कि तबादलों के बाद भी उनके हस्ताक्षरों से ई-टेंडर प्रक्रियाएं पूरी की गईं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) अहस्तांतरित डिजिटल हस्ताक्षरों का दूसरे व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर जांच कर रही है कि किसकी सहमति या आदेश से डिजिटल हस्ताक्षर का दूसरे व्यक्तियों ने उपयोग किया।

राज्य शासन द्वारा जिन नौ ई-टेंडरों में छेड़छाड़ की प्रारंभिक जांच कर ईओडब्ल्यू को मामला सौंपा था, उसमें जिन अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग किए गए थे उनके खिलाफ जांच शुरू हो रही है। जल निगम में प्रवीण दुबे, जल संसाधन में आशीष महाजन, लोक निर्माण विभाग में अखिलेश उपाध्याय, मप्र सड़क विकास निगम में पीयूष चतुर्वेदी और पीआइयू में विजय कुमार सिंह के डिजिटल हस्ताक्षरों से ई-टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई थी। जल निगम के दुबे और पीआइयू के विजय कुमार तो छेड़छाड़ के दौरान भी ई-टेंडर प्रक्रिया से जुड़े थे, लेकिन पीडब्ल्यूडी के उपाध्याय, सड़क विकास निगम के चतुर्वेदी व जल संसाधन के महाजन का तबादला हो चुका था।

सूत्रों के मुताबिक, लोक निर्माण विभाग में उपाध्याय की जगह नरेंद्र कुमार तो आरडीसी में चतुर्वेदी की जगह आरके तिवारी ई-टेंडर प्रक्रिया से जुड़े, लेकिन उपाध्याय और चतुर्वेदी के डिजिटल हस्ताक्षरों का दोनों जगह उपयोग किया जाता रहा। इसी तरह जल संसाधन विभाग में महाजन के बाद कई अधिकारी ई-टेंडर प्रक्रिया से जुड़े और सभी ने महाजन के डिजिटल हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया।

बताया जाता है कि डिजिटल हस्ताक्षर का पासवर्ड कोई भी अधिकारी किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकता। सूत्र बताते हैं कि ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है कि तबादले के बाद भी अगर किसी अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से टेंडर प्रक्रिया की गई है तो उसमें शामिल सभी पक्षों के बयान लिए जाएंगे। इसी तरह जिन अधिकारियों का तबादला नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपना पासवर्ड किसी भी साथी को दिया तो भी उन सभी लोगों के बयान लिए जाएंगे।

- डिजिटल हस्ताक्षर का पासवर्ड कोई भी अधिकारी किसी को नहीं कर सकता हस्तांतरित
- ईओडब्ल्यू कर रही जांच, किसकी सहमति या आदेश से किया गया ऐसा

मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये के ई-टेंडर घोटाले की चल रही जांच। प्रतीकात्मक

> डिजिटल हस्ताक्षर के लिए हर अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होता है। उसे वह किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को हस्तांतरित नहीं कर सकता। उससे होने वाली कार्रवाई के लिए वह खुद जिम्मेदार होता है। ई-टेंडर घोटाले में जिन टेंडर में छेड़छाड़ की गई है और डिजिटल हस्ताक्षर दूसरे व्यक्ति ने इस्तेमाल किया है उन दोनों से पूछताछ की जाएगी। जिम्मेदारी तय की जाएगी।
> – केएन तिवारी, महानिदेशक, ईओडब्ल्यू

डाटागीरी

सड़क दुर्घटनाओं में उत्तर प्रदेश में जाती हैं सबसे ज्यादा जानें

देश में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा जानें उत्तर प्रदेश में जाती हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देश के उन शीर्ष 10 राज्यों में भी शामिल हैं, जहां बीते वर्षों में सड़क पर जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। 2016 में राज्य में जहां सड़क दुर्घटनाओं में 19,320 लोगों की जान गई थी, वहीं 2017 में यह संख्या बढ़कर 20,124 हो गई। वहीं, मध्य प्रदेश की बात करें तो 2016 और 2017 में क्रमशः 9,646 और 10,177 लोगों ने जान गंवाई। यह जानकारी कुछ समय पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लोकसभा में दी थी।

2017 में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा जानें तमिलनाडु (16,157) में गईं, लेकिन 2016 (17,218) की तुलना में हालात सुधरे हैं। आबादी के लिहाज से दूसरे बड़े राज्य महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। 2015 में महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटनाओं में 13,212 जानें गई थीं, वहीं 2016 और 2017 में क्रमशः 12,935 और 12,264 लोगों की मौत हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2015 से 2017 के बीच सड़क दुर्घटनाओं में देशभर में रोजाना 140-145 लोगों की जान गई। (नेशनल डेस्क)

साल	राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटनाएं	राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेसवे पर गई जानें
2015	1,42,268	51,204
2016	1,42,359	52,075
2017	1,41,466	53,181

दुनिया का पहला टूरिस्ट स्पेसपोर्ट

1

2

3

1. दुनियाभर के देशों में स्पेस (अंतरिक्ष) में जाने की होड़ मची है और इसी के साथ अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में भी काम चल रहा है। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए न्यू मेक्सिको रेगिस्तान में दुनिया का पहला टूरिस्ट स्पेसपोर्ट खोला गया है। इसका नाम है स्पेसपोर्ट अमेरिका। भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में यह उम्मीद की पहली किरण है। यह एहसास दिलाने के लिए है कि आप यहां से भविष्य में स्पेस के लिए फ्लाइट पकड़ सकेंगे।

2. **ग्राउंड फ्लोर :** वर्जिन समूह की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने बीते सप्ताह इस पर से पर्दा उठाते हुए इसकी कुछ तस्वीरें जारी की हैं। इस तस्वीर में वर्जिन गैलेक्टिक के कर्मचारी ग्राउंड फ्लोर खाने का आनंद ले रहे हैं। कंपनी का कहना है कि ये तस्वीरें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जारी की गई हैं।

3. **प्रवेश द्वार :** यह तस्वीर स्पेसपोर्ट के प्रवेश द्वार की है, जिसकी छत शीशे से तैयार की गई है। इसे इतना भव्य तैयार किया गया है, मानों यह किसी महल का हिस्सा हो। यहां एक कॉफी बार भी है, जिसके निर्माण में इटली के संगमरमर का प्रयोग किया गया है।

शब्द संसार

नेताजी के जीवन पर मिस्ट्री थ्रिलर

नई दिल्ली : नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डालने वाली दो नई पुस्तकें आई हैं, जिनमें से एक को उनकी पुत्री ने नेताजी जैसे व्यक्ति का जीवंत वृतांत बताया है। विश्वास पाटिल की पुस्तक महानायक नेताजी के भारत से जर्मनी, इटली, सिंगापुर, जापान, बर्मा (अब म्यांमार) जाने तक की कहानी बताती है। इसमें आजादी के लिए भारत के संघर्ष की दास्तां को एक थ्रिलर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन मराठी में भी किया जा चुका है। नेताजी की पुत्री अनिता बोस कहती हैं, नेताजी सरीखे व्यक्तित्व का जीवन रोमांच और नाटकीयता से अलग हो ही नहीं सकता। एक उपन्यास किसी व्यक्ति की असली जिंदगी को कहीं अधिक सटीकता से दर्शा सकता है। इसके माध्यम से पाठकों के लिए संबंधित किरदार को समझना कहीं अधिक आसान होता है। दूसरी पुस्तक श्रेयस भावे की प्रिजनर आफ याकुस्क है। यह किताब 18 अगस्त को रिलीज की गई। गौरतलब है कि 74 साल पहले 18 अगस्त को ही वह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें नेताजी सवार थे। इस किताब में 2005 में सामने आई मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट का ब्योरा दिया गया है। इस किताब को भी मिस्ट्री थ्रिलर के रूप में लिखा गया है, जिसके केंद्र में है सुभाष चंद्र बोस का रहस्यमय तरीके से परिदृश्य से गायब हो जाना। (प्रेट्र)

जानें क्या होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इससे क्या होगा बदलाव

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

360 डिग्री

भारत में सैन्य सुधार के लिहाज से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति का एलान एक बड़ा कदम है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका एलान किया है तब से इस पद को लेकर देश में दिलचस्पी बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि सेना के तीनों अंगों में तालमेल बढ़ाने के लिए इस पद की जरूरत है, ताकि संकट की स्थिति में एकीकृत निर्णय लेने में आसानी हो। आइए जानते हैं इस घोषणा के तमाम पहलुओं को...

अहम सैन्य पद : यह एक उच्च सैन्य पद है, जिस पर बैठने वाले व्यक्ति को तमाम अहम फैसले लेने होंगे। सबसे बड़ा काम यह है कि सेना के सभी अंगों के बीच समन्वय कायम हो। उसे कार्यपालिका, भारत के मामले में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार को तीनों सेनाओं के नजरिये की स्पष्ट जानकारी देनी होगी। यह जानकारी दीर्घकालीन योजनाओं के संदर्भ में भी होगी और प्रबंधन के लिहाज से भी। उसे यह बताना होगा कि कितनी मानव शक्ति की जरूरत है, क्या-क्या उपकरण चाहिए। रणनीति क्या होनी चाहिए। युद्ध अथवा किसी अन्य टकराव की स्थिति में सीडीएस की भूमिका बेहद अहम होगी।

तमाम देश ऐसे हैं जिनके पास आधुनिक सेनाएं हैं और उन्होंने इस पद का गठन कर रखा है। हालांकि, इन देशों में सीडीएस के अधिकारों और शक्तियों में अंतर है। उदाहरण के लिए अमेरिका में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन अधिकारों के मामले में बेहद संपन्न है। वह सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी है और राष्ट्रपति को सैन्य मामलों में सलाह देता है।

भारत में क्या स्थिति रही है? : इस पद के गठन को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चलती रही हैं। एक पद पहले से है-चेयरमैन, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी)। यह पद काफी कुछ सीडीएस जैसा ही है, लेकिन अधिकारों के लिहाज से इसका ज्यादा मतलब नहीं है। अभी तक परंपरा रही है कि थलसेना, वायुसेना, नौसेना प्रमुखों में जो सबसे अधिक वरिष्ठ होता है उसे सीओएससी बना दिया जाता है। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है तो यह पद स्वतः समाप्त हो जाता है। इस समय चेयरमैन सीओएससी के पद पर वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ हैं। उन्होंने 31 मई को नौसेना प्रमुख सुनील लांबा की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद धारण किया है। धनोआ को सितंबर 2019 तक वायुसेना प्रमुख के पद पर रहना है। इसका मतलब है कि वह चेयरमैन सीओएससी के पद पर केवल चार माह रह सकेंगे। 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने इस पद को असंतोषजनक बताया था। सीओएससी सिस्टम दरअसल उपनिवेश काल की विरासत है। कहा जाता है कि भारत में राजनीतिक वर्ग के बीच सीडीएस को लेकर एक आशंका यह रही है कि ऐसे किसी पद का गठन नहीं किया जाना चाहिए, जिसके अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने का खतरा हो।

कब आया था पहला प्रस्ताव? : सीडीएस के लिए पहला प्रस्ताव कारगिल रिव्यू कमेटी (2000) में आया था। कमेटी ने पूरे सैन्य तंत्र में सुधार के लिए सुझाव दिए थे। इसके बाद मंत्रियों के एक समूह ने भी सीडीएस के विचार का अध्ययन किया। समूह ने सुझाव दिया कि फाइव स्टार रैंक के इस पद का गठन किया जाना चाहिए। इस आशय का प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी आन सिक्योरिटी (सीसीएस) को दिया गया।

प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका : सीडीएस के प्रस्ताव पर सेनाओं के बीच कोई आम सहमति कायम नहीं हो सकी। माना जाता है कि वायु सेना ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। कारगिल रिव्यू कमेटी के समय कांग्रेस विपक्ष में थी। उसने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि उसे लगा कि किसी सैन्य अधिकारी में इतनी अधिक शक्तियां निहित कर देना ठीक नहीं होगा। करीब एक दशक बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने 2011 में नरेश चंद्रा समिति का गठन किया। इस समिति में 14 सदस्य शामिल थे। इनमें सेवानिवृत्त सैन्य प्रमुख और दूसरे रक्षा विशेषज्ञ शामिल थे। समिति ने कम अधिकारों के साथ सीडीएस के गठन की वकालत की। इसके मुताबिक, सीडीएस फोर स्टार रैंक का अधिकारी होना चाहिए।

प्रधानमंत्री को इस समय कैसे मिलती है सलाह? : अभी जो ढांचा है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अहम मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। यह सिलसिला 2018 के बाद से ही चल रहा है, जब डिफेंस प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की अध्यक्षता एनएसए करते हैं। मौजूदा समय अजीत डोभाल इस भूमिका में हैं। समिति में विदेश, रक्षा और वित्त सचिव शामिल होते हैं। इसके साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इसके सदस्य हैं।

सेना के तीनों अंगों में तालमेल बढ़ाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत बताई जा रही है। फाइल फोटो

विरोध में तर्क भी हैं

सीडीएस की वकालत करने वाले तमाम लोग हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि अभी तक कोई ऐसा स्पष्ट खाका सामने नहीं आया है जो यह बताता हो कि सीडीएस की मुख्य रूप से क्या भूमिका होगी। उसका कार्यालय किस तरह का होगा यानी उसके कामकाज की प्रकृति क्या होगी? भारत में राजनीतिक वर्ग सुरक्षा संबंधी मामलों के प्रति कुल मिलाकर बेरुखी का भाव दर्शाता रहा है। इसलिए इस पर आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता कि सीडीएस सही तरह से कार्य कर सकेगा।

5 साल में खादी की बिक्री में 145 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ 2018-19 में खादी का करोबार 74,323 करोड़ रुपये से अधिक का हो गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने यह जानकारी दी।

उम्मेद ने जगाई गांव में रोजगार और विकास की उम्मीद, रोका पलायन

जागरण सरोकार ▶ चंडीगढ़ से नौकरी छोड़कर 2010 में गांव लौटे उत्तरकाशी के उम्मेद सिंह कलूड़ा, 42 लोगों को रोजगार दिलाकर बदली उनकी जिंदगी

शैलेंद्र गोदियाल, उत्तरकाशी

रोजगार के लिए पहाड़ से पलायन की कहानी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो गांव में ही स्वरोजगार और उन्नति की राह बनाकर मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसी ही मिसाल कायम की है उत्तरकाशी जिले के सिंगोठ गांव निवासी 50 वर्षीय उम्मेद सिंह कलूड़ा ने। गांव में ही थोड़ी-बहुत नई तकनीकी सीख और कुछ पारंपरिक तरीके अपनाकर वह खुद भी कमा रहे हैं और गांव के 42 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। किसी को मछली पालन में लगाया हुआ है तो किसी को बेमौसमी सब्जी उत्पादन में। उन्होंने गांव की गरीब विधवा महिलाओं से लेकर घोड़ा-खच्चर वालों को भी रोजगार से जोड़ा है।

जनसंख्या नियोजन

उम्मेद सिंह कलूड़ा। जागरण

सिंगोठ जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 20 किमी की दूरी पर सड़क से जुड़ा गांव है। उम्मेद सिंह कलूड़ा 2010 में चंडीगढ़ स्थित एक कंपनी की अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर गांव लौटे और यहां स्वरोजगार की नई इबादत लिख डाली। उम्मेद कहते हैं, 'मैंने 1984 में दसवीं पास की और नौकरी की तलाश में चंडीगढ़ चला गया। कुछ सालों तक इधर-उधर भटकने के बाद एक प्रसिद्ध दवा कंपनी में नौकरी मिली। मैं जब-जब छुट्टी पर घर आता, गांव के लोग अपने बेरोजगार बेटों को साथ में चंडीगढ़ ले जाकर नौकरी लगवाने का आग्रह करते। शुरुआत में मैंने काफी युवाओं को चंडीगढ़ ले जाकर होटल और कंपनियों में नौकरी दिलवाई, लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। कब तक रोजी के लिए पहाड़ के युवा मैदानों की ओर भागते रहेंगे। आखिरकार 2010 में नौकरी छोड़कर मैं गांव लौट आया।' इसके बाद उम्मेद सिंह ने नाकुरी के पास एक होटल खोला और वहां गांव के युवाओं को काम देना शुरू किया। इसके साथ ही गांव में भी भेड़-बकरी पालन के साथ बागवानी शुरू की। इसके अलावा मछली पालन करने के लिए मत्स्य विभाग से प्रशिक्षण भी लिया। उम्मेद सिंह के अनुसार इसी बीच 2012-13 में जब असी गंगा में बाढ़ आई तो ट्राउड मछली के बारे में जानकारी मिली। 2014 में गांव के गदेरे के पानी से ही ट्राउड पालन के लिए तीन तालाब बनाए। 2016 से ट्राउड का उत्पादन मिलने लगा। अब हर साल सात से आठ क्विंटल ट्राउड का उत्पादन हो जा रहा है, जबकि कॉमन क्रॉप, ग्रास क्रॉप, सिल्वर क्रॉप, चाइनीज क्रॉप प्रजाति की मछलियों के लिए आठ तालाब बनाए हैं। इन मछलियों का हर साल नौ से दस क्विंटल उत्पादन हो रहा है। बताते हैं कि मछली के तालाब तैयार करने में मत्स्य विभाग ने भी उनका सहयोग किया।

सिंगोठ गांव में ट्राउट मछली के तालाब के बारे में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान को जानकारी देते उम्मेद सिंह कलूड़ा। जागरण

पशु पालन का भी है मॉडल

उम्मेद सिंह ने सिंगोठ गांव में पशुपालन का भी मॉडल तैयार किया है। उनके पास 300 भेड़-बकरी, दो गाय, बैल और दो भैंस भी हैं। दूध-घी बेचने के अलावा वे इन पशुओं के गोबर से जैविक खाद भी तैयार कर रहे हैं।

ट्राउड की मांग है अधिक

उम्मेद सिंह बताते हैं कि ट्राउड मछली पालन के लिए साफ रनिंग वाटर चाहिए। पानी का तापमान भी कम होना चाहिए। साल में दो बार ट्राउड का उत्पादन होता है। इसकी देहरादून, मसूरी और चंडीगढ़ से बहुत अधिक मांग है और प्रति किलो 800 रुपये कीमत भी मिल जाती है।

अपने बेटों के साथ ग्रामीणों को भी दिया रोजगार : उम्मेद सिंह के दो बेटे हैं। बड़े बेटे नीरज कलूड़ा ने पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई की है और मछली पालन का कार्य देखते हैं, जबकि दूसरे बेटे विनय सिंह कलूड़ा ने सिविल इंजीनियरिंग की है और होटल का व्यवसाय देख रहे हैं। उम्मेद सिंह ने गांव के 42 लोगों को भी रोजगार दिया है। जो मछली और पशु पालन, फल-सब्जी उत्पादन और होटल व्यवसाय से जुड़े हैं। इसके अलावा गाड़ी और खच्चर वालों को भी रोजगार मिला हुआ है।

फल एवं सब्जी उत्पादन : उम्मेद सिंह ने गांव में करीब एक हेक्टेयर क्षेत्र में आड़ू, अखरोट, खुबानी, नींबू और नाशपाती का बागीचा लगाया हुआ है। इसके साथ ही आलू, अरबी, अदरक, हल्दी, मशरूम आदि सब्जियों का भी अच्छा-खासा उत्पादन करते हैं। बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए उन्होंने पॉली हाउस बनाए हुए हैं। इसके अलावा नाकुरी के पास वे होटल भी संचालित कर रहे हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

अब स्कूबा डाइविंग से देखें द्वारका नगरी

स्कूबा डाइविंग के जरिये प्राचीन नगर के अवशेष छूकर देखना हुआ आसान। जागरण

शत्रुघ्न शर्मा, द्वारकापुरी

समुद्र में समाई प्राचीन द्वारका नगरी को अब आप समुद्र तल तक जाकर अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। इसके लिए थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी। स्कूबा डाइविंग के छोटे से प्रशिक्षण और हिम्मत जुटाकर समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य को देखा-समझा जा सकेगा। मानव सभ्यता की इस विकसित स्वर्ण नगरी के समुद्र में समा जाने को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें एक कथा कल्कि का अवतार होने से पहले एक सभ्यता का खुद को समाप्त कर लेने का भी है। कई द्वारों से मिलकर बनी द्वारका के तीन भाग समुद्र में समा गए हैं। एक भाग आज की बेट द्वारका (समुद्र में बने टापू पर स्थित) उसके गवाह के रूप में खड़ी है। ऐसी मान्यता है कि मेवाड़ से निकलकर मीरा बाई जब यहां पहुंचीं तो श्रीकृष्ण के ध्यान में रहते हुए ही वह यहां उनकी मूर्ति में समा गईं। गोमती (गुजरात), कोशावती व चंद्रभागा नदी का संगम यहीं पर है और आसपास समुद्र होने से सब जगह का पानी खारा है, लेकिन यहां बने पांडवों के पांच कुओं का पानी मीठा है।

दर्शन द्वारका के

दर्शन द्वारका भाग-2

- श्रीकृष्ण की प्राचीन नगरी का एक भाग है बेट द्वारका
- यहीं पर श्रीकृष्ण की मूर्ति में विलीन हुई थीं मीरा बाई

स्कूबा डाइविंग

स्कूबा (सेल्फ कंटेंड अंडरवाटर ब्रीथिंग एपरेटस) पानी के नीचे डाइविंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें गोताखोर एक ऐसे उपकरण का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से पानी के अंदर आसानी से सांस लेता रहता है। इसमें एक या एक से अधिक डाइविंग सिलेंडर होते हैं, जिसमें उच्च दबाव पर सांस लेने वाली गैस होती है।

स्कूबा डाइविंग ट्रेनर शांतिभाई बंबानिया बताते है, लोगों में समुद्र तल खासकर प्राचीन द्वारका के खंडहरनुमा अवशेषों को देखने का खासा उत्साह और जिज्ञासा होती है। वे पहले स्कूबा डाइविंग का कुछ घंटे प्रशिक्षण देते हैं, जब व्यक्ति पानी के अंदर रहने की हिम्मत और अनुभव जुटा लेता है तो फिर अंडर वाटर यात्रा शुरू होती है। 60 से 80 फीट नीचे जाने के बाद दिव्य द्वारका नगरी के अवशेषों के दर्शन होते हैं। समुद्री शैल के आवरण में लिपटे, लाखों मछलियों की अठखेलियों व क्रीड़ा का स्थल बने ये अवशेष खुद अपनी कहानी बयां करते हैं। यहां विशालकाल प्रतिमाओं के अवशेष, जंगली जानवरों की आकृतियां, कई तरह की कलाकृतियां व विशालकाय द्वार और स्तंभ नजर आते हैं।द्वारका भारत के सात प्राचीन शहरों में से एक है। अन्य छह शहरों में मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या हैं। द्वारका को ओखा मंडल, गोमतीद्वार, आनर्तक, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, वारीदुर्ग आदि नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथानकों के अनुसार भगवान कृष्ण ने यहां 36 साल राज किया। यदुवंश के वज्रनाभ द्वारका के अंतिम शासक बने जो कुछ साल राज करने के बाद हस्तिनापुर चले गए। प्राचीन द्वारका पहले एक मिथक और काल्पनिक कथा के रूप में प्रचलित थी। सबसे पहले वायुसेना के पायलटों की इस पर नजर पड़ी। जामनगर के गजट में भी इस नगरी का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने तट से 20 किमी अंदर सोनार तकनीक से 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में शोध शुरू किया तो लकड़ी, पत्थर, हड्डियों के हजारों साल पुराने अवशेष मिले। सोनार जल के अंदर वस्तुओं को पता करने की ऐसी तकनीक है, जिसमें पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल होता है। स्कूबा डाइविंग ट्रेनर अत्री मेहता बताते हैं कि सितंबर से अप्रैल माह तक करीब एक हजार लोग समुद्र में गोता लगाने आते हैं। अगले सीजन तक वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑसिनोग्राफी गोवा से द्वारका प्राचीन मंदिर के सामने की लोकेशन की स्वीकृति लेना चाहेंगे ताकि प्राचीन नगरी के दर्शन करा सकें। (क्रमशः)

गैंग्स ऑफ वासेपुर का खौफ कोई नहीं डाल रहा टेंडर

रुकावट ▶ मटकुरिया से वासेपुर तक सड़क निर्माण को तीसरी बार टेंडर की तैयारी

500 परिवारों की आबादी को हटाने की समस्या और रंगदारी के कारण एजेंसियां नहीं दिखा रहीं दिलचस्पी

आशीष सिंह, धनबाद

झारखंड के धनबाद के मटकुरिया से वासेपुर वाया आरा मोड़ तक फ्लाईओवर और अंडरपास के साथ सड़क निर्माण के लिए बने 256 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए दो बार टेंडर हो चुका है। बावजूद इसके, किसी एजेंसी ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब तीसरी बार टेंडर निकल रहा है। दरअसल, गैंग्स ऑफ वासेपुर का खौफ ऐसा है कि काम की इच्छुक एजेंसियों की भी हिम्मत नहीं हो रही है। उनको डर है कि इस काम को हाथ में लेने पर रंगदारी तो देनी ही पड़ेगी, यहां रह रहे लोगों को हटवाने में भी लोहे के चने चबाने होंगे। इसलिए काम तय समय पर पूरा कराना भी बड़ी चुनौती होगी। इधर, किसी भी एजेंसी द्वारा टेंडर में दिलचस्पी नहीं दिखाने से गैंग्स ऑफ वासेपुर का खौफ और बढ़ रहा है। इस बढ़ते खौफ का फायदा उसे रंगदारी की रकम बढ़ाने में निश्चित रूप से मिलेगा। वैसे, इस टेंडर को लेकर गैंग्स क्या चाहता है, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

सड़क, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने के लिए रेलवे से एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) मिल गया है। योजना की राह में 500 परिवारों के मकान अड़ंगा बने हुए हैं। बेशक इनके पुनर्वास के लिए 100 करोड़ की राशि का भी प्रावधान किया गया है। पर, पुनर्वास कराना टेढ़ी खीर है। गैंग्स को भी बतौर रंगदारी हिस्सा चाहिए। यही डर एजेंसियों को निविदा डालने से रोकता है।

स्टेट हाइवे अथॉरिटी पर है सड़क बनवाने का जिम्मा : स्टेट हाइवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड (शाज) पर सूबे की सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी है। वह यह काम एजेंसियों को टेंडर के माध्यम से देती है। सड़क मटकुरिया चेक पोस्ट से धनबाद-चंद्रपुरा रेलवे लाइन के नीचे से अंडरपास के माध्यम से वाया आरा मोड़ वासेपुर तक जाएगी। रास्ते में गुलजारबाग और पंजाबी बस्ती के पांच सौ परिवार हैं। इन्हें हटाना जरूरी है।

दो बार टेंडर निकाला गया है। किसी एजेंसी ने काम करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर से टेंडर निकाल रहे हैं। जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करेंगे। किसी भी एजेंसी को कोई काम से रोक नहीं सकता। लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की है।

- चंद्रशेखर अग्रवाल, मेयर, धनबाद

एजेंसियों ने किया निरीक्षण तो फूले हाथ-पांव

छह माह में दो बार टेंडर निकाला गया तो कई एजेंसियों ने इस काम में रुचि दिखाई। तीन एजेंसियों के अधिकारी इलाके में भी गए। वहां पता चला कि सड़क गैंग्स ऑफ वासेपुर के गढ़ गुलजारबाग, आरामोड़ और वासेपुर से होकर निकलेगी। यहां कई गुटों को रंगदारी का चढ़ावा दिए बिना पत्ता भी नहीं हिल सकेगा। बस्ती भी आड़े आ रही है। तब उनके हाथ पांव फूल गए। सड़क निर्माण जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के फंड से होना है। ट्रस्ट बोर्ड से 256 करोड़ रुपये से सड़क निर्माण की मंजूरी फरवरी में मिल चुकी है। बावजूद इसके, एजेंसियां खौफ के कारण हाथ खींच रहीं हैं। सूत्रों ने बताया कि यदि सुरक्षा के पुख्ता प्रावधान का भरोसा एजेंसियों को मिल जाए तो वे काम में आगे आ जाएंगी। यह सड़क धनबाद के लिए बेहद अहम है।

मियावाकी पद्धति से तैयार जंगल दूर करेगा प्रदूषण

अनिल अवस्थी, उन्नाव

- उप्र के उन्नाव में तैयार होगा राज्य का पहला 'गुरु नानक पवित्र जंगल'
- मियावाकी पद्धति से एक साल के भीतर तैयार होंगे 15 फीट ऊंचे पौधे

गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव के 550 वर्ष पूरे होने पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने उत्सव को यादगार बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया है। मियावाकी पद्धति से चमरौली क्षेत्र में गुरु नानक पवित्र जंगल तीर्थाटन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पद्धति से तैयार यह उत्तर प्रदेश का पहला जंगल होगा।

श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान गुरुवीर सिंह ने बताया कि सभा के सदस्य और इको सिख संस्था के उत्तर प्रदेश कोआर्डिनेटर सरदार अजीत पाल सिंह ने काम शुरू कर दिया है। अजीत पाल ने बताया कि इको सिख संस्था के संस्थापक राजवंत सिंह के साथ मिलकर प्रदेश का पहला गुरु नानक पवित्र जंगल विकसित करने के लिए दो हजार वर्ग फीट जमीन आरक्षित है। मियावाकी पद्धति से पवित्र जंगल तैयार किया जाएगा। पहले चरण में सितंबर तक 550 पौधे रोपित किए जाएंगे। मिट्टी की जांच के साथ बाउंड्री का निर्माण कराया जा चुका है। पंजाब में 20 जंगल उगाने वाले रवनीत सिंह और दिल्ली में 2500 पौधों के साथ मियावाकी जंगल तैयार कर रहे संस्था के गगनदीप सिंह गिन्नी और महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कृत चरनप्रीत सिंह व पवनीत सिंह इसमें सहयोग करेंगे।

क्या है मियावाकी पद्धति : मियावाकी पद्धति तेजी से जंगल उगाने की तकनीक है। यह पद्धति जापान के डॉ. अकीरा मियावाकी ने 40 साल पहले विकसित की थी। इस पद्धति से 10 हजार वर्ग फीट जगह में 3500 पौधे उगाए जाते हैं। कम स्थान और बंजर जमीन में भी झाड़ीनुमा, मध्यम आकार के पेड़ और छांव देने वाले बड़े पेड़ लगाकर जंगल उगाया जा सकता है। अर्बन फॉरेस्ट कैटेगरी की इस तकनीक से बगीचे या आसपास की खुली जगह में भी मिनी मियावाकी जंगल उगा सकते हैं। इस तकनीक से लगाए गए पौधे एक वर्ष में 10-15 फीट ऊंचे हो जाते हैं।

बंजर जमीन में भी उगाया जा सकता है पेड़। फाइल

ऐसे लगाए जाते हैं पौधे : जमीन को तीन फीट गहरा खोदा जाता है। मिट्टी की जांच के बाद उर्वरता बढ़ाने के लिए चावल का भूसा, गोबर, जैविक खाद या नारियल के छिलके डालकर ऊपर से मिट्टी डाली जाती है। पौधों को आधे-आधे फीट की दूरी पर लगाया जाता है। दो फीट चौड़ी और 30 फीट लंबी पट्टी में 100 से अधिक पौधे रोपे जा सकते हैं।

अच्छी खबर : देश में अब नहीं रहेगी डीपीटी वैक्सीन की कमी

मनमोहन वशिष्ठ, सोलन

- सीआरआइ कसौली की जीएमपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन शुरू
- बच्चों को होने वाली गलघोंटू, काली खांसी और बैक्टीरियल बीमारी के लिए लगता है टीका

केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआइ) कसौली की गुड्स मैन्यूफेक्चरिंग प्रैक्टिस (जीएमपी) लैब में अब डीपीटी वैक्सीन का उत्पादन डब्ल्यूएचओ के मानकों के तहत शुरू हो गया है। देश में अब इन वैक्सीन की कमी नहीं रहेगी। छोटे बच्चों को लगने वाले इन वैक्सीन का यहां बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। संस्थान में कई साल से इसके उत्पादन की प्रक्रिया चल रही थी। सभी ट्रायल पूरा करने के बाद अब उत्पादन शुरू हो गया है।

सीआरआइ कसौली जीवन रक्षक वैक्सीन के उत्पादन के लिए देशभर में जाना जाता है। इस साल दिसंबर तक इस वैक्सीन के 40 लाख डोज तैयार करने का लक्ष्य है। 15 लाख डोज की फिलिंग हो चुकी है।

बच्चों के लिए हैं ये डीपीटी वैक्सीन : डीपीटी (डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस) वैक्सीन से शिशु का तीन तरह के संक्रामक रोग से बचाव किया जाता है। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इन रोगों से लड़ने के लिए विकसित किया जाता है। यह टीका बच्चों में होने वाली गलघोंटू, काली खांसी और बैक्टीरियल बीमारी के लिए लगता है।

सरकारी क्षेत्र में पहली जीएमपी लैब : सीआरआइ कसौली में डीपीटी वैक्सीन के उत्पादन के लिए देश में सरकारी क्षेत्र में यह पहली जीएमपी लैब है। इसका उद्घाटन 24 अप्रैल, 2016 को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया था। संस्थान पहले भी डीपीटी वैक्सीन का उत्पादन करता था, लेकिन डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुरूप वैक्सीन प्रोडक्शन करने के लिए जीएमपी लैब का होना जरूरी था। इसलिए यहां पर साठ करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया था।

डीपीटी वैक्सीन का उत्पादन जीएमपी लैब में शुरू हो गया है। संस्थान हर माह 20 लाख डोज की प्रोडक्शन करेगा।

- डॉ. अजय कुमार तहलान, निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली

वर्दी बताएगी कहां हैं जवान

जागरण विशेष

विक्सन सिक्रोड़िया, कानपुर

असम की पहाड़ियों में सेना के हेलीकॉप्टर गायब होने की घटना तो आपको याद ही होगी, जिसमें वायु सैनिकों के शव खोजने में काफी समय लगा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान (यूपीटीटीआइ) सेना के लिए स्मार्ट क्लॉथ (वर्दी) तैयार करने जा रहा है। इसमें लगे सेंसर व चिप से सैनिकों की लोकेशन आसानी से जानकर उनकी मदद की जा सकेगी। इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर जल्द ही सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सेंसर युक्त कपड़ों पर अनुसंधान के लिए डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से 60 लाख रुपये का अनुदान भी मिल चुका है। इसके लिए वरिष्ठ प्रोफेसरों के निर्देशन में पीएचडी व एमटेक छात्रों की टीम बनाई जा रही है।

वर्दी में अंतर्निहित रहेगा सेंसर : प्रोजेक्ट प्रमुख व यूपीटीटीआइ के निदेशक प्रोफेसर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि सेंसर व चिप युक्त वर्दी पहने सैनिकों की लोकेशन यूनिट के अधिकारी कभी भी जान सकेंगे। इसके लिए सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो जैकेट व ट्राउजर में अंतर्निहित रहेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नैनो क्लॉथ पर शोध शुरू हो चुका है। प्रयोगशाला में ऐसे कपड़े विकसित करने पर काम चल रहा है जो पसीने की दुर्गंध का अहसास भी नहीं होने देंगे। इसमें तुलसी, नीम व एलोवेरा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक मुकेश सिंह। जागरण

उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी संस्थान का प्रवेश द्वार। जागरण

विशेष सिक्योरिटी फीचर भी होगा : इसमें ऐसे सेंसर इस्तेमाल किए जाएंगे जो धुलाई करने से भी खराब नहीं होंगे। ये सेंसर सेना के विशेष सिक्योरिटी फीचर से लैस होंगे जिसके कोड को सिर्फ सेना ही डिकोड कर पाएगी। कपड़ों पर इस तरह से सेंसर लगाए जाएंगे जिससे पहनने में परेशानी न हो। सेंसर बैट्री व वायरलेस से जुड़े रहेंगे।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

तलाशी राह

नाबालिग को बचाने के लिए इंजीनियर पिता व भाई ने तैयार किया हेलमेट, इंजन के साथ हेलमेट को को खास तरह के ट्रांसमीटर-रिसीवर से किया कनेक्ट

बगैर हेलमेट पहने स्टार्ट नहीं होगी स्कूटी

गोविंद बिष्ट, हल्द्वानी

अपने बच्चों के लिए परिवार के लोग सब कुछ करते हैं। बात अगर उनकी सुरक्षा से जुड़ी हो तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक नाबालिग के पिता और भाई ने ऐसा हेलमेट तैयार किया है, जिसे न पहनने पर स्कूटी स्टार्ट ही नहीं होगी। अगर बीच रास्ते में हेलमेट उतारने की कोशिश की तो स्कूटी भी बंद हो जाएगी। खास किस्म का हेलमेट बनाने वाले पिता इंजीनियर हैं, तो बड़ा बेटा भी उसी फील्ड की पढ़ाई कर रहा है।

देवलचौड़ सत्यलोक कॉलोनी निवासी पवन वर्मा पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वर्तमान में वह गुरुग्राम की एक सोलर कंपनी में कार्यरत हैं। बड़ा बेटा तनिष्क सोनी (19) गुजरात में बैचलर ऑफ डिजायन का कोर्स कर रहा है, जबकि छोटा बेटा वृतांत (17) बिरला स्कूल में 12वीं का छात्र है। पवन के मुताबिक, स्कूटी चलाते समय वृतांत कभी-कभार हेलमेट उतार देता था। पड़ोसियों के माध्यम से यह बात मां ऋतंभरा को पता चली तो घर के अन्य सदस्य भी सुरक्षा को लेकर चिंतित हुए। इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे तनिष्क ने ऐसा डिजायन तैयार किया, जिससे बगैर हेलमेट पहने स्कूटी स्टार्ट ही न हो। संसाधन जुटाकर पिता-पुत्र इस काम में लग गए। कड़ी मशक्कत के बाद ऐसा हेलमेट तैयार हो गया, जिसे न पहनने पर स्कूटी चालू ही नहीं होगी। इस आविष्कार के जरिये परिवार ने समाज को भी सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया है।

डिवाइस बनाने वाले हल्द्वानी निवासी इंजीनियर पवन वर्मा अपने पुत्र तनिष्क के साथ।

ऐसे काम करेगी तकनीक : पवन के मुताबिक, स्कूटी के इंजन में एक खास किस्म का ट्रांसमीटर लगाया गया। इसका रिसीवर हेलमेट में फिट किया गया। गाड़ी चलाने वाले के सिर पर जब तक यह हेलमेट नहीं होगा, इंजन को स्टार्ट होने का सिग्नल नहीं मिलेगा। चलती गाड़ी में अगर सेकंड भर के लिए भी हेलमेट उतारा तो सिग्नल ऑफ होने की वजह से स्कूटी बंद हो जाएगी।

सिस्टम तैयार होने में लगा एक माह का समय : इंजीनियर पवन के मुताबिक, इस सिस्टम को तैयार करने में कई तकनीकी दिक्कतें भी सामने आईं। इससे पिता-पुत्र का लगभग एक माह का समय लग गया। हेलमेट की दूसरी बड़ी खासियत यह है कि गाड़ी चोरी भी नहीं होगी, क्योंकि बगैर उस हेलमेट गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो सकती।

हेलमेट नहीं पहनने से पारिवारिक सदस्य की हो चुकी है मौत : पवन के मुताबिक, उनके एक रिश्तेदार की एक हादसे में जान चली गई थी। हादसे के दौरान हेलमेट नहीं पहनने की वजह से सिर पर गंभीर चोट आई थी। इसलिए सभी को दुपहिया वाहन चलाते समय बेहतर क्वालिटी का हेलमेट जरूर पहनना चाहिए।

दिव्यांग बच्चों के लिए रोशनी हैं डॉ. अलका

नितिन शर्मा, यमुनानगर

- बेटियों को मंच प्रदान करने में निभाती हैं अहम भूमिका
- खुद की संतान नहीं, विशेष बच्चों को अपनाकर दे रहीं नई जिंदगी

तुम्हारे पास नहीं है तो क्या, मैं हूं तुम्हारी आंख और कान। अपने पैरों से पूरा करूंगी तुम्हारी दौड़, तुम्हारे सपनों को दूंगी उड़ान। दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ ऐसा ही साथ ही हरियाणा के यमुनानगर की डॉ. अलका शर्मा का। वह ऐसे बच्चों के लिए रोशनी हैं। इन बच्चों की प्रतिभा को पहचान मंच प्रदान करा रही हैं। यही बच्चे सोनीपत में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विजेता बनकर लौटे हैं। लीगल लिट्रेसी मिशन की ओर से यह कार्यक्रम करवाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज ने इनकी प्रस्तुति को पसंद किया। इसके साथ ही डॉ. अलका जरूरतमंद बेटियों को उचित मंच प्रदान कराने में भूमिका निभा रही हैं। अब तक 55 से ज्यादा बेटियों को इनके माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल चुका है।

डॉ. अलका बताती हैं कि उनके संपर्क में ऐसे 25 बच्चे आए। जब उन्होंने इनकी प्रतिभा देखी तो वे हैरान हो गईं। इनमें तीन सुन और बोल नहीं सकते। किसी के पांव नहीं हैं। पांच बच्चे देख नहीं पाते, लेकिन इनमें हौसला गजब का है।

अपने बच्चों की तरह करती हैं देखभाल : डॉ. शर्मा इकोनॉमिक्स की लेक्चरर हैं। सरोजनी कॉलोनी में बने एनजीओ में भी अपनी सेवाएं देती हैं। यहां जरूरतमंद परिवारों की बेटियां प्रशिक्षण लेने आती हैं। पति शुगर मिल से सेवानिवृत्त हैं। इनकी अपनी संतान नहीं है। जरूरतमंद बच्चों की सेवा कर उनको लगता है कि जैसे अपने ही बच्चों की जिंदगी संवार रही हों। उन्होंने हमेशा ऐसी बेटियों का चयन किया है, जिन्हें सच में मदद की जरूरत थी। काबिलियत पहचान कर ऐसा मंच प्रदान किया कि वे कई बार सम्मानित की गईं।

शुरुआत नहीं थी आसान : शुरुआत का सफर आसान नहीं था। कुछ ऐसी युवतियां थीं, जो प्रतिभा होने के बावजूद मंच पर आना नहीं चाहती थीं। उनकी झिझक को दूर करने के लिए उन्होंने माहौल तैयार किया। दो लड़कियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अच्छा स्थान प्राप्त किया। इनके दिए गए प्रशिक्षण से जगाधरी की अरुणा प्रदेश स्तरीय गायन प्रतियोगिता में प्रदेश में प्रथम रही। उनको तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सम्मानित किया।

हरियाणा के यमुनानगर की डॉ. अलका शर्मा दिव्यांग बच्चों के साथ। जागरण

यूको बैंक को जल्द पीसीए से बाहर आने की उम्मीद

अहमदाबाद : सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता यूको बैंक को उम्मीद है कि वह चालू वित्त वर्ष के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के पीसीए दायरे से बाहर आ जाएगा। बैंक के एमडी व सीईओ अतुल कुमार गोयल ने कहा कि अगले वर्ष मार्च तक हम प्रांप्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) के बंधन से मुक्त होने की पूरी उम्मीद रखते हैं। गौरतलब है कि पीसीए के दायरे में आए बैंकों पर कर्ज बांटने समेत कई अन्य मामलों में पाबंदियां लगी होती हैं। (प्रेट्र)

चालू वित्त वर्ष में हम 14 फीसद तक कर्ज विकास दर की उम्मीद कर रहे हैं। बैंक की बैलेंस शीट को देखते हुए यह आकार संतोषजनक है।

— रजनीश कुमार
चेयरमैन, एसबीआइ

बदलाव ▶ नई सरकार के गठन के बाद शुरू हुआ विभागों और उद्योगों के साथ बैठक का सिलसिला

इस बार 'उद्योग भवन' की सक्रियता बढ़ी

अब तक तीन दर्जन से अधिक बैठकें कर चुके हैं वाणिज्य व उद्योग मंत्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मैन्यूफैक्चरिंग की धीमी रफ्तार, वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों का घटता हिस्सा और चालू वित्त वर्ष के लिए आम बजट के बाद एफपीआइ द्वारा लगातार निकासी - ये सब आर्थिक विकास के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इन दिक्कतों को दूर करने की दिशा में प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप सरकार के विभिन्न मंत्रालय निरंतर इन समस्याओं के निवारण में जुटे हुए हैं। इसके संकेत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से मिल रहे हैं, जहां वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में पूरा मंत्रालय उद्योग जगत को यह भरोसा दिलाने में जुटा है कि परेशानी की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है।

कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली नई सरकार में स्पष्ट दिख रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में नई सरकार के गठन के बाद से विभिन्न सेक्टर के प्रतिनिधियों, विदेशी निवेशकों से लेकर रिटेल कारोबार से जुड़ी कंपनियों, एसोसिएशन और अन्य पक्षों के साथ मंत्रालय की तीन दर्जन से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। इनकी शुरुआत छह जून को बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक से हुई थी, जिसमें उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। बैठकों का यह सिलसिला अभी तक चल रहा है। खास बात यह है कि गोयल इन सभी बैठकों में उपस्थित रहे हैं, ताकि उद्योग जगत को भरोसा दिलाया जा सके कि सरकार उनके मसलों को लेकर गंभीर है। बीते ढाई महीनों में गोयल ने स्टील व अन्य मेटल, आइटी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग, जेम एंड ज्वैलरी, निर्यातक, ई-कॉमर्स समेत फिक्की और फियो के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इनकी समस्याओं को सुना है।

अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पिछले दिनों इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में बैठक हुई। जागरण

भले ही तात्कालिक तौर पर इन बैठकों का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा हो, लेकिन उद्योग मानता है कि आने वाले समय में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सक्रियता के परिणाम दिखेंगे। फियो के प्रेसिडेंट शरद सराफ ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि मंत्रालय के कामकाज में बदलाव दिख रहा है। खासतौर पर वाणिज्य मंत्री का रुख बेहद सकारात्मक रहता है। हमेशा उनकी कोशिश बैठक के दौरान ही समस्या का हल निकालने की होती है। उद्योग जगत के अन्य प्रतिनिधि भी मानते हैं कि पहले की तुलना में इस सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय काफी अधिक सक्रिय है। फियो के वाइस प्रेसिडेंट महेश चंद्र केयल कहते हैं गोयल का पिछली सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर अनुभव इस मंत्रालय के काम में काफी मददगार साबित हो रहा है। वह जानते हैं कि उद्योग की क्या आवश्यकता है और वित्त मंत्रालय से कितनी राहत मिल सकती है। इसलिए वह बैठक में ही वैकल्पिक उपायों पर चर्चा कर लेते हैं।

उद्योग भवन में कामकाज में बदलाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गोयल विदेश व्यापार से जुड़े समझौतों को लेकर केवल मंत्रालय के अधिकारियों से ही नहीं, बल्कि उनसे प्रभावित होने वाले उद्योगों के भी संपर्क में हैं। रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) करार को लेकर होने वाली बैठक से पहले गोयल ने बाकायदा विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से अलग-अलग दिल्ली व मुंबई में बैठकें कीं। ऐसी ही एक बैठक में शामिल होने वाले स्टील उद्योग की एक कंपनी के प्रमुख ने बताया कि सरकार के स्तर पर ऐसी सक्रियता पहले कभी नहीं दिखी। जबकि मंत्रालय के ही एक अधिकारी कहते हैं कि अब अक्सर देर शाम तक बैठकों का सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि फोकस मामले के निपटारे पर रहता है।

धीरे-धीरे लागू होंगे नए मोटर एक्ट के प्रावधान

- दो हफ्तों में जारी होगी बढ़ा जुर्माना लागू करने की अधिसूचना
- अन्य प्रावधानों का कार्यान्वयन कुछ महीनों बाद होगा

इस बार नियम तोड़ने पर जुर्माने की रकम बहुत ज्यादा रखी गई है। फाइल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद से पारित होने के बाद संशोधित मोटर वाहन एक्ट, 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन इसके अमल में आने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। शुरू में केवल जुर्माने के प्रावधान लागू होंगे। बाकी प्रावधानों को उसके बाद लागू किया जाएगा। इसमें कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने का वक्त लग सकता है।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बावजूद संशोधित मोटर एक्ट तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि सड़क मंत्रालय इसे लागू करने की अधिसूचना जारी नहीं कर देता। हालांकि यह अधिसूचना भी फिलहाल एक्ट के सारे प्रावधानों को लागू करने के बारे में न होकर केवल बढ़े जुर्माने संबंधी उपबंधों को लागू करने के बाबत होगी। कानून मंत्रालय की सलाह से अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। अब इसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद इसे गजट में प्रकाशित होने के लिए भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया में दो सप्ताह तक का वक्त लगने की संभावना है। अधिसूचना जारी होते ही पूरे देश में यातायात पुलिस को नियम उल्लंघन पर बढ़े हुए जुर्माने लगाने का अधिकार मिल जाएगा।

जहां तक एक्ट के अन्य प्रावधानों के कार्यान्वयन का प्रश्न है तो उनके बारे में बाद में समय-समय पर अलग से अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी। इससे पहले उन प्रावधानों के बारे में विभिन्न पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर नियम निर्धारित किए जाएंगे। उदाहरण के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तथा दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजे से संबंधित प्रावधानों को नियम निर्धारण के बाद अधिसूचना के जरिए लागू किया जाएगा। इसी प्रकार ओला और उबर जैसी टैक्सी एग्रीगेटर्स, त्रुटिपूर्ण वाहनों के रिकॉल तथा सड़क निर्माण में खामी की स्थिति में निर्माता कंपनी पर पेनाल्टी के प्रावधान भी नियम बनने के बाद लागू होंगे।

इस वक्त लागू मोटर वाहन एक्ट वर्ष 1988 में बना था। तब भी इसके नियम बनाने और लागू करने में साल भर का समय लग गया था। और इसे 1989 के केंद्रीय मोटर नियम आने के बाद पूरी तरह अगल में लाया जा सका था। संशोधित मोटर वाहन एक्ट, 2019 को भी पूरी तरह लागू करने में तीन महीने से लेकर छह महीने तक का समय लग सकता है।

वैसे, यदि संशोधित मोटर एक्ट को उसकी वास्तविक भावना के साथ लागू किया गया तो इससे लोग यातायात नियमों के अनुपालन के लिए प्रेरित भी होंगे और बाध्य भी। जुर्मानों में कई गुना बढ़ोतरी लोगों को बाध्य करने के लिए की गई है। उदाहरण के लिए लाल-बत्ती जंप करते अथवा मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर 1,000 रुपये तथा एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये की भारी पेनाल्टी का डर किसी को भी कानून के पालन के लिए विवश करेगा।

मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार जुर्मानों में भारी बढ़ोतरी इसलिए जरूरी हो गई थी क्योंकि मौजूदा जुर्माने की मौजूदा रकम यात्रियों को अपनी आदत बदलने को विवश नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि हादसों पर कोई कारगर अंकुश नहीं लग पा रहा है। वर्ष 2017 में देश में कुल 4,64,910 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इनमें सबसे ज्यादा 3,27,448 दुर्घटनाएं ज्यादा तेज गति से वाहन चलाने की वजह से हुईं। उस वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में कुल 1,47,913 लोग मारे गए। इनमें 98,613 मौतें निर्धारित गति से अधिक रफ्तार पर वाहन चलाने के कारण हुईं। वर्ष 2017 में हुए सड़क हादसों में 4,70,975 घायल भी हुए थे। इनमें भी ज्यादा रफ्तार के कारण घायल होने वालों की संख्या सर्वाधिक 3,43,083 थी।

न्यूज गैलरी

संशोधित आइबीसी कानून शनिवार से हुआ लागू

नई दिल्ली : अब से इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के तहत दिवालिया प्रक्रिया के लिए आने वाले मामलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 330 दिनों की मोहलत मिलेगी। सरकार ने आइबीसी कानून में संशोधन को शनिवार को अधिसूचित कर दिया है। संशोधन के तहत कानूनी अब किसी भी दिवालिया मामले को अधिकतम 330 दिनों में निपटाना होगा। दिवालिया प्रक्रिया के तहत आने वाली कंपनियों के सभी कानूनी मामले भी इन्हीं दिनों के अंदर सुलझाने होंगे। आइबीसी संशोधन कानून, 2019 के तहत कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग योजनाओं, वोटर के अधिकृत प्रतिनिधियों के अधिकार और कर्तव्य तथा वित्तीय और परिचालन कर्जदाताओं के बीच रकम का बंटवारा समेत कई अन्य मुद्दों को और स्पष्ट किया गया है। (प्रेट्र)

एमएसएमई को 45 दिनों में हो भुगतान : गडकरी

नागपुर : एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस उद्योग में समय पर भुगतान नहीं हो पाना बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी तरफ से ऐसी कोशिशों में जुटी है कि चाहे निजी हो या सरकारी, इस सेक्टर को 45 दिनों के भीतर भुगतान हो जाए। उनके मुताबिक सरकार इस समस्या के अंतिम समाधान की कोशिशों में जुटी है। लघु उद्योग भारती के एक सम्मेलन में गडकरी का कहना था कि एमएसएमई को कभी भी वक्त पर भुगतान नहीं मिलता है। (प्रेट्र)

अशोक लेलैंड लाई वीआरएस

चेन्नई : ऑटो सेक्टर की मंदी से त्रस्त और कर्मचारियों का प्रदर्शन झेल रही ऑटो कंपनी अशोक लेलैंड ने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लांच की है। अशोक लेलैंड के कर्मचारी यूनियन ने कहा कि कंपनी ने सोमवार तक के लिए बंदी की घोषणा कर रखी है। हम तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे, जब तक वे सौहार्द्रपूर्ण नतीजे तक नहीं पहुंच जाते। कंपनी के कर्मचारियों ने बोनस में 10 फीसद बढ़ोतरी की मांग रखी है। (प्रेट्र)

प्रसाद की बैठक स्थगित

नई दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के प्रमुखों के साथ आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की सोमवार को प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दी गई है। अब यह बैठक 16 सितंबर को संभावित है। हालांकि अंतिम क्षणों में इस तरह के बदलाव के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि सेक्टर के प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बैठक स्थगित की गई है। (प्रेट्र)

करदाताओं से दोस्ताना व्यवहार करेंगे टैक्स अधिकारी

नई दिल्ली, आइएएनएस : आयकर विभाग ने फैसला किया है कि वह टैक्स मामलों की छानबीन के वक्त आयकरदाताओं से दोस्ताना रवैया अपनाएगा। पिछले सप्ताह शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहमदाबाद में स्पष्ट कहा था कि आयकर अधिकारियों को अपनी परंपरागत सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। फिर, सीतारमण ने शनिवार को आयकर विभाग को निर्देश दिया के वे टैक्स अधिकारियों और जांच के दायरे में आए करदाता (असेसी) के बीच संवादहीनता की स्थिति को खत्म करें। सूत्रों के मुताबिक इसे देखते हुए विभाग ने फैसला किया है कि वह करदाताओं पर अनावश्यक दबाव पड़ने की संभावनाओं को खत्म करने की कोशिशें करेगा।

सीतारमण ने पिछले सप्ताह दो-टूक कहा था कि टैक्स प्रशासकों की भूमिका बेहद नाजुक होती है। देश का नागरिक जानकार और जागरूक हो रहा है और ऐसे नागरिकों के साथ व्यवहार के लिए टैक्स अधिकारियों को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। जहां तक असेसी और उनके मामलों का सवाल है, तो हमें उनके साथ संवाद करना चाहिए और पूरे सम्मान के साथ उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए।

सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग असेसी के साथ बातचीत और व्यवहार में दोस्ताना बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा करते वक्त वह असेसी की कानूनी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करेगा। गौरतलब है कि आयकर अधिकारियों पर अक्सर यह आरोप लगते रहे हैं कि असेसी के साथ उनका बातचीत का लहजा धमकाने और दोष मढ़ने का रहता है। हाल के वर्षों में लोग इसे टैक्स-आतंकवादकी भी संज्ञा देने लगे हैं। इसी को देखते हुए पिछले सप्ताह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि अब किसी भी असेसी को कोई भी आयकर नोटिस डॉक्यूमेंट पहचान संख्या (डिन) के बगैर नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद किसी को भी फर्जी टैक्स नोटिस भेजा जाना संभव ही नहीं होगा।

वित्त मंत्री ने पिछले दिनों टैक्स अधिकारियों को व्यवहार बदलने की सख्त हिदायत दी थी। प्रतीकात्मक

- सीतारमण की नसीहत के बाद टैक्स अधिकारियों के लहजे में आया बदलाव
- हालांकि जांच के दायरे में आए करदाता की कानूनी गलती नजरअंदाज नहीं की जाएगी

केंद्र और अधिकारियों में संवादहीनता

नई दिल्ली, आइएएनएस : कॉरपोरेट जगत को टैक्स अधिकारियों के किसी भी बेजा दबाव से मुक्त रखने के लिए सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला हर उद्यमी सम्मान का हकदार है। लेकिन लगता है कि केंद्र सरकार और टैक्स विभाग के अधिकारियों में संवादहीनता है। विशाखापत्तनम जोन के सीमा शुल्क और सीजीएसटी चीफ कमिश्नर नरेश पेनुमाका ने कहा है कि जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने वालों पर वे सख्त कार्रवाई करेंगे।

पिछले दिनों मशहूर भारतीय कॉफी चेन कैफे कॉफी डे (सीसीडी) के मालिक वीजी सिद्धार्थ ने कर्नाटक के मेंगलुरु में गायब होने से पहले अपने कर्मचारियों को लिखे ईमेल में उन्होंने टैक्स अधिकारियों की तरफ से दबाव का भी जिक्र किया था। गायब होने के अगले ही दिन मेंगलुरु के निकट एक नदी से उनका शव बरामद किया गया था।

फसल बीमा दावा भुगतान में तेजी लाएं कंपनियां

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनियों को सख्त हिदायत दी है कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल बीमा दावों का भुगतान जल्द से जल्द करें। इनमें कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्य शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सभी बीमा दावों का जल्द से जल्द सत्यापन और भुगतान करें।

बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने भी बीमा कंपनियों से कहा है कि बाढ़ग्रस्त जिन क्षेत्रों में भी मृतक की लाश नहीं मिली है, वहां वर्ष 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ के वक्त अपनाए गए तरीके पर ही दावा भुगतान करें।

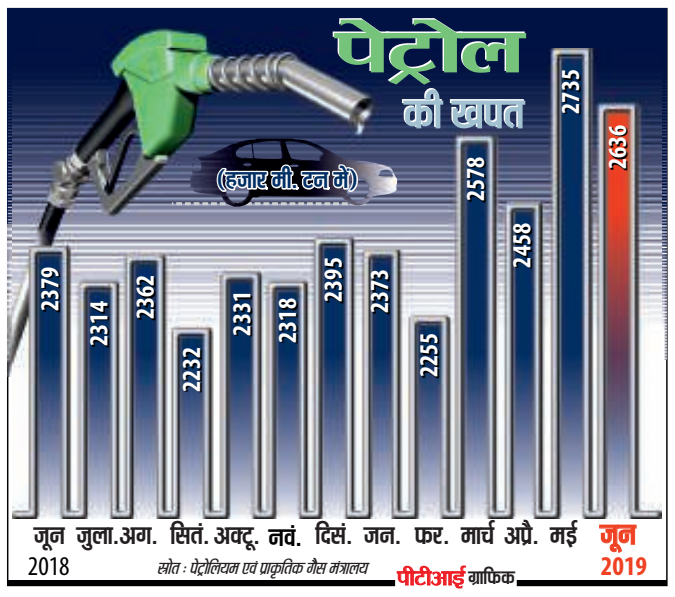

छोटे कर्जदारों को कर्जमाफी की तैयारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार छोटे कर्ज का दबाव झेल रहे कर्जदारों को मौजूदा इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के तहत कर्जमाफी का रास्ता निकालने की तैयारी कर रही है। हालांकि सरकार अगले तीन-चार वर्षों की अवधि में इस तरह की 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर्जमाफी नहीं देगी। कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने बताया कि माफी उन्हें ही मिलेगी, जिनके कर्ज का कुल आकार 35,000 रुपये से ज्यादा नहीं हो। यह पेशकश आइबीसी के 'नई शुरुआत' प्रावधानों के तहत की जा सकती है। श्रीनिवास ने कहा कि माइक्रोफाइनेंस उद्योग के साथ इस पर विचार-विमर्श हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के छोटे और दबाव झेल रहे कर्जदारों की कर्जमाफी की कसौटी क्या हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कर्जमाफी ईडब्ल्यूएस वर्ग में सबसे ज्यादा दबाव झेल रहे कर्जदारों को ही मिलेगी।

श्रीनिवास का कहना था कि कर्जदाताओं के लिए यह हेयरकट (कुल कर्ज और ब्याज में मामूली कटौती के साथ भुगतान) की तरह होगा, और इसका आकार भी बड़ा नहीं होगा। गौरतलब है कि ऐसे छोटे कर्ज माफ करने से बेहद दबाव में रहे कर्जदारों को भी फायदा मिलेगा, और बैंकों की बैलेंस शीट में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।

ऑटो डीलरों को एसबीआइ की बड़ी राहत

- डीलरों को कर्ज चुकाने के लिए 60 के बदले दी 90 दिनों तक की मोहलत
- मोहलत बढ़ाने से पहले हर डीलर की स्थिति का आकलन कर रहा बैंक

नई दिल्ली, प्रेट्र : मंदी की मार झेल रहे ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने बड़ी राहत दी है। बैंक ने ऑटो डीलरों के कर्ज भुगतान के लिए दी अवधि को बढ़ा दिया है। हालांकि बैंक ने कहा है कि यह हर ऑटो डीलर की व्यक्तिगत परिस्थितियों और मामले की पूरी समीक्षा के हिसाब से होगा।

एसबीआइ के एमडी (रिटेल व डिजिटल बैंकिंग) ने रविवार को कहा कि हम ऑटो डीलर्स के साथ लगातार बात कर रहे हैं। चूंकि यह सेक्टर अभी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसलिए हमने ऑटो डीलर्स को उनके मामलों के आधार पर कर्ज चुकाने की अवधि में छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर कर्ज चुकाने की अवधि 60 दिनों की होती है। लेकिन हम इसे 75 से 90 दिनों तक के लिए बढ़ा रहे हैं।

अधिकारी का कहना था कि एक बैंक के रूप में हम केवल समस्या के वित्तीय मदद के पहलू पर ही विचार कर सकते हैं। हमारा मुख्य मकसद वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराना है। हम मैन्यूफैक्चरर से वाहन खरीदने के लिए डीलरों को भी कर्ज देते हैं। लेकिन जहां तक मांग के वापस पटरी पर लौटने या लाने का सवाल है, तो इसमें सरकार के प्रयासों की बहुत बड़ी भूमिका है।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के मुताबिक पिछले तीन महीनों के दौरान ऑटो सेक्टर में करीब दो लाख कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। इसकी वजह यह है कि किसी भी विषम वित्तीय परिस्थिति में ऑटो डीलरों के पास मानव संसाधन कम करने के अलावा खर्च घटाने का और कोई प्रभावी तरीका नहीं बच जाता है।

बैंक ने कहा कि वह वित्तीय मामलों में मदद कर सकता है, बड़ी राहत सरकार ही दे सकती है। फाइल

कर्ज में 14 फीसद तक बढ़ोतरी की उम्मीद

कोलकाता, प्रेट्र : एसबीआइ को चालू वित्त वर्ष में कर्ज में 14 फीसद तक बढ़ोतरी की उम्मीद है। बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान भी बैंक द्वारा दिए जाने वाले कर्ज में इतनी ही बढ़ोतरी हुई थी। उन्होंने कहा कि बैंक की बैलेंस शीट का आकार देखते हुए 12-14 फीसद तक की विकास दर संतोषजनक रहेगी।

शेयर समीक्षा

तिमाही नतीजों का दौर लगभग खत्म, सरकार के कदमों से बाजार को मिलेगा दम, विदेशी घटनाक्रमों और डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल भी करेगी बाजार को प्रभावित

सरकारी मदद और वैश्विक बाजारों पर रहेगी नजर

नई दिल्ली, प्रेट्र : कई सेक्टरों की माली हालत में तंगी को देखते हुए सरकार ने उनकी हालत में सुधार के लिए सभी संभव मदद का आश्वासन दिया है। कहा जा रहा है कि सरकार कई सेक्टरों के लिए कुछ उत्साहवर्धक उपायों की घोषणा इस सप्ताह कर सकती है। घरेलू बाजार में निवेशकों की पैनी नजर इन उपायों की घोषणा पर रहेगी। इसके अलावा निवेशक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआइ) की चाल, चीन और अमेरिका में कारोबारी बातचीत की प्रगति और डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल पर भी घरेलू निवेशकों की पैनी नजर रहेगी।

सैमको सिक्युरिटीज एंड स्टॉकनोट के संस्थापक व सीईओ जिमीत मोदी मानते हैं कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजों का सिलसिला लगभग खत्म हो गया है। अधिकतर कंपनियों के वित्तीय परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं रहे हैं। इस वक्त बाजार में जिस तरह की मंदी दिख रही है, उसे देखते हुए वर्तमान तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भी ऐसी उम्मीद नहीं है कि कंपनियां अपनी हालत में उल्लेखनीय सुधार कर सकें। ऐसे में अब सारा दारोमदार सरकार द्वारा उठाए कदमों और राहत पैकेज पर रहने वाला है।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका-चीन का ट्रेड वार और नहीं गहराया तथा सरकार ने घरेलू उद्योग को राहत देने के लिए कुछ उपायों की घोषणा कर दी, तो शेयर बाजार पलटवार कर सकते हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्रा का भी यही मानना है कि घरेलू कंपनियों के वित्तीय नतीजों का दौर खत्म हो जाने के बाद अब निवेशकों को डॉलर और रुपये की चाल तथा अमेरिका-चीन वार्ता जैसे घटनाक्रमों से ही संकेत लेने होंगे।

पिछले सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में बकरीद और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दो दिन कारोबार बंद रहे। तीन दिनों के कारोबार वाले पिछले सप्ताह में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों साप्ताहिक नुकसान के साथ बंद हुए।

एफपीआइ की बेरुखी से चिंतित बाजार को सरकार से भी इस सप्ताह राहत की उम्मीद है। प्रतीकात्मक

एफपीआइ ने की 8,319 करोड़ रुपये की निकासी

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने अगस्त में अब तक भारतीय इक्विटी व डेट बाजारों से संयुक्त रूप से 8,319 करोड़ रुपये की निकासी की है। एफपीआइ पर प्रस्तावित टैक्स को लेकर सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिलने से विदेशी निवेशक थोड़े आशंकित हैं।

वैश्विक बाजारों की चिंता भी निवेशकों को परेशान कर रही है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक एफपीआइ ने पहली से 16 अगस्त तक इक्विटी बाजारों से 10,416.25 करोड़ रुपये निकाल लिए। हालांकि इसी दौरान उन्होंने डेट सिक्युरिटीज में 2,096.38 करोड़ रुपये का निवेश भी किया। मॉर्निंगस्टार के सीनियर एनालिस्ट मैनेजर रिसर्च हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि अगस्त में अब तक एफपीआइ का रुख स्पष्ट दिखा है। इस महीने में अब तक के 10 कारोबारी सत्रों में से नौ में एफपीआइ ने विशुद्ध रूप से बिकवाली की है। इससे पहले जुलाई में भी वे भारतीय इक्विटी व डेट बाजारों से 2,985.88 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली कर चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक घरेलू बाजार की परिस्थितियां थोड़ी खराब हैं। लेकिन विदेशी बाजारों की अस्थिरता ने कुल मिलाकर एफपीआइ के लिए माहौल ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

नौ कंपनियों का पूंजीकरण 84,354 करोड़ रुपये गिरा

नई दिल्ली, प्रेट्र : महज तीन दिनों के पिछले सप्ताह के कारोबार में बीएसई-सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से नौ कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में कुल 84,394.1 करोड़ रुपये की गिरावट आई। समीक्षाधीन सप्ताह में सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) के पूंजीकरण में बढ़त हुई। पिछले सप्ताह पूंजीकरण के लिहाज से सबसे ज्यादा 30,807.1 करोड़ रुपये का नुकसान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को हुआ। इस गिरावट के साथ कंपनी का बाजार पूंजीकरण 8,11,828.43 करोड़ रुपये रह गया। फिर भी यह सप्ताह के अंत में आरआइएल के 8,09,755.16 करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण से ऊपर ही है। एचडीएफसी के पूंजीकरण में भी पिछले सप्ताह 19,495.4 करोड़ की गिरावट आई। एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड (एचयूएल), इन्फोसिस, आइटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और एसबीआइ के बाजार पूंजीकरण में भी पिछले सप्ताह के दौरान गिरावट दर्ज की गई।

50 हजार लोग बेघर हो गए बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बड़ी झुग्गी बस्ती में आग लगने से। मीरपुर के चलंतिका इलाके में स्थित इस बस्ती में लगी आग से 15 हजार झुग्गियां जलकर राख हो गईं।

सरगना के भाई की मौत का शांति वार्ता पर नहीं पड़ेगा असर : तालिबान

कराची, प्रेट्र : आतंकी संगठन तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बम धमाके में सरगना मुल्ला हैबतुल्ला अखुनजादा के भाई की मौत के कारण अमेरिका के साथ चल रही शांति वार्ता पटरी से नहीं उतरेगी। अफगानिस्तान में करीब दो दशक से चल रही जंग की समाप्ति के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जल्द ही कोई समझौता हो सकता है। इस द्विपक्षीय वार्ता में पाकिस्तान की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। ऐसे में बलूचिस्तान में हुए विस्फोट से वार्ता के पटरी से उतरने की आशंका थी, लेकिन तालिबान ने इन आशंकाओं को खारिज कर दिया है। बीते शुक्रवार को क्वेटा से 25 किलोमीटर दूर कुचलाक क्षेत्र की एक मस्जिद में उस वक्त बम धमाका हुआ था जब वहां नमाज पढ़ी जा रही थी। इस धमाके में हैबतुल्ला के भाई हाफिज अहमदुल्ला समेत सात लोगों की मौत हो गई थी और 22 घायल हुए थे। अहमदुल्ला उस मस्जिद का इमाम था। अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, इस धमाके में आठ से दस किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था।

हांगकांग में प्रदर्शनकारियों ने फिर की बड़ी रैली

हांगकांग, रायटर : हांगकांग में रविवार को लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने फिर बड़ी रैली की। बारिश के बावजूद इस रैली में करीब एक लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मार्च की अनुमति नहीं मिलने के कारण सभी प्रदर्शनकारी विक्टोरिया पार्क में इकट्ठा हुए। भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण बड़ी संख्या में लोग पार्क के बाहर की सड़कों पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ लोगों ने शहर के वित्तीय केंद्र तक मार्च भी किया।

आयोजकों ने दावा किया कि रविवार की रैली में 17 लाख लोग शामिल हुए। हालांकि, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की संख्या लगभग 1.28 लाख बताई। शनिवार की रैली में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, जिनमें बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में थे। हांगकांग की आबादी लगभग 75 लाख है। रैली में शामिल छात्र जोनाथन ने कहा, 'बहुत अधिक गर्मी के साथ ही बारिश भी हो रही है। ऐसे में रैली में शामिल होना किसी चुनौती से कम नहीं। फिर भी हम यहां हैं क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। जब तक यह सरकार हमें हमारे अधिकार और इज्जत नहीं देती, यह जारी रहेगा।' संदिग्धों और अपराधियों को मुकदमे के लिए चीन प्रत्यर्पित किए जाने से संबंधित कानून के विरोध में जून में यहां विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। भारी विरोध के दबाव में हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लाम ने बिल निलंबित कर दिया है। लेकिन इस बिल का विरोध व्यापक होकर अब लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में बदल गया है। पिछले हफ्ते प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग एयरपोर्ट को घेर लिया था जिसके चलते कई उड़ानें रद करनी पड़ी थीं। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को मिल रहे समर्थन में कमी आने की आशंका थी। लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं दिखा। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक बीजिंग में चीनी विधायिका के प्रवक्ता यू वेंज ने हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का समर्थन करने पर अमेरिकी सांसदों की निंदा की है।

दिखाई मानवीयता : हांगकांग में रविवार को प्रत्यर्पण बिल को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारियों ने एक एंबुलेंस को रास्ता देकर इंसानियत का परिचय दिया। भारी बारिश के बीच साप्तहिक रैली में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे थे। एपी

पाक सेना और इमरान के बीच बढ़ी दूरियां

नई दिल्ली, एएनआइ

पाकिस्तानी सेना और प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका दौरे और भारत से संबंधों को लेकर कुछ अहम मौकों पर इमरान खान के बयानों से पाकिस्तानी सेना चिढ़ गई है।

पाकिस्तानी सेना भारत में आतंकियों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन कभी पाकिस्तानी सेना की कठपुतली कहे जाने वाले पीएम इमरान खान ने कई दफा दावा किया कि उनकी सरकार आतंकियों पर कार्रवाई कर रही है। लिहाजा, पाकिस्तानी सेना इमरान से नाराज है। दस सालों तक अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को अपने देश में छिपाने वाली पाकिस्तानी सेना का इरादा सेना के लोगों को राजनीति के जरिए मुख्यधारा में लाना है। ध्यान रहे कि अक्टूबर, 2017 में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि वह सशस्त्र बल के लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में लाने के लिए एक विशेष योजना पर काम कर रहे हैं।

एक यूरोपीय थिंक टैंक एफसास के लिखित दस्तावेज के अनुसार गफूर का मकसद आतंकियों और आतंकी संगठनों को आपस में जोड़कर उन्हें पाकिस्तान की मुख्यधारा में लाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में एक सकारात्मक भूमिका दी जाएगी। इसके विपरीत पिछले साल ही पाकिस्तानी सेना की हेराफेरी से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले इमरान खान ने हाल ही में मजबूरी में कुछ ऐसे बयान दे दिए कि पाकिस्तानी सेना के जनरल उनके खिलाफ हो गए हैं, जो आतंकी समूहों को बकायदा प्रशिक्षण देते हैं।

इमरान खान। फाइल

पहले तो अमेरिका यात्रा के दौरान इमरान ने दुनिया के सामने यह कुबूल कर लिया कि उनके देश में करीब 30 हजार से 40 हजार आतंकी हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार देश में जेहाद की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रही है।

अभी हाल ही में पाकिस्तान के आजादी दिवस पर इमरान खान यह भी कुबूल कर बैठे कि भारत गुलाम कश्मीर में बालाकोट से भी बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है। पाकिस्तानी सेना को इस बात की पूरी जानकारी है। हमारी जानकारी के मुताबिक भारत की और भी भयावह योजनाएं हैं। इमरान खान के इस कुबूलनामे से भी पाकिस्तानी सेना बेहद नाराज है। चूंकि पाकिस्तानी सेना हमेशा से इस बात से इंकार करती रही है कि बालाकोट के हवाई हमले में भारत को कोई कामयाबी मिली थी। भारतीय हमले को नाकाम साबित करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने विदेशी पत्रकारों को भी हमले वाली जगह पर ले जाने का नाटक रचा था। उसका दावा था कि हमले में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जबकि भारतीय वायुसेना ने कहा था कि बालाकोट स्थित आतंकी शिविर पर सटीक निशाना था और कम से कम 200 आतंकी मारे गए थे।

बौखलाए इमरान खान का नया पैंतरा, बोले-भारत के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं

इस्लामाबाद, एएनआइ : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मुंह की खाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेहद बौखला गए हैं। इमरान ने भारत की छवि खराब करने के लिए एक नया शिगूफा छोड़ा। इमरान ने कहा कि भारत के परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में नहीं हैं और इस पर दुनिया को गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। इमरान का सुरक्षा परिषद में जब कोई दांव नहीं चला तो दुनिया का ध्यान खींचने के लिए इस तरह के दुष्प्रचार का एक और पुलिंदा खोल दिया। इमरान ने कई ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में भारत के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए दुनिया को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

राजनाथ के बयान पर चिढ़ा पाक

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान की आलोचना की है कि इस्लामाबाद के साथ बातचीत केवल गुलाम कश्मीर के मसले पर की जाएगी। कुरैशी ने कहा, हमने राजनाथ का बयान देखा है। यह बताता है कि कश्मीर को लेकर भारत ने जो फैसला लिया है उसके बाद वह खुद को कठिन स्थिति में पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत विश्व समुदाय ने कश्मीर के हालात का संज्ञान लिया है।

काबुल में आत्मघाती हमला, 63 की मौत

कायराना हरकत ▶ शादी समारोह को बनाया निशाना, 182 घायल, आइएस ने ली जिम्मेदारी

अल्पसंख्यक शिया समुदाय बना इस वारदात का निशाना

काबुल, रायटर : आतंकियों ने एक शादी समारोह को निशाना बनाया है। शनिवार रात एक वेडिंग हॉल में हुए आत्मघाती धमाके में 63 लोगों की मौत हो गई और 182 घायल हुए हैं। मृतकों और घायलों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। अमेरिका और तालिबान में चल रही शांति वार्ता के बीच हाल के महीनों की इस सबसे भीषण वारदात की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) ने ली है। मैसेजिंग एप टेलीग्राम के जरिए किए पोस्ट में आइएस ने कहा कि एक आत्मघाती हमलावर ने शादी समारोह में खुद को उड़ा लिया। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की है।

एक बयान में, विदेश मंत्रालय ने कहा कि जघन्य आतंकी हमले के अपराधियों के साथ-साथ आतंकवादियों को पनाह देने वालों को 'शीघ्र' न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए।

अल्पसंख्यक शिया समुदाय की इस शादी समारोह में धमाका उस वक्त हुआ जब लोग नाच-गा रहे थे। धमाका होते ही उनकी खुशियां चीखों में बदल गईं। धमाके के बाद की तस्वीरों में उलटी हुई कुर्सियों और मेजों के बीच शव बिखरे दिखे।

इस हमले में दूल्हा-दुल्हन तो बच गए लेकिन उनके कई रिश्तेदार और दोस्त मारे गए। मीरवाइज नाम के दूल्हे ने कहा, 'इस हमले ने मेरी खुशियों को गम में तब्दील कर दिया। मेरा परिवार, मेरी पत्नी सदमे में है। मेरे कई दोस्तों और रिश्तेदारों की मौत हो गई।' दुल्हन के पिता के अनुसार इस हमले में उनके परिवार के 14 लोग मारे गए।

सुन्नी बहुल अफगानिस्तान में आतंकी अक्सर शिया समुदाय को निशाना बनाते रहे हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने हमले की निंदा की और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं जताईं। आइएस की ओर से हमले की जिम्मेदारी लिए जाने से पहले वह तालिबान को इस हमले का जिम्मेदार मान रहे थे। ट्विटर पर अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा, 'तालिबान इस जवाबदेही से नहीं बच सकता कि वह आतंकियों की सहायता करता है।' तालिबान ने धमाके की निंदा की है।

शादी में धमाके के 12 घंटे के भीतर अफगानिस्तान में एक और धमाका हुआ। रविवार को बल्ख प्रांत के दौलत अब्द जिले में एक बम धमाके में नौ लोग मारे गए।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित वेडिंग हॉल में हुए भीषण बम धमाके में मारे गए दुबई के नागरिक के विलाप करते परिजन और आतंकी वारदात के बाद अस्त-व्यस्त पड़ा वेडिंग हॉल। रायटर

आतंकियों पर कार्रवाई का ढोंग कर रहा पाकिस्तान

गुजरांवाला (पाकिस्तान), एएनआइ : पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब वह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के प्रतिबंधों से बचने के लिए अपने देश में पल रहे आतंकियों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करा रहा है। बता दें कि दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वह आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसने यह नया तरीका ढूंढा।

दरअसल इस तरह की दिखावे की कार्रवाई एफएटीएफ की बैंकॉक में होने वाली अहम बैठक से पूर्व कर रहा है। बता दें कि एफएटीएफ की इस संबंध में आखिरी महत्वपूर्ण बैठक अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकती है और इस दौरान पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने, रखने या उसको ब्लैकलिस्ट करने पर फैसला होगा। समाचार एजेंसी एएनआइ को इसी तरह की एक एफआइआर की प्रति मिली है। एक जुलाई को एक एफआइआर गुजरांवाला थाने में दर्ज की गई। यह एफआइआर प्रतिबंधित दावत-वल-इरशाद द्वारा की गई एक लैंड डील को लेकर दर्ज की गई। यह संगठन हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही सहायक संगठन है। एफआइआर को इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि इस मामले की न तो जांच हो सके और न ही वह किसी कोर्ट में ठहर सके। लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद और चार अन्य अब्दुल गफ्फार, हाफिज मसूद, आमिर हमजा और मलिक जफर इकबाल के खिलाफ एफआइआर में इस बात का जिक्र नहीं है कि इन आतंकियों के पास जमीन कब थी। एफआइआर में केवल इतना कहा गया कि लश्कर-ए-तैयबा और दावत-उल-इरशाद आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। वे आतंकी संगठनों की फंडिंग के लिए धन एकत्र करते हैं। एफआइआर में जमात-उद-दावा या फलाह-ए-इंसानियत का कोई जिक्र नहीं है। दावत-उल-इरशाद के नाम का जिक्र है जो जमात-उद-दावा का पुराना नाम है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया को भी नहीं भाए पाक के घड़ियाली आंसू

नई दिल्ली, एएनआइ : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के बाद पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामले का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा परिषद में हार के बाद पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश की। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने पाकिस्तान को गंभीरता से नहीं लिया। जम्मू कश्मीर से जुड़ी फर्जी तस्वीरों और घटिया वीडियो दिखाकर पाकिस्तान बरगलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया को पाकिस्तान के आरोपों पर भरोसा नहीं है। वॉल स्ट्रीट में प्रकाशित एक लेख में पत्रकार सदानंद धूमे ने लिखा, 'पाकिस्तानी सेना का पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार, अल्पसंख्यक बलूचों और पश्तूनों का प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्षी नेता का ढीला रवैया, इन सबको देखने पर पाकिस्तान का यह तर्क गलत है कि कश्मीरी पाकिस्तान में बेहतर होंगे।'

उइगरों की गिरफ्तारी में मिस्र ने की थी चीन की मदद

काइरो, एएफपी : करीब दो साल पहले सुन्नी मुस्लिमों के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अल-अजहर में अध्ययनरत उइगर छात्र अब्दुलमलिक अब्दुलअजीज को मिस्र की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने पहले उन्हें हथकड़ी लगाई और फिर उनका चेहरा ढक दिया। जब उनका नकाब हटाया गया तो वह राजधानी काइरो के पुलिस थाने में थे और चीनी अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे थे। अब्दुलअजीज अकेले उइगर नहीं हैं जिन्हें इस तरह गिरफ्तार कर यहां चीन के सुपुर्द कर दिया गया था। जुलाई, 2017 में 90 से ज्यादा उइगर मुस्लिमों को मिस्र में इसी तरह हिरासत में ले लिया गया था। उनमें से कई अल-अजहर में इस्लाम की पढ़ाई कर रहे थे।

अब्दुलअजीज ने कहा, 'चीनी अधिकारी मुझे मेरे उइगर नहीं बल्कि चीनी नाम से संबोधित कर रहे थे। मिस्र की पुलिस ने बताया कि चीन सरकार मुझे आतंकी बता रही है, लेकिन मैंने उन्हें नहीं में जवाब दिया था।' गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों से भी इसी तरह के सवाल पूछे गए थे। कई दिन तक हिरासत में रखने के बाद सभी को तीन समूहों में बांटकर लाल, पीले और हरे कार्ड दिए गए थे। इन कार्ड से तय होता था कि उन्हें रिहा करना है, प्रत्यर्पित करना है या आगे पूछताछ की जानी है। नार्वे में रहने वाले भाषाविद अब्दुलवेली अयुप कहते हैं, चीन के शिनजियांग प्रांत में यही किया जाता है। शिनजियांग में करीब दस लाख उइगरों और अन्य मुस्लिमों को हिरासत केंद्रों में रखा गया है। चीन की सरकार इन्हें प्रशिक्षण केंद्र बताती है। उसका कहना है कि धार्मिक कट्टरता रोकने के लिए यह जरूरी है।

2017 में 90 से ज्यादा उइगर मुसलमानों की मिस्र में हुई थी गिरफ्तारी

मिस्र में सबसे बड़ा निवेशक है चीन

अयुप के अनुसार मिस्र में उइगरों की गिरफ्तारी संयोग नहीं है। दरअसल चीन, मिस्र में सबसे बड़ा निवेशक है। उइगरों की गिरफ्तारी से तीन हफ्ते पहले ही चीन और मिस्र ने आतंकवाद का सामना करने के लिए एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

हमले में पत्नी खोने वाले बुजुर्ग का सहारा बनी दुनिया

अमेरिका के अल पासो में स्थित वालमार्ट में पिछले दिनों एक बंदूकधारी के हमले का शिकार बनी 63 वर्षीय महिला मार्गी रेकार्ड के पति एंटोनियो बास्को की मदद के लिए दुनियाभर से लोग उनकी मदद को आगे और उनके दुख में सहभागी बने। पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए एंटोनियो ने पूरी दुनिया को बुलावा भेजा था। इस पर मार्गी के अंतिम संस्कार में कई शहरों से सैकड़ों लोग आ पहुंचे। इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित कई देशों से 10, 000 श्रद्धांजलि संदेश व फूल भी उन्हें भेजे गए। रायटर

ग्रेस को पकड़ने से जिब्राल्टर का अमेरिका को इन्कार

कहा, यूरोपीय यूनियन में लागू नहीं होते अमेरिकी प्रतिबंध

जिब्राल्टर, एएफपी/प्रेट्र : जिब्राल्टर सरकार ने ईरानी तेल टैंकर ग्रेस वन को फिर से कब्जे में लेने की अमेरिकी मांग अस्वीकार कर दी है। फिलहाल यह टैंकर भूमध्य सागर में जिब्राल्टर की जलसीमा में लंगर डाले हुए है लेकिन बहुत जल्द वहां से रवाना होगा। इससे पहले गुरुवार को जिब्राल्टर के सुप्रीम कोर्ट ने भी ईरानी टैंकर को न छोड़े जाने की अमेरिकी मांग अस्वीकार कर दी है। जिब्राल्टर ब्रिटिश उपनिवेश है और ग्रेस वन प्रकरण ब्रिटेन और अमेरिका की दांतकाटी रोटी वाले रिश्ते में किरकिरी माना जा रहा है।

अमेरिका की कोर्ट ने ग्रेस वन पर आतंकवाद में शामिल होने समेत कई आरोपों के लिए शनिवार को वारंट जारी किया है। लेकिन जिब्राल्टर की सरकार ने इसे मानने से इन्कार कर दिया है। उसने कहा है कि ईरान पर लगाए अमेरिकी प्रतिबंध यूरोपीय यूनियन क्षेत्र में लागू नहीं होते। अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार पर प्रतिबंध लगा रखा है। वह अपना तेल न बेच सकता है और न कोई देश ईरान का तेल खरीद सकता है। भूमध्य सागर में खड़े ग्रेस वन पर भारतीय कैप्टन के नेतृत्व में 28 सदस्यीय चालक दल है। चालक दल में कुल 24 भारतीय हैं। यही चालक उसे लेकर आगे बढ़ेंगे। आशंका यह भी है कि जिब्राल्टर की जल सीमा से बाहर निकलते ही अमेरिकी नौसेना इस तेल टैंकर को अपने कब्जे में ले ले।

टैंकर का नाम बदलकर एडरेन दरया किया

ग्रेस वन ने अपना बदलकर एडरेन दरया रख लिया है। ग्रेस वन की जगह पेंट से नया नाम लिख दिया गया है। साथ ही पनामा का झंडा हटाकर तेल टैंकर पर अब ईरान का झंडा लगा दिया गया है। पनामा ने कहा है कि आतंकवाद से जुड़े कारोबार में शामिल होने के कारण एक साल पहले ही ग्रेस वन का पंजीकरण रद कर दिया गया था और उससे झंडा हटाने के लिए कहा गया था। टैंकर में 21 लाख बैरल तेल भरा है और इसके ईरानी इलीट फोर्स ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड से मिले होने का शक है।

यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन में जरूरी सामान की हो जाएगी किल्लत!

लंदन, रायटर : अलग होता है तो उसे ईंधन, खाद्य पदार्थों और दवाओं की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। यह बात ब्रिटिश सरकार के एक गोपनीय दस्तावेज में कही गई है, जो लीक होकर मीडिया के पास पहुंच गया है। 100 से ज्यादा सांसदों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पत्र लिखकर ब्रेक्जिट के बाद की स्थिति पर विचार के लिए संसद का आपात बैठक बुलाने की मांग की है। इस बीच ब्रेक्जिट प्रक्रिया पर विचार के लिए जॉनसन ने यूरोपीय नेताओं से मिलने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में वह बुधवार को जर्मनी, गुरुवार को फ्रांस जाएंगे।

31 अक्टूबर को पूरी होने वाली संबंध विच्छेद की इस प्रक्रिया के बाद ब्रिटेन में बंदरगाहों पर जहाजों का तांता लग सकता है, विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं और अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इस आशंका से संबंधित खुफिया रिपोर्ट कैबिनेट कार्यालय के पास पहुंची है। लेकिन ब्रेक्जिट मामले में समन्वय बना रहे मंत्री माइकल गोव ने मीडिया में आई इन बातों का खंडन किया है। कहा कि सबसे बुरी स्थिति के विषय में ये बातें कही गई हैं। जरूरी नहीं है कि यह सब हो। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में 85 प्रतिशत माल ढुलाई का कार्य ट्रकों के जरिये होता है। ब्रेक्जिट के बाद ये ट्रक फ्रांस के सीमा शुल्क विभाग की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए बचे हुए समय में व्यवस्थाओं में सुधार के लिए तत्परता से कदम उठाए जाएं।

बोरिस जॉनसन। फाइल

- लीक हुए सरकारी दस्तावेज में जताई गई है आशंका
- बोरिस जॉनसन के कार्यालय ने सरकारी दस्तावेज पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार किया

प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्यालय ने सरकारी दस्तावेज पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यूरोपीय यूनियन से चल रही वार्ता को प्रभावित करने के लिए एक पूर्व मंत्री ने यह रिपोर्ट लीक कराई है। रविवार को ब्रेक्जिट मामलों के मंत्री स्टीफन बर्कले ने कानूनों में बदलाव के प्रस्ताव तैयार करने के आदेश पर दस्तखत कर दिए। नए कानून 31 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन से अलगाव के बाद लागू होंगे।

यमन के हाउती विद्रोहियों ने ईरान में नियुक्त किया अपना राजदूत

दुबई, एएफपी : यमन के हाउती विद्रोहियों ने ईरान में अपना राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। इसको लेकर यमन की सरकार ने कड़ा विरोध जताया है। यमन की राजधानी सना और देश के उत्तरी हिस्से पर कब्जा जमाए हाउती विद्रोहियों की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति के आदेश के तहत सहयोगी देश ईरान में इब्राहिम मुहम्मद अल-दैलामी को राजदूत बनाने का निर्णय लिया गया है। पिछले सप्ताह हाउती विद्रोहियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई से मुलाकात की थी। यमन की सरकार ने इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा है कि ईरान और हाउती विद्रोहियों के बीच राजनयिक संबंध अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। यह हाउती और ईरान के बीच गुपचुप तरीके से स्थापित रिश्तों को भी उजागर करता है। इस निर्णय को लेकर ईरान के तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। यमन में 2014 से हाउती विद्रोहियों और सऊदी अरब समर्थित राष्ट्रपति अब्दरब्बू मंसूर हादी की सरकार के बीच जंग जारी है।

बलूचिस्तान के वरिष्ठ नेता और तीन अन्य लोगों की हत्या

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक वरिष्ठ राजनेता, उनके किशोर पोते और दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खुजदार जिले के पुलिस उपायुक्त मेजर मुहम्मद ने कहा कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी-मेनगल (बीएनपी-एम) नेता अमानुल्ला जेहरी तड़के अपने आवास पर लौट रहे थे। इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया।

मुहम्मद ने कहा, 'जेहरी, उनके 14 वर्षीय पोते मर्दान जेहरी और दो सुरक्षाकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। उपायुक्त ने कहा कि पूरे तहसील की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। बीएनपी-एम के प्रमुख नवाब अख्तर मेंगल ने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक व्यक्त किया है।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, 'बीएनपी और बलूचिस्तान के लोगों के लिए यह एक और काला दिन है। मैं अपने को शब्दों में बयां नहीं कर सकता।' इससे पहले शुक्रवार को बलूचिस्तान प्रांत में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में हुए शक्तिशाली बम धमाके में पांच लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में अफगान तालिबान के एक नेता मुल्ला हैबतुल्ला के भाई भी शामिल थे।

पाकिस्तान में विस्फोट में पांच लोगों की मौत, 17 अन्य घायल

पेशावर, प्रेट्र : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार को रिमोट कंट्रोल के जरिये किये गये एक विस्फोट में पांच लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गये। पुलिस ने बताया कि पर्वतीय दिर अप्पर जिले में अज्ञात बदमाशों ने एक स्थानीय सरदार मोतबर खान के वाहन को निशाना बना कर यह विस्फोट किया। इस हमले में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गये। घायलों में खान के तीन सरकारी सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। बहरहाल, अधिकारियों ने इस हमले में खान के मारे जाने की पुष्टि नहीं की है।

ब्रिटेन ने छीनी आइएस से जुड़ने वाले युवक की नागरिकता

लंदन, आइएएनएस : आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) से जुड़ने वाले युवक जैक लेट्स (24) की ब्रिटिश नागरिकता छीन ली गई है। जैक 2014 में 18 साल की उम्र में ऑक्सफोर्डशायर के स्कूल से भागकर सीरिया के रक्का में आइएस से जुड़ गया था। जंग के दौरान 2017 में तुर्की भागते वक्त उसे कुर्दिश सेना ने पकड़ लिया था। उसने 16 साल की उम्र में इस्लाम धर्म अपना लिया था।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, ब्रिटिश सरकार ने हाल में जैक की ब्रिटिश नागरिकता खत्म कर दी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि यह कदम देश को आतंकवाद से दूर रखने के लिए उठाया गया है। आतंकी संगठन से जुड़ने वाले बेटे को आर्थिक मदद का दोषी पाए जाने पर इस साल जून में जैक के मां-बाप को 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। पिता के कनाडाई नागरिक होने की वजह से जैक को कनाडा की नागरिकता भी मिली है। इसी तरह के एक अन्य मामले में इस साल ब्रिटिश युवती शमीमा बेगम की नागरिकता भी खत्म कर दी गई थी।

मैं खेल रत्न अवार्ड को अपने पिता को समर्पित करती हूं क्योंकि वह इस तरह के सम्मान का इंतजार कर रहे थे।
— दीपा मलिक, पैरा-एथलीट

हिमा, अनस ने एथलेटिकी मिटिनेक रीटर में जीते स्वर्ण

नई दिल्ली : भारत के शीर्ष धावकों हिमा दास और मुहम्मद अनस ने चेक गणराज्य में जारी एथलेटिकी मिटिनेक रीटर-2019 स्पर्धा में क्रमश: पुरुष और महिला वर्ग के 300 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। अनस ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। इस साल के अर्जुन अवार्ड के लिए चुने गए अनस ने पुरुषों के 300 मीटर रेस को 32 .41 सेकंड के समय के साथ पूरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

आर्चर के हमले से सहमे कंगारू

एशेज सीरीज ▶ लॉर्ड्स टेस्ट में स्टोक्स का शतक, ऑस्ट्रेलिया को 267 का लक्ष्य

जोफ्रा ने दिए ऑस्ट्रेलिया को दो शुरुआती झटके

लंदन, रायटर : बारिश की वजह से करीब दो दिन का खेल खराब होने के बाद भी इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के पांचवें दिन यहां लॉर्ड्स मैदान पर तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के दमदार प्रदर्शन से टेस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इंग्लैंड की टीम ने पांचवें दिन बेन स्टोक्स के शतक के बाद अपनी पारी पांच विकेट पर 258 रनों पर घोषित करके ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 267 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने खबर लिखे जाने तक पांच विकेट के नुकसान पर 144 रन बना लिए हैं। ट्रेविस हेड 37 और टिम पेन चार रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन स्टीव स्मिथ की जगह शामिल किए गए स्थानापन्न खिलाड़ी मार्नस लाबुशाने ने बनाए। उन्होंने 100 गेंद में आठ चौकों की मदद से 59 रन की पारी खेली। इसके अलावा कैमरोन ब्रैनक्राफ्ट ने 18 और मैथ्यू वेड एक ही रन बना सके। दोनों को लेग स्पिनर लीच ने आउट किया।

267 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। तेज गेंदबाज आर्चर ने पहली ही गेंद से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर आक्रमण शुरू कर दिया। फॉर्म से बाहर चल रहे डेविड वार्नर आर्चर की तेज गेंदों के आगे जूझते दिखे। नतीजा यह रहा कि चौथे ही ओवर में इंग्लैंड को उनके रूप में पहला विकेट मिल गया। आर्चर ने उन्हें मात्र पांच रनों पर पवेलियन भेजा। इसके बाद उस्मान ख्वाजा भी आर्चर की बाहर जाती गेंद पर गच्चा खा गए और विकेट के पीछे जॉनी बेयरस्टो ने उनका कैच लपकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। दो विकेट गंवा चुकी ऑस्ट्रेलिया को संभालने अब चौथे नंबर पर लाबुशाने आए। आर्चर ने पहली ही गेंद पर लाबुशाने को चारों खाने चित करके अपने कद का अहसास कराया। आर्चर की बाउंसर गेंद पर चोटिल होने के बाद लाबुशाने को दूसरी पारी में स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला और पहली ही गेंद आर्चर ने लाबुशाने को बाउंसर फेंकी। यह गेंद लाबुशाने के हेलमेट पर जाकर लगी और लाबुशाने मैदान पर गिर पड़े। स्मिथ के साथ हुई घटना के बाद पूरा ऑस्ट्रेलियाई और इंग्लैंड का खेमा इस दृश्य को देखकर हतप्रभ रह गया। आर्चर को छोड़कर मैदान पर मौजूद इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी लाबुशाने के पास उनका हाल जानने पहुंचे। यह गेंद इतनी तेज थी कि लाबुशाने का हेलमेट भी अंदर से टूट गया जिसके बाद उन्हें दूसरा हेलमेट मंगवाना पड़ा। हालांकि इसके बाद दोनों ही खिलाड़ी चायकाल तक विकेट नहीं देने में कामयाब रहे।

इससे पहले, चौथे दिन के स्कोर चार विकेट पर 96 रन से आगे खेलते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों स्टोक्स और जोस बटलर ने संभलकर बल्लेबाजी की। दोनों ही बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 90 रन जोड़ डाले और इससे इंग्लैंड अच्छी स्थिति में चला गया। बटलर हालांकि 31 रनों के निजी स्कोर पर पैट कमिंस का शिकार बन आउट होने वाले दिन के पहले बल्लेबाज बने। यहां से फिर स्टोक्स और बेयरस्टो ने पारी को आगे बढ़ाया। उम्मीद थी कि भोजनकाल के बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भोजनकाल के कुछ देर बाद स्टोक्स ने अपना शतक पूरा किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक शॉट खेले और पांच विकेट पर 258 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। स्टोक्स ने 165 गेंद में 11 चौके और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 115 रन बनाए। वहीं बेयरस्टो ने 37 गेंद में एक चौके और दो छक्कों की मदद से 30 रन बनाए। इससे पहले इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 258 रन और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 250 रन बनाए थे।

डेविड वार्नर का विकेट लेने के बाद जश्न मनाते इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। एपी

तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने मुझे 2005 की याद दिला दी : पोंटिंग

एशेज डायरी

लंदन, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाद जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी ने उन्हें 2005 एशेज सीरीज की याद दिला दी। उस एशेज सीरीज में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टीव हर्मिसन ने दमदार गेंदबाजी की थी और पोंटिंग, मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर को चोटिल कर दिया था।

पोंटिंग ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट को बताया कि वह सुबह बहुत खतरनाक थी और शनिवार को कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई। मुझे याद है जब मुझे गेंद लगी तब माइकल वॉन ने अपने खिलाड़ियों से कहा कि कोई भी पोंटिंग के पास जाकर उसका हाल नहीं पूछेगा। मेरे लिए यह सही था क्योंकि मैं भी उन्हें अपने से दूर रहने के लिए कहता। शनिवार को लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान आर्चर की गेंद स्टीव स्मिथ को लगी जिससे वह थोड़ी देर के लिए मैदान से बाहर गए। हालांकि, वह वापस बल्लेबाजी करने आए और कुल 92 रनों की पारी खेली। पोंटिंग ने कहा कि मैं नहीं समझता कि यह स्पैल सीरीज का रुख तय करेगा। उन्होंने फिर से 92 रन बनाए, मुझे पता था कि वह 70 के करीब रन बनाएंगे और अगर अब गेंदबाज स्मिथ पर ज्यादा आक्रमण करेंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा।

पोंटिंग ने कहा कि आर्चर हालांकि, स्मिथ को आउट नहीं कर पाए। स्मिथ ने अपना विकेट नहीं गंवाया और उनका समाना किया। मैं मान रहा हूं उनके गले पर लगी चोट ठीक है। आप नेट में गेंदबाजों का सामना करते हैं और आपको हमेशा चोट लगी रहती है, लेकिन कोई भी चीज आपकी मानसिकता को नहीं बदलती है।

अख्तर ने शिष्टाचार नहीं दिखाने पर आर्चर की आलोचना की

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने रविवार को इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की आलोचना की। दरअसल, शनिवार को लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान आर्चर का एक बाउंसर स्टीव स्मिथ को लगा जिससे वह मैदान पर गिर गए थे।अख्तर ने ट्वीट किया कि बाउंसर खेल का एक हिस्सा है, लेकिन जब भी कोई गेंदबाज सिर पर बल्लेबाज को मारता है और वह गिर जाता है, तो शिष्टाचार के लिए जरूरी है कि गेंदबाज उसके पास जाए और उसकी जांच करे।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग। फाइल

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ स्मिथ की हूटिंग से निराश

सिडनी, एएफपी : ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट संघ (एसीयू) ने जोफ्रा आर्चर के बाउंसर से पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ के गर्दन पर चोट लगने के बाद हुई हूटिंग की आलोचना करते हुए कहा कि खेल में अच्छे आचरण की जरूरत है। चोटिल होने के बाद जब स्मिथ मैदान पर वापस लौट रहे थे तब कुछ दर्शकों ने उनकी हूटिंग की। गेंद से छेड़छाड़ मामले में एक साल की प्रतिबंध झेलने के बाद स्मिथ की यह पहली टेस्ट सीरीज है।

बोर्ड को नागवार गुजरा : ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों की अगुआई करने वाले एसीए ने कहा चोटिल खिलाड़ी के साथ ऐसा आचरण गलत है। एसीए के अध्यक्ष ग्रेग डायर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलिस्टर निकोलसन ने कहा कि क्रिकेट में इससे कहीं बेहतर आचरण की अपेक्षा की जाती है। लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है वहां इससे काफी बेहतर आचरण होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमने जो देखा वह एक युवा की बहादुरी थी, जिसका अपमान नहीं, सम्मान किया जाना चाहिए था।

इंग्लैंड में दर्शकों का आचरण शानदार रहा है, लेकिन जब कोई चोटिल होता है तब हूटिंग नहीं किया जाना चाहिए थी। मार्क टेलर और इयान हिली जैसे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने भी दर्शकों के इस आचरण को निराशाजनक बताया।

चेतेश्वर पुजारा के शतक से संभली भारतीय क्रिकेट टीम

अभ्यास मैच

- वेस्टइंडीज-ए के खिलाफ भारत ने पहले दिन पांच विकेट पर 297 रन बनाए
- चेतेश्वर ने बनाए 100 रन, रोहित ने भी खेली 68 रन की पारी

कूलिज (एंटीगा), प्रेट्र : चेतेश्वर पुजारा के शानदार शतक और रोहित शर्मा के 68 रन से भारत ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए वेस्टइंडीज-ए के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच के शुरुआती दिन यहां पांच विकेट पर 297 रन बनाए। पुजारा और रोहित ने चौथे विकेट के लिए 132 रन की साझेदारी निभाई, जिससे भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंची। टेस्ट विशेषज्ञ पुजारा 187 गेंद में आठ चौके और एक छक्के की मदद से 100 रन बनाकर रिटायर्ड हो गए। रोहित 115 गेंद में 68 रन बनाने के बाद आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान आठ चौके और एक छक्का लगाया। पुजारा के अंतिम सत्र में रिटायर होने के बाद रिषभ पंत और हनुमा विहारी ने स्कोर को 300 रन के करीब पहुंचाया। स्टंप उखड़ने तक पंत 53 गेंद खेलकर चार चौके और एक छक्के की मदद से 33 रन बानाकर आउट हो गए। दिन का खेल 88.5 ओवर में समाप्त हुआ, तब हनुमा 101 गेंद पर 37 रन बनाकर, जबकि रवींद्र जडेजा एक रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। वेस्टइंडीज-ए के लिए तेज गेंदबाज जोनाथन कार्टर ने 39 रन देकर तीन विकेट हासिल किए, जबकि कीयोन हार्डिंग और अकीम फ्रेजर को एक-एक विकेट मिला।

भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। अभ्यास मैच के लिए कप्तान बनाए गए अजिंक्य रहाणे फिर विफल रहे, जिससे भारत ने भोजनकाल तक 89 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे। रहाणे केवल छह गेंद तक ही क्रीज पर टिक सके। केएल राहुल अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए। राहुल ने 46 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 36 रन बनाए और मयंक अग्रवाल (12) के साथ पहले विकेट के लिए 36 रन जोड़े। भारत ने हालांकि 16 रन के अंदर इन दोनों के अलावा रहाणे (01) का भी विकेट गंवाया। राहुल ने शुरू से लय पकड़ ली थी, जबकि अग्रवाल ने सतर्कता बरती। इस बीच राहुल ने रन बनाने की जिम्मेदारी संभाली। कार्टर ने अग्रवाल को बोल्ड करके यह साझेदारी तोड़ी। राहुल फिर से अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील करने में नाकाम रहे और हार्डिंग की गेंद पर रोमेरियो शेफर्ड को कैच दे बैठे। कार्टर ने अगले ओवर में रहाणे को विकेट के पीछे कैच करवाकर स्कोर तीन विकेट पर 53 रन कर दिया। रहाणे पिछले दो वर्षों में शतक नहीं बना सके हैं, उन्होंने अगस्त 2017 में श्रीलंका टीम के लिए सैकड़ा जड़ा था। पिछले 12 टेस्ट मैचों में वह 20 पारियों में केवल पांच बार ही अर्धशतक तक पहुंच पाए हैं। इस दो टेस्ट की सीरीज के लिए अंतिम एकादश में हालांकि उनके स्थान को खतरा नहीं है, लेकिन अगर वह इस सीरीज में विफल रहते हैं तो दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए यह नहीं कहा जा सकता है। हनुमा और श्रेयस अय्यर ऐसे मौके के इंतजार में हैं।

भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा। फाइल

करुणारत्ने का शतक, श्रीलंकाई टीम ने दर्ज की कीवियों पर ऐतिहासिक जीत

गॉल टेस्ट

गॉल, एएफपी : श्रीलंका क्रिकेट टीम ने रविवार को यहां खेले गए दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को छह विकेट से मात देकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जीत के साथ आगाज किया। इसी के साथ मेजबान टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मेजबान टीम ने पांचवें दिन कप्तान दिमुथ करुणारत्ने के 122 रनों की बदौलत शानदार जीत दर्ज की। करुणारत्ने को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया।

श्रीलंका ने पांचवें दिन बिना नुकसान के 133 रन से आगे खेलना शुरू किया। सलामी बल्लेबाज करुणारत्ने और लाहिरु थिरिमाने स्कोर को 161 तक ले गए। विलियम समरविले ने दिन के 11वें ओवर में थिरिमाने (64) को पवेलियन भेजकर मेजबान टीम को पहला झटका दिया। अगले ही ओवर में एजाज पटेल ने कुशल मेंडिस को आउट कर दिया। मेंडिस ने छह गेंदों में महज 10 रन बनाए। ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज एक छोर पर टिके रहे और मेजबान टीम के कप्तान ने अपने टेस्ट करियर का नौवां शतक जड़ा। यह पहली बार था जब करुणारत्ने ने किसी मैच की चौथी पारी में शतक लगाया।

साउथी ने किया दिमुथ को आउट : तेज गेंदबाज टिम साउथी ने करुणारत्ने (122) को पवेलियन की राह दिखाई। यहां से मेजबान टीम को जीत के लिए केवल 50 रनों की आवश्यकता थी। हालांकि, कुशल परेरा ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को अपनी टीम पर हावी नहीं होने दिया। परेरा को उनकी पारी की आठवीं गेंद पर ही आउट दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने रिव्यू सिस्टम का उपयोग किया और वह बच गए। एक ओवर बाद मेहमान टीम ने उनके खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की और अंपायर द्वारा आउट नहीं दिए जाने के बाद रिव्यू लिया। इस बार भी निर्णय परेरा के पक्ष में रहा। परेरा (23) को 250 के कुल योग पर ट्रेंट बोल्ट ने आउट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैथ्यूज एवं धनंजय डिसिल्वा मेजबान टीम को जीत तक ले गए। मैथ्यूज 28 और डिसिल्वा 14 रन बनाकर नाबाद रहे।

शतक लगाने के बाद दर्शकों का अभिवादन करते श्रीलंका के कप्तान करुणारत्ने। एएफपी

चौथी पारी में बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। हम एक अच्छी साझेदारी चाहते थे। जब आप एक बार सेट हो जाते हैं तो फिर आप अपना काम खत्म करते हैं।
– दिमुथ करुणारत्ने, कप्तान श्रीलंका

हमने बल्लेबाजी तो अच्छी की, लेकिन हम गेंदबाजी अच्छी नहीं कर पाए। इस मैच से हमें काफी सकारात्मक चीजें मिली हैं। इस मैच में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन मेजबान टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और वह वास्तव में जीत की हकदार थी।
– केन विलियमसन, कप्तान न्यूजीलैंड

योग्य चिकित्सक करेंगे भारतीय क्रिकेटरों का डोप टेस्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) बेंगलुरु में दलीप ट्रॉफी के अगले मैच के दौरान बीसीसीआइ से पंजीकृत खिलाड़ियों का परीक्षण शुरू कर देगा। नाडा ने प्रमुख डोप नियंत्रण अधिकारियों (डीसीओ) के रूप में योग्य चिकित्सकों को रखने की बीसीसीआइ की मांग स्वीकार कर ली है।

हाल में बीसीसीआइ के महाप्रबंधक (क्रिकेट परिचालन) सबा करीम और डोपिंग रोधी इकाई के प्रमुख डॉ. अभिजीत साल्वी ने नाडा के सीनियर अधिकारियों से आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए मुलाकात की, जिसमें महानिदेशक नवीन अग्रवाल शामिल थे। नाडा ने बैठक के बाद कहा, 'हम यह भागीदारी जल्द से जल्द दलीप ट्रॉफी से ही शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं।'

नाडा हालांकि बेंगलुरु में इंडिया ब्लू और इंडिया ग्रीन टीमों के बीच चल रहे शुरुआती मैच में किसी खिलाड़ी की जांच नहीं करेगी। हालांकि, ऐसी संभावना है कि कुछ परीक्षण 23 अगस्त से शुरू होने वाले अगले मैच में किए जाएं। बीसीसीआइ ने सत्र के घरेलू मैचों के पूर्ण कार्यक्रम की सूची सौंप दी है जिसमें तारीख और स्थल शामिल हैं, ताकि नाडा अपने परीक्षण के लिए क्रिकेट कार्यक्रम तैयार कर सके।

साल्वी ने कहा, 'दिलीप ट्रॉफी पहले ही शुरू हो चुकी है और शायद वे आगे के मैचों के लिए आएं। उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है कि वे किस तरह का परीक्षण (औचक या निर्धारित समय पर) करेंगे। उम्मीद है कि वे मैच के दिनों (टूर्नामेंट के दौरान) में कुछ परीक्षण करेंगे।' बीसीसीआइ के डोपिंग रोधी अधिकारी ने उच्च मानक सुनिश्चित करने के लिए 'अतिरिक्त भुगतान' की बात पर कहा, 'हमारी मुख्य चिंता डोप नियंत्रण अधिकारियों की योग्यता पर और मामलों के निपटारे के लिए लिया जाने वाला समय थी। नाडा ने हमें दोनों के बारे में आश्वस्त किया है। हमने अनुरोध किया था कि बीसीसीआइ के लिए जो डोप नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किए जाएं, वे मान्यता प्राप्त चिकित्सक (एमबीबीएस) हों जिन्हें डोपिंग के संबंध में जानकारी हो।' डीसीओ अगर डॉक्टर होगा तो इसमें अतिरिक्त भुगतान होगा और बीसीसीआइ इसका भुगतान करेगा।

दूसरे दिन का खेल बारिश में धुला, एक गेंद नहीं फेंकी गई

बेंगलुरु, प्रेट्र : इंडिया ब्लू और इंडिया ग्रीन के बीच खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी के पहले मैच के दूसरे दिन का खेल मैदान गीला होने के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द करना पड़ा। अंपायरों ने काफी इंतजार करने के बाद दोपहर दो बजे दिन का खेल रद्द करने का फैसला किया। शनिवार को वर्षा से प्रभावित पहले दिन 49 ओवर का खेल हो पाया था, जिसमें इंडिया ग्रीन ने इंडिया ब्लू का स्कोर छह विकेट पर 112 रन कर दिया था।

हितों के टकराव मुद्दे पर चर्चा करेंगे पूर्व क्रिकेटर

मुंबई, प्रेट्र : पूर्व क्रिकेटर सोमवार को यहां बीसीसीआइ के मुख्यालय में होने वाली अनौपचारिक बैठक के दौरान विवादास्पद 'हितों के टकराव' के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई शीर्ष क्रिकेटरों के इस बैठक में शिरकत करने की उम्मीद है जिसमें सीओए का कम से कम एक सदस्य मौजूद होगा। उनके इस मुद्दे पर लंबी चर्चा की उम्मीद है। विनोद राय की अध्यक्षता वाली सीओए में अन्य सदस्य डायना इडुल्जी और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल रवि थोडगे शामिल हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर और तेज गेंदबाज अजीत अगरकर के बैठक में भाग लेंगे, यह तय है। यहां तक कि वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ के इसमें शिरकत करने की उम्मीद है। हालांकि पता चला है कि सचिन तेंदुलकर बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह सोमवार को बैठक में शिरकत नहीं करेंगे।

मुकाम

18 अगस्त 2008 को खेला था अंतरराष्ट्रीय किक्रेट का पहला मैच, प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर की विराट की सराहना

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोहली के 11 साल पूरे

नई दिल्ली, एएनआइ : 18 अगस्त 2008 ही वह तारीख है जब भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार कदम रखा था। तब कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ दांबुला वनडे के जरिये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, लेकिन वह अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मैच में केवल 12 रन ही बना पाए थे। कोहली ने अपना पहला शतक 2009 में बनाया था, लेकिन आज वह सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। कोहली वनडे क्रिकेट में 43 शतक लगा चुके हैं और वह बस मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं।

कोहली के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर में 11 साल पूरे होने पर उनके चाहने वालों ने जमकर स्वागत किया है और 11 ईयर्स ऑफ विराटिज्म के नाम से हैशटैग चलाया जो भारत में रविवार को सुर्खियों में रहा। एक प्रशंसक ने लिखा, आज ही के दिन किंग ने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय गेंद खेली। वहीं एक अन्य ने लिखा कि मेरे आदर्श और प्रेरणा हैं विराट कोहली। आपकी वजह से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और आपकी वजह से मुझे क्रिकेट से लगाव हुआ। 11 ईयर्स ऑफ विराटिज्म। वहीं एक अन्य ने लिखा, जब भी मैं आपको खेलता देखता हूं तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और मुझे प्रेरित करती है। मुझे क्रिकेट पसंद है लेकिन आपको खेलते देखना बहुत अच्छा लगता है। एक अन्य ने लिखा, विराट का कवर ड्राइव, 11 ईयर्स ऑफ विराटिज्म। विराट कोहली वनडे और टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज हैं जिनके नाम कुल 68 अंतरराष्ट्रीय शतक दर्ज हैं। 30 वर्षीय कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में लगातार दो शतक जड़े थे और एक दशक में 20000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने थे। साथ ही वह भारत की ओर से वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे और वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने। उन्होंने टी-20 में 2010 में और टेस्ट में 2011 में पदार्पण किया। कोहली अब तक भारत के लिए 239 वनडे, 77 टेस्ट और 70 टी-20 खेल चुके हैं। वनडे में उनके नाम 11520, टेस्ट में 6613 और टी-20 में 2369 रन दर्ज हैं।

भारतीय कप्तान विराट कोहली। फाइल

कोटला में होगा विराट के नाम का स्टैंड

नई दिल्ली, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली की शानदार उपलब्धियों को देखते हुए दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने फिरोजशाह कोटला मैदान का एक स्टैंड का नाम भारतीय कप्तान कोहली के नाम पर रखने का फैसला किया है। दिल्ली के दो अन्य पूर्व खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी और मोहिंदर अमरनाथ के नाम पर भी कोटला में स्टैंड हैं, लेकिन उन्हें यह सम्मान उनके संन्यास लेने के बाद मिला।

कोहली सबसे युवा सक्रिय क्रिकेटर हैं, जिनके नाम पर स्टैंड का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। डीडीसीए अध्यक्ष रजत शर्मा ने कहा, 'विश्व कप में विराट कोहली के शानदार योगदान ने डीडीसीए को गौरवान्वित किया है। कई उपलब्धियां और कप्तानी में रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें उन्हें सम्मानित करने में खुशी होगी।' वीरेंद्र सहवाग और अंजुम चोपड़ा दिल्ली के दो अन्य क्रिकेटर हैं, जिनके नाम पर कोटला में गेट हैं, जबकि हॉल ऑफ फेम को पूर्व भारतीय कप्तान एमएके पटौदी का नाम दिया गया है। साथ ही डीडीसीए भारतीय टीम के सदस्यों को 12 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सम्मानित करेगा। उन्होंने कहा, 'यादों को सहेजने के लिए डीडीसीए एक स्टैंड का नाम उनके नाम पर रखना चाहता है। मुझे यकीन है कि 'विराट कोहली स्टैंड' दिल्ली के युवा क्रिकेटर के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। हमें खुशी है कि टीम इंडिया का कप्तान ही दिल्ली का खिलाड़ी नहीं है।

सोशल मीडिया पर कोहली के सर्वाधिक फॉलोअर

नई दिल्ली, आइएएनएस : विराट कोहली सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों की सूची में पहले नंबर पर हैं। ताबड़तोड़ रन बनाने के अलावा कोहली सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहते हैं। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनके तीन-तीन करोड़ से अधिक फॉलोअर हैं। इस सूची में सचिन तेंदुलकर दूसरे नंबर पर आते हैं। उनके ट्विटर पर तीन करोड़ से अधिक, फेसबुक पर 2.8 करोड़ और इंस्टाग्राम पर 1.65 करोड़ फॉलोअर हैं। एमएस धौनी सोशल मीडिया पर उतने सक्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी वह तीसरे पायदान पर मौजूद हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 1.54 करोड़, ट्विटर पर 77 लाख और फेसबुक पर 2.05 करोड़ फॉलोअर हैं। रोहित शर्मा के तीनों प्लेटफॉर्म पर एक करोड़ से अधिक फॉलोअर हैं। सुरेश रैना के ट्विटर पर 1.67 करोड़, इंस्टाग्राम पर 90 लाख और फेसबुक पर 31 लाख फॉलोअर हैं। युवराज सिंह ट्विटर पर 47 लाख, इंस्टाग्राम पर 75 लाख और फेसबुक पर 1.4 करोड़ फॉलोअर हैं, जबकि पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह के ट्विटर पर 1.01 करोड़, इंस्टाग्राम पर 36 लाख और फेसबुक पर 66 लाख फॉलोअर हैं।

जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को तीन पदक

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : भारतीय पहलवान सचिन राणा को एस्टोनिया की राजधानी ताल्लिन में जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की ग्रीको रोमन स्पर्धा के रेपेचेज दौर में रविवार को हार का सामना करना पड़ा, जिससे टूर्नामेंट में भारत का सफर तीन पदक के साथ खत्म हुआ। राणा के सामने 60 किग्रा में रेपेचेज दौर में जॉर्जिया के डिएगो चख्वादजे की चुनौती थी। चख्वादजे ने भारतीय पहलवान को 5-1 से हराया।

ग्रीको रोमन में सिर्फ साजन भानवाल ही भारत के लिए कांस्य पदक जीत पाए। उन्होंने शनिवार को तुर्की के अब्दुररहमान कालकन को 77 किग्रा में तकनीकी दक्षता से हराया था।

बदलूंगा पदक का रंग : विक्की चाहर

नई दिल्ली : भारत के फ्री स्टाइल के पहलवान विक्की चाहर ने कहा कि वह भले जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत पाए लेकिन वह आगामी टूर्नामेंटों में पदक का रंग जरूर बदल देंगे। विक्की ने कहाकि मुझे इस चैंपियनशिप में स्वर्ण की उम्मीद थी।

सेना के साथ समय बिताकर वापस आए धौनी

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी टेरिटोरियल आर्मी यूनिट के साथ समय बिताकर वापस लौट आए हैं। धौनी फिलहाल, अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ नई दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद ब्रेक लेकर दो सप्ताह के लिए जम्मू में 106 टीए बटालियन (पैरा) के साथ समय बिताया। टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि पा चुके धौनी ने 15 अगस्त को अपनी ड्यूटी समाप्त की।

काफी मेहनत के बाद अब मेरा अपने जूतों को टांगने का समय आ गया है। जिंदगी के अगले सफर की शुरुआत जल्द।
–एश्ले कोल, इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर

बेल की मौजूदगी में रीयल ने सेल्टा को हराया

फुटबॉल डायरी ▶ ला लीगा सत्र के अपने पहले मैच में 3–1 से जीती जिदान की टीम

गोल करने के बाद क्रूस को बधाई देते गेरेथ बेल। एएफपी

बेंजमा, क्रूज और वाज्क्यूज ने दागे गोल

विगो (स्पेन), आइएएनएस : स्पेनिश फुटबॉल क्लब रीयल मैड्रिड ने ला लीगा के मौजूदा सत्र के अपने पहले मुकाबले में सेल्टा विगो को 3-1 से हरा दिया। इस दौरान रीयल के स्टार गेरेथ बेल को शुरुआती लाइन-अप में जगह मिली और उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। काफी समय से बेल के क्लब छोड़ने की खबरें चल रही हैं जिसके बाद रीयल के मैनेजर जिनेदिन जिदान ने पहले ही कह दिया था कि बेल उनकी भविष्य की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं। हालांकि, इस मुकाबले के जरिये एक बार फिर उन्होंने अपने मैनेजर का भरोसा जीत लिया है।

खेल के 12वें मिनट में बेल के शानदार क्रॉस पर करीम बेंजमा ने रीयल को बढ़त दिलाई। हाफ टाइम के कुछ समय बाद ही 55वें मिनट में रीयल के स्टार लुका मॉड्रिक को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर किया गया, लेकिन 61वें मिनट में टॉनी क्रूज ने बॉक्स के बाहर से एक दमदार किक पर गोल करके रीयल को राहत दिलाई। वहीं 80वें मिनट में स्थानापन्न लुकास वाज्क्यूज ने गोल करके रीयल को 3-0 से आगे कर दिया। सेल्टा विगो की ओर से इंजुरी टाइम में 18 वर्षीय आइकर लोसादा ने इकलौता गोल दागा। हालांकि हाफ टाइम से ठीक पहले सेल्टा विगो के ब्रैस मेंडेज ने एक गोल दागा, लेकिन रेफरी ने उनके ऑफ साइड होने की वजह से गोल को अयोग्य करार दिया। हाल ही में क्लब से जुड़े चोटिल ईडन हैजार्ड की जगह बेल को मैदान में उतरा गया और उन्होंने अपने खेल से प्रभावित किया। जिदान ने उन्हें प्री-सीजन के कई मुकाबलों से बाहर रखा था, जिसके बाद उनके रीयल को छोड़ने की खबरों को बल मिला था। मैच के बाद रीयल के स्टार मिडफील्डर कासेमिरो ने अपने साथी खिलाड़ी बेल की जमकर सराहना की और उन्हें एक महान खिलाड़ी बताया।

भारत की अंडर-19 टीम जीती

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुमित राठी द्वारा 78वें मिनट में किए गए गोल की बदौलत रविवार को भारत की अंडर-19 राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने पोर्ट विला में चल रहे ओएफसी डेवल्पमेंटल टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में मेजबान वनुआतू को 1-0 से हरा दिया। भारतीय टीम के कोच फ्लोयड पिंटो ने डिफेंस में चार खिलाड़ियों को खिलाने का फैसला किया, जबकि अमन छेत्री को आगे खिलाने का फैसला किया। अब भारतीय टीम अपने अगले मुकाबले में बुधवार को न्यू कैलेडोनिया से भिड़ेगी।

उलटफेर का शिकार हुए जोकोविक

- सिनसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में मेदवेदेव से मिली शिकस्त
- खितावी मुकाबले में मेदवेदेव का सामना गोफिन से होगा

सिनसिनाटी, एएफपी : विश्व के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविक को यहां जारी सिनसिनाटी मास्टर्स के सेमीफाइनल में उलटफेर का शिकार होना पड़ा। जोकोविक को रूस के डेनिल मेदवेदेव ने तीन सेटों तक चले एक कड़े मुकाबले में 3-6, 6-3, 6-3 से पराजित किया।

सर्बियाई खिलाड़ी ने पिछले साल इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था, लेकिन इस बार वह अपने शानदार फॉर्म को दोहराने में कामयाब नहीं हो पाए। इससे पहले, मेदवेदेव ने इस साल हुए मोंटे कार्लो मास्टर्स में जोकोविक को मात दी थी। अंतिम चार के मुकाबले से पहले जोकोविक को दायें हाथ में चोट लगी थी, लेकिन मेदवेदेव के खिलाफ उन्होंने शानदार शुरुआत की। पूरे मैच में जोकोविक ने कुल 14 एस लगाए। पहला सेट उन्होंने 6-3 से अपने नाम किया और ऐसा लगा कि वह आसानी से फाइनल में जगह बना लेंगे। दूसरे सेट को जीतकर रूसी खिलाड़ी ने वापसी की। जोकोविक तीसरे सेट में फॉर्म में नजर नहीं आए और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। फाइनल में मेदवेदेव का सामना बेल्जियम के डेविड गोफिन के खिलाफ होगा। गोफिन ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस के रिचर्ड गास्केट को 6-3, 6-4 से शिकस्त देकर पहले एटीपी मास्टर्स 1000 फाइनल में प्रवेश किया। गत चैंपियन जोकोविक जुलाई में विंबलडन खिताब जीतने के बाद पहला टूर्नामेंट खेल रहे थे। मैच के बाद विश्व के आठवें नंबर के खिलाड़ी मेदवेदेव ने कहा, 'मैं पहले सेट में काफी थक गया था। मुझे लगा कि मैं कोर्ट पर तेजी से नहीं खेल पाऊंगा। इसके बाद दूसरे सेट में मैंने कुछ बदलाव किया और फिर खेल अपने आप शानदार हो गया।' 23 वर्षीय मेदवेदेव लगातार तीसरी बार किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। इससे पहले वह वाशिंगटन में निक किर्गियोस, जबकि मांट्रियल टूर्नामेंट में राफेल नडाल से हार गए थे। वहीं, जोकोविक ने कहा, 'मेदवेदेव ने काफी अच्छा टेनिस खेला। दूसरे सेट में वह 4-3 से आगे था। वह शीर्ष-पांच में आने के लिए अपने तरीके से काम कर रहा है। मैं एक टेनिस मैच गंवाया और इसमें कुछ गलत नहीं है।'

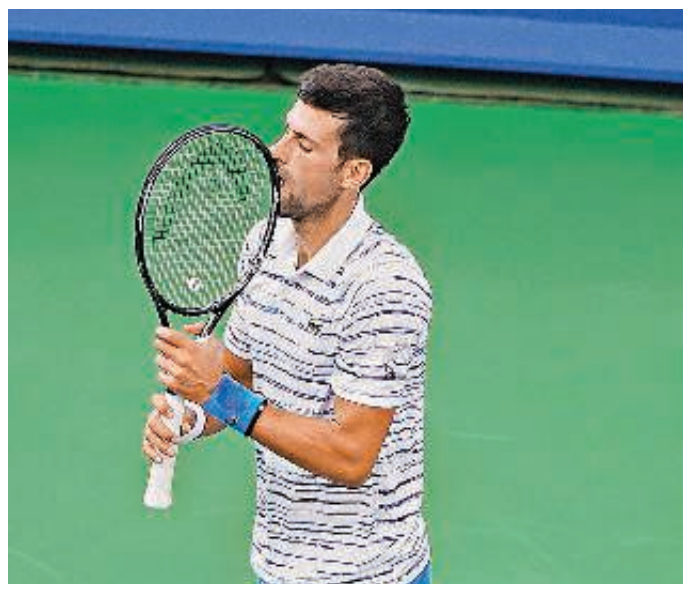

हार के बाद निराश नोवाक जोकोविक। एपी

भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया संग खेला ड्रॉ

टोक्यो, प्रेट्र : भारतीय महिला हॉकी टीम ने दो गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए रविवार को यहां ओलंपिक टेस्ट इवेंट के राउंड रोबिन लीग मैच में दुनिया की दूसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया को 2-2 से ड्रॉ पर रोका। टूर्नामेंट के दूसरे मैच में भारत के लिए वंदना कटारिया (36वें मिनट) और गुरजीत कौर (59वें मिनट) ने गोल किए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैटलिन नोब्स ने 14वें और ग्रेस स्टीवर्ट ने 43वें मिनट में गोल दागे। भारत ने शनिवार को पहले मैच में मेजबान जापान को 2-1 से शिकस्त दी थी।

दुनिया की 10वें नंबर की भारतीय टीम ने आक्रामक तरीके से मैच की शुरुआत की। उसने ऑस्ट्रेलिया की आक्रामक हॉकी जैसा ही खेल दिखाया, जिससे दोनों टीमों ने पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए। हालांकि, दोनों ही गोल नहीं कर सकीं। लेकिन, 14 वें मिनट में भारतीय डिफेंडर ने गोल पर एक शॉट रोक दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी स्ट्रोक दिया गया। नोब्स ने गोल कर टीम को 1-0 से बढ़त दिलाने में कोई गलती नहीं की। दुनिया की दूसरे नंबर की टीम दूसरे क्वार्टर में पूरी तरह से हावी रही और कई पेनाल्टी कॉर्नर हासिल कर भारतीय टीम को दबाव में ला दिया। भारतीय गोलकीपर सविता ने कई अच्छे बचाव किए, जिससे हाफटाइम तक ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे रही। तीसरे क्वार्टर में फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम का दबदबा रहा और पेनाल्टी कॉर्नर के जरिये गोल करने के कुछ मौके बनाए, पर सविता ने फिर शानदार बचाव किए। वंदना ने 36 वें मिनट में बराबरी का गोल दागा, पर ऑस्ट्रेलिया ने 43 वें मिनट में ग्रेस स्टीवर्ट के गोल की बदौलत स्कोर 2-1 से कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने मजबूत वापसी करने की कोशिश की। टीम ने 59 वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया।

सुनहरी चाहत के साथ विश्व चैंपियनशिप में उतरेंगीं सिंधू

- आज से बासेल में शुरू हो रही है विश्व चैंपियनशिप
- फाइनल की फिसलन से पार पाने की कोशिश में उतरेंगी पीवी

बासेल (स्विट्जरलैंड), प्रेट्र : दो बार की रजत पदक विजेता भारत की दिग्गज महिला शटलर पीवी सिंधू सोमवार से शुरू होने वाली बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने की चाहत लिए एक बार फिर कोर्ट पर उतरेंगीं।

सिंधू पिछले कुछ वर्षों में विश्व चैंपियनशिप में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं, जहां उन्होंने लगातार दो रजत और इतने ही कांस्य पदक हासिल किए हैं, लेकिन अब तक स्वर्ण पदक अपने नाम नहीं कर पाई हैं। 24 वर्षीय भारत की शीर्ष खिलाड़ी हमेशा विश्व चैंपियनशिप में अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म हासिल करने में सफल रही हैं, लेकिन दो बार उन्हें खिताबी मुकाबले में शिकस्त मिली है। वह 2017 में 110 मिनट तक चले मुकाबले में जापान की नोजोमी ओकुहारा से हार गई थीं, जबकि 2018 के फाइनल में उन्हें स्पेन की ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन ने हराया था। पांचवीं वरीयता प्राप्त सिंधू पिछले महीने इंडोनेशिया ओपन में उप विजेता रहीं और प्रतिद्वंद्वियों को पस्त करने के लिए अपनी फिटनेस और डिफेंस पर काम कर रही हैं।

पहले दौर में सिंधू को बाई मिली है और वह अपने अभियान की शुरुआत चीनी ताइपे की पाई यू पो और बुल्गारिया की लिंडा जेचिरी के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता के खिलाफ करेंगी। सिंधू ने कहा कि मैं अपने डिफेंस, शारीरिक फिटनेस और कोर्ट के अंदर के कौशल पर भी काम कर रही हूं। मैंने कड़ी मेहनत की है और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकती हूं। मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा, लेकिन मुझ पर कोई दबाव नहीं है। अगर वह जीत जाती हैं तो तीसरे दौर में अमेरिका की बेवन झांग से उनका सामना हो सकता है जबकि क्वार्टर फाइनल में वह चीनी ताइपे की ताई जु यिंग के सामने हो सकती हैं। अगर सिंधू शुरुआती बाधा पार कर जाती हैं तो सेमीफाइनल में वह हमवतन साइना नेहवाल से भिड़ सकती हैं। विश्व चैंपियनशिप में रजत और कांस्य पदक जीतने वाली आठवीं वरीय साइना को भी पहले दौर में बाई मिली है और उनकी पहली भिड़ंत स्विट्जरलैंड की सबरीना जाकेट और नीदरलैंड्स की सोराय डे विक एजबर्गन के बीच होने वाले मैच की विजेता से होगी। अगले दौर में उनके डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट से भिड़ने की संभावना है। क्वार्टर फाइनल में साइना का सामना चीन की चेन यू फेई से होने की उम्मीद है, जिन्होंने साल की शुरुआत में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप हासिल की थी। पुरुष सिंगल्स में पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत घुटने की समस्या से उबरने के बाद अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। वह मार्च में इंडिया ओपन के फाइनल में पहुंचे थे। वह 2018 की तरह इस चरण में भी अपने शुरुआती मुकाबले में आयरलैंड के नॉट एनगुयेन के सामने होंगे। कंधे की चोट से परेशान समीर वर्मा भी ड्रॉ में उसी हाफ में हैं, जिसमें श्रीकांत हैं और वह अपने अभियान की शुरुआत सिंगापुर के लोह कीन ययू के खिलाफ करेंगे। स्विस ओपन के फाइनल तक पहुंचने वाले बी साई प्रणीत का सामना पहले दौर में कनाडा के जेसन एंथनी हो-श्यू से होगा, जबकि एचएस प्रणय शुरुआती दौर में फिनलैंड के ईटू हीनो से भिड़ेंगे। डबल्स में सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष जोड़ी ने चोट की वजह से इस प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया है जिन्होंने हाल ही में बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 सीरीज का खिताब जीता था।

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू। फाइल

विविध

अब कृषि शिक्षा में क्रांति लाएगा पंत विवि

'जय हिंद' प्रोग्राम के तहत डिजिटल शिक्षा ग्रहण करेंगे कृषि के परास्नातक छात्र

सुरेंद्र कुमार वर्मा, पंतनगर

कृषि शिक्षा के तीन प्रमुख संस्थानों जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विवि, हिसार और पंजाब कृषि विवि, लुधियाना ने ब्लैक बोर्ड शिक्षण को वर्चुअल शिक्षण में बदलने के लिए हाथ मिलाया है, जिससे देश में कृषि शिक्षा की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी।

उच्च कृषि शिक्षा में छात्रों को प्रेरित करने एवं पारंगत बनाने के लिए तीन कृषि विश्वविद्यालयों की संयुक्त पहल पर अभिनव प्रोग्राम 'जय हिंद-ज्वाइंट इनीशिएटिव ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया फॉर होनिंग एंड इंस्पायरिंग एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स अंडर न्यू डाइमेंशंस' तैयार किया गया है। देश में यह पहली बार है, जब किसी डिग्री प्रोग्राम के नियमित पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है। व्याख्यान किसी एक विवि में विषय विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा, जबकि अन्य विवि के छात्रों को वर्चुअल क्लासेज के माध्यम से लाइव प्राप्त होगा।

पंतनगर विवि के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अजीत नैन ने बताया कि जय हिंद विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध साझा बौद्धिक संसाधनों पर निर्भर करेगा। इसके लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए तीन विवि के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की पहचान की जाएगी। बताया कि शुरुआत में इस प्लेटफार्म से तीन-चार कोर्स शैक्षणिक सत्र 2019-20 के पहले सेमेस्टर से शुरू करने का प्रयास है। पंतनगर विवि में आभासी कक्ष सुविधाओं से लैस समन्वय सेल की स्थापना की गई है। जहां लाइव प्रसारित होने वाले ऑडियो-वीडियो व्याख्यान रिकॉर्ड भी किए जाएंगे और वेबसाइट पर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे।

कुलपतियों ने बताया समय की जरूरत : पंतनगर विवि के कुलपति डॉ. तेज प्रताप ने कहा कि संकाय संसाधनों में तेजी से कमी एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल के कारण छात्रों को नवीनतम कौशल और ज्ञान से लैस करने की आवश्यकता बढ़ गई है। यह तभी संभव है जब विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के संकाय संसाधनों को नवीनतम तकनीकी का उपयोग करके एकीकृत किया जाए। इस नवाचार को कृषि मौसम विज्ञान विषय में लागू किया जा रहा है और धीरे-धीरे अन्य विषयों में ले जाया जाएगा। हरियाणा कृषि विवि के कुलपति डॉ. केपी सिंह ने कहा कि जय हिंद की पहल कृषि शिक्षा को ब्लैकबोर्ड शिक्षण से डिजिटल शिक्षण में बदल देगी।

पाठ्यक्रमों का चयन

समान नाम और सामग्री वाले पाठ्यक्रमों को पायलट अध्ययन के रूप में चुना जाएगा। पीजी और पीएचडी के दो-तीन पाठ्यक्रमों को प्रारंभिक रूप से चुना जाएगा और धीरे-धीरे सभी पाठ्यक्रमों को वर्चुअल क्लास रूम सुविधा के माध्यम से कवर किया जाएगा।

पाठ्यक्रम आवंटन

छात्रों की प्रतिक्रिया एवं शिक्षकों के योगदान के आधार पर तीन विश्वविद्यालयों से प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक प्रमुख शिक्षक का चयन किया जाएगा। एक-एक सहयोगी शिक्षक अन्य दो विश्वविद्यालयों के संलग्न किए जाएंगे। प्रमुख शिक्षक एवं सहयोगी पाठ्यक्रम शिक्षक एक साथ कक्षाओं और उपस्थिति की व्यवस्था करेंगे।

प्रसारण के दौरान व्याख्यान को समुचित रूप से ग्रहण करने एवं उपस्थिति व अनुशासन बनाए रखने के लिए सहयोगी शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। आने वाले समय में परीक्षा का प्रश्न पत्र समान होगा एवं मूल्यांकन विश्वविद्यालयों की वर्तमान पद्धति के अनुसार होगा।

अबकी पूजा मंडपों में गूंजेंगे रानू के गीत

जागरण संवाददाता, कोलकाता : लता मंगेशकर का गीत 'एक प्यार का नगमा है' गाकर लोकप्रिय हुईं रानू मंडल के गीत अब पूजा मंडपों में गूंजते सुनाई देंगे।

संगीत का शौक रखने वाले शहर के ही चाय विक्रेता विजय शील और पत्रकार प्रीतम दे ने रविवार को स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड किए। वहीं रानू को उम्मीद है कि पूजा की थीम पर गाए गए उनके गीत को सभी पसंद करेंगे। दरअसल, हाल ही में रानाघाट की रानू मारिया मंडल का संगीत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद लगातार उन्हें ऑफर मिल रहे हैं और बंगाल में तो उनका क्रेज देखते बन रहा है। लता मंगेशकर के गीत 'एक प्यार का नगमा है' से लोकप्रिय हुई रानाघाट की रानू ने एक क्लब के लिए खुद का गाना गाने का मौका।

इस गीत की खास बात यह है कि इसकी धुन एक चायवाले ने तैयार किया है, जो पिछले लंबे समय से रवींद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन के बाहर चाय बेचता है।

तीन दिन में नहीं आया तो कौशल को लाने में लग सकते हैं छह महीने

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

गैंगस्टर कौशल को दुबई पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की सूचना के बाद फरीदाबाद और गुरुग्राम की पुलिस टीमें वहां पहुंच गई हैं। फरीदाबाद से इंस्पेक्टर विमल और इंस्पेक्टर संदीप मोर पहुंचे हैं। वहां कौशल को भारतीय पुलिस को सौंपे जाने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। फरीदाबाद पुलिस के अधिकारियों के अनुसार यदि गैंगस्टर को दो या तीन दिन के अंदर हमारी टीम को सौंप दिया गया तो ठीक है। देरी हुई तो यह छह महीने तक खिंच सकती है।

दरअसल, दुबई से किसी भारतीय अपराधी को लाने के लिए दो तरीके हैं। इनमें एक तरीका वहां की पुलिस सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर गैंगस्टर को भारतीय पुलिस अधिकारियों को सौंप दे। यह आसान तरीका है। इसमें दो या तीन दिन का समय लगेगा। यदि कोई अपराधी या उससे संबंधित कोई मामला देश-विदेश की मीडिया में ज्यादा सुर्खियों में नहीं है तो यह तरीका अपनाया जाता है। यह तरीका दोनों देशों की पुलिस के आपसी समझ और सामंजस्य पर आधारित है। वहीं, अगर दुबई की पुलिस प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया अपनाती है तो इसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय दूतावास के माध्यम से दुबई सरकार को सूचित करेगा। इसके बाद एक अधिकारी की नियुक्ति प्रत्यर्पण के लिए लगाई जाएगी। वह अधिकारी अरेस्टिंग वीजा पर दुबई जाएगा। वहां दूतावास और विदेश मंत्रालय के माध्यम से दुबई प्रशासन आरोपित को भारतीय अधिकारी को सौंपेगा। तब उसे भारत लाया जा सकेगा। इस बीच आरोपित वहां अदालत में भी अपील कर सकता है। तब अदालत से मंजूरी के बाद ही गैंगस्टर को लाया जा सकता है। इसमें दो महीने से लेकर छह महीने तक का वक्त लग सकता है।

कौशल को पकड़ने की प्रक्रिया में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि आरोपित को शुक्रवार को ही दुबई में डिटेन कर लिया गया था। इसकी सूचना उन्हें मिल गई थी। वे सूचना को पूरी तरह सीक्रेट रखकर काम कर रहे थे ताकि मामला सुर्खियों में न आए और कौशल को चुपचाप भारत ले आएं। मगर सोशल मीडिया के माध्यम से यह सूचना लीक हो गई व भारतीय मीडिया में चल गई। इससे अब इस बात की संभावना ज्यादा है कि दुबई सरकार प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया अपनाए।

दुबई में नरेश यादव बन कर रहता था कौशल

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : हरियाणा के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कौशल ने साल 2015 में ही विदेश भागने की योजना बना ली थी। सूत्रों के मुताबिक साल 2015 तक कई बड़ी वारदातों को अंजाम देकर वह पुलिस की नजर में आ गया था। दो साल तक वह शांत रहा और छोटी-मोटी वारदातों को अंजाम दिया। इस दौरान वह विदेश भागने की तैयारी करता रहा। बीच में कुछ दिन वह थाईलैंड घूमकर आया। वहां उसने विभिन्न जगहों पर मोबाइल में अपनी फोटो ले लीं। वहां से सिम भी ली। इसके बाद वापस भारत लौट आया। यहां जयपुर से फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया। नए पासपोर्ट में उसने अपना नाम नरेश यादव रखा। इसी पासपोर्ट से वह दुबई पहुंच गया।

गूगल मैप की मदद से पुलिस ने बच्ची के परिजनों को ढूंढा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पश्चिमी जिला पुलिस ने चार महीने पहले लापता हुई 12 साल की बच्ची को गूगल मैप की मदद से परिजनों से मिला दिया। पुलिस के अनुसार बच्ची की मानसिक हालत ठीक नहीं है।

पुलिस के अनुसार, बीती 21 मार्च को बच्ची मेट्रो स्टेशन जाने के लिए कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट के पास ई-रिक्शा में बैठी। मेट्रो स्टेशन पर नहीं उतरी तो चालक बच्ची को रात साढ़े आठ बजे कीर्तिनगर पुलिस थाने ले गया। थाने में बच्ची ने सिर्फ इतना बताया कि वह खुर्जा गांव से है और पिता का नाम जीतन है। पुलिस ने खुर्जा से मिलते-जुलते खजूरी खास और खुरेजी इलाके से जानकारी जुटाई, लेकिन जानकारी नहीं मिली। पुलिस बच्ची को कीर्तिनगर स्थित पुनर्वासित कॉलोनी ले भी गई, लेकिन प्रयास विफल रहे। पुलिस लड़की को लेकर कई बार बुलंदशहर स्थित खुर्जा गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इसी बीच 31 जुलाई को लड़की ने बताया कि उसके गांव के पास की एक जगह का नाम शकापुर व सोनबरसा है। पुलिस ने गूगल मैप में शकापुर व सोनबरसा सर्च किया। पुलिस के अनुसार, ये जगहें उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर इलाके में हैं।

शिक्षक का तबादला, फूट-फूटकर रो पड़े बच्चे

नईदुनिया, कटनी

गुरु को भगवान का दर्जा देने वाले देश में अब ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं, जब शिक्षक के तबादले पर दुखी बच्चे रोने लगें। लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक गांव में ऐसा ही हुआ। जब उन्हें पता चला कि उनके प्रिय शिक्षक का तबादला हो गया है तो वे उनसे लिपटकर रोने लगे। शिक्षक ने उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन बच्चों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। छात्र-छात्राओं को रोता देखकर शिक्षक की आंखें भी भर आईं।

यह दृश्य शनिवार का है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। ढीमखेड़ा तहसील के तिलमन गांव के सरकारी माध्यमिक स्कूल के शिक्षक मंगलदीन पटेल 17 साल से यहां बच्चों को पढ़ा रहे थे। शनिवार को उनके तबादले की सूचना मिली तो बच्चे रो पड़े। बच्चों को रोते देख आंसू भरी आंखों के साथ मंगलदीन उनसे बोले कि वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। यह सब यूं ही नहीं था। छठी के छात्र शिवराज ने बताया कि पटेल मास्साब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। छात्र अभयराज सिंह ने बताया कि पढ़ाने का तरीका इतना सरल था कि सब समझ में आ जाता था। मंगलदीन की छात्रों को पढ़ाने की रुचि का नतीजा ही था कि 2017 में जूनियर ओलिंपियाड परीक्षा में जिले से सिर्फ इसी तिलमन गांव के स्कूल के 11 छात्र पास हुए थे। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य के लिए मंगलदीन को तत्कालीन राज्यपाल आनंदी बेन और कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने सम्मानित किया था।

शिक्षक से लिपटकर रोते बच्चे। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो ग्रैब

डीएमआरसी की इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत

जागरण संवाददाता, नोएडा : दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) के सेक्टर 62 स्थित दफ्तर में कार्यरत इंजीनियर स्वाति (26) की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। रविवार सुबह पति उन्हें लेकर निजी अस्पताल पहुंचे जहां डाक्टरों ने मृत घोषित किया। करीब दो वर्ष पहले ही युवती की शादी हुई थी और वह गर्भवती थीं। कोतवाली सेक्टर 49 पुलिस मौके पर पहुंची व शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

अस्पताल प्रबंधन की तरफ से पुलिस को बताया गया कि महिला के पति ने फंदा लगाने की जानकारी दी है। इस मामले में इंजीनियर युवती की मां ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर दहेज के लिए प्रताड़ित करने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि मूलरूप से रोहतक की रहने वाली स्वाति की करीब दो वर्ष पहले बुलंदशहर के रहने वाले अजय राघव से शादी हुई थी। स्वाति डीएमआरसी में इंजीनियर थी तो पति अजय दिल्ली स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत है। दोनों सेक्टर 51 केन्द्रीय विहार सोसायटी के बी ब्लाक स्थित एक फ्लैट में रह रहे थे। स्वाति करीब चार माह की गर्भवती थीं।

मौसम विशेष

पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान तथा दिल्ली में वर्षा में कमी आएगी। दिन के तापमान में वृद्धि होगी। बदलीयुक्त आसमान के साथ मौसम गर्म रहेगा। एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा संभव है। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में वर्षा में कमी आएगी। मौसम आरामदायक रहेगा।

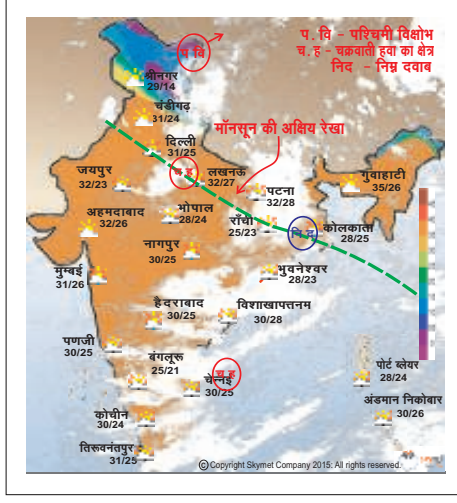

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	32/26/व	अहमदाबाद	35/25/आंबा
कोलकाता	30/25/व	बड़ोदा	32/25/व
चेन्नई	33/27/व	नागपुर	27/23/आंबा
हैदराबाद	33/24/व	इन्दौर	28/23/आंबा
बंगलूरू	26/21/व	रांची	31/25/व
त्रिवेन्द्रम	31/25/व	पटना	33/27/व
गुवाहाटी	29/25/व	जमशेदपुर	32/26/आंबा
शिलांग	15/09/व	पुणे	25/22/व

ईस्ट इंडिया कंपनी ने रुपये का पहला सिक्का बनाया

1757 में आज ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में रुपये का पहला सिक्का बनाया था। बंगाल के नवाब के साथ एक संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने टकसाल खोला था। यह वह जगह होती है, जहां रुपये और सिक्के बनाये जाते हैं।

अफगानिस्तान को ब्रिटेन से आजादी मिली

तीसरे एंगोल-अफगान युद्ध के बाद ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर के बाद 1919 में आज ही अफगानिस्तान को ब्रिटेन से पूरी तरह से आजादी मिली थी। हालांकि अफगानिस्तान कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। फिर भी दोनों देशों के बीच तीन युद्ध हुए।

सादगी की मिसाल सुधा मूर्ति को जन्मदिन मुबारक हो

देश की बड़ी आइटी कंपनी इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी और इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति का जन्म 1950 में आज ही कर्नाटक में हुआ था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता कंपनी टेल्को में काम पर करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर बनीं। इन्होंने कई अनाथालयों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। वह एक प्रभावशाली लेखिका भी हैं। वह मराठी, कन्नड और अंग्रेजी में लिखती हैं। 2006 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया।

इधर-उधर की

महिलाओं का दिल टूटने से बचाएगी सरकार

डोडोमा, एजेंसी : तंजानिया के सबसे बड़े शहर दार-अस-सलाम के गवर्नर ने महिलाओं का 'दिल टूटने' से बचाने के लिए विवाहित पुरुषों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने और उसे प्रकाशित करने की योजना की घोषणा की है। रीजनल कमिश्नर के मुताबिक महिलाओं से काफी शिकायतें मिली हैं, जिन्हें शादी के प्रस्ताव के बाद उनके प्रेमियों द्वारा छोड़ दिया गया। इस योजना को परवान चढ़ाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय आयुक्त कार्यालय में एक डाटाबेस स्थापित किया जाएगा। इसमें उन सभी पुरुषों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जो महिलाओं से शादी का वादा करते हैं। डाटाबेस में महिलाएं यह देख सकेंगी कि शादी का वादा करने वाला पुरुष विवाहित है या नहीं।

जलवायु परिवर्तन की भेंट चढ़ गया ग्लेशियर 'ओकजोकुल'

- आइसलैंड के पश्चिम में स्थित 'ओकजोकुल' अब ग्लेशियर नहीं रहा
- ग्रीन हाउस गैसों के लगातार उत्सर्जन से तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर

16 वर्ग किमी तक बर्फ फैली थी 'ओकजोकुल' में वर्ष 1890 में, 2012 में यह मात्र 0.7 वर्ग किमी में बची थी

40 से 50 मीटर तक बर्फ की चौड़ाई होनी चाहिए एक जीवित ग्लेशियर के लिए

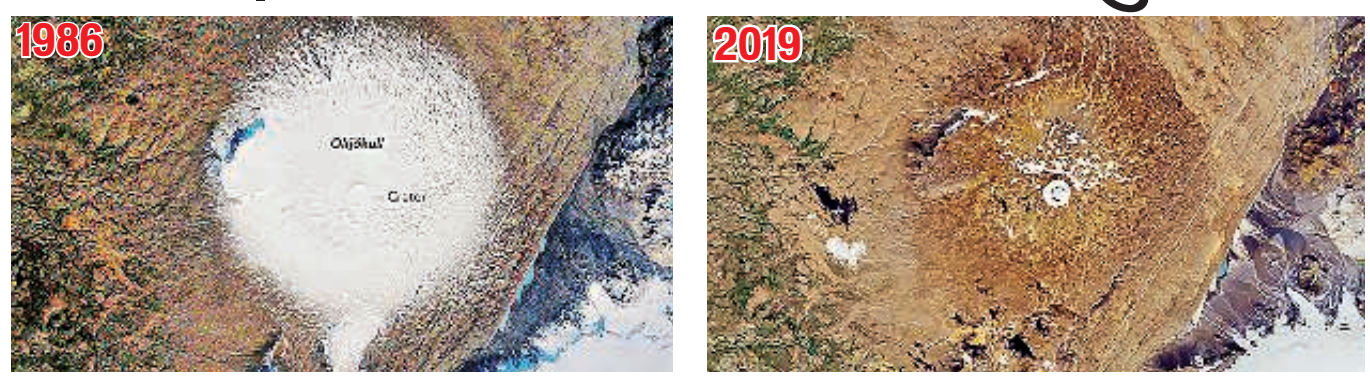

पहली तस्वीर नासा द्वारा सात सितंबर 1986 को खीचीं गई थी। दूसरी तस्वीर नासा द्वारा एक अगस्त 2019 को ली गई। 23 वर्षों में यहां बर्फ का एक-एक कतरा पिघल गया। एएफपी

रेक्जाविक, एएफपी : जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तरी पश्चिमी यूरोप के द्वीप आइसलैंड के पश्चिम में स्थित ग्लेशियर 'ओकजोकुल' ने अपनी पहचान खो दी है। जी हां 'ओकजोकुल' अब ग्लेशियर नहीं रहा, उसने अपना यह दर्जा खो दिया है। यहां एक समारोह में कांस्य पट्टिका का अनावरण किया जाएगा, जिसमें इसकी वर्तमान स्थिति बयां करने के साथ ही बाकी ग्लेशियर के भविष्य को लेकर भी आगाह किया गया जाएगा।

इस पर लिखा होगा, 'ओक' अपना ग्लेशियर का दर्जा खोने वाला आइसलैंड का पहला ग्लेशियर है। आने वाले 200 वर्ष में हमारे सभी ग्लेशियरों का यही हाल होने की आशंका है। अब समय आ गया है कि हम देखें की क्या हो रहा है और क्या किए जाने की जरूरत है।' इसके साथ ही इस पट्टिका में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी लिखा होगा। जोकि यहां पर 415 पीपीएम है।

आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकोब्स्दोतिर, पर्यावरण मंत्री गुडमुंडुर इनगी गुडब्रांडसन और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त मेरी रॉबिंसन भी इस समारोह में शामिल होंगे। राइस यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर सायमीनी हावे ने जुलाई में ही इसकी स्थिति को लेकर आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी पहचान खोने वाला यह पहला ग्लेशियर होगा।

आइसलैंड में हर साल पिघल रही करोड़ों टन बर्फ : आइसलैंड द्वीप में हर साल करीब 1100 करोड़ टन बर्फ पिघल जाती है। शोधकर्ताओं ने चिंता जताई है कि वर्ष 2,200 तक यहां के 400 से अधिक ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। शोधकर्ताओं का कहना है कि हमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत जल्द रोकना होगा। उन्होंने बताया कि स्थिति इतनी विकट है कि यदि हम अभी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य कर दें फिर भी सामान्य स्थिति आने में एक से दो सदी लग जाएंगी।

'ओकजोकुल' में बहुत ही गायब हुई बर्फ : शोधकर्ताओं ने बताया कि आइसलैंड के ग्लेशियर 'ओकजोकुल' में जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ बहुत से तेजी से पिघली है। 1890 में यहां 16 वर्ग किलोमीटर तक बर्फ फैली थी, लेकिन 2012 तक आते-आते यहां मात्र 0.7 वर्ग किलोमीटर में ही बर्फ बची। आइसलैंड के मौसम विज्ञान कार्यालय की ओर से कहा गया कि 2014 में यह ग्लेशियर पूरी से मृत हो चुका था। ग्लेशियर की स्थिति के लिए यह जरूरी होता है कि यहां बर्फ की मोटाई 40 से 50 मीटर (130 से 165 फीट) तक होनी चाहिए। यह इतना मोटा होना चाहिए कि अपने आप खिसक सके।

2100 तक वैश्विक धरोहरों के आधे ग्लेशियर हो जाएंगे खत्म : इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा अप्रैल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ऐसे ही होता रहा तो दुनिया की लगभग आधी धरोहरें वर्ष 2100 तक अपने ग्लेशियरों को खो देंगी।

हेलो ! मैं चंद्रयान-2, शानदार चल रहा है मेरा सफर

संदेश ▸ स्पेस एजेंसी इसरो ने ट्विटर पर दी यान की सेहत की जानकारी

नई दिल्ली, एएनआइ : भारत का चंद्रयान-2 कदम दर कदम लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। यान ने धरती पर अपनी अच्छी सेहत और शानदार यात्रा के बारे में संदेश भेजा है। यान के संदेश में कहा गया है कि वह सात सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने रविवार को इस संबंध में आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। इसरो ने लिखा, 'हेलो ! मैं चंद्रयान-2 हूं, विशेष अपडेट के साथ। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अब तक का मेरा सफर शानदार रहा है और मैं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सात सितंबर को उतरूंगा। मैं कहां हूं और क्या कर रहा हूं, यह जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।' 22 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया चंद्रयान-2 अब तक अपनी कक्षा में छह बदलाव से गुजर चुका है। छठा बदलाव 14 अगस्त को किया गया था। इस बदलाव के जरिये यान को लुनार ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी

(एलटीटी) पर पहुंचा दिया गया था। इसके लिए यान के लिक्विड इंजन को 1203 सेकेंड के लिए चलाया गया था। एलटीटी वह पथ है, जिस पर बढ़ते हुए यान चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। इस प्रक्रिया को ट्रांस लुनार इंसर्शन (टीएलआइ) कहा जाता है। एलटीटी पर बढ़ते हुए 20 अगस्त को जब यान चांद के मुहाने पर पहुंचेगा, तब एक बार फिर लिक्विड इंजन चलाकर इसे चांद की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। इसके बाद यान को चांद की निकटतम कक्षा तक पहुंचाने के लिए कक्षा में चार बदलाव और किए जाएंगे। निकटतम कक्षा चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर पर होगी।

पिछले महीने हुआ था प्रक्षेपण : चंद्रयान-2 को 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी-मार्क 3 की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान-2 के तीन हिस्से हैं- ऑर्बिटर, लैंडर 'विक्रम' और रोवर 'प्रज्ञान'। ऑर्बिटर करीब सालभर चांद की परिक्रमा करते हुए प्रयोगों को अंजाम देगा। वहीं लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे। लैंडिंग के साथ ही भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक अमेरिका, रूस और चीन अपना यान चांद पर उतार चुके हैं। चंद्रयान-2 के लैंडर-रोवर चांद के जिस हिस्से पर उतरेंगे, वहां अब तक कोई यान नहीं पहुंचा है। 2008 में भारत ने आर्बिटर मिशन चंद्रयान-1 भेजा था। यान ने करीब 10 महीने चांद की परिक्रमा करते हुए प्रयोगों को अंजाम दिया था।

वाट्सएप को फेसबुक से जोड़ा गया

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : वाट्सएप अपने नवीनतम बीटा में अपडेट करते हुए एप्लीकेशन में 'वाट्सएप से फेसबुक' टैग को जोड़ रहा है। यह नवीनतम बीटा संस्करण एक हफ्ते से भी कम समय में आ जाएगा। यह सुविधा फेसबुक स्वामित्व वाले प्लेटफार्म द्वारा फिंगरप्रिंट लॉक के फीचर को लागू करने के बाद होगा। यह सुविधा एंड्रायड बीटा इस्तेमाल करने वालों को मिलेगी।

यह टैग वाट्सएप सेटिंग्स के तहत दिखाई देगा और यह फेसबुक के अपने क्षेत्र को चिन्हित करने का स्पष्ट संकेत है। एमएसपॉवरयूजर की शनिवार की रिपोर्ट के मुताबिक, फेसबुक ने इस एप को अलग रखा है, लेकिन कंपनी ने अपने एकीकृत प्लेटफार्म के सपने को छोड़ा नहीं है।

सोशल नेटवर्क कंपनी ने वाट्सएप को फरवरी 2014 में खरीदा था और यह सुनिश्चित किया कि लोग इस खरीद के बारे में जाने और यह उस दिशा में दूसरा कदम है। इस बीच जब फिंगरप्रिंट लॉक सुविधा सक्षम हो जाएगी तो लोग वाट्सएप को खोलने के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करेंगे।

वाट्सएप की अपडेट्स की खबर रखने वाली फैन वेबसाइट डब्ल्यूएबीटाइंफो ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा कि उपभोक्ता अभी भी वाट्सएप के लॉक होने पर कॉल का जवाब देने में सक्षम हैं।

दुनिया में सबसे अच्छी नींद लेते हैं भारत में रहने वाले लोग

नईदिल्ली, आइएएनएस : जब गुणवत्तापरक नींद लेने की बात होती है तो आश्चर्यजनक रूप से भारत शीर्ष पर आ गया है। भारत एक एसा देश है जहां लोगों को रात में सबसे अच्छी नींद मिलती है। भारत के बाद सऊदी अरब और चीन हैं।

फिलिप्स की ओर से ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म केजीटी ग्रुप द्वारा इस सर्वे को अंजाम दिया गया है। यह सर्वे 12 देशों में किया गया है। इसमें 18 वर्ष की ऊपर के 11006 लोगों पर अध्ययन किया गया और पाया गया कि 62 प्रतिशत लोगों को लगता है कि जब वह बिस्तर पर जाते हैं तो उन्हें अच्छी नींद नहीं आती है। इस मामले में सबसे खराब स्थिति दक्षिण कोरिया और जापान की है। औसतन विश्व भर में लोग काम के दिनों में 6.8 घंटे सोते हैं तो वहीं वीकेंड पर एक घंटा ज्यादा सोते हैं।

26 फीसद लोगों का कहना है कि उनकी नींद में सुधार हुआ है तो 31 फीसद लोगों का मानना है कि उनकी नींद में कोई बदलाव नहीं आया है। दुनिया भर में नींद की गुणवत्ता घटने के शीर्ष पांच कारणों में तनाव (54 प्रतिशत), नींद का माहौल (40 प्रतिशत), काम या स्कूल का कार्यक्रम (37 प्रतिशत), मनोरंजन (36 प्रतिशत) और स्वास्थ्य की स्थिति (32 प्रतिशत) शामिल हैं।

स्पेक्ट्रम

अरुणाचल प्रदेश में मछली की पांच नई प्रजाति खोजी गईं

ईटानगर, प्रेट्र : अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अलग-अलग जिलों में मछली की पांच नई प्रजातियों की खोज की है। प्रदेश के दिबांग घाटी में दिबांग और सिनकिन नदी में मिली प्रजाति का वैज्ञानिक नाम मिस्टस प्रबीनी तो सुबनसिरी जिले की रंगा नदी में खोजी गई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम एक्सोस्टोमा कोट्टेलटी रखा गया है। इसके साथ ही तवांग जिले की तवांगचू नदी, दिबांग की लोहित नदियों में भी मछलियों की नई प्रजातियां खोजी गई हैं। शोधकर्ताओं की टीम का नेतृत्व यूनिवर्सिटी के जूलोजी विभाग के प्रोफेसर डीएन दास ने किया। उन्होंने बताया कि शोध के दौरान तमाम तरह की मुश्किलें सामने आईं। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में भविष्य में और प्रजातियों की खोज की जा सकती है।

शोध अनुसंधान

दिमाग के खास हिस्से से खाने की इच्छा होती है नियंत्रित

वैज्ञानिकों ने चूहों में एक ऐसे न्यूरोसर्किट का पता लगाया है, जिसके सक्रिय होने से तनाव बढ़ता है और उनकी खाने की इच्छा कम हो जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस शोध की मदद से खानपान की अनियमितता से जुड़ी एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसी बीमारियों का इलाज खोजने का रास्ता खुल सकता है। इस बीमारी में व्यक्ति खाना छोड़ देता है या बस किसी-किसी भोजन की बहुत थोड़ी सी मात्रा का सेवन करता है। ऐसे लोग अपना वजन बहुत कम होने पर भी खुद को मोटा समझते हैं। यह सभी मानसिक बीमारियों में सर्वाधिक जानलेवा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि चूहे के दिमाग के एक ऐसे हिस्से की पहचान में सफलता मिली है, जहां से खाने की इच्छा नियंत्रित होती है। मनुष्यों में भी यह प्रयोग सफल रहा, तो इस तरह की बीमारियों के इलाज का नया रास्ता खुल सकता है। - एएनआइ

महिलाओं की भावनाओं पर भोजन का ज्यादा पड़ता असर

महिलाओं को भावनात्मक रूप से स्वस्थ और मजबूत बने रहने के लिए पुरुषों की तुलना में ज्यादा पोषक भोजन की जरूरत होती है। विज्ञान पत्रिका 'न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंस' में प्रकाशित शोध में यह बात सामने आई है। शोधकर्ता लीना बेदेश की अगुआई में 563 लोगों पर अध्ययन किया गया। इनमें 48 फीसद पुरुष और 52 फीसद महिलाएं थीं। अध्ययन में पाया गया कि पुरुष मानसिक और भावनात्मक रूप से तब तक संतुलित बने रहते हैं, जब तक कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो जाए। वहीं महिलाओं की भावनात्मक मजबूती के लिए जरूरी है कि उन्हें पर्याप्त पोषण मिलता रहे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन नतीजों से यह भी पता लग सकता है कि आखिर महिलाओं में मानसिक तनाव की आशंका ज्यादा क्यों रहती है। इन नतीजों की मदद से दिमाग पर भोजन और पोषण से पड़ने वाले असर को समझते हुए इन समस्याओं से निपटने के तरीके भी ईजाद किए जा सकेंगे। - एएनआइ

भारी-भरकम प्लेन खींचने की अनोखी प्रतियोगिता

अक्सर आपने गाड़ियां और ट्रक खीचकर रिकार्ड बनाने देखा-सुना होगा, लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच पर प्लेन खीचने की अनोखी और रोमांचकारी प्रतियोगिता होती है। यह प्रतियोगिता बौद्धिक दिव्यांगों और एथलीटों की मदद के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से की जाती है। इसमें करीब 25 सदस्यों वाली 80 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान 24,000 पाउंड (लगभग 56 हजार किलोग्राम) वजनी विमान खींचना पड़ता है। जो टीम सबसे तेजी से प्लेन को निर्धारित दूरी तक खीचने में सफल होती है, उसे विजेता घोषित किया जाता है। इस वर्ष इस प्रतियोगिता के जरिए करीब दो लाख डॉलर की राशि जुटाई गई। एएफपी

51 साल बाद मिला विमान का मलबा

डोगरा स्काउट्स के एक अभियान दल ने बांग्लादेश के ढाका ग्लेशियर से 51 साल पहले बर्फीले पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायु सेना के एएन-12 परिवहन विमान के हिस्सों को बरामद किया है। एएन-12 बीएल 534 विमान में सवार 90 से अधिक लापता सैनिकों के शव के अवशेष बरामद करने के लिए 26 जुलाई को एक ऑपरेशन शुरू किया था। यह विमान 7 फरवरी 1968 को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रोहतांग दर्रे के ऊपर से लापता हो गया था। 5, 240 मीटर की ऊंचाई पर ढाका ग्लेशियर में कठिन खोज अभियान के बाद टीम ने विमान के कुछ हिस्सों जैसे एयरो इंजन, धड़, इलेक्ट्रिक सर्किट, प्रोपेलर, फ्यूल टैंक यूनिट, एयर ब्रेक असेंबली और कॉकपिट डोर को बरामद किया। एएनआइ

स्क्रीन शॉट

अच्छे शॉट के लिए अनन्या को मिला था 500 रुपये का इनाम

करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर2' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अभिनेत्री अनन्या पांडे फिल्म रिलीज होने के तुरंत बाद ही अपने करियर की दूसरी फिल्म 'पति, पत्नी और वो' की शूटिंग में जुट गई थीं। वैसे डेब्यू फिल्म में अभिनय के लिए अनन्या की बतौर न्यूकमर तारीफ भी हुई थी। बहरहाल, अभिनेत्री ने अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है और इसी से जुड़ा एक किस्सा भी सामने आया है। अनन्या ने बताया है कि, 'पति, पत्नी और वो' की शूटिंग के दौरान मैं कार्तिक आर्यन के साथ एक सीन का शॉट दे रही थी। इसमें सीन में एक भी लाइन का संवाद नहीं था और मुझे केवल कार्तिक की बातों पर चेहरे के हावभाव से प्रतिक्रिया देनी थी। यह मेरे

लिए शूटिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा था। हालांकि शॉट पूरा हो गया। हमने आम दिनों की तरह ही अपना काम किया था। तभी ब्रेक के दौरान मुदस्सर सर मेरे पास आए और उन्होंने मेरे हाथ में 500 रुपये का नोट रखते हुए कहा- 'मुझे तुम्हारा शॉट बेहद पसंद आया।' यह किसी भी नए कलाकार को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका है।' मुदस्सर अजीज निर्देशित यह फिल्म 1978 में आई इसी नाम की फिल्म की रीमेक है। इसमें भूमि पेडणेकर भी हैं। फिल्म अगले साल जनवरी में रिलीज होगी।

थ्रिलर होगी कृति सैनन की अगली फिल्म

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'अर्जुन पटियाला' में दिखाई दीं अभिनेत्री कृति सैनन अपने करियर में पहली बार थ्रिलर फिल्म करने वाली हैं। इस फिल्म में कृति एक आरजे का किरदार निभाएंगी, जिसकी कहानी मेडिकल स्कैम पर आधारित होगी। इस बारे में कृति ने बताया, 'यह मेरी हिंदी में पहली थ्रिलर फिल्म होगी और मैं इसके लिए वास्तव में उत्साहित हूं। हालांकि मैंने इससे पहले तेलुगु भाषा में एक थ्रिलर फिल्म की थी और मुझे थ्रिलर पसंद है।' इस प्रोजेक्ट को लेकर अभिनेत्री ने बताया, 'इस फिल्म के जरिए हम देश के एक महत्वपूर्ण विषय को भी दिखाएंगे, जिसके बारे में हम जल्द ही बात करेंगे। मेरे लिए किरदार महत्वपूर्ण है और उसके लिए काफी अधिक मेहनत करनी होगी। वैसे मैं फिल्म के विषय से बहुत प्रभावित हूं।' फिल्म के निर्देशक राहुल ढोलकिया हैं और फिल्म इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक फ्लोर पर आ जाएगी। वैसे कृति सैनन आशुतोष गोवारिकर की पीरियड ड्रामा फिल्म 'पानीपत' में भी नजर आएंगी।

मेरी फिल्मों में कहानी मजबूत होती है : आर. बाल्की

सात सवाल

सामाजिक मुद्दे पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली 'पैडमैन' के निर्देशक आर. बाल्की ने ही 'मिशन मंगल' की कहानी भी लिखी है। इससे पहले वह 'चीनी कम', 'पा', 'शमिताभ' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। उनसे बातचीत :

'पैडमैन' को सामाजिक मुद्दा उठाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है... ?

- इस पुरस्कार का श्रेय अरुणाचलम मुरुगनाथम को जाता है, जिन्होंने अपने जीवन संघर्ष से यह कहानी लिखी। मैंने अपनी कल्पना से कुछ बदलाव जरूर किया। 'मिशन मंगल' को भी पुरस्कार मिलना चाहिए। यह फिल्म भी इसकी हकदार है। उसका श्रेय इसरो को जाएगा।

आजकल वास्तविक कहानियों और किताबों पर ज्यादा फिल्में बन रही हैं, क्या वजह मानते हैं ?

- दर्शकों को वास्तविक कहानियां काल्पनिक कहानियों से ज्यादा रोचक लग रही हैं। मैं 'पैडमैन' के बाद फिर से वास्तविक घटना पर फिल्म नहीं बनाना चाहता था, पर 'मिशन मंगल' के निर्देशक जगन शक्ति के आग्रह पर इसे प्रोड्यूस करने पर राजी हो गया। अक्षय कुमार को भी कहानी अच्छी लगी। वह फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए। मैंने लेखकों से कहा कि साइंस पर आधारित हर चीज को इतना आसान कर दो कि सबको समझ आए। फिर हमें वीएफएक्स में ज्यादा वक्त लगा।

आप 'मिशन मंगल' को महिला सशक्तीकरण की फिल्म नहीं मानते हैं ?

- यह मानव सशक्तीकरण की फिल्म है। हमें इंसान को सशक्त बनाने के बारे में सोचना चाहिए। लिंगभेद नहीं होना चाहिए। इसरो कभी महिला या पुरुष वैज्ञानिक में भेद नहीं करता है। हमें अपने शब्दकोश से महिला सशक्तीकरण के शब्द को निकाल देना चाहिए। हमें मानव सशक्तीकरण की बात करनी चाहिए।

हॉलीवुड से अपनी फिल्मों की तुलना में क्या वास्तव में बजट ही सबसे बड़ी समस्या है ?

- इसरो ने हमें सिखाया कि हम सीमित संसाधनों में भी काम कर सकते हैं। लोग क्यों फिल्मों को हॉलीवुड के बजट में बनाना चाहते हैं? अगर हम भी दो-तीन उदाहरण पेश करेंगे, तो हमें भी बजट मिलेगा। हमारा बजट भी आजकल कम नहीं है। धीरे-धीरे बढ़ ही रहा है।

आपकी फिल्मों में महिला किरदार मजबूत होते हैं ?

- मेरी फिल्मों में महिला या पुरुष किरदार मजबूत नहीं होते, बल्कि कहानी मजबूत होती है। कहानी मजबूत होगी तो किरदार भी मजबूत होंगे। 'चीनी कम' में अमिताभ बच्चन का किरदार भी मजबूत था।

आजकल लोग कहानियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्या अब स्टार वैल्यू खत्म हो रही है ?

- पहले भी कहानियों पर जोर दिया जाता था। मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा की स्क्रिप्ट लाजवाब हुआ करती थी। बहुत ही कम फिल्में हैं, जो सिर्फ स्टार के चेहरे के कारण सफल हुई हों। हमें एक अच्छी फिल्म के लिए हमेशा एक अच्छी कहानी की जरूरत होती है।

अगली फिल्म क्या है ?

- अभी 'मिशन मंगल' रिलीज हुई है। अगली फिल्म के बारे में विचार करूंगा। मैं कहानी लिखने में थोड़ा वक्त लेता हूं।

स्मिता श्रीवास्तव

उम्मीद

कैंसर कोशिकाओं के आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना ईलाज करती है यह प्रोटॉन थेरेपी, रेडिएशन का साइड इफेक्ट भी नहीं होता

टोमो व प्रोटॉन थेरेपी से खत्म होगा कैंसर

जागरण संवाददाता, मेरठ

अगर रेडिएशन की डोज कैंसरग्रस्त कोशिकाओं में पहुंचकर घुल जाए, आसपास के ऊतकों को नुकसान न पहुंचाए तो ये किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर के इलाज में प्रोटॉन थेरेपी बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। इससे निकलने वाली हाई एनर्जी बीम अंगों को भेदकर आगे नहीं निकलती है। प्रोटॉन थेरेपी से मरीज में रेडिएशन का साइड इफेक्ट नहीं उभरता है। डॉ. जिलानी ने बताया कि प्रोटॉन थेरेपी की सुविधा फिलहाल चेन्नई में है, जबकि टोमोथेरेपी मेरठ जैसे शहरों में चिकित्सा की दिशा बदल रही है।

कैंसर खत्म करते हैं प्रोटॉन के कण

वेलेंटिस कैंसर अस्पताल की ओर से गत दिवस मेरठ में आयोजित वर्कशॉप में पहुंचे प्रोटॉन कैंसर सेंटर चेन्नई के विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश जलाली ने बताया कि कोबाल्ट-60 से शुरू रेडियोथेरेपी अब काफी सुरक्षित फेज तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि टोमोथेरेपी की रेंज व्यापक है। तकरीबन सभी प्रकार के कैंसर में बेहद कारगर साबित हुई है। प्रोटॉन थेरेपी के लिए हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रान निकाल दिया जाता है। सिर्फ प्रोटॉन बचता है, जिसका प्रयोग रेडिएशन में करते हैं। ये हाई एनर्जी बीम मरीज की

डॉ. राकेश जलाली। जागरण

कैंसरग्रस्त कोशिका पर पड़कर वहीं रुक जाती है। ये बीम आसपास नहीं भटकती हैं। ऐसे में स्वस्थ कोशिकाओं पर रेडिएशन का कोई असर नहीं पड़ता। ये थेरेपी ब्रेन, स्पाइन के सूक्ष्म ट्यूमर, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट एवं बच्चों के साफ्ट टिश्यू के कैंसर में काफी प्रभावी साबित होती है। इस थेरेपी से न मरीज के बाल झड़ते हैं और न ही त्वचा पर असर पड़ेगा।

सामान्य जिंदगी की सौगात : डॉ. जलाली ने बताया कि टोमोथेरेपी व फोटॉन थेरेपी भी काफी सुरक्षित हैं, लेकिन प्रोटॉन थेरेपी से मरीज में रेडिएशन का दुष्प्रभाव बाद में भी नहीं उभरता। दिमाग के ट्यूमर में कई बार रेडिएशन से स्मरण शक्ति व आइक्यू वाले न्यूरान्स नष्ट हो जाते हैं। किंतु प्रोटॉन थेरेपी इस लिहाज से बेहद सुरक्षित है।

स्लीप एप्निया से पीड़ित महिलाओं में कैंसर का खतरा ज्यादा

लंदन, आइएएनएस : शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया (ओएसए) यानी सोते समय सांस का अटकना जिससे खर्राटे आते हैं, इस समस्या से पीड़ित महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कैंसर होने का खतरा ज्यादा है। द यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल में प्रकाशित यह अध्ययन यूरोपियन डेटाबेस ईएसएडीए दारा एकत्र किए गए स्लीप एप्निया के 20,000 वयस्क मरीजों के डाटा के विश्लेषण के आधार पर किया गया है। स्वीडन में गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक लुडगर ग्रॉट ने कहा, 'यह मान लेना उचित है कि स्लीप एप्निया कैंसर के लिए एक जोखिम कारक है वहीं दूसरी ओर इसकी संभावना कम है कि कैंसर से स्लीप एप्निया हो सकता है।' शोधकर्ताओं के मुताबिक, बढ़ती उम्र में कैंसर का जोखिम भी बढ़ता है, लेकिन उम्र, लिंग, बॉडी मास इंडेक्स, धूमपान और मादक द्रव्यों के उपयोग के आंकड़ों को समायोजित करने से पता चलता है कि स्लीप एप्निया के कारण रात में हाइपोक्सिया यानी शरीर के ऊतकों में सही मात्रा में ऑक्सीजन न पहुंचने से कैंसर होने का खतरा और भी बढ़ जाता है।